

प्रथम प्रकाशन

अक्टोबर, १९५०

मूल्य ३।।।)

अर्थ-वाणिज्य-गवेषणा मंदिर, १२, हाफ स्ट्रीट, कलकत्ता-६ से कमला देवी के द्वारा प्रकाशित तथा सुराना प्रिन्टिंग वर्क्स, ४०२, अपर चितपुर रोड कलकत्ता से नवरतनमल सुराना द्वारा मुद्रित ।

नाममात्र भूमि है। इन खेत-मजदूरों की संख्या इतनी अधिक होती हुए भी संगठनके अभावसे इनकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय है। आज गाँव सुधारके लिए खेत-मजदूर-वर्गकी समस्या बहुत जटिल है और जब तक इनके लिए कामका प्रबन्ध नहीं होगा, न्यूनतम मजदूरी कानूनकी व्यवस्था नहीं होगी तब तक गाँव सुधारका एक बड़ा भारी दायित्व हमारे ऊपर लगा रहेगा। हमारे देशकी अधिक से अधिक त्रियां सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जीवनमें दाय नहीं घंटा सकती हैं। एक तो उनमें इतनी योग्यता ही नहीं और दूसरे, वातावरण भी उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। इस देशकी स्त्रियोंमें शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्यकी कमी है; जिनकी दृष्टिमें आधुनिकताको छाप तक नहीं है वे किस प्रकारसे भविष्यके नागरिकोंको तैयार बना सकती हैं? इस लिए स्त्रियोंकी सामाजिक मर्यादा बढ़ानेकी विशेष आवश्यकता है ताकि वे नो विभिन्न समस्याओंको समझ सकें, इनपर ध्यान दे सकें, और हर तरहके पुरुषोंके साथ सहयोग कर सकें। इसके साथ ही साथ शिक्षाका विस्तार तथा सामाजिक सुधारकी विशेष आवश्यकता है।

भारतकी कृषि-समस्यायें और उनका सुधार

अतीत कालमें हमारी आर्थिक स्थिति जैसी भी क्यों न रही हो वर्तमान समय में हमारी जनसंख्या का तीन-चौथाई भाग एक मात्र इसी उपयोग ही निर्भर करता है तथा ९०% जनता गाँवोंमें ही रहती है। हमारे आर्थिक जीवन में कृषि इतनी महत्वपूर्ण होती हुए भी यह समस्याओं से भरी हुई है। हमारी कृषि-समस्या बहुमुखी है। अति प्राचीन कालसे जिस रीतिसे खेतीका

सूचीपत्र

निबन्धावली :

पृष्ठ-संख्या

गांधीवादो अर्थशास्त्रकी रूपरेखा	...	१-५
विभाजनका आर्थिक आधार	...	६-११
भारतकी जन समस्या—क्या भारतकी जनसंख्या अधिक है ?	...	११-१८
गाँव-सुधार	...	१८-२४
भारतकी कृषि-समस्याएँ और उनका सुधार	...	२४-३३
हमारी खाद्य-समस्या—क्या हम खाद्यान्नके बारेमें पूर्ण स्वतन्त्र बन सकते हैं ?	...	३४-४०
दामोदर घाटी-योजना	...	४१-४८
जमींदारी-प्रणालीका भविष्य—आगे क्या ?	...	४८-५५
भारतमें औद्योगिक विकास	...	५५-६२
भारतीय उद्योग-धन्धोंमें रकमकी पूर्ति—औद्योगिक पूँजी विनियोग संस्था—विदेशी पूँजीकी महत्ता	...	६२-६८
हमारी आर्थिक योजना—उसका लक्ष्य और आधार	...	६८-७५
राष्ट्रीयकरणकी समस्या	...	७५-८०
स्वतन्त्र भारतकी आर्थिक नीति—युद्धोत्तर भारतका आर्थिक पुनर्गठन	...	८१-८३
भारतमें औद्योगिक शिथिलता	...	८४-८७
आर्थिक संकट या व्यापारिक मन्दी—बेकारीकी समस्या—भारतमें पूर्ण-विनियोगकी आवश्यकता	...	८७-९२
भारतमें मजदूर समस्या—भारतमें मजदूर आन्दोलन—मजदूर हित-कार्य—सामाजिक बीमा—भारतमें सामाजिक बीमा	...	९२-१००

सीमित न रहेगा बल्कि भारतीय युक्तराष्ट्र से सम्बन्धित देशीय राज्य में भी उद्योग-धन्धों को आर्थिक मदद देने की योग्यता इसमें रहेगी (२) यह मदद सिर्फ सार्वजनिक परिमित दायित्व कम्पनियों को तथा सदकारी समितियों को प्राप्त होगी । (३) इस संस्था की रकम १० करोड़ रुपयेकी होगी जिसमें ५ करोड़ रुपये कीमतकी शेयरें अभी-अभी जारी की जायेंगी एवं अवशिष्ट धनमें केन्द्रिय सरकार की अनुमति लेकर आवश्यकतानुसार जारी की जायेंगी । (४) इस संस्थाकी शेयरें किसी व्यक्ति को नहीं दी जायेंगी । (५) पूँजी तथा निदिष्ट लाभांश देनेकी जिम्मेदारी केन्द्रिय सरकार पर रहेगी । (६) संस्थाका सारा प्रबन्ध एक बोर्डपर रहेगा जिसमें १२ पदाधिकारी रहेंगे । इनमें से ६ केन्द्रिय सरकार तथा रिजर्व बैंक के द्वारा मनोनीत होंगे तथा अवशिष्ट ६ दूसरे शेयरधारियों के प्रतिनिधि होंगे । (७) यह संस्था अपनी प्राप्त हिस्सा पूँजी तथा संचित अधिकोप से ५ गुणा अधिक रकम कर्ज ले सकेगी तथा जनसाधारणसे भी यह ५ सालकी स्थायी अमानत लेगी । (८) यह संस्था उद्योग-धन्धोंको जो कर्ज देगी वह भारतीय रुपया या दूसरे किसी देश का सिक्का हो सकेगा । १ साल में यह संस्था ३ करोड़ रुपया कर्ज मंजूर की है/जिसमें १ करोड़ रुपया सन १९४६ के जून महीने तक दे दिया गया एवं अवशिष्ट हिस्सा दिया जा रहा है । सर्वोच्च कर्ज का परिमाण ४० लाख रुपया है एवं सर्वनिम्न कर्ज का परिमाण २ लाख रुपया है । २५ कम्पनियों को इससे फायदा पहुँचा है जिनमें अधिक से अधिक कम्पनियाँ सिमेंट तथा कपड़े की पैदावार से सम्बन्धित हैं । संस्था के दफ्तर कलकत्ता तथा बम्बई में स्थापित किये गये हैं एवं और दफ्तर मद्रास तथा कानपुर में स्थापित किये जानेवाले हैं । इसे १ साल में २८५५०७ रुपया मुनाफा हुआ है एवं २१% लाभांश दिया गया है ।

विदेशी पूँजीकी महत्ता—विदेशी पूँजी भारतके उद्योग-धन्धोंमें विशेषतः रेल, कोयले, चाय, पाट इत्यादि उद्योगों में अधिक मात्रा में लगी हुई है ।

निबन्धावली :	पृष्ठ-संख्या
भारतका आयात-निर्यात वाणिज्य और उसका भविष्य	१००-१०७
हमारे स्टार्लिंग पावने	१०७-११४
डालरकी कमी—मार्शल योजना	११५-११८
संरक्षण नीति, शिल्प तथा व्यापार	११८-१२३
भारतीय यातायात प्रबन्ध—जहाज-निर्माण-शिल्प असामरिक उद्घन-विद्या	१२३-१२२
भारतमें मुद्रास्फीतिके दुष्परिणाम—युद्धोत्तर समयमें मुद्रास्फीति	१२३-१४०
रुग्णका मूल्यहास	१४०-१५१
भारतीय बैंक-व्यवस्था—बैंक-व्यवस्थाका सुधार	१५१-१५७
भारतीय रिजर्व बैंककी महत्ता—रिजर्व बैंकका राष्ट्रीयकरण	१५७-१६२
भारतमें बीमा व्यवसाय	१६३-१६८
धनका असम विभाजन और उसका परिणाम— आधुनिक राष्ट्रीकी करनीति	१६९-१७२
समाजवादकी रूपरेखा—भारतीय जीवनमें समाजवादकी उपयोगिता	१७२-१७८
शब्दावली	

विदेशी पूंजी की आवश्यकता—हमारी वर्तमान आर्थिक स्थितिसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि देशमें संचय का परिमाण संतोषजनक नहीं है। पूंजी-बाजार की स्थिति आज इतनी बिगड़ गई है कि सरकारी ऋणपत्र भी अधिक नहीं खरीदे जाते। हमारी भविष्य आर्थिक योजना में यन्त्रों तथा विदेशी कलाविदों की आवश्यकता होगी। विदेशी पूंजी के बारे में सरकार की नवीन नीति निम्न प्रकार है :—(१) वर्तमान उद्योग-धन्धों में लगी हुई विदेशी पूंजी पर—जोकि सरकार की औद्योगिक नीति से सहयोग रखती है—सरकार कोई भी ऐसी शर्त नहीं लगायेगी जो भारतीय उद्योगों पर लगू न हो ; (२) विदेशी पूंजी देशमें लाभ कमा सकेगी और साधारणतः विदेश को लाभ भेजने पर कोई रोक नहीं लगायी जायेगी परन्तु विदेशी विनिमय की कठिनाइयों को ध्यानमें रखकर ही इस प्रकार की सुविधा दी जा सकेगी ; (३) साधारणतः उद्योग-धन्धों के स्वामित्व और प्रबन्ध में भारतीय नागरिकों का मुख्य हाथ होगा और विशेष अवस्था में सरकार कितनी भी उद्योग को हस्तान्तरित या नियन्त्रित कर सकती है ; यदि आवश्यक योग्यताके भारतीय श्रमिक न मिले तो विदेशी कारखाने विदेशियोंको नौकरी दे सकते हैं, परन्तु, साथ ही साथ ऐसे कामोंके लिये इन कारखानाओंको कुशल भारतीय कलाविद और श्रमिक तैयार करने होंगे ; (४) भारतीय उद्योग-धन्धों को उत्साहित करना सरकारकी नीति है लेकिन आज भी और भविष्यमें भी देशके औद्योगीकरणमें विदेशी पूंजीके लिये बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा। सरकार की नवीन नीतिके बारेमें अर्थ-संदेशाने लिखा है :— विदेशी और भारतीय पूंजीमें किसी प्रकारका भेद-भाव नहीं किया जायेगा यह आश्वासन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक औद्योगिक क्षेत्रोंकी बढ़ जोरदार मांग रही है कि भारतीय पूंजीके विकासके लिये विदेशी पूंजी पर कड़ी शर्तें लगानी आवश्यक है। उस वक्तव्यने सदाके लिये इस मांगको समाप्त कर दिया है। दूसरा भय विदेशी पूंजीकी राष्ट्रीयकरणका बना हुआ था। सरकारने स्पष्ट घोषित

गांधीवादी अर्थशास्त्रकी रूपरेखा

भारतीय अर्थ व्यवस्थामें गांधीवादी अर्थशास्त्रकी उपयोगिता—अविभक्त भारतकी ३९ करोड़ जनसंख्यामें ग्रामीणोंकी संख्या ३४ करोड़ है। (ग्रामीणोंकी सामाजिक तथा आर्थिक दुरवस्थाका कारण—भारतकी कृषि समस्याएं तथा गृह-उद्योगकी कमी—गांव सुधारके सम्बन्धमें निबन्ध देखिये।)

स्वाभाविक तथा शाश्वत अर्थशास्त्रकी रूपरेखा—(क) शोषण तथा आर्थिक विषमताका अभाव,—(ख) उत्पादन रीतिका सरल व सीधी होना,—(ग) जीवनमें उच्चता होना एवं उसमें आवश्यकताओंकी इतनी प्रचुरताका न होना कि रहन सहनका सारा ढाँचा कृत्रिम व परनिर्भर हो जाए,—(घ) उत्पादन, वितरण, व्यापार तथा उपभोगका इस प्रकार नियन्त्रित होना कि क्रय विक्रयकी शक्ति अधिक केन्द्रित न होने पावे—“जब तक हमारी प्रधान आवश्यकताओंकी पूर्ति बिना किसी अन्यके अधिकारोंपर आघात किये न कर सकें तबतक अहिंसाका कोई प्रयोजन नहीं रहता।” (श्रीकुमारप्पाजी) स्वाभाविक अर्थव्यवस्थामें प्रधान आवश्यकताओंकी पूर्ति अवश्य होती है जिससे हमारा शरीर सतत स्वस्थ सजीव एवं कार्यक्षम रहे। इसी दृष्टिसे गांधीवादी अर्थव्यवस्थामें खादी तथा गृह-उद्योगका स्थान है।

गांधीवादी अर्थशास्त्रकी मौलिकता—अर्थशास्त्र जनताके जीवनका स्तर ऊँचा करना चाहता है लेकिन वास्तवमें पूंजीवादी अर्थशास्त्रमें अर्थ ही मुख्य स्थान पर आ जाता है, जनताका जीवनस्तर नहीं। गांधीजी

उत्पादन व्यवस्था को घटाने की भी आवश्यकता है। इससे प्रत्येक देश आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र बन जायेंगे। कुछ दिन पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अर्थ-सचिवों का जो जलसा लण्डनमें हुआ था उसमें यह निश्चय किया गया कि साम्राज्य के विभिन्न देश प्रतिशत २५, हिस्सा कम सामग्रियाँ उालर सम्बन्धित देशों से सरोहेंगे। हाल में स्ट्रालिंग, रुपना आदि कई सिक्कों की विनिमय कीमत घटाई गई है ताकि इन सब देशों का निर्यात व्यापार उल्लाहित हो सके। (रुपये का मूल्य इस विषयक निबन्ध देखिए)

संरक्षणनीति, शिल्प तथा व्यापार

प्रथम महायुद्ध के पहले भारत सरकार की किसी भी प्रकार की निर्यात संरक्षण नीति नहीं थी। सरकार कभी कभी आयात बाणिज्य पर शुल्क लगाती थी लेकिन यह सिर्फ सरकारी आमदनी बढ़ाने के लिये, उद्योग-धर्मों को संरक्षित करने के लिये नहीं। ब्रिटिश सरकार की तरह सन् १८८२ से लगाकर इस समय तक भारत सरकार की नीति अन्तर्गत बाणिज्य की नीति थी। प्रथम महायुद्धके प्रभाव से भारतीय उद्योग-धर्मों कुछ हद तक उत्साहित हुए। सन् १९१९ की भारत शासन विषयक कानून बनाने के लिए कानून की हुई सम्मिलित संस्था ने यह सलाह दी कि निर्यातसंरक्षण के बारे में भारतीय स्वतन्त्रता को मान लेनी चाहिये। इस सलाह के अनुसार सन् १९२२ में एक विधायक कमीशन नियुक्त हुई। इस कमीशन ने उद्योग-धर्मों को संरक्षित करने के प्रश्न पर गंभीर ध्यान दिया और इसके पक्ष तथा विपक्षी पक्षों का पूरा विश्लेषण किया। अन्त में उद्योग निर्यात प्रस्ताव रखा कि

वास्तवमें अर्थको जनकल्याणका साधन बनाना चाहते थे—“मेरी राय यह है कि पड़े पैंगानेपर उद्योगधन्ये दुर्नीतिका स्थान घन जाते हैं । समाजवाद कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, इसको जड़मूलसे उखाड़नेकी शक्ति इसमें नहीं है ।” राष्ट्र-नियन्त्रित समाजवाद व्यक्तित्वके विकासके प्रतिकूल है । इसलिए गांधीवादी अर्थशास्त्रमें विकेन्द्रित अर्थव्यवस्थाका समर्थन किया गया है, कारण कि विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था व्यक्तित्वके विकासका सहायक है ।

गांधीवादी अर्थव्यवस्थानें व्यक्तिका स्थान—अर्थव्यवस्थाके साथ व्यक्तित्वके विकासका गहरा सम्बन्ध है । व्यक्तित्वके विकासका सम्बन्ध अभावकी अधिक अनुभूतिसे नहीं है । उन्नत जीवनस्तरका लक्ष्य भौतिक सम्पत्तिका बाहुल्य नहीं है । गुणात्मक दृष्टिसे व्यक्तिके जीवनका विचार करना चाहिए । “हम तो यही कहेंगे कि गांधीजीके जीवनका मापदण्ड अधिक ऊँचा था क्योंकि उनके जीवनमें उदार, मानवी गुणोंकी सम्पन्नता थी और उनकी भौतिक आवश्यकताएं सरलतासे भरी हुई थीं जबकि (गुणात्मक दृष्टि से) ब्रिटिश टॉमिका जीवन-प्रमाण निम्नकोटीका तथा इयत्तात्मक दृष्टिसे जटिलताके दोषों से परिपूर्ण है अतएव हम अपने राष्ट्रको जो जीवन-स्तर देना चाहते हैं वह सरलताकी दृष्टिसे उन्नत होगा” (कुमारपाजी)

गांधीवादी अर्थव्यवस्था में समाज—प्रमाजको जीवनोपयोगी सामग्रियां देना गांधीवादी-योजनाका लक्ष्य है । साथही साथ सारी जनताके लिए पूर्ण विनियोग का प्रबन्ध होना चाहिए, धन वितरण धनोत्पादनकी विधिके अनुकूल होना चाहिए ताकि समाजमें एक ओर विपुल धन संचय और दूसरी ओर शोचनीय-निर्धनता न दिखाई पड़े इसके लिए उत्पादन का ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए जिसमें हमारे श्रमके अनन्त साधनोंका पूर्ण उपयोग हो सके ।

गांधीजीकी दृष्टिमें स्वतन्त्र भारतका आर्थिक संगठन—आर्थिक दृष्टिसे स्व-राज्य—गांधीजीका कहना है कि यदि हम अपनी पहुंचके भीतरके

जहाज निर्माण शिल्प—प्राचीन कालमें भारतीय जहाज निर्माण शिल्प विशेष महत्वपूर्ण था। पाश्चात्य देशोंमें औद्योगिक क्रान्ति आनेके पहले इष्ट इंडिया कम्पनी भारत में बनी हुई जहाजोंसे काम लेती थी। लेकिन जबसे पाश्चात्य देशोंमें वैज्ञानिक उन्नतिके कारण यातायात साधनोंमें गम्भीर परिवर्तन हुआ एवं लोहा तथा इस्पातसे जहाजें बनने लगीं तबसे भारतीय जहाज निर्माण शिल्प में हानि पहुंचने लगी कारण, राजनैतिक अव्यवस्था के कारण भारत वैज्ञानिक उत्कर्षके साथ अपनी आर्थिक स्थितिको अपनी नहीं चला। इस समयसे भारत में बनी हुई सामग्रियां विदेशी जहाजों पर लद कर बहल जाती हैं और इससे हमारे व्यापारियोंको काफी नुकसान पहुंचता है। हमारा विदेशी व्यापार बहुत बढ़ा चढ़ा है; सन् १९३९ में भी इसकी सीमत ४२९०४६ करोड़ रुपये थी। इसका प्रतिशत ४ दिस्का मात्र भारतीय जहाजोंमें भेजा या मंगवाया जाता था। समुद्रतटीय व्यापारमें भी विदेशी जहाज कर्मचारियोंका प्रभुत्व बहुत दिन तक कायम था जिससे कि सन् १९३९ में इसका प्रतिशत २१ या २२ दिस्का मात्र भारतीय कर्मचारियों के हाथमें था।

भारतीय जनमत अनेक दिनोंसे भारतमें जहाज-निर्माण शिल्प कायम करनेके पक्षमें खड़ा होता आ रहा है। कभी-कभी यहाँ तक भी बढ़ गया है कि समुद्रतटीय व्यापारको पूरी तौरसे भारतीय कर्मचारियोंके लिये संरक्षित किया जाय। पहले लड़ाईके बाद भारतीय जनमतची (दली) इसकी महत्त्वपूर्ण भी कि सरकार उसे उपेक्षा न कर सके तथा इसको उपसोषितारके बरिमें निर्णय करनेके लिये सन् १९२३ में एक कमेटी भी कायम की गई। इस कमेटीकी सलाह निम्नप्रकार थी :—इतिहासिक महत्त्वपूर्णतामें जहाज कर्मन्धी शिक्षाका प्रबन्ध किया जाय तथा समुद्रतटीय व्यापारमें निम्न जहाजोंमें भारतीयोंके शिक्षाका प्रबन्ध किया जाय; समुद्रतटीय व्यापार भारतीय या भारतमें बनी हुई कर्मचारियों के लिये संरक्षित किया जाय; अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारमें दिस्का लेदेवाली कर्मचारियोंको अधिक बढ़ावा दी जाय तथा

साधनों से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लग जायें तो उन आवश्यक पदार्थों का पर्यवेक्षण हमारे लिए सुगम हो जायेगा। आर्थिक स्व-राज्य तथा खादी—हाथसे कपड़ा उत्पन्न करनेका महत्व हम इस सिद्धान्त पर मानेंगे कि जीवनके लिए प्रारम्भिक आवश्यकताओं को पूरी करनेवाली वस्तुएँ विकेन्द्रित उद्योगों द्वारा पैदा की जा सकें तो अच्छा है। गांधीजीकी व्यक्तिवादी दृष्टि में राष्ट्रीय दृष्टिकोण का सुयोग सबसे कम है और इसलिए भारतीय आर्थिक संगठनको ग्रामकेन्द्रिक बनानेकी आवश्यकता है।

गांधीवादी अर्थशास्त्रमें राष्ट्रवालिप्त पूँजीवाद तथा समाजवादकी तीव्र समालोचना—गांधीजी व्यक्तित्वका विकास चाहते थे, व्यक्तिवालिप्त पूँजीवादका नहीं। व्यक्तित्वके विकास के लिए तथा बेकारी को रोकनेके लिए वे यान्त्रिक उद्योग-धन्योंको नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि जब आवश्यक कार्यके लिए श्रमिकोंकी संख्या कम है तब यन्त्रोपकरणों को निःसन्देह काममें लाना चाहिए लेकिन जब कार्य के अनुपातसे कार्य निर्वाह करनेवालों की अधिक संख्या है जैसे कि भारतमें, तब यन्त्रोपकरणोंका प्रयोग बहुतही हानिकारक होगा। यन्त्रोपकरणों द्वारा अत्यसंख्यक मनुष्योंका जीवन-स्तर ऊँचा हो सकता है एवं उनके लिये आरामका प्रबन्ध भी हो सकता है लेकिन यदि देशकी विराट जनसंख्याके लिए पूर्णविनियोगका प्रबन्ध करना हो तो यन्त्रोपकरणोंका प्रयोग सीमित करना पड़ेगा, विकेन्द्रित उद्योग-धन्ये स्थापित करने होंगे एवं छोटे पैमाने पर खेतोंका काम शुरू करना होगा। समाजवादो व्यवस्थामें भी ठीक इसी कारणसे यन्त्रोपकरणोंका प्रयोग सीमित रखना होगा। यान्त्रिक सभ्यताके विरुद्धमें गांधीजी का कहना है कि इसमें एक ओर तो धन वितरणकी विषमता आती है, बेकारियां फैलती हैं एवं व्यापारिक संकट बार बार आता रहता है एवं दूसरी ओर व्यक्तिगत जीवन तथा समाजगत जीवन पर इसका असर बहुतही क्षतिकारक होता है। बालसेभिड़म या उग्र साम्यवादके विरुद्धमें गांधीजीका कहना है

कि यह दीर्घ-स्थायी नहीं हो सकता तथा अपने आदर्शमें अटल भी नहीं रह सकता। मेरा तो यह निश्चित विश्वास है कि हिंसाके आधारपर किसी मुख्य आदर्शका संस्थापन नहीं हो सकता।

ग्रामकेन्द्रित गांधीवादी अर्थव्यवस्था और अ-राष्ट्रवाद—अ-राष्ट्रवादियों की तरह गांधीजीका आदर्श भी स्व-राज्य है यानी व्यक्ति-प्रधान राज्य है और यह व्यक्तित्व के पूर्ण विकास होने पर ही सम्भव हो सकता है। गांधीवादी अर्थ-व्यवस्था में उपनिधि-वाद-तत्त्व यानी ट्रस्टीसोपत्तत्व—धन वितरणकी विपमता को हटानेके लिए क्रान्तिकारी समाजवादकी आवश्यकता नहीं है; व्यक्ति समाजको सम्पत्तिका उपनिधि या ट्रस्टी है एवं व्यक्तित्वके विकास होने पर वह इस सम्पत्ति को अपने आप जनकल्याणमें लगा देगा।

गांधीवादी अर्थशास्त्र और विदेशी व्यापार—गांधीजीका कहना है कि हमें आवश्यक वस्तुओंके लिए विदेशियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और न नित्य प्रतिकी आवश्यक वस्तुओंमें विदेशी व्यापारको कोई स्थान ही रहना चाहिए; विदेशी व्यापारको पूर्णतया उन्हीं वस्तुओं तक सीमित रखना चाहिए जिनकी हमें आवश्यकता नहीं रह जातो। इस प्रकारका अतिरिक्त वस्तुओं पर आश्रित विदेशी व्यापार कभी भी युद्धका कारण नहीं बन सकता। विदेशसे आवश्यक वस्तुओंका क्रय निश्चय ही विदेशियोंको अपने देश पर आधिपत्य करनेके लिए निमंत्रण है—विदेशी आधिपत्यसे साम्राज्यवाद आता है तथा पूंजीवादी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। उद्योग-धन्धों पर आश्रित देश पिछड़े हुए देशोंको कब्जेमें रखना चाहते हैं ताकि उन्हें सस्ता कच्चा माल मिलता रहे तथा उनकी शिल्पजात सामग्रियोंका बाजार बना रहे लेकिन जब एकाधिक देश पूंजीवादी उद्योग-धन्धों पर आश्रित हो जाते हैं तब साम्राज्य तथा बाजारके लिए लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं यानी युद्ध एक आर्थिक वस्तु है। “जहाँ मृत शरीर होगा वहाँ गृद्ध भी होंगे ही। गृद्धोंसे मुक्ति पानेका सर्वोत्कृष्ट मार्ग तो मृत शरीरको गाड़ देनेमें है।

विदेशी वस्तुओं द्वारा आवश्यकताओंकी पूर्ति ऐसाही नृत शरीरका द्योतक है ।”

गांधीवादी मजदूर नीति—गांधीवादमें वर्ग-संघर्षका स्थान नहीं है एवं यह टूट्टीशिपके आधारपर प्रतिष्ठित है । श्रमिकोंमें वेकारी रोकनेके लिए गांधीजी मशीनके यथोचित नियंत्रण पर जोर देते थे । गांधीवादी अर्थ-व्यवस्थाका लक्ष्य उत्पत्तिके साधनोंका पूर्ण विकेन्द्रीकरण है जिससे काम करने वाला अपने उत्पादनका स्वयं ही मालिक बन सके—“आज मजदूरों के सामने एक ही ध्येय है, मीलोंके स्वामित्वमें तथा-कथित मालिकोंके साथ बराबरी का हिस्सा प्राप्त करना । जिस तरह पूंजी धन है उसी तरह मेहनत भी धन है । मीलों पर इन दोनों धनपतियोंका स्वामित्व होना चाहिए” । (महादेव देशाई) गांधीवादी आर्थिक योजनामें श्रमिकके अधिकार :—(१) निर्वाह योग्य मजदूरी, (२) काम करनेकी आरामप्रद सूत्रें, (३) सीमित घन्टे, (४) म्हाड़ोंके सम्झौतेके लिए उपयुक्त व्यवस्था ।

गांधीवादी अर्थव्यवस्थामें पूर्णविनियोग—पूँजीवादी तथा समाजवादी अर्थ-व्यवस्था वेकारीको रोक नहीं सकती और न आर्थिक योजनाके द्वारा ही पूर्णविनियोगका प्रबन्ध हो सकता । गांधीजीने भारतके आर्थिक आयोजनमें पूर्णविनियोगकी नीति पर बहुत अधिक जोर दिया । “बेरोजगारीकी सयसे बड़ी बुराई भौतिक नहीं, नैतिक है । इससे जो आवश्यकता उत्पन्न होती है वह नहीं, परन्तु यह जो नफरत और डर पैदा करती है वह और भी बुरी चीज़ है” । विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा पूर्णविनियोग का प्रबन्ध हो सकता है और इसीसे व्यापार चक्र को रोका जा सकता है ।

गांधीवादी अर्थव्यवस्था को कायम करनेका एक मात्र उपाय उनका रचनात्मक कार्यक्रम है ।

विभाजनका आर्थिक आधार

राजनैतिक कारणोंसे भारत आज हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तानमें विभक्त हो चुका है। इसका फल देशके लिये शुभ या अशुभ होगा, जनकल्याण के अनुकूल या प्रतिकूल होगा इस बातका निर्णय अभी नहीं किया जा सकता लेकिन साधारण तौरपर कहा जा सकता है कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थितिमें प्रत्येक देशको आर्थिक-शक्ति तथा जन-शक्तिको विशेष आवश्यकता है। इन दोनोंमें एकका अभाव होनेसे ही वह देश निःसन्देह शक्तिहीन हो जायेगा। हमारे जिन अर्थशास्त्रियोंने पाकिस्तानकी आर्थिक उन्नति की सम्भावनाका समर्थन किया है उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा है कि भारत तथा पाकिस्तानमें पूर्ण आर्थिक सहयोगकी आवश्यकता है, इन दोनों देशोंकी अर्थ-व्यवस्था बीते हुए दो सौ वर्षोंसे जिस तरहसे विकसित हो रही है उसमें विभिन्न प्रान्तोंका आर्थिक सम्बन्ध बहुत ही गम्भीर तथा अविच्छिन्न रहा है। इस परिस्थितिमें यदि हटाने इन दोनोंको पृथक् कर दिया जाय तो दोनोंके लिए ही इसका फल खराब होगा तथा दोनोंके आर्थिक विकाशके रास्तेपर रुकावटें पहुँचेगी। यह बात केवल देशरक्षा तथा आय-व्ययके विषयोंमें ही लागू नहीं है बल्कि आर्थिक विषयोंमें भी। इस संकीर्ण दृष्टिसे भी विभाजनका नतीजा अनिष्टकारक होगा। आधुनिक समयमें यदि आर्थिक जीवनको चारों ओरसे विकसित करना हो तो उसके लिये कृषि तथा उद्योगधन्योंकी आवश्यकता है। इस दृष्टिसे भी हमारे देशका एक प्रांत दूसरे प्रांतपर अवलम्बित है। पूर्वी बंगालकी पाटकी पैदावार पश्चिम बंगालके पाट शिल्पमें खपत होती है ; पंजाबकी रुईसे बम्बईमें कपड़ा बनाया जाता है। परन्तु विभाजनके कारण ये सब विभिन्न प्रांत एक दूसरेसे पृथक् हो गये हैं। यदि नए तौरसे इन प्रांतोंमें आर्थिक सम्बन्ध स्थापित न किया जाय तो एक ओर पाट तथा रुईकी

खपत न होगी और दूसरी ओर इसके कई कारखाने बन्द हो जायेंगे । पाकिस्तानकी शिल्प-सम्भावना निःसन्देह कम है, कारण कि खनिज सम्पत्ति अधिकसे अधिक पाकिस्तानकी सीमासे बाहर है । जो भी कुछ वषों न हो देश जब विभक्त हो गया है तब हमें अपनी आर्थिक सम्पत्तिकी जांच करके ही देखना होगा कि हमारी आर्थिक सम्भावना किस प्रकारकी है । इसके बारेमें कुछ आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं :

सम्पत्ति	भारत	पाकिस्तान
(१) कलकारखानोंकी स्थिति :—		
(क) कपड़ेके कारखाने	३८० कारखाने	९ कारखाने
(ख) पाटके ,,	१०८ ,,	—
(ग) चीनीके ,,	१५६ ,,	१० ,,
(घ) लोहा तथा इस्पात के	१८ ,,	—
(ङ) सीमेंटके ,,	१६ ,,	३ ,,
(च) कागजके ,,	१६ ,,	—
(छ) कांचके ,,	७७ ,,	२ ,,

(२) विभिन्न धन्धोंसे आय :—

	(रुपया)	(रुपया)
(क) खान प्रभृतिसे	६४१४७६२४	२३५४०८८०
(ख) वस्त्र शिल्पसे	४४८६८१४६०	२७२१८२२३
(ग) धातु या धातु पदार्थोंसे	६५२४४८३५	१८६३३९७४
(घ) गृह निर्माणसे	७८६६७४६२	१९१७३२७३
(ङ) परिवहनसे	१०४६३५४४७२	१८४७४६७२१
(च) राजस्वसे	२०६२११५१९	३८८०७४७२

(३) कृषि तथा खाद्यान्न :—

	भारत	पाकिस्तान
(क) पाट	९८३५१९ एकड़	१४०३७०० एकड़
(ख) रुई ✓	१३७७००००० ”	१६७००००० ”
(ग) चाय ✓	६४१२४३ ”	९६६५७ ”
(घ) चावल ✓	१७२२९००० टन	५३७६००० टन
(ङ) गेहूं ✓	४१९९७४० ”	२७८५२६० ”
(च) चीनी ✓	२६३१००० ”	५१७००० ”
(छ) मुंगफली ✓	२२७४००० ”	नाममात्र

(४) खनिज सम्पत्ति :—

(क) कोयला	२५०७९४०२ टन	१९८४७६ टन
(ख) पेट्रोल	६५९६८९५१ गेलन	२१११३४२० गेलन
(ग) क्रोमाइट	५१९४ टन	२१८९२ टन
(घ) तांबा	२८८०७६ ”	—
(ङ) लोहा	१४२१७०१ ”	—
(च) मेगनीज	७६६३४१ ”	—
(छ) मेगनेसाइट	२३००२ ”	—
(ज) धावरक	१०८८३४ इन्डर	—

(५) रेल रास्ते	२५९७० मील	१४५४२ मील
(६) साधारण रास्ते	२४६६०५ ”	४९८६३ ”
(७) जलशक्तिकी सम्भावना	१३४३०० किलोवाट	२८४७००० किलोवाट ✓
(८) आयात-निर्यात वाणिज्य	१६५४८००० टन	२४४१००० टन

इनके अतिरिक्त और भी कुछ आवश्यक आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं :—

आयतन	१२५०००० वर्गमील	३३०००० वर्गमील
जन संख्या	३३२७८०००	६६१२२०००

शिक्षितोंकी संख्या (प्रतिशत) ९ ५३

जनसंख्याका दबाव २५५ २००

(प्रतिवर्ग मील पर)

जोतने लायक जमीन १६६७ लाख एकड़ ४२७ लाख एकड़

अनाज पैदा करनेवाली ज० ११८१ ,, ३५८ ,,

कसर जमीन ६५२ ,, ✓ २९० ;

ऊपरके आंकड़ेसे यह बात स्पष्ट हो रही है कि पाकिस्तान आर्थिक दृष्टिसे कमजोर नहीं है। निःसन्देह पाकिस्तानकी शिल्पसम्पत्ति तथा शिल्प-सम्भावना कम है लेकिन कृषिसम्पत्ति पाकिस्तानके हाथमें काफी परिमाणमें है। देश विभक्त होनेपर गेहूं पैदा करनेवाली जमीन अधिक से अधिक पाकिस्तान के हिस्सेमें पड़ी है। १९४४-४५ सालके हिसाबके अनुसार वर्तमान पाकिस्तानकी ९९ लाख एकड़ जमीन गेहूंकी पैदाके लिये जोती गई थी और उसमें गेहूंकी पैदावार हुई थी ३५ लाख टन। सिन्ध प्रदेश तथा पश्चिमी पंजाबसे वार्षिक १२८ हजार टन चनेका निर्यात होता है। जौ, ज्वार, बाजरा आदिकी पैदावार पाकिस्तानमें बहुत कम होती है। १९४४-४५ सालके हिसाबके अनुसार पाकिस्तानकी १७८७१०० एकड़ जमीनसे २४५५००० टन तिलहन पैदा हुआ था। मूंगफली पाकिस्तानमें बहुत कम होती है, इसकी पैदावारके बारेमें पृथ्वीके विभिन्न देशोंमें भारत ही प्रधान हिस्सा लेता है। १९४६-४७ सालके हिसाबके अनुसार भारत तथा पाकिस्तानके १९८० हजार एकड़ जमीन पाट उत्पन्न करने योग्य है; इसमें से १३५८८०० एकड़ जमीन अर्थात् प्रतिशत ७२३० हिस्सा जमीन पाकिस्तान के हिस्सेमें आई है। पाकिस्तानमें लगभग १७ लाख गांठ (एक गांठ = ४०० पाउण्ड) रुईकी उपज होती है। लम्बे रेशेवाली रुईकी पैदावार ज्यादातर पाकिस्तानमें ही होती है। १९४६-४७ सालमें पश्चिमी पंजाबमें ३० करोड़ रुपये तथा सिन्ध प्रदेशमें १५ करोड़ रुपए कीमतकी रुईकी उपज हुई थी।

१९४४ सालके हिसाबके अनुसार पूर्वी पाकिस्तानकी ८० हजार एकड़ जमीनसे ४१९९ हजार पाउण्ड चाय पैदा हुई थी। १९३८-३९ सालके हिसाबसे ३८०७०० एकड़ जमीनसे १५६३०० टन तम्बाकूकी उपज होती है। जानवर भी पाकिस्तानमें कम नहीं हैं। सारे देशकी बकरियों तथा भेड़ोंकी संख्याका प्रतिशत २५, गाय, भैंस आदि जानवरोंके प्रतिशत ३३ एवं घोड़ा, गधा, ऊंट आदि भारवाही जानवरोंके प्रतिशत ५.० पाकिस्तानके हिस्सेमें आये हैं। जलशक्ति पैदा करनेका साधन भी पाकिस्तानके हाथमें अच्छा है। संक्षेपमें पाकिस्तानके हाथमें खाद्यपदार्थ, दूध, मांस तथा कच्चा माल पर्याप्त अंशमें हैं। इस परिस्थितिमें भारत तथा पाकिस्तानका आर्थिक सहयोग होना विशेष आवश्यक है। जब तक ये दोनों राष्ट्र एक दूसरेका विश्वास न कर सकेंगे, तब तक ये दोनों आर्थिक सहयोगके द्वारा अपनी योजनाओंको आगे न बढ़ा सकेंगे, जब तक राजनैतिक तथा साम्प्रदायिक जीवनका विच्छेद हमारे आर्थिक जीवनको भी प्रभावित करता रहेगा, तब तक इन दोनोंमें एककी भी आर्थिक उन्नति नहीं होगी।

सारे देशके लिये जो बात लागू है बंगाल तथा पंजाबके लिये भी वही बात लागू है। बंगाल विभक्त होनेपर पश्चिमी बंगालका आयतन २८२१५ वर्गमील यानी संयुक्त बंगालके प्रतिशत ३६.४ हुआ है। इस प्रांतमें जनसंख्या का दबाव पहले बहुत कम था लेकिन पूर्वी बंगालसे बहुत हिन्दू आनेके कारण अभी पश्चिमी बंगालके प्रति वर्गमील जमीनपर औसतने ७५० आदमी बसते हैं। इनमेंसे प्रतिशत लगभग ५० खेतीका काम करते हैं; प्रतिशत १६ उद्योगधन्धोंमें नियुक्त हैं एवं अवशिष्ट लोग दूसरे कामोंसे गुजारा करते हैं। पूर्वी बंगालमें उद्योगधन्धे कम होनेके कारण ज्यादातर लोग खेतीपर ही निर्भर करते हैं; इसलिये शहरोंमें बसनेवालोंकी संख्या पश्चिमी बंगालमें प्रतिशत २२ तथा पूर्वी बंगालमें प्रतिशत ४ है। पश्चिमी बंगालमें कृषि-सम्पत्ति, वर्षा तथा जोतने योग्य जमीन बहुत कम है एवं सिंचाईका प्रदन्ध

भी अच्छा नहीं है। इन सब कारणोंसे पश्चिमी बंगालकी खाद्य-समस्या एक स्थायी समस्या है और जब तक दामोदर तथा मोर घांटो योजनाओंके द्वारा सिंचाईका पूरा प्रबन्ध नहीं होगा तब तक पश्चिमी बंगालकी यह समस्या हल नहीं होगी। पूर्वी बंगालमें जमीन अधिक उर्वरा है, नदीनाला भी बहुत हैं, वर्षा भी काफी होती है तथा जमीन सलाना दो बार जोती जाती है। कर्णफुली नदीपर जब बांध बन जायगी तो पूर्वी पाकिस्तानमें काफी जल-शक्ति उत्पन्न होने लगेगी। विदेशी व्यापारका बड़ा साधन पाट पाकिस्तानके ही हाथमें है तथा चीनी भी वहाँ काफी होती है। पूर्वी पाकिस्तानकी शिल्पसम्भावना कम है; इस दृष्टिसे पश्चिमी बंगालकी अवस्था कुछ अच्छी है और उद्योगधन्धोंका बड़ा साधन कोयला भी इसीके हाथमें है। ऊपरकी आलोचनासे यह बात स्पष्ट हो रही है कि राजनैतिक तथा साम्प्रदायिक कारणों से भारत विभक्त होनेपर भी आर्थिक दृष्टिसे एक देश दूसरे देशपर पूरी तौरसे निर्भर करता है। हो सकता है कि भविष्यमें ये दोनों देश आर्थिक दृष्टिसे पूर्णतया पृथक् हो जायेंगे। भविष्यके बारेमें निश्चित कुछ कहना असम्भव है लेकिन अभीकी परिस्थितिमें यदि वास्तविक आर्थिक सहयोगकी इच्छा इन दोनों देशोंमें न रहे तो यह क्या पाकिस्तान क्या भारत उभय देशोंके लिये ही हानिकारक होगा।

भारतकी जनसमस्या — क्या भारतकी जनसंख्या अधिक है ?

जनसंख्याकी दृष्टिसे चीन देशके बाद भारतका ही स्थान है लेकिन केवल संख्याके द्वारा किसी देशकी जन सम्पत्तिका विचार नहीं हो सकता। यूरोपके विभिन्न देशोंकी जनसंख्या कम होते हुए भी उनमें योग्यताकी कमी

नहीं है और इसी योग्यताके आधारपर ज्ञान-विज्ञान शिल्प-कला प्रभृतिका तथा उनकी संस्कृतिका गहरा प्रभाव अन्यत्र पड़ रहा है ।

जनसंख्याकी दृष्टिसे भारतको देश नहीं कहकर महादेश कहना ही उचित होगा । इस देशमें विभिन्न रंग, विभिन्न ढंगके विभिन्न जाति तथा धर्मके, विभिन्न भाषा बोलनेवाले मनुष्य रहते हैं । गुरखा, पठान, सिख, राजपूतोंसे लेकर आर्य, अनार्य, द्राविड़, मंगोल प्रभृति जातियाँ इस देशमें दिखाई पड़ती हैं । इनमें किसीके साथ प्राचीन आर्यों का सादृश्य है, किसीके साथ मलाया, सुमात्रा तथा मेडागास्करके अधिवासियों का सादृश्य है और कोई सेमिटिक, मंगोल आदि जातियोंके साथ सम्बन्ध रखनेवाले मादृश पड़ते हैं । इस प्रकारसे देशो-विदेशी, नवीन-प्राचीन रक्त संमिश्रण तथा सहयोगके द्वारा कई एक शताब्दियोंसे भारतकी जनसम्पत्तिकी रचना हो रही है ।

किसी भी देशमें जनसंख्याका दबाव उसका भौगोलिक अवस्थान, धनसम्पत्ति तथा जीवनको निरापद रखनेका प्रबन्ध, रहन सहनका स्तर (दर्जा) आर्थिक सम्पत्ति तथा आर्थिक विकास आदिपर निर्भर करता है । देश यदि समृद्धिशाली हो, देशमें यदि काफी आर्थिक सम्पत्ति रहे तथा आर्थिक विकास की यथेष्ट सम्भावना भी रहे तो जनसंख्या जितनी भी क्यों न बढ़े रहन सहनका स्तर नीचा नहीं होगा । प्रति वर्गमील जमीनपर ५ आदमी रहें या ५०० साथ ही साथ अगर आर्थिक विकास चलता रहे तो उनके जीवन पर इसका कुछ भी प्रतिकूल असर नहीं होगा । प्राकृतिक नियमोंके अनुसार जनसंख्याकी वृद्धि भी सीमित है लेकिन इस सीमारेखाके भीतर जब जनसंख्याकी वृद्धिके साथ साथ आर्थिक विकास नहीं होता तभी सभी समस्याएँ आ उपस्थित होती हैं । इंग्लैंड तथा वेल्समें प्रति वर्गमील जमीनपर ६८५ मनुष्य रहते हुए भी उनके रहन सहनका दर्जा ऊँचा है । हमारे इस देशमें प्रति वर्गमील जमीनपर कुलमें २५५ मनुष्य रहते हैं और

इसीमें ही हमें माल्यसकी प्रेतात्मा दिखाई दे रही है। इंग्लैंडमें उद्योगधन्वोंने क्रांतिकारी उन्नति होनेके कारण जनसंख्याको द्रुतगतिसे वृद्धि होनेपर भी किसी भी समस्याका प्रादुर्भाव नहीं हुआ। हमारा आर्थिक विकास नाममात्र हुआ है ; इसीलिये यदि जनसंख्या कुछ भी बढ़े तो हमारे लिये वह एक विशाल बोझ हो जाती है।

भारतके ज्यादातर अधिवासियोंको खेतीपर निर्भर करना पड़ता है। दूसरे कामोंके अभावके कारण ही ऐसा करना पड़ता है। इस देशमें प्रतिशत ४४ आदमी परिश्रम करते हैं और अवशिष्ट ५६ आदमी इनके परिश्रमपर निर्भर करते हैं। जो लोग परिश्रम करते हैं उनमें प्रतिशत ६६ या उससे भी अधिक आदमी खेती या कच्चे मालके पैदा करनेमें लगे हैं ; प्रतिशत लगभग १० आदमी उद्योग-धन्वोंमें स्थान पाते हैं ; यातायातका प्रबन्ध एवं खबरोंका आदान-प्रदानके काममें प्रतिशत ११ आदमी, व्यापारमें ५, सरकारी नौकरीमें २१, गृहस्थोंके कामोंमें ७ तथा दूसरे कामोंमें ६ आदमी नियुक्त हैं। जो लोग उद्योग-धन्वोंमें काम करते हैं वे भी दूसरी दृष्टिसे कृषिपर ही निर्भर कर रहे हैं। कारण कि हमारे देशमें जो दो चार उद्योग-धन्धे प्रतिष्ठित हुये हैं उनमें कच्चे मालकी पूर्ति कृषिसे ही होती है। हमारे व्यापारियोंकी सामग्रियाँ भी ज्यादातर कृषिसे ही पैदा होती हैं। इस प्रकारसे करीब हमारी सारी जनसंख्या कृषिसे ही सम्बन्ध रखनेवाली है। कृषि एक बहुत ही अनिश्चित धन्धा है तथा कृषिमें उल्लेखनीय कोई उन्नति भी नहीं हुई है। कृषिसे सम्बन्ध नहीं रखनेवाले उद्योग-धन्वोंकी प्रतिष्ठा अभी तक विशेष कुछ नहीं हुई। इन सब कारणोंसे देशके जिधर ही क्यों न देखा जाय दरिद्रताका एक नम्ररूप हमारे नजरोंमें आयेगा।

अब जन्म तथा मृत्युकी संख्याके बारेमें आलोचना की जाय। भारतमें जन्मसंख्या दूसरे देशोंसे अधिक है। इस देशमें प्रति हजारमें ३२ बच्चे

पैदा होते हैं। पाश्चात्य देशोंमें इंग्लैंड, स्पेन, अमेरिकाके संयुक्तराष्ट्र तथा कॅनाडा जहाँ कि जन्मसंख्या सबसे अधिक है वहाँ इनकी संख्या प्रति हजारमें २२ से २४ तक होती है। इंग्लैंडमें जन्मसंख्या प्रति हजारमें कुलमें १६·३, जर्मनीमें १६·२ तथा आस्ट्रेलियामें २०·२ है। एक और उल्लेखनीय बात यह है कि बोते हुए ४० वर्षोंमें इन सब देशोंमें जनसंख्याकी दिनपर दिन कमी होती जा रही है लेकिन इस देशमें इसके बारेमें विशेष कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इंग्लैंडमें १९११-१३ सालमें जन्मसंख्या २४·१ थी, १९४१-४३ में वह १६·३ हो गई; जर्मनीमें जनसंख्या २२·१ के जगह १६·२ हो गई; स्पेनमें ३१·२ की जगहमें २२·८ हो गई; और भारतमें वह ३८·६ की जगह ३२ हो गई। जनसंख्याकी अधिकताके कारण हमारी दुर्बलता एवं क्षय रोगमें वृद्धि हो रही है। इस देशमें जन्मसंख्या अधिक होनेका कुछ कारण भी है। हमारा देश प्रोप्त प्रधान होनेके कारण स्त्री-पुरुषोंमें जीवनका विकास जल्द होता है तथा कम उम्रमें शादी होनेके कारण भी जनसंख्या अधिक होती है। दरिद्रताका असर भी इसपर होता है। दरिद्र व्यक्तियोंके लिये रहन सहनका कोई निर्दिष्ट दर्जा भी नहीं है और वे सोचते हैं कि जितने बच्चे पैदा होंगे वे कुछ न कुछ काम या रोजगार करके परिवारकी आर्थिक मदद पहुँचावेंगे। इसलिये दरिद्र परिवारोंमें उम्रदातर बच्चोंकी पलटन दिखाई पड़ती है, यहाँ तक कि भीखसंगोंमें भी। मध्यवर्ती परिवारोंमें ऐसा हो नहीं पाता, कारण उन्हें पहले तो रहन सहनपर ध्यान देना पड़ता है और दूसरे बच्चोंकी शिक्षा-दिक्षाका प्रबन्ध करना पड़ता है। पाश्चात्यके जिन सब देशोंमें बच्चोंके लिये बाध्यतामूलक शिक्षाका प्रबन्ध हुआ है उनके लिये भी यह बात लागू है। दरिद्रताके अलावा अज्ञानताके कारण भी मनुष्यमें प्राकृतिक क्षमताएँ विकसित होकर जनसंख्या बढ़ानेमें मदद पहुँचाती हैं।

जनसंख्याकी तरह नृत्य संख्या भी इस देशमें सबसे अधिक है। प्रति

हजारमें इस देशमें २२ आदमी मरते हैं। इंग्लैंडमें प्रति हजारमें मृत्यु संख्या कुलमें १२.१ है, जर्मनीमें १२.६, अमेरिकाके युक्तराष्ट्रोंमें ११.७, कैनाडामें १० एवं डेनमार्कमें ९.६ है। दरिद्रता एक ओर जैसे जनसंख्या बढ़ती है दूसरी ओर ठोक वसे ही मनुष्यकी व्याधि प्रतिरोध करनेकी शक्ति विनष्ट कर देती है। इसीलिये इस देशमें व्याधिओंका ताण्डव नृत्य चल रहा है। विज्ञानके प्रभावसे पाश्चात्य देशोंमें जिन सब व्याधिओंको मूलसे विनष्ट कर दिया गया है उन सब व्याधिओंको आज भी हमारे देशमें काफी शिकार मिलती है। हमारी जनसम्पत्तिका एक उल्लेखनीय हिस्सा है, जो चेचक, मलेरिया, क्षयरोग आदि व्याधिओंसे हरसाल मौतका सामना करता है। हमारे देशमें स्त्री तथा बच्चोंकी मृत्युसंख्या भी काफी है। बहुतसे बच्चे जन्म लेनेके साथ-ही-साथ प्रसवगृह में ही मर जाते हैं और बहुतोंको बचपनमें ही मौतका शिकार बन जाना पड़ता है। वैज्ञानिक प्रसव-व्यवस्थाका अभावही इसका मुख्य कारण है। हमारी स्त्रियोंमें जीवनी शक्तिका बहुत अभाव है। बचपनमें अयत्न एवं यौवनमें अनादर तथा उपेक्षाके कारण अनेक स्त्रियोंमें ही ज्यादा दिन जीनेकी शक्ति नहीं रहती। छोटी उम्रमें शादी होनेके कारण मातृत्वका दायित्व भी उन्हें बहुत जल्दी ग्रहण करना पड़ता है और इससे जीवनशक्ति क्षय हो जाती है। भारतमें लड़की होकर जन्म लेना महापाप है। जिस देशमें माताओंका स्वास्थ्य इतना खराब है उस देशके मनुष्योंमें जो जीवनशक्तिका अभाव होगा इसमें आश्चर्य ही क्या है? इसीलिये इस देशमें औसतपर परमायु कुलों २७ वर्ष है। ३० वर्ष तक पहुँचते ही प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है एवं ५५ वर्षके बाद अदसर ग्रहण करनेका समय आ जाता है। पाश्चात्य देशोंमें ३० वर्षके बाद वास्तविक यौवनका प्रारम्भ होता है एवं ५० वर्षके बाद काफी अभिज्ञता प्राप्त होनेपर उन्हें ज्ञान-विज्ञान, शिल्प-साहित्य, राजनीति प्रवृत्ति क्षेत्रोंमें नेतृत्वकी प्राप्ति होती है।

जनसमस्याकी विभिन्न पहलुओंके बारेमें आलोचनाकी गई है। अब आर्थिक स्थितिके साथ जनसंख्याका क्या सम्बन्ध है इसपर विचार किया जाय। अनेक नोतिशोंकी धारणा है कि भारतको विराट् जनसंख्या इस देशकी दरिद्रताका मूल कारण है। हमारा जितना आर्थिक विकास हुआ है उसके द्वारा इतनी जनसंख्याका जीवन निर्वाह होना कठिन है। अपनी युक्तिके समर्थनमें वे मल्यसके सिद्धांतकी बातें करते हैं। इस युक्तिको हम पूर्णतौरसे ग्रहण नहीं करते और बिल्कुल उपेक्षा भी नहीं कर सकते। हमारे वर्तमान आर्थिक विकासकी दृष्टिसे यदि विचार किया जाय तो वर्तमान स्थितिमें हमारी जनसंख्याका जीवन निर्वाह होना कठिन है, यह बात स्पष्ट होगी। बीते हुए ५० वर्षोंमें हमारी जनसंख्या कुछ बढ़ी है लेकिन आर्थिक विकासमें कोई विशेषता नहीं दिखाई पड़ी; इसलिये जनसंख्या जितनी ही क्यों न बढ़े वही आर्थिक व्यवस्थाके लिये बोझ जो जाती है। निःसन्देह हमारे देशमें जन्मसंख्या दूसरे देशोंसे अधिक है लेकिन मृत्युसंख्या भी कम नहीं है; प्रति वर्गमील जमीन पर जनसंख्याका दबाव अनेक देशोंसे कम है; इसपर भी हमारी जनताका आर्थिक कल्याण नहीं हो रहा है, उनके रहन सहनका दर्जा ऊँचा नहीं हो रहा है इसका मूल कारण यह है कि बीते हुए ५० वर्षोंमें विभिन्न कारणोंसे हमारा आर्थिक विकास नहीं हुआ है। आज जो साम्प्रदायिक समस्या, प्रान्तीयतावाद आदि देशके विभिन्न प्रान्तोंमें जहर फैला रहा है, आज जो मनुष्यके साथ मनुष्यका अन्तर स्पष्ट हो रहा है, स्वार्थ संघर्षसे आज अनेक मनुष्योंका दृष्टिकोण जिस प्रकारसे संकुचित हो रहा है इनके पीछे भी जनसमस्याका स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। प्रत्येक सम्प्रदाय आज अपने स्वार्थकी बातें सोच रही है, प्रत्येक प्रान्त आज संकीर्ण दृष्टिसे अपनी उन्नतिकी बातें सोच रहा है चाहे यह कितना ही जातीयता विरोधी क्यों न हो, प्रत्येक देश आज उदार अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिको छोड़कर आर्थिक जातीयतावादपर ध्यान दे रहा है। ये सब शक्तियाँ जितनी ही

मानवता विरोधी क्यों न हों यही सत्य हैं, वास्तव हैं, इन्हें अस्वीकार करना असम्भव है। इसपर भी निराशा का कोई कारण नहीं है। वर्तमान स्थिति में हमारी जन-संख्याका दबाव बहुत ही ज्यादा मालूम पड़ता है। लेकिन इसमें भी शक नहीं कि हमारे सामने विराट् आर्थिक सम्भावना भी है। बीते हुए दो सौ वर्षोंमें पृथ्वीके अनेक देश अपनी आर्थिक सम्पत्तियों का उपयोग कर चुके हैं या कर रहे हैं लेकिन हम इस विषय में उदासीन हैं। अगर हमारी जन समस्याको हल करना हो तो हमें दो कार्रवाइयां करनी पड़ेगी। पहले तो हमें जन-संख्या घटानेकी कोशिश करनी पड़ेगी और दूसरी हमारी विराट् आर्थिक सम्भावना का उपयोग करना होगा। जन-संख्या घटानेकी जो समस्या है इस पर चारों ओरसे ध्यान देना चाहिए। जन्मनियंत्रण, जन्मनिरोध, रोगप्रस्त व्यक्ति-ओंकी जनन शक्तिका विनाश प्रभृति जो सब वैज्ञानिक पद्धतियां पाश्चात्य देशोंमें चल रही हैं उन्हें हमें ग्रहण करनी पड़ेगी। जन-समस्या के घारेमें हमारे देशमें एक सुचिन्तित जन-संख्या विषयक योजना ग्रहण करनेकी आवश्यकता है। साथ ही साथ हमें आर्थिक विकास की बातें भी सोचनी पड़ेगी। राजनीतिक कारणोंसे जो सब रुकावटें आज तक हमारा आर्थिक विकास नहीं होने देती थी, देश स्वतंत्र होने पर भी यदि हम आगे न बढ़ सकें तो उन्हें हम किस प्रकारसे दायी कर सकते हैं ? आज हमारे आर्थिक विकासका काम पूरी तौरसे हमारे ऊपर आ चुका है। हम यदि इस ओर आगे बढ़ सकें, हमारी कृषिमें यदि वैज्ञानिक रीतिसे सुधार किया जाय, हमारे उद्योग धन्धोंका यदि वास्तविक प्रसार हो सके एवं विभिन्न धन्धोंमें यदि हमारी जन-संख्याका यथार्थ वितरण हो तो हमारे सामने आर्थिक उन्नति की सम्भावना आ जायेगी एवं हम अपनी जनताके जीवन निर्वाह का यथार्थ प्रबन्ध कर सकेंगे। हमें इस प्रबन्धको वास्तव मे सफल करनेके लिये शक्ति इकट्ठी करनी पड़ेगी, आर्थिक उन्नतिके विषय पर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि जन-कल्याणके लिये हमारे आर्थिक साधनोंका पूर्ण उपयोग हो सके। ऐसा

करने पर ही हमारे साधनों की पूरी सार्थकता होगी, हमारे देशके मनुष्य जो कि आज साधारण प्राणियोंकी तरह जीवन गुजार रहे हैं उन्हें मनुष्यकी तरह जीवन निर्वाह करनेका अधिकार प्राप्त होगा, वे मनुष्यके सम्मानको पुनः प्राप्त कर मनुष्यकी मर्यादा पर पुनः स्थित हो सकेंगे जो कि २०० वर्षोंके विदेशी शासनमें उनसे छीन लिया गया था ।

गाँव सुधार

भारतकी अधिक से अधिक जनता देहातोंमें बसती है लेकिन जब हम ग्रामोंकी सदियोंसे जर्जरित दुरवस्थाकी ओर देखते हैं तो हमें हमारे ग्राम जीवनके बारे में गौरव का अनुभव नहीं होता । एक समय हमारा ग्राम-जीवन आदर्श जीवन था, इसमें शान्ति विराजती थी, आर्थिक दृष्टिसे भी यह पर-निर्भर नहीं था । ब्रिटिश शासनके प्रारम्भ कालसे हमारे देशमें आर्थिक अव्यवस्था शुरू हुई जिससे हमारे उद्योग-धन्धे नष्ट हो गए, सारी जनता कृषि पर निर्भर हो गई, सारे देश पर दगिद्रताका अभियान शुरू हुआ । साथ ही साथ प्राचीन पंचायत व्यवस्था गिरनेके कारण देहातियोंके सामाजिक जीवनमें भी बिभ्रलता आ उपस्थित हुई । इस समय पाश्चात्यके विभिन्न देश औद्योगिक क्रांतिके सुयोगसे आगे बढ़ रहे थे लेकिन हमारी सामाजिक तथा आर्थिक बिभ्रलताके कारण हम इससे फायदा नहीं उठा सके । उन्नीसवीं शताब्दीके मध्यभाग से भारतमें यातायात-साधनों की उन्नति हुई एवं नए नए शहर बसाए जाने लगे । इस परिवर्तनके साथ-साथ गाँवों से शहरों की ओर जन-

संख्या का प्रवाह आरम्भ हुआ। महत्वाकांक्षी, कुशाग्रबुद्धि तथा स्वस्थ युवक गांवोंको छोड़कर नगरोंमें जाकर बसने लगे, फलतः गांव वीरान हो गए। ग्राम-जीवन निरक्षरता, अज्ञानता तथा संकीर्णताका आधार बन गया। आधुनिक समयमें साम्प्रदायिकता तथा प्रान्तीयताके विशाल वातावरणमें हमारा ग्राम जीवन और भी कुत्सित हो गया है।

हमारे देशमें इस वक्त भी अधिक से अधिक जनता गांवोंमें बसती है परन्तु सामाजिक तथा आर्थिक दबावसे शहरोंकी ओर जन-संख्या का प्रवाह बढ़ना आरम्भ हो गया है जैसे कि औद्योगिक क्रान्तिके बाद पाश्चात्य देशोंमें हुआ था। जल्द ही इन देशोंमें इसके दुष्परिणाम दृष्टि गोचर होने लगे। पहले तो कुछ लोगोंका यह विचार था कि शहरोंमें उचित शिक्षा, सफाई, चिकित्सा आदि वार्ताकी सुविधा है। इसका नतीजा यह हुआ कि गांवोंमें अपेक्षाकृत निम्न श्रेणीके स्त्री पुरुष ही रह गये और जातिमें अवनतिके चिह्न स्पष्ट होने लगे। इसीलिये पाश्चात्य देशोंमें "गांवको ओर लौटो" का आन्दोलन चलाया गया। ब्रिटिश सरकारने इंग्लैंडमें बड़ी बड़ी जमींदारियोंको खरीदकर शिक्षित तथा स्वस्थ युवकोंको पूंजी तथा जमीन देकर उनका बसाना आरम्भ किया। सच तो यह है कि प्रत्येक देशमें, विशेषतः भारतमें, गांवोंकी जन-संख्या पर ही राष्ट्र-शक्तिका आधार है। यदि गांवोंकी जन-संख्या गिरी हुई दशमें रहे तो राष्ट्र-शक्ति क्षीण हुए बिना नहीं रह सकता। इसीलिये सामाजिक, आर्थिक तथा राष्ट्रीय दृष्टिसे गांव सुधारकी आवश्यकता है। पंजाबमें गांव सुधारके विख्यात उद्योगी श्री ब्रायनजीने कहा था कि गांव सुधारके लिये भारतके प्रत्येक गांवमें 'डिनामो' प्रतिष्ठित करनेकी आवश्यकता है। इस 'डिनामो' का मतलब यह समझना चाहिये कि प्रत्येक ग्रामीणमें यदि अपनी अवस्थाको सुधारनेकी इच्छा आ जाये तो वह सिर्फ अपनी गलतियोंको ही नहीं समझ सकेगा बल्कि इनको दूर करनेके लिये भी प्रयत्न करेगा।

भारतमें शताब्दियोंके शोषणके कारण गांवोंकी दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई है। आज हमारे गांवोंकी दशा ऐसी है कि जो ग्रामीण कुछ पढ़-लिख जाता है वह सदैवके लिए गांव छोड़कर शहरमें जा बसता है। जमींदार शहरोंके आकर्षणसे अपनी जमींदारियोंको छोड़कर दूर शहरोंमें जा बसे हैं एवं जमींदारीकी सारी पैदाशहरोंमें व्यय करते हैं। भारतीय गांवोंकी पूँजी तथा मस्तिष्क इस तरहसे बाहर चले जानेके कारण गांव सब प्रकारसे निर्धन होना जा रहा है। शहरोंमें जो लोग आते हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, विशेषतः शिक्षित मध्यमवर्ग की, जहां बेकारी फैल रही है। इसलिये शहरोंमें जाकर हमारे प्रथम श्रेणीके व्यक्ति निस्तेज और शक्ति हीन हो गये हैं। सारी जाति पर इसका गहरा असर पड़ा है। आज देश स्वतन्त्र होनेपर भी आशाकी रोशनी दिखाई नहीं पड़ती। इसका मुख्य कारण तो यह है कि हमारे प्रथम श्रेणीके व्यक्ति आर्थिक अभावके कारण शक्ति हीन तथा पुष्टार्थ हीन हो गये हैं और गांवोंमें द्वितीय और तृतीय श्रेणीके लोग हो शेष रह गये हैं एवं गांवोंके साथ शहरोंका सम्यन्ध दिन पर दिन नष्ट होता जा रहा है।

गांव सुधारकी समस्या बहुत जटिल तथा बहुमुखी है। इसलिये गांव-सुधार-योजना व्यापक होनी चाहिये ताकि ग्रामीणोंके पारिवारिक, सामाजिक, राजनै-तिक तथा आर्थिक जीवन इसमें शामिल हो सके। गांवों में मनुष्यकी छांटन रह जानेके कारण रुढ़ियोंकी प्रबलता ईर्ष्या, द्वेष, भाग्यवाद आदि प्रबल हो चुके हैं। इस स्थितिको सुधारनेके लिये समाजकी जो सब त्रुटियां ग्रामीणोंको पीछेकी ओर खींच रही हैं उनका अन्त करना होगा। उत्तराधिकार-कानून, भूमि-व्यवस्था, सामुहिक-परिवार पद्धति-प्रथा, जाति-भेद प्रभृतिको सुधारनेकी या उनका अन्त करनेकी आवश्यकता है लेकिन सबसे पहले ग्रामीणोंकी निरक्षरताको दूर करनी होगी ताकि वे इन सब सुधारों में सहयोग दे सकें। निरक्षरतासे दरिद्रता बढ़ती है, मितव्ययिताका अभाव होता है, जोत-दे-बोआईके काममें

रूकावटें आती हैं, संक्षेपमें निरक्षरताके कारण ग्रामीणोंका काम सफल नहीं हो सकता। परन्तु यह शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिये जिससे जनसाधारण निकम्मे और कल्पना-प्रवण बन जाये। जिस शिक्षासे मनुष्यमें स्वतंत्र चिन्तनेकी इच्छा प्रबल नहीं होती वह शिक्षा अशिक्षा है। शिक्षा तो ऐसी होनी चाहिए जिससे एक ओर मानवताका विकास हो सके, नैतिक चरित्र संगठित हो सके एवं दूसरी ओर मनुष्य स्वावलम्बी हो सके। यह शिक्षा सिर्फ बच्चोंको ही नहीं बल्कि प्राप्त वयस्क स्त्री पुरुषोंको भी मिलनी चाहिए।

गांव सुधारके लिये संगठन तथा परिवर्तनकी आवश्यकता है। संगठन बढ़ानेके लिये ग्रामीणोंके साथ आदर्श नागरिकोंका तथा सरकारी पदाधिकारियोंका घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित होना चाहिये ताकि ग्रामीण इनकी जीवन पद्धतिको अपना सके। नवयुवकोंको भी इसके बारेमें अपना दायित्व समझना चाहिए। संगठनका काम समाजके निम्नवर्गसे नहीं हो सकता, इसके लिये प्रेरणा तथा आदर्श समाजके प्रथम वर्गसे आनेकी आवश्यकता है। ग्रामीणोंमें अगर प्रेरणा आ जाये, आदर्शके द्वारा यदि वे उत्साहित हो जायें तो उसके बाद वे अपने आप गांव सुधारका उत्तरदायित्व ले सकेंगे। संगठनके अतिरिक्त गृहस्थीमें भी परिवर्तनकी आवश्यकता है। भारतके किसी भी प्रान्तमें, किसी भी गांवमें जाय न क्यों, ग्रामीणोंमें रहन सहनका कोई दर्जा ही नजरमें नहीं आता। आर्थिक अव्यवस्था इस स्थितिके लिये कुछ हद तक दायी है लेकिन जिनकी आर्थिक अवस्था अच्छी है उनका भी जीवन स्तर बहुत नीचा है। ग्रामीणगण जिस तरहके घरोंमें रहते हैं उनमें न तो हवा ही खेलती है और न रोशनी ही पहुँचती है। गृह-निर्माण पद्धतिमें त्रुटियां रहनेके कारण ही ऐसा होता है। देहातोंमें जगहकी कमी नहीं है तो भी ये एक दूसरेसे सटाकर अपना घर बनाते हैं जिससे कि हवा और रोशनी घरोंमें प्रवेश नहीं कर सके। शिक्षाका विस्तार होने पर ही ग्रामीणोंकी दृष्टिमें परिवर्तन सम्भव होगा। ग्रामीणोंमें सफाईका भी अभाव है—सिर्फ शारीरिक सफाई ही नहीं बल्कि

घरकी, सारी गृहस्थीकी, सारे गांवकी । सफाई रखनेके लिए पैसेकी जितनी आवश्यकता नहीं है उससे अधिक रुचि तथा धीर्य-बोधकी है । हमारे ग्रामीणोंमें इन दोनोंका अभाव है । गांवोंमें कूड़ा कचरा गिगनेका कोई निर्दिष्ट प्रवन्ध नहीं है । दूषित जल बाहर निकालनेके लिये भी कोई व्यवस्था नगरमें नहीं आती । टट्टी, पेशाबके लिये भी बहुत कम गांवमें पृथक् बन्दोबस्त है इसलिये प्रत्येक गांवमें विभिन्न प्रकारकी बिमारियाँ फैली रहती हैं और मृत्यु-संख्या भी अधिक है । पीनेके पानीके लिये गांववासियों को कुआं तलाब, नाला आदि पर निर्भर करना पड़ता है इनकी किस तरहसे सफाई करना चाहिये इसके बारेमें भी उन्हें जानकारी नहीं है । संक्षेपमें रहन-सहन किस प्रकारका होना चाहिये इसके बारेमें हमारे ग्रामीणों को कम अनुभव है ।

गांव सुधारकी सबसे बड़ी समस्या तो आर्थिक समस्या है । गांवमें जमींदारी के अतिरिक्त बड़े-छोटे आयके साधन, ऊँचे दर्जे का सामाजिक जीवन, मानसिक विकास तथा स्वास्थ्यप्रद मनोरंजनके साधन उपलब्ध नहीं हैं । आज देशमें आर्थिक योजनाओं की बहुत चर्चा है परन्तु गांवोंको सन्तुष्टिकारी बनाने की ओर अभी तक पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है । ज्यादातर ग्रामीण खेती पर निर्भर हैं, लेकिन खेतीकी अवस्था बड़ी अच्छी नहीं है । इसको सुधारनेके लिये जिन सब साधनोंकी आवश्यकता है उनमें रकमकी पूर्ति, बिजुली, खेतों को इकट्ठा करना, खेतों को आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बनाना, सिंचाईका प्रवन्ध करना, ऊसर भूमि का उपयोग करना, भूमि स्वत्वमें परिवर्तन करना, यातायात तथा संदेश साधनों का अयोजन करना, जमीनका पट्टाब रोकना, शस्य-आयोजन करना, खाद तथा उन्नत बीजोंकी पूर्ति बढ़ाना, उन्नत नशिनें तथा औजारोंका प्रयोग करना प्रभृति विशेष उद्योग-गतीय हैं लेकिन अभी तक इन सब विषयोंमें काफी कमजोरियाँ नजरमें आती हैं । इन सबको यदि सहकारके आधार पर सहकारी समितियोंके माध्यम

सुधारनेका प्रबन्ध किया जाय तो इस समस्याका हल किया जा सकता है। साथ ही साथ मौसमी कारखाने जो कि खेतीकी पैदावारको कच्चे मालके रूपमें काममें लाते हैं छोटे पैमाने पर वे गाँवोंमें स्थापित हों। यह भी सहकारी समितियोंके द्वारा हो सकता है। इसके अलावा ये समितियाँ उपजको बड़ी-बड़ी मंडियोंमें बेचनेका प्रबन्ध करेंगी, खेती तथा गृह-उद्योगके लिये जरूरी सामग्रियाँ खरीद सकेगी, सहकारी खेतीका प्रबन्ध करेंगी, गृह-उद्योग कायम करेंगी, पंच फैसलेका सारा काम भी इन समितियों पर सौंपा जा सकेगा। ग्रामीणोंके रहन सहनमें परिवर्तन करनेका, शिक्षाके विस्तारक। दवादाहका तथा सफाईका सारा प्रबन्ध भी इनके द्वारा करवाया जा सकेगा। इस प्रकारसे यदि प्रत्येक गाँवके लिए या कई एक गाँवोंके लिए सहकारी समितियाँ कायम की जायँ एवं ग्रामिणोंके सामाजिक तथा आर्थिक जीवनके पुनरुद्धारका दायित्व इनपर सौंप दिया जाय तो गाँव सुधारका काम द्रुत गति से आगे बढ़ सकेगा।

आज देशमें आर्थिक योजनाओंकी बहुत चर्चा है; परन्तु गाँवोंको समृद्धिशाली बनानेकी ओर जब तक ध्यान नहीं दिया जाता है तबतक राष्ट्रीय अवनतिको हम नहीं रोक सकेंगे। गाँवोंको समृद्धिशाली बनानेके लिए सिर्फ कृषि-सुधारसे काम नहीं चलेगा बल्कि हमें अपनी भावी औद्योगिक संगठनकी रूपरेखाको बदलनी होगी। सरकारको ऐसी व्यवस्था करना होगी कि मौसमी कारखाने जो कि खेतीकी पैदावारका उपयोग कर सकेंगे, गृह-उद्योगकी तरह गाँवोंमें ही स्थापित किए जायँ ताकि बढ़ती जन-संख्या गृह-उद्योगसे जीवन-निर्वाह कर सके। केवल गृह-उद्योग पुनःस्थापित करनेसे ही गाँवोंकी आर्थिक समस्याका समाधान नहीं होगा। इसका कारण यह है कि इनमें अपेक्षाकृत थोड़े ही लोग काम पा सकते हैं। आज हमारे गाँवोंमें जन-संख्या बढ़नेके कारण भूमिका अकाल हो गया है एवं उन खेत-मजदूरोंकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है जिनके पास या तो तनिक भी भूमि नहीं है अथवा

काम चला आ रहा है उसमें अभी तक विशेष परिवर्तन नहीं हुआ; जमीन घेरने को जो रीति पाश्चात्य देशोंमें बहुत दिन पहले शुरू हुई थी वह अभी भी हमारे देशवासियों के लिये अपरिचित है ; जोते हुए खेतोंकी ओर ध्यान देने से जमीन की असंख्य छोटी-छोटी टुकड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं और इनका आयतन भी दिन पर दिन छोटा होता जाता है ; सिंचाई का पूरा प्रबन्ध न होनेके कारण जमीनकी उर्वरता नष्ट होती जा रही है । यूरोपके विभिन्न देशोंमें वैज्ञानिक रीतिसे जमीनकी उन्नति होने के कारण जमीन की कीमत बढ़ गई है ; आज यदि वे सिर्फ प्राकृतिक शक्ति पर निर्भर करते रहते तो जमीन की कीमत बढ़ना तो दूर रहा बल्कि वह दिन पर दिन घटती ही जाती । हमारे देशमें जमीन की स्थायी उन्नति का कुछ भी प्रबन्ध नहीं हुआ है । साथ ही साथ उत्पादन रीति एवं आवश्यकीय औजारों में भी कुछ सुधार नहीं हुआ है । हमारे किसानों की निपुणता भी दूसरे देशोंके किसानों की निपुणता से कम है । इसके लिये हम प्राकृतिक कारणोंका पूरा दोष नहीं दे सकते । चम्बई के धारवाड़ प्रांत में रोजाना पाँच आने मजदूरी पर मजदूरीन कुल में ५० पाउन्ड रुई संग्रह करती थी ; काम के अनुपात से मजदूरी निश्चित होने पर वही रोजाना करीब १५० पाउन्ड रुई संग्रह करने लगी । कृषि-मजदूरों को साल भर पूरा काम भी नहीं मिलता ; ज्यादा तर उनका समय बेकार जाता है । हमारे बहुत से गृह-उद्योग नष्ट होने के कारण यह समस्या और भी गम्भीर हो रही है । दूसरे उद्योग धन्धोंके अभाव से हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या पूरी तौर से कृषि पर ही निर्भर है । जाति प्रथा, सम्मिलित परिवार, उत्तराधिकार कानून आदि सामाजिक कारणों से अधिकांश मनुष्यों को काम करने की प्रेरणा कम हो जाती है । पँजी के अभाव से बहुत से किसान कृषिकी उन्नतिके बारे में सोच भी नहीं सकते और जिनके पास कुछ आर्थिक साधन हैं वे भी निरक्षरता के कारण वैज्ञानिक आविष्कारों को काम में नहीं ला सकते ।

ऊपर की समस्याएँ हमारे लिये नई नहीं हैं ; पादचात्य देशोंमें भी कृषि क्रांतिके पहले ये सब समस्याएँ कम या अधिक रूपमें दिखाई पड़ती थीं लेकिन कृषि क्रांति शुरू होने के पहले ही ये हल हो चुकी थीं, चाहे वे अपने आप, या संस्कार के द्वारा या विदेशी अभियान के द्वारा इसलिये जब इन सब देशोंमें कृषि क्रांति शुरू हुई तब इन्हें इन सब समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा था । इसलिये इन सब देशोंकी कृषि में आगूठ परिवर्तन हो सका था—किसानों को आज्ञादी मिली, जमीन तथा लगान के बारे में जो सब कानून थे उनमें परिवर्तन हुये, छोटे-छोटे खेतोंकी जगह खेतोंकी चक्रवन्दी हुई, नए औजारों से नए तरीकों से खेतीका काम शुरू हुआ । यदि उनकी सामाजिक तथा आर्थिक संगठन की कुरीतियां लगी हुई होती तो कृषि क्रांति कभी भी सम्भव नहीं हुई होती । आज अमेरिका, रूस प्रभृति देशोंमें बड़े पैमाने पर जमीन जोती जा रही है । हमारी कृषिमें यदि क्रांति लानी हो तो उसके लिये सबसे पहले इन सब कुरीतियों तथा रुकावटों को नष्ट कर देना पड़ेगा । इस विषयपर ध्यान नहीं देने के कारण बोते हुए दो सौ वर्षोंमें कृषि सुधार के लिये जो भी कुछ कार्रवाइयां हुई हैं वे सफल न हो सहीं । पादचात्य देशोंकी कृषि क्रांति से हमें जो शिक्षा मिली है उन्हें हम कामयाब न कर सके । इसीलिये दूसरे विषयों में कितनी ही गवेषणा क्यों न हो कृषि के सुधार में उसका कुछ भी असर नहीं होता ।

यह तो कृषिकी मुख्य समस्या है ; अब कृषि की कुछ विशेष समस्याओं पर ध्यान देना चाहिये । ये त्रुटियां निम्न प्रकार हैं :—

(१) जमीन की समस्या :—

(क) जमीन की उर्वरता में कमी, (ख) जमीन का पट्टाव, (ग) आवश्यक प्राकृतिक तथा कृत्रिम सादको कमी, (घ) सिंचाई के प्रबंध का अभाव, (ङ) छोटे और बिलखे हुए खेत—ये अधिकांश में बेमुनाके

के हैं और इनके विभिन्न उत्पादन साधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता, (च) दोष युक्त भूमि-स्वत्व पद्धति ।

(२) किसानों का स्वास्थ्य, उनकी निरक्षरता और उनके शरीर तथा मन पर आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव ।

(३) कृषिमें पूँजीकी समस्या :—

(क) अत्यधिक तथा पुराना कर्ज, (ख) रकम के लिये मंदाजनों पर निर्भर, (ग) पूँजी प्राप्त करने के साधनोंकी कमी, (घ) अच्छे औजारों का अभाव, (ङ) बैल आदि पशुओं की कमजोरी, (च) दोषयुक्त बीजों का उपयोग, इत्यादि

(४) संगठन में त्रुटियाँ :—

(क) किसानोंमें संगठनका अभाव, (ख) कृषि-नियंत्रण तथा आयोजनकी कमी, (ग) उपजको बाजारमें लानेकी दोषयुक्त पद्धति, (घ) अच्छे यातायात साधनों की कमी, (ङ) गाँवोंके सामूहिक जीवनमें शिक्षितता का आविर्भाव. इत्यादि ।

कृषि व्यवस्थामें भूमि प्रधान साधन है इसलिये हमें इस पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिये । एक ओर हमें भूमि की उर्वरता बढ़ानी होगी और दूसरी ओर हमें प्रत्येक किसानको 'आर्थिक-जोत' देनी होगी जिससे उनका जीवन निर्वाह हो सके । जमीनमें खाद देकर उर्वरता बढ़ाने पर ही समस्याका समाधान हो सकता है । देशमें कम खर्चमें रसायनिक उपायोंसे खाद बनाने का प्रबन्ध जिस प्रकार हो सके उस पर राष्ट्रको ध्यान देना चाहिये । भूमिपर बढ़ते हुए भारके लिए गहरी खेती आवश्यक है ; इसलिये भी कृत्रिम खादोंको पैदावार होनी चाहिए । साथ ही साथ कृषकको यह सिखानेकी आवश्यकता है कि वह घरके सारे अग्रशिष्ट पदार्थों और मलोंको उचित परिवर्तनके बाद जमीनमें डाले । इससे न केवल आस पासका वातावरण शुद्ध रहेगा बल्कि

भूमिकी पदावार भी बढ़ेगी । हमारे देशकी अधिकांश जमीनमें पानीका हिस्सा बहुत कम है । इसलिये हमे वर्षापर पूरीतौरसे निर्भर रहना पड़ता है । भारत नदी-मातृ देश होते हुये भी जल सिंचाई तथा निकासके प्रबंध से वंचित है, इसलिए मौसमी वायु पर हमारी कृषि पूर्णतया आश्रित है । मौसमी वायु बहुत ही अनिश्चित होनेके कारण हमारे खेतोंमें हानि पहुँचती है ; साथ ही साथ हमारी जल-सम्पत्तिकी बर्बादी होती है । इसका प्रतिपात ६ हिस्सा ही वर्तमानमें सफल हो रहा है । हमारे सामने सिन्ध तथा पंजाबके वे उदाहरण हैं जहाँ कि सिंचाईका प्रबन्ध होने पर ऊपर जमीनमें भी काफी ताईदादमें फसल होने लगी है । दूसरे प्रान्तोंमें जहाँ पर जमीनमें प्राकृतिक उर्वरता है वहाँ अगर सिंचाईका प्रबन्ध हो जाय तो कृषिमें क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा । पश्चिमी बंगालमें अगर दामोदार घाटी योजना सफल हो जाय तो उम्मीद की जाती है कि उससे १० लाख एकड़ जमीनमें सिंचाईका प्रबन्ध होगा, १ करोड़ ८ लाख मन ज्यादा फसल मिलेगी, जाड़ेके समय ५ करोड़ रुपयेकी फसल प्राप्त होगी, ३ लाख किलोवाट जल विद्युत् पैदा होगी एवं कलकत्तेकी बन्दरगाहकी भी काफी उन्नति होगी । इस तरहसे अगर सारे देशमें सिंचाई एवं विद्युत् उत्पादन प्रबन्ध हो जाय तो हमारी कृषि तथा शिल्पके सुधारमें एक उल्लेखनीय मदद पहुँचेगी ।

इस देशमें जितनी जमीन है उसमें प्रतिशत २२ हिस्सा जमीन जोतनेके काबिल नहीं समझी जाती लेकिन इस समय जमीनकी बेकार रखना कोई गौरवकी बात नहीं है, विशेष कर जब हमारे देशमें अनाजकी इतनी कमी है । जर्मनी, अमेरिका प्रभृति देशोंमें काफी जमीन जोतनेके आशेष थी लेकिन विज्ञानकी सहायतासे वहाँ आज तिल मात्र भी जमीन बेकार नहीं मिलेगी । हमारे देशमें बेकार जमीन कम होते हुए भी हम उन्हें अभी तक पूरी तौरसे कामयाब नहीं कर सके हैं । कुछ दिनोंसे किसी-किसी प्रान्तीय सरकारका इस पर ध्यान गया है । संयुक्त प्रांत तथा पश्चिमी बंगालमें इन

सब जमीनोंको जोतनेका काम शुरू हुआ है लेकिन इसमें प्रेरणाका अभाव दिखाई पड़ रहा है। अगर अपनी ख़ास स्थितिको सुधारनी है तो हमें सारी बेकार जमीनोंको मशीनोंके प्रयोगसे जोतने पर ध्यान देना होगा।

उत्तराधिकार कानूनके प्रभावसे तथा सम्मिलित परिवार टूटनेके कारण सारी जमीन छोटे-छोटे टुकड़ोंमें खंडित तथा विभक्त हो रही है। इस प्रकारसे आज एक-एक किसानके हाथमें इतनी कम जमीन है जिससे एक परिवारका भरण-पोषण नहीं हो सकता। १९३१ सालमें बम्बई प्रान्तमें एक-एक किसानके हाथमें औसत पर कुलमें १६'८ एकड़ जमीन थी; दूसरे प्रान्तोंमें विशेषतः बंगाल, बिहार एवं संयुक्त प्रान्तमें एक-एक किसानके हाथमें इसका चौथाई हिस्सा जमीन भी नहीं थी। इस स्थितिके साथ अगर रूसको कृषिकी तुलना की जाय तो देख सकते हैं कि रूस देशमें सबसे छोटा खेत ६०० एकड़ पर है एवं सबसे बड़े खेतका आयतन ५००० एकड़ है औसत पर एक-एक खेतका आयतन लगभग १६०० एकड़ है। सिर्फ इतने बड़े-बड़े खेतोंमें ही आधुनिक तरीकेसे खेतीका काम चल सकता है। हमारे देशमें कमसे कम इतनी जमीन प्रत्येक किसानको मिलनी चाहिए जिससे वे जीवन निर्वाह की आवश्यकीय सामग्रियाँ प्राप्त कर सकें। बेशक सारे देशके किसानोंको समान जमीन देनेकी ज़रूरत नहीं है। जहाँकी जमीन अधिक उर्वरा है वहाँ कम जमीनसे भी काम चल सकता है। किस प्रान्तमें किसानको कितनी जमीन देनी चाहिए इस बातको तय करनेके पहले हमें जमीनकी उर्वरता, साधारण परिवारकी जनसंख्या एवं जमीनकी उपयोगिता पर ध्यान देना पड़ेगा। इसको सफल करनेके लिए या तो "उत्प्रेषणके नियम" के द्वारा, जिससे सबसे बड़ा लड़का भूमिका अधिकारी होता है वर्तमान कानूनोंमें परिवर्तन करना होगा या फिर किसी अन्य युक्तिका आयोजन करना होगा जिससे की भूमिका विभाजन तथा उपविभाजन होना बन्द हो जाय। सहकारी समितियाँ भी टोस चक्र-बन्द जोतोंका निर्माण कर सकती हैं।

भूमि-स्वत्व पद्धतियों में भी कुछ परिवर्तनको आवश्यकता है। हमारे देशके लिये सबसे अच्छी पद्धति कृषक-स्वत्व-पद्धति है। जमींदारी बंदोबस्त या तालुकेदारी पद्धतिको चालू रखना अब उचित नहीं है। यह सुधार कई वर्षोंसे अपेक्षित है; वास्तवमें इन परिवर्तनको कामयाब करनेमें कुछ असुविधाएँ जरूर आयेगी; क्षतिपूर्ति का सवाल ही सबसे अधिक जटिलताकी सृष्टि करेगा; लेकिन निकट भविष्यमें यदि जमींदारी प्रथाका अंत करना व्यवहारिक न हो, तो कम-से-कम कृषकका भूमि-स्वत्व अवश्य सुरक्षित होना चाहिए। पुनः कुछ प्रान्तोंमें कई प्रकारकी भूमि-स्वत्व पद्धतियाँ हैं, जो सरल बनाई जानी चाहिए।

सिर्फ जमीनकी समस्याओंका हल करने पर ही कृषिमें सुधार नहीं होगा, साथ ही साथ किसानोंकी निपुणता बढ़ाने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। इसके बारेमें हमें दो विषयों पर ध्यान देना पड़ेगा—एक, किसानकी निपुणता और दूसरा, जमीनके साथ उसका सम्बन्ध। हमारे किसान दरिद्र तथा निरक्षर हैं इसलिये वे जमीनकी स्थायी उन्नतिकी बातें सोच नहीं सकते और न सोचनेका साधन ही उनके पास है। जिन प्रान्तोंमें जमींदारी प्रथा प्रचलित है वहाँ भी जमींदार सिर्फ सज्जानेके साथ सम्बन्ध रखते हैं, कृषिकी उन्नतिके साथ नहीं। यूरोप तथा अमेरिकाके जमींदारों तथा हमारे जमींदारों में इस विषयमें कितना ही न अन्तर है। उन सब देशोंमें जमींदार तथा राष्ट्रकी चेष्टासे कृषिकी बहुत जल्द उन्नति सम्भव हुई है। हमारे देशमें जमीनके शोषण करनेवालोंका अभाव नहीं है; लेकिन जमीनकी उन्नतिके साथ वे लोग सम्बन्ध नहीं रखते। जहाँ पर जमींदारी प्रथा नहीं है वहाँ पर भी शोषण करनेवालोंका अभाव नहीं है। इस स्थितिको अगर सुधारनी हो तो एक ओर किसानोंमें उपयुक्त शिक्षाका प्रसार करना होगा एवं दूसरी ओर इन सब मज्जरथ शोषकोंको हटा कर किसानोंकी दाय सुक करना होगा। आज जमींदारी बंदोबस्त हटा देनेकी बात गहरी तौर पर सोची जा रही है।

इसमें कुछ असुविधाएँ भी ज़रूर आ रही हैं लेकिन जब भूमि पूरा दायित्व किसानों पर आ जायगा तो वे इसका सुधार करने पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।

किसानोंके हाथमें रकमका अभाव होनेके कारण भी कृषिमें बहुत-सी समस्याएँ आ जाती हैं। किसानको कर्ज तो प्रत्येक कृषि प्रधान देशमें लेना ही पड़ता है, लेकिन हमारे कृषि ऋणकी विशेषता यह है कि किसान अपनी दरिद्रताके कारण जितना कर्ज लेता, कृषिके सुधारके लिए उतना नहीं। कर्जके लिए वे साहुकारों पर निर्भर करते हैं। इस व्यवस्थामें कृषकों पर हर तरहके अत्याचार होते रहते हैं। १९२९ की विश्व मन्दोके बाद वेदखलीके मामले तथा भूमिका ज़बरन विक्रय काफी बढ़ गया और एक भूमिहीन कृषक-वर्गका उन्मेष दिखाई दिया जोकि सामाजिक स्थायित्व तथा देशकी शान्तिके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिकाके युक्कराष्ट्रमें विभिन्न प्रान्तोंमें भूमि-बैंक प्रतिष्ठित होने पर कृषक-सम्प्रदाय साहुकारों पर निर्भर नहीं करती हैं; जर्मनी में सहकार आन्दोलन के द्वारा इस समस्याका हल किया गया है। भारत में कुछ सहकारी समितियाँ ज़रूर कायम की गई हैं लेकिन इनकी जड़ नीचे तक नहीं पहुँच सकी। इस समस्याका अगर हल करना हो तो एक ओर देशके विभिन्न प्रान्तों में कृषि-बैंक प्रतिष्ठित करना होगा ताकि किसानोंको कम व्याज पर काफी रकम मिल सके और दूसरी ओर कृषिमें ऐसी उन्नति करनी होगी जिससे सिर्फ जीवन निर्वाह करने के लिए कर्ज लेनेकी ज़रूरत न पड़े। आज किसान जितना भी कर्ज लेता है वह सारा उसके जीवन निर्वाह करने में ही खत्म हो जाता है। कृषि यदि लाभदायक पेशा बन जाय तो उन्हें जीवन निर्वाह करने के लिए कर्ज लेनेकी आवश्यकता न रहेगी और सारी रकम वे कृषिकी उन्नति करने में लगा सकेंगे।

अब किसानोंकी वास्तविक रकम के बारे में दो एक बातें कही जाय। हमारे किसान उन पुराने ऋणकारों को काममें ला रहे हैं जो उन्हें उनके

पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं। यह बात अवश्य माननी पड़ेगी कि हमारी कृषि क्षेत्र वर्तमान प्रणाली में नई सुधारी हुई भूमि के अतिरिक्त भारी मशीनों तथा यांत्रिक हलों के लिए कोई स्थान नहीं। इसलिए हमें उन्हीं तरीकों का उपयोग करना चाहिए जिसमें पूँजीकी वचत हो और श्रमका अधिक से अधिक उपयोग हो। किन्तु इसका यह अर्थ कभी नहीं होता कि हम उन्नत औजारोंका उपयोग कभी और कहीं भी न करें। जब कृषिका वातावरण बदल जायेगा, जब बड़े पैमाने पर जोतनेका काम शुरू होगा तो मशीनों तथा यांत्रिक हलोंका पूर्ण उपयोग हो सकेगा। भारत में संसार की पशु संख्या का सबसे बड़ा भाग रहता है लेकिन दुःख इस बातका है कि हमारी जनता की तरह हमारे पशु भी भूखे रहते हैं। अतः उनकी स्वास्थ्य-क्षीणता होती जा रही है एवं वंश वृद्धि भी अधिक नहीं होती। पशु-उत्पत्ति ठीक चारा-दाना एवं भोजन तथा वैज्ञानिक पालन पोषण से बढ़ायी जा सकती है। प्रत्येक ग्राममें सार्वजनिक चरागाह के लिए कुछ जगह रक्षित होनी चाहिए और विशेष प्रकार की घास बोनी चाहिए। वंश-वृद्धि करनेवाले साढ़े ग्राम जनता को बिना लागत के या कम न्यून पर मिलने चाहिये। देशसे खली को निर्यात बंद होनी चाहिए। जो गाँव सड़कों द्वारा शहरों से जुड़े हुए हैं वहाँ मिश्रित-कृषि कायम करनी चाहिए।

किसानों में संगठन का भी काफी अभाव है। इसलिए उन्हें बहुत से मध्यस्थ व्यक्तियों के हाथमें पड़ना पड़ता है। यदि अपनी सामग्रीयोंको वे मंडियों में बेच सकें तो उन्हें अच्छी कीमत मिल सकती है लेकिन वही उनकी जैसी स्थिति है उसमें वे मंडियों के साथ बहुत कम सम्यन्ध रत्न सकते हैं। एक तो वे देहातों में रहते हैं और दूसरा बातायात का साधन भी काफी नहीं है। हमारे यहां रेलोंकी तथा सड़कोंकी लम्बाई देशके परिमाण तथा आबादी को देखते हुए बहुत ही नगण्य है। अब तक रेल-निर्माण-नीति यह भी कि विदेश के बन्दरगाहों की पासके स्थानों से जोड़

दिया जाय जिससे कि देशका विदेशी व्यापार बढ़े। यदि इन खर्वीली लाइनों के स्थानपर भारत में रेलोंका जाल बिछ जाता तो देशका आन्तरिक व्यापार बहुत बढ़ जाता। इसके अलावा एक एक किसानकी उपज भी इतनी कम होती है कि उसको मंडियोंमें लानेमें काफी खर्च पड़ जाता है। इसलिए वे उपजको या तो व्यापारियोंको या साहूकारोंको बेच देते हैं। किसानोंमें यदि संगठन किया जाय, और सहकारी विक्रय समितियां प्रतिष्ठित हो सके तो इन सब मध्यस्थ व्यक्तियोंके हाथोंसे उन्हें मुक्ति मिल सकती है और वे अपनी सारी सामग्रियां इकट्ठी करके बड़ी बड़ी मंडियोंमें उपयुक्त कीमतपर बेच सकते हैं। साथ ही साथ यातायातका आधुनिक तथा सस्ता प्रबन्ध भी हमें करना चाहिए। अन्तिम प्रयत्न सामूहिक ग्राम जीवनको पुनर्जीवित करनेके लिए करना चाहिए। हमारे प्राचीन ग्राम जीवनमें कई प्रकारकी सहकारिताएँ थीं किन्तु अब वे लुप्त तथा कालगत हो गई हैं। भारतके किसी किसी प्रान्तमें ग्राम पंचायत फिरसे कायम करनेका प्रबन्ध हुआ है लेकिन इनमें योग्य व्यक्तियोंका अभाव हमें हरवक्त मालूम पड़ता है। सरकारी कर्मचारी छोटेसे बड़े तक सब कोई अपनेको मालिक समझ बैठे हैं; इसलिए जनताके साथ उनका वास्तविक सम्बन्ध नहीं है। गावोंमें शिक्षितोंकी संख्या भी कम होती जा रही है। इस स्थितिमें गावोंका पुनर्निर्माण कौन करे? वास्तवमें यदि ग्रामशाला, ग्राम सहकार समिति तथा ग्राम पंचायत योग्य रीतिपर संगठित की जा सके तो ग्राम सुधार की समस्या काफी सुलभ सकती है।

हमारी खाद्य-समस्या—क्या हम खाद्यान्न के बारे में पूर्ण स्वतंत्र बन सकते हैं ?

“धाते हो (खाद्य-मन्त्री बननेके बाद) मैंने देखा कि पूज्य गांधीजीने जो-कुछ पहले कहा था वही ठीक है । उन्होंने कहा था कि विदेशोंपर हम बहुत भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँसे अन्न लानेमें हजारों अड़चने पड़ सकती हैं । हमारे लिए अपने देश और अपने लोगोंपर ही भरोसा करना ठीक है । पर हुआ इसके सर्वथा उल्टा हो । पीछले दो वर्षोंमें अन्तरिम मन्त्री-मण्डल बननेके बादसे हम और भी अधिक विदेशोंपर निर्भर हो गये हैं । ”

—आरमकथा, डॉ० गजेन्द्रप्रसाद

भारत कृषि प्रधान देश है फिर भी इस देशमें खाद्यपदार्थोंकी बहुत कमी है । सन १९४२ के दुर्भिक्षके समयसे जो खाद्य समस्या शुरू हुई है वह आज भी समाप्त नहीं हुई । सन १९४२ के मार्च महीने तक हमारी खाद्य समस्या सिर्फ कृषिसे उत्पादित वस्तुओंकी कीमत बढ़ानेकी ही समस्या थी ; कारण १९२९ के व्यापारिक संकटके समयसे लगाकर १९४२ तक खाद्यपदार्थोंकी कीमत गिरी हुई थी । इस स्थितिसे किसानोंकी जो नायिक क्षति हो रही थी सरकार भी उसका अन्त करना चाहती थी । इस मन्दीका असर हमारे देशपर सबसे अधिक हुआ था । सन १९४२ से जो समस्या शुरू हुई वह और भी जटिल तथा भीषण है । अन्न संकट हमारे लिए कोई नई अभिज्ञता नहीं है ; भारतमें अंगरेजी राज कायम होनेके बादसे इस देशमें बहुतसे दुर्भिक्ष पड़े हैं । पहली लड़ाईके वक़्त भी पैदावार कम हो जानेके कारण हमारी खाद्यस्थिति नाजुक हो चुकी थी लेकिन विक्रमक प्रसन्न ठीक था । इसलिए अन्न संकट इतना जटिल नहीं हो पाया जिसना कि दूसरी लड़ाईके वक़्त हुआ । प्रायः आधारभूत समयमें भी हमारी अन्नसुरकी

पुति प्रयोजनसे कुछ कम रहती थी और इसलिए हर साल हमें बर्मा, थाईलैंड हिन्द चीन, प्रभृति देशोंसे चावल मंगवाना पड़ता था। दूसरी लड़ाईमें जब ये सब देश जापानियोंके कब्जेमें चले गए तो चावलकी आयात बन्द हो गई ; साथ ही साथ विक्रयकी अव्यवस्था, चोरबाजारका आविर्भाव, संग्रह एवं वितरणमें सरकारी दुर्नीतियोंके कारण हमारी खाद्यस्थिति बेहद खराब हो गई।

लड़ाईके पहलेको साधारण स्थितिमें हमारे देशमें खाद्यपदार्थोंकी पूर्ति प्रयोजन से कुछ कम थी परन्तु सम्पूर्ण पृथ्वीकी प्राप्ति प्रयोजनके लिए अम्यासि नहीं थी बल्कि आवश्यकतासे अधिक प्राप्ति होनेके कारण दरवक्त मन्दोकी समस्या बनो रहती थी। इसलिए कभी-कभी पैदावारकी भी रोक देना पड़ता था। अमेरिकाके युक्त राष्ट्रोंमें पहली लड़ाईके बादसे गेहूँकी पैदावार बहुत बढ़ गई थी। १९०९-१३ सालोंमें औसतपर ४८० लाख एकड़ जमीन गेहूँकी पैदाईके लिए जोती जाती थी। १९१९ सालमें ७३० लाख एकड़ जमीनमें गेहूँकी पैदावार होती थी। इस समय सामग्रियोंकी कीमत साधारणसे दुगुनी हो चुकी थी परन्तु यूरोपमें पैदावार कम होनेके कारण गेहूँकी काफी खपत वहाँ पर होती थी। १९२० सालके बाद यूरोपमें पैदावार शुरू होनेके कारण अमेरिकासे गेहूँका निर्यात कम हो गया और खेतीमें मन्दो शुरू हुई। सन १९३२ में वह मन्दो हद तक पहुँच गई। युक्तराष्ट्रोंके बारेमें जो बातें कही गई हैं वे कनाडा, आर्जेन्टाइन प्रभृति कृषि प्रधान देशोंके लिए भी लागू हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद भी खाद्य पदार्थोंकी पैदावार बढ़ती रही। सन १९२२-२६ में औसतपर प्रति वर्ष सारी पृथ्वीमें १६९२८००० टन गेहूँ मौजूद था। सन १९३२ में, २७८१५००० टन गेहूँ एवं १९४० में ३५७३५००० टन गेहूँ मौजूद था। सन १९३५ से लगाकर १९३७ सालतक फसल नष्ट हो जानेके कारण पैदावार कुछ कम हुई थी लेकिन इन चन्द सालोंको छोड़कर १९४२ साल तक

सारी पृथ्वीकी ख़ाद्यस्थिति अच्छी थी। हमारे देशमें इन सब त्थोंमें खाद्यपदार्थोंकी प्राप्ति कुछ कम होनेपर भी कीमत बहुत कम थी एवं कभी-कभी विदेशोंसे आये हुये खाद्यपदार्थोंपर आयात-कर लगानेकी ज़रूरत पड़ती थी। परन्तु सबसे दुःखकी बात यह है कि सारी पृथ्वीमें जब अनाजकी पैदावार बढ़नेके कारण मन्दो चल रही थी उस वक़्त भी अनेक देशोंमें—भारत भी उनमें एक देश था—दरिद्रताके कारण अनेकोंको पूरी राय सामग्रियाँ नहीं मिलती थी। इस प्रकारसे लड़ाईके पहलेकी ख़ाद्य समस्याएँ कुछ दूसरे ही प्रकारकी थीं।

लड़ाई शुरू होनेके बादसे खाद्य समस्याका रूप पलट गया। एक ओर तो मुद्रा प्रसारके कारण कुछ व्यक्तियोंकी आमदनी बढ़ती गई एवं खाद्य-पदार्थोंकी कीमत भी बिना रुकावटके बढ़ती गई और दूसरी ओर पैदावार तथा विक्रयके प्रबन्धमें विघटन होनेके कारण उर्ज घटती गई। दूसरे देशोंमें लड़ाईके समय पैदावारकी कमी ज़हर हुई लेकिन विक्रयका उपयुक्त प्रबन्ध किये जाने पर ख़ाद्यसमस्या इतनी जटिल नहीं हो सकी। भारतमें जो अन्न संकट आनेवाला था भारत सरकारने बहुत दिन तक उस पर ध्यान नहीं दिया। १९४२ साल तक मुद्रास्फीति एवं सरकारी ख़रिदोंके कारण अनाजकी कीमत बढ़ती रही। खाद्य पदार्थोंका मूल्य बांध देनेकी कोशिश सरकारकी तरफसे हुई थी लेकिन कामयाबी न मिलनेके कारण सरकारने उस कोशिशको छोड़ दिया। सन १९३५ में बर्माके अंग्रेजोंके हाथसे निकल जाने पर हमारी ख़ाद्य स्थिति और भी बिगड़ गई। प्रति वर्ष हम बर्मानि १० लाख टनसे भी अधिक चावल मंगवाते थे। इनका आयात बन्द हो चुका एवं लड़ाई जितनी भारतके नजदीक आती रही उतना ही सरकार भारतके पूर्वी प्रान्तोंमें अनाज हटाने लगी। सारे देशमें चोर-व्यापारी तथा पदरथ सरकारी कर्म-चारियोंने छुट मचा दी। सभ्यता पर गर्व करनेवाली चीनकी सड़कीमें व्यक्तिगार की एक नमनूति हमारे सामने दिखाई पड़ी एवं इनके तान्त्रिक चरमसे इस

देशकी निर्वाक जनताका बड़ा एक हिस्सा कौट-गतोंकी तरह मौतका निशाना बना। सभ्यताके इतिहासमें इस प्रकारकी कुत्सित घटनाओंकी संख्या इमीगिनी ही है।

बहुत युक्ति विचार तथा आलोचनाके बाद भारत सरकारने १९४३ सालमें खाद्यस्थितिके बारेमें सलाह देनेके लिये एक कमिटी बैठाई और इसकी सलाहके अनुसार एक स्थूल खाद्यनीति ग्रहण किया जिसको उल्लेखनीय बातें निम्न प्रकारकी थीं:—(क) दूसरे देशोंसे खाद्यपदार्थोंकी आयात जहां तक हो सके बढ़ाना एवं भविष्यकी नाजुक स्थितिके लिये ५ लाख टन अनाज मौजूद रखना ; (ख) देशमें पैदावार बढ़ानेके लिये यथा रीति प्रबन्ध करना, जैसे किसानोंको हर तरहसे प्रोत्साहित करना, कच्चे मालकी पैदावार घटाकर लसी जमीनपर अनाज पैदा करना, सिचाईका प्रबन्ध करना, इत्यादि। इसी नीति के अनुसार सरकार ने “अधिक अन्न उपजाओ” का प्रचार शुरू किया ; (ग) केन्द्रवर्ती सरकार के निर्देशानुसार एक मौलिक आर्थिक योजना ग्रहण करना ; (घ) खाद्य-पदार्थों की कीमत बांध देना ; (ङ) बड़े-बड़े शहरों में खाद्य पदार्थों के विक्रय पर नियंत्रण लगाना।

*

*

*

दूसरी लड़ाई का अन्त हो चुका है लेकिन अभी तक खाद्य समस्या का अन्त नहीं हुआ। सारी पृथ्वी पर आज जो अन्न संकट चल रहा है हमारी समस्या उस में शामिल होते हुए भी अनेक देशों से अधिक जटिल बन गई है। लड़ाई के बाद के प्रथम साल में कहीं तो बाढ़ के कारण और कहीं वर्षा के अभाव के कारण अनाज की पैदावार यों ही कम हुई थी ; इसके अलावा मृदु तूफान से फसलको काफी हानि पहुंची। इस समय विदेशों से अनाज नहीं आता था। इन कारणों से १९४५-४६ साल में हमारे देश में वर्तमान रहन सहन के हिसाब से ८० लाख टन अनाज की कमी थी। अन्तरराष्ट्रीय खाद्य स्थिति पर विचार करने के लिए इस समय

एक अन्तरराष्ट्रीय खाद्य-संस्था कायम की गई। इस पर भी हमारी गंभीर स्थिति नहीं सुधरी। १९४६ साल के अन्त में बड़े बड़े शहरों में नियंत्रित खाद्य विक्रय का प्रबन्ध किया गया। इस साल भी हमारी अनाज की उब्जा ४० लाख टन कम थी जिसमें १७ लाख टन की पूर्ति बाहर से हुई। १९४७ साल में भी हमारी खाद्य स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ।

भारत विभक्त होनेपर हमारी खाद्य स्थिति और भी बिगड़ गई। भारत में १७२ लाख टन चावल तथा ४१ लाख टन गेहूं की पैदावार होती है; पाकिस्तान में इनकी पैदावार ५३ लाख टन एवं २७ लाख टन क्रमशः है। पूर्वी पाकिस्तान चावल तथा पाट के लिए एवं पश्चिमी पंजाब गेहूं तथा दई के पैदावार के लिए विख्यात है। इन दोनों प्रान्तों के भारत से निकल जाने से हमारी खाद्य एवं कच्चे माल की पैदावार कम हो गई है। बिचाई का जो कुछ प्रबन्ध हुआ था वह भी अधिकतर पाकिस्तान के हिस्से में ही पड़ा है। इस प्रकारसे खाद्य पदार्थों की दृष्टि से विभाजन का नतीजा हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ।

अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार ने जो कुछ कारवाइयाँ की उसका सारा ऊपर किया गया है परन्तु इनसे सफलता कितनी हुई यह विचारणीय बात है। १९४३ साल से लगाकर छिछरे साल तक केन्द्रापी तथा प्रान्तीय सरकारों ने इस काम में लगभग ३३ करोड़ रुपये खर्च किया लेकिन इससे सफलता क्या हुई? सन १९४७ के अप्रैल महीने में एक प्रेस नोट में सरकार ने बताया कि भारत में ६४० लाख टन खाद्य पदार्थों की उब्जा है एवं ५६० लाख टन की पैदावार होती है। बाद दफ्तर का कहना है कि होते हुए ४ वर्षों में खाद्य पदार्थों की पैदावार १२० लाख टन बढ़ी है। अगर यह आंकड़ा ठीक हो तो हमारे वर्षा खाद्य वस्तुओं की कमी न होनी चाहिए, मरिह कुछ बचत ही होनी चाहिए। आँकड़े के द्वारा वास्तविक

स्थितिका अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार के आंकड़े के बावजूद भी हमें हर साल काफी ताबदाद में खाद्य सामग्रीयां बाहर से मंगानी पड़ती हैं। निरुद्ध भविष्य में आयात घटने की या पैदावार बढ़ने की कोई भी टम्मीद नहीं है। जिन खेतों में कच्चे माल की पैदावार होती है वहां अनाज की पैदावार भी हो सकती है या नहीं इसके बारेमें जाँच करने के लिए सरकार ने एक कमिटी कायम की थी। इस कमिटिका निष्कर्ष ऐसा है कि अगर इस प्रकार परिवर्तन किया जाय तो उससे कच्चे मालकी पैदावारमें काफी हानि होगी एवं अनाज की पैदावारमें भी आशानुष्य सफलता नहीं होगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे सामने कच्चे मालकी पैदावार बढ़ाने की भी समस्या है। देश विभक्त होनेके सबब भारतमें रूई, पाट प्रभृति कच्चे मालोंकी काफी कमी हो चुकी है जिसे अनेक कारखानोंके लिए उत्पादन बढ़ाना या लगातार काम करना असम्भव हो रहा है। इसलिए जोताई, चोआईमें इस प्रकारका परिवर्तन करना असम्भव नहीं होगा और न करनी ही चाहिए। खाद्य पदार्थोंकी पैदावार यदि बढ़ानी हो तो हमारे सामने दो रास्ते हैं—एक, कृषिका सुधार करना एवं दूसरा, बेकार जमीनोंको जोतनेका प्रयत्न करना। कृषिके सुधारके लिए हमें कृषि-योजना ग्रहण करनी होगी जिसमें कृषिकी विभिन्न समस्याओं पर ध्यान दिया गया है। बेकार जमीनोंको जोतनेकी एक जटिल समस्या भी हमारे सामने है। जिस देशमें खपतके अनुसारसे पैदावार बहुत कम होती है उसमें जमीन बेकार रखना कोई गौरवकी बात नहीं। भारतमें लगभग ८८० लाख एकड़ जमीन बेकार है। इसके अलावा और भी बहुत-सी जमीनें हैं जहाँ घास आदि होती हैं या मामूली-से जंगल हैं। ऐसी जमीन भारतके विभिन्न प्रान्तोंमें, जैसे कि पूर्वी पञ्जाब, संयुक्त प्रान्त, बिहार, आन्ध्र, उड़ीसा, मध्यप्रान्त, मद्रास एजेन्सी, मालवा, तथा विन्ध्य प्रदेशमें दिखाई पड़ेगी। खाद्य नीतिपर सलाह देनेवाली समितिकी राय यह है कि निरुद्ध भविष्यमें १०० लाख टन अनाजकी पैदा बढ़ानी होगी जिसमें सिंचाईके

प्रबन्धसे ४० लाख टनकी वृद्धि होगी। विभिन्न प्रान्तोंकी कृषि योजनाओं से ३० लाख टन एवं दोष ३० लाख टन बेकार जमीनोंको जोतकर बढ़ा जा सकेगी। सरकारकी तरफसे बताया गया है कि संयुक्त प्रान्त एवं पश्चिमी बंगाल में बेकार जमीनोंको जोतनेका काम आरम्भ हो गया है। परन्तु इस प्रकारसे जितनी जमीनें अभी तक जोती गई हैं उनसे हमारे अन्न संकटका सुलझाव नहीं होगा। हमारी पुरानी जमीनोंकी उर्वरता दिन पर दिन घटती जा रही है; बेकार जमीनें जिस तरहसे जोती जा रही हैं उनसे सिर्फ इस कमीको दूर की जा सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इस विषय पर यदि सरकार गम्भीरतापूर्वक ध्यान दे एवं सुचिन्तित आर्थिक योजनाओंको कार्यान्वित कर सके तो हमारे अन्न संकटका सुलझाव हो सकता है। सरकारका कहना है कि १९५१ साल तक हम इस विषयमें आत्म-निर्भर बन जायेंगे एवं बाहर से खाद्यान्न मंगानेकी कुछ भी आवश्यकता न रहेगी। परन्तु इतने जल्द स्वतन्त्र बननेकी सम्भावना कम है। अभी तक कागजी कारवाइयोंकी छोड़ कर कोई उल्लेखनीय काम नहीं हुआ। इसमें सरकारी दफ्तरोंकी काफ़ी त्रुटियाँ हैं। वास्तवमें जब काम शुरू होगा उसके बाद भी सिंचाई का प्रबन्ध करनेमें, आर्थिक योजनाओंकी कार्यरूप देनेमें एवं बेकार जमीनोंको जोतने योग्य बनाने में कुछ समय जरूर लगेगा। हालमें सरकारने रुग्नेकी कीमत घटानेका जो निश्चय किया है उससे ढालरकी कीमत लगभग ४४ प्रतिशत बढ़ गई है एवं अमेरिकासे जो खाद्यान्नामप्रीश आती थीं उनकी आयात शेष बिलकुल बन्द हो जायेगी, या उन पर हमें अधिक कीमत देने पड़ेगी इससे हमारी अन्न समस्या और भी जटिल होगी। इन सब बातोंकी महत्त्व करते हुए यदि अभीसे काम शुरू किया जाय तो उम्मीद है कि अन्न-दवायकोंमें एक खाद्यान्नके बारेमें स्वतन्त्र बन सकेंगे।

दामोदर घाटी-योजना

भारतके कृषि-सुधारके इतिहासमें दामोदर घाटी-योजना एक नया अध्याय जोड़ रही है। अब तक अनेक नदियों पर सिंचाईके उद्देश्यसे बांध, बांधे गये हैं; कुछ तो बाढ़ नियन्त्रणकी दृष्टिसे और कुछ विद्युत-शक्ति उत्पादन करनेके लिये। दामोदर घाटी-योजना आधुनिक सिंचाई व्यवस्थाके मूल सिद्धान्तके आधार पर बनाई गई है। सिंचाई, बाढ़-नियन्त्रण, विद्युत-शक्ति उत्पादन, जहाजरानी आदि सारी बातें इस बहुमुखी योजनामें सम्मिलित हैं। इस बहुमुखी योजनाके कार्यान्वित होनेपर न केवल दामोदर नदी-क्षेत्र निवासियोंके आर्थिक जीवनमें ही क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा, बल्कि सारे देशकी आर्थिक काया तक पलट जायेगी एवं हमारी जनताका जीवन-स्तर ऊँचा करनेमें यह विशेष रूपसे सहायक होगी।

दामोदर नदी का उद्गम और बहाव का विवरण देते हुए अर्थ-सन्देश ने लिखा है :—दामोदर घाटी का उद्गम छोटा नागपुर प्रांत में पालामऊ और राँची जिले से घिरे हुए पठार में है। यह पठार कई नदियों का उद्गम-स्थान है। दामोदर के अतिरिक्त यहाँ से निम्न नदियाँ निकलती हैं—उत्तर की ओर बहनेवाली औरंगा और उत्तरी कोयल; दक्षिण की ओर बहनेवाली दक्षिणी कोयल, कारो और साँख; पूर्व की ओर बहनेवाली चाराकर, कोनौर, काँचो और करकरी। इसी पठार के घने जंगलों की गहरी घाटियों से निकल कर दामोदर पालामऊ जिले में लगभग २५ मील बहने के पश्चात् हजारीबाग जिले में प्रवेश करता है। कुछ मील और आगे बहने पर इसमें उत्तर से आनेवाली कोनौर नदी भी आ मिलती है। लगभग ३५ मील और आगे बहने के पश्चात् यह बिहार-प्रांत की अपनी यात्रा समाप्त कर देती है। ठीक बंगाल-प्रांत में प्रवेश करने के स्थान पर

इसमें उत्तर से बड़ी बेगवती सहायक नदी बाराकर आ मिलती है। यहां तक दामोदर की घाटी समुद्र तलसे लगभग १३२६ से ७१३ फीट ऊँची रहती है। बाराकर नदी के मिलनेके पश्चात् दामोदर का बहाव कुछ फैलना आरम्भ होता है और रानीगंज तथा वर्दमान के बीच यह धीमी और विस्तृत नदी बन जाती है। हुगली पहुँचते-पहुँचते जल की मात्रा यद्यपि बढ़ जाती है, तथापि नदी की गति शिथिल और गहराई कम हो जाती है। दामोदर ३३६ मील लम्बी है, जिसमें से इसका १८० मील मार्ग बिहार-प्रान्त में और १५६ मील बंगाल-प्रान्त में है। लगभग ८५०० वर्गमील में दामोदर और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र फैला हुआ है।

जल सम्पत्ति किसी भी देशके लिए आर्थिक दृष्टिसे गौरव की वस्तु होती है यदि उस जल सम्पत्ति का पूरी तौरसे प्रयोग हो। परन्तु, वास्तव में दामोदर नदी ने अबतक बिहार और बंगाल में संहारका ही कार्य किया है। प्रत्येक वर्षा-ऋतु में दामोदर नदी अतिरिक्त मात्रा में बालू लाकर मैदानी क्षेत्र में जमा कर देती है अतः जब बाढ़ आती है इससे इस क्षेत्र के निवासियों को, विशेष करके वर्दमान जिलेके निवासियों को, काफी हानि पहुँचती है। दामोदर नदी में अधिक बाढ़ आनेके कई कारण हैं। जिस क्षेत्रमें इस नदी का बहाव है वहाँ हर साल वर्षा-ऋतु में अधिक वर्षा होती है जिस को बालू से भरी हुई दामोदर की तली बहावर ले जाने में समर्थ नहीं होती और नदी अपने स्वाभाविक मार्ग को छोड़कर आस-पासकी जमीन को बहाना शुरू कर देती है। इस क्षेत्रमें न नील हैं और न पत्तों के पत्त हैं जो कि पानी को रोक सकें। दामोदर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में जो भी पत्त थे वह भी नष्ट हो चुके हैं। अतः जलवेग रोकने का कोई साधन अब नहीं है।

एक समय यह था जबकि आर्थिक दृष्टिसे अमेरिका के टेनेसी क्षेत्र

निवासियों की अवस्था दामोदर क्षेत्र निवासियों की अवस्था से कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन विज्ञान के द्वारा इस नदीको जिस प्रकार से टेनेसी-क्षेत्र निवासियोंके जीवनका दर्जा ऊँचा करनेके काममें लगाया गया है और जिसे आज पृथ्वी के इस प्रांत में सारे वीरान-क्षेत्र उर्वर क्षेत्रों में परिवर्तित हो चुके हैं वह वास्तवमें वैज्ञानिक तथा यांत्रिक साधना के चरम सफलता को सूचित कर रही हैं । इस क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण इनके भौतिक जीवन की धारा विलकुल बदल गई है और आज वे कह सकते हैं कि न तो दरिद्रता कोई दैविक घटना ही है और न रोग-शोक आदि शायतानके द्वारा किये जाने योग्य हैं । टेनेसी नदी उत्तरी अमेरिका के सात पश्चिमी रियासतोंमें से बहकर मिसिसिपी नदीमें मिलती है । इसकी पाँच सहायक पहाड़ी नदियाँ हैं । टेनेसी घाटी-योजना कोई एकांगी योजना नहीं है ; यह एक बहुमुखी योजना है जिसका लक्ष्य सिर्फ बाढ़ नियन्त्रण करना ही नहीं है बल्कि सिंचाई तथा जलशक्ति उत्पादन भी इसमें सामिल हैं तथा जल, भूमि, वन, खनिजपदार्थ—इन सबको इकट्ठा करके, परस्पर सम्बन्धित करके टेनेसी-निवासियों के जीवनका दर्जा ऊँचा करना, उनकी सुख-समृद्धि बढ़ानो ही इसका मूल लक्ष्य रहा है । इस नैतिक आधार पर यह योजना बनो है । लगभग १७५००० एकड़ जमीन इसके लिए साफ की गई है जहाँ कि आज विज्ञान और यांत्रिक कौशल के द्वारा २१ बाँध बाँधे गए हैं । इसमें १९४४ ईसवी तक लगभग ७०० मिलियन डालर रकम व्यय हो चुकी है । यह पूँजो-विनियोग कितना सफल हुआ है उसका श्रेष्ठ निदर्शन वहाँ के खेतों में, पशु-शालाओं में, कल-कारखानों में, सामाजिक उन्नति में पाया जाता है । यह तोरा प्रबन्ध टेनेसी-भूमि को एक नया जीवन प्रदान किया है । जहाँ एक समय जमीन का कटाव होता था, जमीन खाईयाँ और टीले से भरी हुई थी वहाँ जमीन आज जोतने योग्य तथा उर्वर बन चुकी है । इस प्रांत में आज वैज्ञानिक रीति से पैदावार

होती है। इस घाटी का लगभग ५४ भाग वन से आच्छादित है और इस वन-सम्पत्ति पर आधारित उद्योगधन्यों से वार्षिक लगभग ११२ मिलियन डॉलर कीमत की पैदावार होती है। इस विराट परिवर्तन के पीछे काम कर रही है मनुष्यकी चिन्तन शक्ति जिसके द्वारा इस प्रांतके निवासियों के जीवन में इतना गहरा परिवर्तन सम्भव हुआ है। 'बाढ़ भरी टेनेसी के स्थान पर नियन्त्रित नहरें, ऊपर भूमिके स्थान पर उपजाऊ खेत, नदी-घाटियों के स्थानपर जहाजरानी के योग्य जलमार्ग, रुढ़-भट्टियों के स्थान पर विद्युत-यन्त्रों द्वारा सुसज्जित रसोईघर और कमरे, भूग और महामारी की जगह पोषक पदार्थ और आरोग्य-केन्द्र, ऊबड़-खाबड़ मार्गों के स्थान पर मोटर और रेलगाड़ी की सुविधा, सारांश में दुखी एवं कष्टसाध्य जीवन सुखी एवं समृद्धिशील जीवन में परिवर्तित कर दिया गया है।' यह सारा परिवर्तन टेनेसी-घाटी-व्यवस्था के फलस्वरूप है।

हमारी दामोदर नदी टेनेसी नदीसे कोई कम नहीं है, लेकिन अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। इसलिये प्रकृतिका यह दान हमारे लिये हानिकारक हो रहा है। भारतके पश्चिमी प्रान्तोंमें जो अभी पाकिस्तानमें शामिल हैं सिंचाईका कुछ प्रबन्ध हुआ था। इसका तथा इस प्रकारके दूसरे मामूली प्रयत्नोंका लक्ष्य था बहते हुए पानीको नहरोंके जरिये खेतों तक पहुंचना देना, किन्तु अब इस प्रकारके योजनाओंकी सम्भावना कम है। दक्षिण भारतकी नदियोंकी तरह अब हमें वर्षा ऋतुमें नदियोंके वर्षाद होने वाले पानीको सुरक्षित स्थानमें रक्ता होगा और आगामी वर्षादक यह सिंचाई के काममें लगा जायगा। हिंदगंगादमें इस प्रकारकी एक छोटी योजना है जिससे नदीका दमकनेवाला जल निम्नम सागर तथा उसमान सागरमें सुरक्षित किया जाता है। यह प्रबन्ध होनेपर नदीमें बाढ़ नहीं आती। दामोदरघाटी योजनासे भी यह उद्देश्य सिद्ध होगा। इसके अलावा इससे बिजली की पैदा

की जा सकेंगी जिसके द्वारा कृषि, गृह-उद्योग, कारखानों तथा यातायात साधनोंको सुविधा होगी ।

इस जल सम्पत्ति पर हमारा दृष्टि १९३७ ईसवीमें आकर्षित हुई थी । सन १९४५ में प्रथम दामोदर-योजना-सम्मेलन बुलाया गया । यह सम्मेलन एक बहुमुखी योजना तैयार करनेका तथा प्रारम्भिक आयोजन करनेका निश्चय किया । सम्मेलनके निर्णयके अनुसार इस योजनाके बारेमें सलाह देनेके लिए अमेरिकाके एक विशेषज्ञ इंजीनियर-मण्डलको बुलाया गया । इनके रिपोर्टके आधार पर योजनाके संगठन सम्बन्धी निर्णय किए गए । सन १९४७ के जनवरी महीनेमें जो शेष सम्मेलन हुआ था वह इस योजनाके इतिहासमें अत्यन्त महत्वपूर्ण था । इस सम्मेलनका सिद्धान्त निम्न-प्रकार था :—

(१) केन्द्रीय कानून द्वारा दामोदर घाटी-कारपोरेशनकी प्रतिष्ठा की जाय ।

(२) जिन स्थानोंमें सुरक्षित जलाशय बनेंगे तथा बांध बांधवागे जायेंगे वहाँसे हटायी हुई जनताको फिरसे यथार्थ परिस्थितिमें बसाया जाय ।

(३) योजना पर लगाए जानेवाले ५५ करोड़ रुपयेके व्ययके वितरणके सम्बन्धमें सम्मेलनने निम्न प्रकार सलाह दी है :—

(क) विद्युत-शक्ति उत्पादनके निर्माण कार्यपर जो रकम लगेगी वह केन्द्रीय सरकार तथा बंगाल और बिहारकी प्रान्तीय सरकारें बाँट लें ।

(ख) सिंचाई-निर्माण-कार्य पर जो व्यय हो उसे बिहार और बंगालकी प्रान्तीय सरकारें बाँट लें ।

(ग) बाढ़-नियंत्रण-कार्य पर जो पुँजी-न्यय होगी उसे केन्द्रीय और बंगालकी सरकारें आधा-आधि बाँट लें ; परन्तु भविष्यमें केन्द्रका इस प्रकारके व्ययसे कोई सम्बन्ध न होगा ।

दामोदर घाटी-योजना सफल होने पर हमें निम्न प्रकारकी सुविधाएँ होंगी :—

(क) प्रतिवर्ष दामोदर घाटीके किसी-न-किसी भागमें बाढ़ आती ही रहती है। इनको रोकनेके लिए उत्तम दामोदर तथा बराकर पर बाँध बाँधनेकी योजना बनाई गई है। निम्न स्थानोंपर बाँध निर्मित करनेका निश्चय किया गया है :—(१) बराकर नदीके मलवान स्थान पर, (२) दामोदर नदीके ऊपर सानोलापुर स्थान पर, (३) देवलवारी बराकर पर, (४) तिडमा बराकर पर, (५) अय्यर दामोदरपर, (६) बोकारो-बोकारो नदी पर, (७) मध्य कोनार पर। इन बाँधों द्वारा १०५७५००० एकड़ क्षेत्रके डु-हिरसेका जलप्रवाह नियंत्रित होगा और इनमें आज तक आई हुई बाढ़से दुगुनी बाढ़ नियंत्रण करनेकी क्षमता रहेगी।

(ख) ये सात बाँधों केवल बाढ़ नियंत्रणमें ही मदद नहीं करेंगे बल्कि समस्त दामोदर-घाटीको विद्युन्मय बना देंगी। इनके अलावा एक और बाँध सिर्फ जलशक्ति उत्पन्न करनेके लिए निर्मित की जायगी। इनसे लगभग ३००००० किलोवट विद्युत-शक्ति उत्पन्न की जा सकेगी।

(ग) बिहार और बंगालकी नदियोंकी स्थिति ऐसी है कि वर्षाकालमें उनमें पानी अत्यधिक होता है और पानीके बढ़ावसे बाढ़ कटकर नदियोंके तल पर जमा हो जाती है, लेकिन शीतकालमें ये प्रायः सूख जाती हैं। इसलिए इन प्रान्तोंकी वास्तविक समस्या यह है कि इन नदियोंको इस प्रकारसे नियंत्रित किया जाय ताकि इनमें हरवक ही समान रूपसे पानी बहता रहे—न तो कभी बाढ़ आवे और न पानी सूख जाय। दामोदर नदी पर सात जलकुण्ड ऐसे स्थानों पर और इतनी ऊँचाई पर बनाए जायेंगे कि बाढ़का नियं-

त्रण तो होना ही साथ-ही-साथ खेतीको भी हरवक्त पर्याप्त पानी मिल सकेगा। इससे लगभग १० लाख एकड़ जमीनमें सिंचाईका प्रबन्ध होगा एवं एक करोड़ आठ लाख मन अधिक उपज मिलेगी। शीत-ऋतुमें भी सिंचाईके प्रबन्धसे लगभग ५ करोड़ रुपयेकी उपज मिलेगी। अब तक इस क्षेत्रमें कभी वर्षाकी अत्यधिकताके कारण और कभी पानीकी कमीसे फसल खराब होती रही है; दामोदर-घाटीकी बहुमुखी योजनाके कार्यान्वित होनेसे छोटानागपुर तथा पश्चिमी बंगालका चेहरा तब पलट जायेगा।

(घ) साधारणतः प्रत्येक नदी—दामोदर भी इनमें सामिल है—वर्षाऋतुमें अत्यधिक बालू मैदानों क्षेत्रमें लाकर जमा कर देती है अतः धीरे-धीरे नदीकी तली भर जाती है। बादमें यह बालू हुगली नदीमें धा जाती है। अगर यह व्यवस्था चलती रही तो हुगली नदीका मुँह भी बन्द हो जायेगा एवं यह कलकत्तेकी बन्दरगाहके लिए खतरा हो जायेगा। दामोदर घाटी-योजनाका सफल प्रयोग होने पर इस बन्दरगाहका स्थितिकाल बढ़ जायेगा।

(ङ) एक समय भारतमें नौका संचालन समृद्ध अवस्थामें था। सस्ते दर पर भारी माल ढोनेके लिये नौका आज भी सर्वोत्तम साधन मानी गई है। इस बातके प्रमाण भी मिलते हैं कि ईष्ट इंडिया कम्पनीके ज़मानेमें खानोंसे कोयला नौका द्वारा कलकत्ते तक पहुंचाया जाता था। गत सौ वर्षोंमें नौका यातायातकी अवहेलना ही नहीं की गई है बल्कि जान घुसकर उसकी प्रगति रोक दी गई है। दामोदर घाटी-योजनामें एक प्रस्ताव यह है कि दूर्गापुरसे लगाकर रघुनाथपुर तक एक नहर बनाई जाय ताकि दामोदरके साथ हुगली नदीका संयोग स्थापित हो जाय। इसमें नौका संचालनकी उन्नति होगी एवं रेल पर दबाव बहुत कम हो जायेगी।

‘अर्थ सन्देश’ के शब्दोंमें इस निबन्धकी समाप्ति की जायः—

बाढ़ नियन्त्रण, विद्युत-शक्ति-उत्पादन, सिंचाई और नौका संचालन—

ये दामोदर घाटी-योजनाके चार प्रमुख अंग हैं। इस प्रकारकी बहुमुखी योजना टेनेसी व्यवस्थाको छोड़कर संसारमें दूसरा प्रयोग है, जिसमें प्रकृति-प्रदत्त नदी, वन भूमि और खनिज-सम्पत्तिको एक इकट्ठी मानकर विज्ञान और यंत्रकोशल द्वारा मानव-सेवाके लिए मनुष्य और प्रकृतिमें तारतम्य स्थापित करनेका सफल प्रयत्न किया है। योजनाकी महानता उसके उत्तुंग बांधोंमें नहीं, प्रकृति पर विजय पानेमें नहीं बल्कि उसकी वास्तविक महानता है घाटीके सत्तालाख निवासियोंकी दरिद्रता, रोग और अज्ञानताकी शृङ्खला तोड़नेमें। दामोदर घाटीके बाढ़, अकालमें भूख और महामारीके कारण किसानोंका जीवन स्रोत सूख चुका है। योजना इस सूखे स्रोतको पुनः प्लावित करने में सफल होगी, इसमें सन्देह नहीं। आज जो दामोदरके जलमें निर्धनता मुर्तमान मालूम पड़ती है, योजना के कार्यान्वित होने पर वह सुख और समृद्धि का प्रतीक बन जायगी।

जमींदारी-प्रणाली का भविष्य-आगे क्या ?

जमींदारी प्रणालीकी-समाप्ति का प्रश्न अब वादविवादका विषय नहीं रह गया। अब तो यह बात मान ली गई है कि जमींदारी-प्रणाली समाप्त हो जाएगी। विभिन्न प्रान्तों में आज ऐसे कानून बनाने जा रहे हैं जिनसे इस प्रणाली का अंत हो जाय और इनके स्थान पर ऐसी भूमि-प्रणाली का निर्माण हो जिनसे किसानों तथा छोटे देशका आर्थिक उत्थार हो।

भारत में जमींदारी प्रणालीका इतिहास बड़ा विचित्र है। पंगल में जिस वक्त, इंग्लिश कानूनों का प्रचलन कायम हुआ तब वक्त उनकी अधिक अवस्था

खराब हो चुकी थी और शासनका काम चलाने के लिए उन्हें रुपये की जरूरत थी लेकिन एक नए देशके जनसाधारण से लगान वसूल करना उनके लिए आसान नहीं था। न तो वे इस देशकी भाषाही जानते थे और न इस प्रान्तके विभिन्न इलाकों से परिचित ही थे। यातायात का कोई अच्छा प्रबन्ध भी उस वक्त नहीं था और न उन्हें इस देश से किसी प्रकारकी अभिज्ञताही थी। इस समय भारतीय राजनीति में विशृंखला चल रही थी। इसके सुयोगसे बहुत से छोटे बड़े लोग जमींदार बन बैठे। इंग्लैन्डकी जमींदारी प्रथासे परिचित होनेके कारण इष्ट इन्डिया कम्पनी समझ नहीं सकी कि ये लोग वास्तवमें जमींदार हैं या नहीं और न समझने का अवसर ही उन्हें मिला। आसानी से लगान का संग्रह करने की उन्हें आवश्यकता थी। कम्पनी ने पहले पंचवार्षिक तथा दशवार्षिक बन्दोवस्त किया परन्तु उन्हें इस में सफलता नहीं प्राप्त हुई। इस लिए सन १७९३ साल में लार्ड कार्नवालिस ने हमारे देश में जमींदारी प्रणाली की नींव डाली। इस में जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया गया—जमींदार लगान संग्रह करें और उसका $\frac{1}{3}$ हिस्सा सरकार को दें ऐसा निश्चित हुआ। वर्तमान समय में यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस तथा उत्तर मद्रास में प्रचलित है। जमींदारी प्रथा कायम होने के बाद करीब ५० साल तक जमींदार को इससे विशेष फायदा नहीं था; १९ शताब्दी के मध्यभाग से यातायात का आधुनिक प्रबन्ध होने लगा, सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तनों के कारण जमीन की कीमत एकाएक बढ़ने लगी। जमींदार लोग इससे फायदा उठाने लगे। जमींदार जो लगान सरकार को देते थे वह पहले से ही निश्चित थी परन्तु जमींदार जमीनपर कितना लगान लगावेगा इसके बारेमें कोई निश्चित विधान नहीं था। इसलिए जिससे जमींदारों को अधिक लगान प्राप्त होती थी उसीको वे जमीन दे देते थे। लालच में पड़कर पुराने किसानों को दूराने में वे जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। इस प्रकार से किसानों की चरम दुर्दशा होने

लगी और कृषिकों को काफी हानि पहुँची । जमींदारों प्रणाली को कायम करने में सरकार का पहला लक्ष्य था किसानों से मालगुजारी वसूल करना एवं दूसरा लक्ष्य कृषिकों सुधार था । मालगुजारी प्रप्त करने में सरकार को लक्ष में बहुत कमी हो गई परन्तु दूसरा उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ । कन्नौ ने सोचा था कि विलायत के जमींदारों की तरह इस देश के जमींदारगण भी कृषि की उन्नति में हाथ बँटावेंगे ।

जमींदारों के इस अत्याचार से किसानों को बचाना विशेष जरूरी हुआ इसलिए सन् १८५९ तथा १८८५ में बंगाल में दो कानूनें बनाई गईं जिनसे उन किसानों का दखल मान लिया गया जो कि १२ वर्षों से लगातार जमीन को जोतते थे । जब तक ये मालगुजारी देते रहेंगे तब तक जमींदार उनको हटा नहीं सकेगा । इन कानूनों के द्वारा जमीनपर किसानों का अधिकार तो हो गया लेकिन विक्रय का अधिकार नहीं । सन् १९२८ के एक कानून के द्वारा विक्रय का अधिकार भी मान लिया गया लेकिन जिस कीमत में जमीन विक्रेता उसका पाँचवाँ हिस्सा जमींदार को मिलेगा तथा जमींदार उसका विक्रय नृच्य देकर उस जमीन को गरीब भी सकेगा । सन् १९३८ के एक कानून के द्वारा इन बाधाओं का शान्त कर दिया गया । अब किसान बिना किसी रकबाबत के जमीन को गरीब भी सकता है और बेच भी । मालगुजारी वसूल करने के अलावा अब जमींदार का और कोई काम नहीं रहा ; किसान ही जमीन का वास्तविक मालिक हो गया ।

इस प्रकार से किसानों के रक्षा का प्रयत्न तो हुआ लेकिन जमींदारी प्रथा ने समाज को जो विराट क्षति दीती रही उसका अन्त नहीं हुआ । दोते हुए देशी वशों में जमीन की कीमत सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारकों से बहुत बढ़ चुकी है, और इससे जमींदार ही फायदा उठ रहा है ।

वास्तव में, सामाजिक कारणों से जमीन की जो कीमत बढ़ी है वह समाज सेवामें ही लगानी चाहिए। इस विषयपर सलाह देने के लिये बंगाल सरकार ने सन १९३८ में एक कमोशन नियुक्त किया; यह फ्लोटड कमोशन के नाम से प्रसिद्ध है। इस कमोशन का कहना यह है कि वर्तमान व्यवस्था इतनी अधिक त्रुटियों से भरी है कि इसको आमूल परिवर्तन करने के अतिरिक्त इसको सुधारने का अन्य कोई उपाय नहीं है। आगे चलकर कमोशन ने बताया कि सन १७९३ में जमींदारी प्रथाके समर्थन में काही युक्तियां थीं परन्तु इन देढ़सौ वर्षों में स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। वास्तव में अन्यत्रवासी जमींदार कृषि की उन्नतिपर कुछ भी ध्यान नहीं देते; सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अव्यवस्था तथा पारस्परिक झगड़ों के कारण बड़े-बड़े जमींदारों की रियासतें कोर्ट आफ वार्डस् के अधिकार में चली जाती हैं। सुव्यवस्थित रूपसे जमींदार अपनी जमींदारी का प्रबन्ध नहीं कर पाते। उनका स्वार्थ तो काश्तकारों से रुपया बसूल करने का होता है। जमींदारों तथा उनके काश्तकारों में सीधा सम्बन्ध भी नहीं रहता; एक दल मध्यस्थ व्यक्ति कृषिका शोषण करने में लगा है। इनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है और किसानों की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। जमीन की कीमत बढ़ने का फायदा भी जमींदारगण उठाते हैं; इससे भी सरकार को कई करोड़ रुपये का नुकसान पड़ता है। रैयतवारी इलाके में स्थिति अच्छी घटाई गई है क्योंकि यहां सरकार के साथ किसानों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने के कारण सरकार को भी नुकसान नहीं पहुँचता है और न किसानों का ही उतना शोषण होता है। इन सब कारणों से कमोशन के संख्याधिक सदस्यों ने जमींदारी प्रथा को उठा देने की सलाह दी है। परन्तु इस कमोशन के दूसरे कई सदस्य संख्याधिक सदस्यों के साथ सहमत नहीं हो सके। उनका कहना यह है कि बंगाल के किसानों की दुर्दशा के लिये सिर्फ जमींदारी प्रथा ही दायी नहीं है। इस दुर्दशा का कारण तो जनसंख्या की

वृद्धि, हमारे उत्तराधिकार कानून, ग्रह-उद्योग की कमी, कृषि में सुधार का अभाव, प्रवृत्ति है। इसलिए जब तक इन विषयों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक सिर्फ जमींदारी प्रणाली को उठाने से ही समस्या का हल नहीं होगा। आगे चलकर इन्होंने बताया है कि जमींदारी प्रथासे कृषि की उन्नति सम्भव नहीं हुई है; जमींदार की जगहपर यदि राष्ट्र का अधिकार हो जाय तो भी कृषि की उन्नति तब तक नहीं होगी जब तककी राष्ट्र इस विषयपर गम्भीरतापूर्वक ध्यान न दे। सन १९३८ की कानून से किसान ही जमीन का वास्तविक मालिक है, जमींदार नहीं। इसपर भी यदि कृषि की उन्नति न हो तो उसके लिए जमींदार किस प्रकार से दायो हो सकता है? लगान वसूल करने में भी जमींदार को विशेष अनुविधाओं का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक की कई सालों का लगान बाकी भी पड़ा रहता है। इन सब कारणों से अनेक जमींदार चाहते हैं कि उन्हें उपयुक्त क्षतिपूर्ति मिल जाय तो जमींदारी को उठा देना ही उनके लिए बेहतर होगा।

चाहे जो हो पर जमींदारी प्रणाली की समाप्ति तो एक सर्वमान्य बात हो गई है। श्री मनोमल नातावती लिखते हैं, "जमींदारी को समाप्त करना ही स्वतः सुधार की उद्देश्य पूर्ति नहीं है बल्कि यह कृषि उत्पाति बढ़ाने में तथा भूमि वितरण को अधिक न्यायपूर्ण बनाने का एक अनिवार्य साधन है।" परन्तु इसकी समाप्ति के रास्ते में कई अनुविधाएँ हैं। जमींदारी प्रथा उठ जानेपर लगान वसूली से लेकर दूर तक प्रबन्ध सरकार को करना पड़ेगा; जमीन की उन्नति का पूरा उत्तराधिकार भी उन्हीं पर रहेगा। इसकी समाप्ति में सबसे बड़ी समस्या तो क्षतिपूर्ति की है। समाजवादियों का यह मत है कि जमींदारों को बिना क्षतिपूर्ति दिए ही उनके अधिकार लेने चाहिये। जिन जमींदारों ने जमीन की उन्नति के लिये कुछ प्रबन्ध किया है सिर्फ उन्हीं को क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिये। कोई-छोई ऐसी मजदूर

भी देते हैं कि जमींदारी को जमींदारों के हाथ से छीनकर कोर्ट आव बर्ड-
 शके हाथमें दे देनी चाहिये और इसके लिये जमींदारों को १५ वर्ष तक कुछ
 भत्ता मिलनी चाहिये । प्लाउड कमिशन के सदस्यगण क्षतिपूर्ति के बारेमें
 सहमत न हो सके परन्तु १९३५ के भारत शासन विधान की २६६ धाराके
 अनुसार जमींदारों को क्षतिपूर्ति देनी ही होगी । इस कमिशन के मतानुसार
 वास्तविक लाभका १५ गुना रूपया देने से बंगाल के जमींदारों की आधुनिक
 आय लगभग आधी रह जायगी । कुछ दिनों से बिहार, मद्रास तथा पश्चिमी
 बंगाल में जमींदारी प्रथा को उठा देने की बात चल रही है । प्रांतीय सरकारों
 का विचार ऐसा था कि दीर्घ मियादी बाँड या ऋण-पत्र जारी करके क्षतिपूर्ति
 कर देंगे । परन्तु कानून के अनुसार प्रांतीय सरकार ऐसा नहीं कर सकती ।
 यदि जमींदारी को उठाना है तो क्षतिपूर्ति के लिए नकद रूपया देना पड़ेगा
 जो कि किसी भी प्रांतीय सरकार के लिए सम्भव नहीं है । भारत सरकार
 वर्तमान आर्थिक स्थितिमें प्रांतीय सरकारों को आर्थिक सहायता नहीं दे
 सकती । इधर जमींदारी प्रणाली उठाई जा रही है, इस अफवाह के फैलने
 के कारण जमींदारों के लिए भी लगान वसूल करना कठिन हो गया है ।
 किसी-किसी प्रांत में अनाज की उपज बढ़ाने के लिए खेती के कामोंपर
 सरकारी नियन्त्रण लगाने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं ; अगर ऐसा हो
 गया तो जमींदारों की मर्यादा की और भी हानि पहुँचेगी और उनके लिए
 लगान वसूल करना और भी मुश्किल हो जायेगा । इससे तो यह बेहतर
 होगा कि जबतक वास्तव में जमींदारी प्रथा को उठा देना सम्भव नहीं हो
 तब तक उन्हें जमीन की उन्नति के लिए उत्साहित करना चाहिए ताकि
 अनाज की उपज बढ़ाने में वे भी पूरी तौर से मदद पहुँचा सकें ।

जमींदारी-प्रणाली की समाप्ति होने पर यह प्रश्न हमारे सामने आयेगा
 कि जमींदारी के पश्चात् कौनसी भूमि प्रणाली स्थापित की जाय जिससे
 कृषि-धन्यों को उन्नति हो एवं किसानों की आर्थिक दशा भी सुधरे । इस

सुधार के लिए तीन प्रणालियाँ हमारे सामने हैं—(१) सामूहिक खेती-प्रणाली, (२) सहकारी खेती-प्रणाली और (३) वैयक्तिक-स्वामित्व खेती-प्रणाली । सामूहिक खेती-प्रणाली हमें अवश्य सफल हुई है परन्तु इसका निर्माण हमारे देश की परिस्थिति के अनुकूल नहीं होगा । हमारे देश में वैयक्तिक-स्वामित्व-अधिकार व्यक्तियों में इतना दृढ़ है कि वास्तविक सामूहिक खेती-प्रणाली के पद में कदापि नहीं हो सकते । परन्तु हमारे देश की कसूर भूमि अभी किसी व्यक्ति के अधिकार में नहीं है ; इन जमीनों को यदि सामूहिक खेती-प्रणाली के रूप में परिणत कर दी जाय तो इसमें किसी को भी आपत्ति करने का अवसर नहीं होगा । किसी-किसी देश में सहकारी खेती को भी कुछ सफलता मिली है परन्तु हमारे देश में सहकारिता में अभी तक पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है । इसलिए जाँचके रूप में यह प्रणाली स्थापित कर दी जा सकती है, व्यापक रूपसे नहीं । इस प्रकार से यदि इसमें सफलता हो तो इसकी विस्तृत स्थापना पर विचार हो सकता है । इस स्थिति में हमारे विचार में जमींदारी के स्थान पर वैयक्तिक-भूमि प्रणाली की स्थापना होनी चाहिए । इससे किसानों में कृषि-उन्नति-कार्य में उत्साह बढ़ेगा और कृषि पदार्थों की उपज में पर्याप्त वृद्धि होगी । वैयक्तिक-भूमि-प्रणाली हमारे देश की प्रथा के तथा मानव प्रकृतिके अनुकूल भी होगी और इससे कोई ऐसी बात भी नहीं होगी जिसको चालू करने में किसी बात का जोखिम समझा जायगा ।

प्रश्न यह है—कृषि-भू-स्वामित्व-प्रणाली का कैसे विकास किया जाय और कैसे इसे सुदृढ़ नींव पर खड़ा किया जाय ? इस विषय में श्री सुनीलाल नानावती ने निम्नप्रकार सलाह दी है :—
(१) सारी भूमि पर सरकार का स्वामित्व घोषित करना, भूमि में मध्यम-द्विती का उन्मूलन, भूमि केवल वास्तविकों कीतनेवालों को मौखिकी हक पर देना, परन्तु उसे भी भूमि बेचने या विभाजित कर देने का अधिकार

न देना । (२) प्रत्येक खेत एक आर्थिक इकाई तथा जहाँ तक हो सके, एक चकमें हो । (३) कृषक को जहाँ तक हो खेतपर या उसके निकट रखना । (४) भूमिको अनुत्पादक ऋणके लिए प्रतिभृति रूप देने पर प्रतिबन्ध लगाना । (५) भूमि वही जोते जिसका उसपर स्वामित्व है अथवा मौलसी हक है । (६) घटाई प्रथा का अन्त करके उसके स्थानपर नकद लगान की, जो सरकारी लगान के कुछ अंशके अनुपात में होगा, खेती संगठित करना तथा लगान को मूल्यस्तर से सम्बन्धित करना । (७) भूमिपर क्रमशः वर्धमान लगान लगाना, अलाभकारी खेतों पर कम अथवा बिलकुल लगान न लगाना, एवं अधिक आयवाले मनुष्यों से कृषि-आय-कर द्वारा राजस्व में वृद्धि करना । (८) उपज के आधार पर भूमि के मूल्य का सट्टा बन्द करना ।

भारत में औद्योगिक विकास

पृथ्वी के शिल्प प्रधान देशोंमें भारत का स्थान आठवां है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत में वास्तविक औद्योगिक विकास हो सका है जिससे वह पाश्चात्य के शिल्प प्रधान देशों का मुकाबला कर सके । हमारे यहाँ सिर्फ उपभोग सामग्रियां पैदा करनेवाले कुछ कारखाने प्रतिष्ठित हुए हैं लेकिन औजार, रसायनिक सामग्रियां (प्रभृति) अभी भी हमें दूसरे देशों से मंगानी पड़ती है । हमारे अधिकांश कारखाने बहुत ही छोटे पैमानेपर हैं या गृह-उद्योग के तौर पर हैं । उद्योगधन्योंमें हमारी जन-

संख्या का प्रतिशत १० व्यक्ति काम करते हैं जिनमें दो कारखानों में प्रतिशत १॥ व्यक्ति ही नियुक्त हैं ।

भारतमें ब्रिटिश-शासन कायम होनेके पहले बहुतसे कारखाने थे । परन्तु उस वक्तके कारखानोंके साथ आधुनिक कारखानोंकी तुलना नहीं की जा सकती । जिस समय पृथ्वीके सारे देश कृषि प्रधान थे उस समय भारतके कारखानोंमें अनेक प्रकारकी सामग्रियां तैयार होती थीं तथा मरकर भेजी जाती थीं । ईस्ट इन्डिया कम्पनीने हमारी सामग्रियां यूरोपमें भेजकर फायदा उठानेका प्रयत्न किया एवं हमारे उद्योग-धन्धोंकी उत्साहित भी किया । जबसे इंग्लैण्डमें औद्योगिक क्रान्ति शुरू हुई तबसे ब्रिटिश नीति बदल गई । साथ-ही-साथ ईस्ट इन्डिया कम्पनीकी वाणिज्य नीति भी बदल गई और वह हमारे उद्योग-धन्धोंको दबानेमें लग गई । उस समय हमारे देश की राजनीतिक स्थिति बहुत ही नाशुद्ध थी ; इसलिए राष्ट्रीय सरकार उद्योग-धन्धोंकी मदद पहुंचानेके लिए या पादनाल येनोंकी औद्योगिक क्रान्तिसे फायदा उठानेके लिए आगे न बढ़ सकी । भारतकी अनाज तथा कच्चा माल पैदा करनेवाला देश बनाना ही कम्पनीका लक्ष्य हुआ । उसीसवीं शताब्दीके उत्तमार्धमें ब्रिटिश सरकारने आधिक विषयोंमें हस्तक्षेप करनेकी नीतिको छोड़ दिया । भारतपर इसका गहरा असर हुआ और भारत सरकारकी भी इसी नीतिका अनुगमन करना पड़ा । इस नीतिसँ इंग्लैण्डमें उद्योग-धन्धोंका काफी विकास हुआ परन्तु भारतकी समस्याका समाधान नहीं हुआ । उसीसवीं शताब्दीके अंतमें मद्रास सरकारने उद्योग-धन्धोंके प्रति कुछ सहाय-भूति दिखाई एवं दो एक कारखाने भी खुलवाई । विदेशी कलदर्शके प्रारम्भमें लार्ड कार्लटने भी उद्योग-धन्धोंकी उत्साहित करनेकी नीतिको प्रारंभ किया एवं सन् १९०५ में एक शिल्प तथा व्यापारिक दफ्तर भारत सरकारके अधीनमें खोला गया । सन् १९०६ में मद्रासमें एक प्रांतीय शिल्प दफ्तर स्थापित हुआ लेकिन भारत मेंजो भारत सरकारके तथा मद्रासके प्रांतीय

सरकारको इस नीतिका अनुमोदन नहीं किया बल्कि विरोधपूर्ण समालोचना किया। इस पर भारत सरकार तथा प्रान्तीय सरकारको उद्योग-धन्धोंसे हाथ समेट लेना पड़ा एवं मद्रासमें सरकारको उद्योगसे जो एलुमिनियमकी फैक्टरी स्थापित हुई थी वह भी उठानी पड़ी। इस प्रकारसे जब पहली लड़ाई शुरू हुई तब हमारे देशमें केवल कुछ पाटके तथा कपड़ेके कारखाने थे एवं १९०७ सालमें टाटाका कारखाना स्थापित हुआ था।

पहली लड़ाई शुरू होनेके बाद उद्योग-धन्धोंमें कुछ उन्नति हुई। बम्बईमें कपड़ेके विभिन्न कारखाने, कागज बनानेके कारखाने, फल्यक्स एवं तेल निकालनेवाले कारखानोंमें कुछ वृद्धि हुई। बंगालके पाटके कारखानों एवं कोयलेकी खानों पर, एवं मद्रासके चमड़ा, सायुन प्रभृतिके कारखानों पर भी लड़ाईका असर पड़ा। संयुक्त प्रान्त तथा पंजाबके गृह-उद्योग भी युद्धकालीन मांगसे प्रभावित हुए। परन्तु लड़ाई के सुयोगसे भारत को जितनी सुविधाएँ मिल सकती थीं उतनी न मिलीं, कारण शिल्पके कई एक साधनोंकी कमी हमारे देशमें थी। औजार तथा रासायनिक सामग्रियां, शक्ति पैदा करनेके साधन तथा निपूण कारिगरोंके अभावसे हम लड़ाईसे पूरा फायदा नहीं उठा सके। औद्योगिक विकाशके बारेमें सरकारने भी कोई सुस्पष्ट नीति ग्रहण नहीं की। इस कारणसे नए उद्योग-धन्धोंका भविष्य अनिश्चित रहा। सरकारने सोचा था कि लड़ाई जल्द ही खत्म हो जायेगी लेकिन वास्तवमें यह अधिक समय तक चलती रही। इसलिए पहले पहल भारतमें उद्योग-धन्धोंको कायम करनेकी बात सरकारको सूझी और भारतको शिल्प सम्भावनाकी जांच करनेके लिए एक औद्योगिक समिति कायम हुई। इस समितिके निष्कर्ष निम्न प्रकारके थे :—(१) केन्द्रवर्ती तथा प्रांतीय सरकारोंके अधीनमें एक-एक शिल्पदफ्तर स्थापित करना चाहिए और जो सामग्रियां भारतमें बनती हैं सरकारको अपने व्यवहारके लिए उन्हें विशेषसे नहीं मंगानी चाहिए। (२) भारतमें औद्योगिक शिक्षाका पूरा प्रबन्ध होना

चाहिए। (३) भारतकी आर्थिक सम्भावनाको कामना करके देशकी आर्थिक दृष्टिसे स्वतंत्र बनाना चाहिए ताकि विदेशसे जहां तक हो सके कम सामग्रियां मंगानी पड़े। इसके लिये उद्योग-धन्योंमें सरकारकी आर्थिक मदद पहुँचानी चाहिए तथा दूसरी सुयोग सुविधाएँ भी देनी चाहिए। सन् १९१९ के अप्रैलसे लगा कर १९२० के मार्च महीने तक भारतमें विभिन्न प्रकारकी बहुत-सी कम्पनियाँ स्थापित हुईं। पहली लड़ाईके वक्त औद्योगिक उन्नतिके बारेमें भारत सरकारमें जो जोत पैदा हुआ था वह स्थायी नहीं हुआ। एक ओर तो यूरोपमें स्वाभाविक परिस्थिति पुनः कायम हो जानेसे यूरोपके देशोंमें बनी हुई सामग्रियां हमारे देशमें हमारी सामग्रियोंके साथ प्रतिस्पर्धा करने लगी एवं दूसरी ओर औद्योगिक विकासके बारेमें भारतकी विदेशी ह्युमत उदासीन बन गई। सुदा-विनिमय-दरकी घटबढ़से भी हमारी आर्थिक स्थिति प्रभावित होने लगी। इन सब कारणोंसे जो सब उद्योग-धन्य प्रतिष्ठित हो चुके थे उन्हें संरक्षित करनेकी आवश्यकता हुई। इस विषयपर सलाह देनेके लिए भारत सरकार ने एक शुल्क समिति कायम किया और इसके सिद्धांतके अनुसार एक संरक्षण नीति प्रदण किया जिसका उद्देश्य चुने-चुने उद्योग-धन्योंको सुरक्षित करना था। किसी उद्योग-धन्यको संरक्षित किया जायेगा या नहीं इसके बारेमें टैरीफ बोर्ड या शुल्क-संस्था सरकारको सलाह देनी एवं इसके बाद आगरी सिद्धांत सरकार प्रदण करेगी। जब किसी उद्योगके लिये शुल्क-संस्था संरक्षणका अनुमोदन करेगी तब सबसे पहले शुल्क-संस्थाको यह चेनना होगा कि उसके व्यवहारमें आनेवाला कच्चा माल, कारीगर प्रभृति इस देशमें पत्ता हैं या नहीं एवं उत्पादन-वस्तुकी मारत इस देशमें हो सकती है या नहीं। इस संस्थाको साथ ही साथ यह भी सोचना होगा कि जिस वस्तुको संरक्षित करनेकी सलाह यह दे रही है वह वस्तु दिनोंमें विदेशमें बनी हुई सामग्रियोंके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेगा या नहीं। सरकारकी इस नीतिमें ऐसी बहुतसी

कमजोरियां थीं जिनके आधार पर सरकारने बहुतसे जल्द्री, उद्योग-धन्धोंको एक न एक बहाना लगाकर संरक्षित करना नामंजूर किया । जो उद्योग धन्धे पहले ही प्रतिष्ठित हो चुके थे सिर्फ उन्हें कुछ मदद मिली एवं संरक्षणनीतिके सुयोगसे चीनीके कुछ कारखाने संस्थापित हुए ।

जब दूसरी लड़ाई शुरू हुई तब फिरसे औद्योगिक स्थिति पर सरकारकी नज़र पड़ी । पहली लड़ाईके बीस साल बाद दूसरी लड़ाई शुरू हुई लेकिन अतीतकी ओर हम जब देखते हैं तो औद्योगिक विकासके बारेमें कोई विशेषता हमारी नज़र में नहीं आती । उपभोगसामग्री पैदा करने वाले कई उद्योग धन्धे हमारे देशमें प्रतिष्ठित हो चुके हैं लेकिन मौलिक शिल्प हमारे देशमें एक भी नहीं है । जब पूर्वी देशमें लड़ाई शुरू होकर परके नज़दीक आ पहुँची एवं बाहरसे मौलिक सामग्रियों की आयात बिलकुल बन्द हो गई तब हमारी कमजोरी और भी स्पष्ट हुई । नया उद्योग प्रतिष्ठित होना तो दूर रहा पुराने उद्योग-धन्धों का भी जीर्णोद्धार होना मुश्किल हो गया । सबसे दुःखकी बात तो यह है कि जब लड़ाईके सुयोगसे ऑस्ट्रेलिया, कैनडा प्रभृति देशोंमें आर्थिक विकास द्रुतगतिसे होने लगा तब भी भागतकी अवस्थामें कोई परिवर्तन नहीं हुआ । पूर्वी प्रदेशमें जो लड़ाई चल रही थी उसमें मदद पहुँचानेके लिए भारत ही केन्द्रवर्ती देश था एवं इसी वजहसे पूर्वी देशोंका एक आम जलषा भी यहाँ हुआ था । इसवक्त अमेरिका और इंगलैन्ड इन दोनों देशोंसे शिल्पविशेषज्ञोंका आगमन भारतमें हुआ था । इन्होंने भी भारतमें मौलिक शिल्प प्रतिष्ठित करनेकी सलाह दी परन्तु विदेशी हुकूमत पर इन सब बातोंका कुछ भी असर नहीं हुआ । सरकारकी युद्धोत्तर औद्योगिक नीति क्या होगी इस पर अनेक शिल्पपतिथोंने प्रश्न उठाया तब सरकारने यह सूचित किया कि जो शिल्प लड़ाई के वक्त लड़ाईमें मदद पहुँचानेके लिए संस्थापित होने जरूरत पड़ने पर लड़ाई के अंतमें उन्हें संरक्षित किया जावेगा । इस पर लड़ाई में मदद पहुँचाने वाले कई एक छोटे छोटे उद्योगधन्धे इस देशमें शुरू हुए ।

हमारे पुण्ड्रे टचोगवन्धों पर लड़ाईका वासर जरूर पड़ा और इनका उत्सादन भी जहाँतक हो सचा बढ़ाया गया । सूती, रेशमी तथा ऊनी-कपड़े, ताँतके कपड़े तथा चट्टीकी पैदावार जहाँतक हुई बढ़ाई गई एवं लड़ाईके लिए जरूरी नए टंगके कुछ कपड़े भी यहाँ बनने लगे । इस वक यूरोपसे कारेछी निर्यात बन्द होनेके कारण आस्ट्रेलिया, न्यूजिलैन्ड, दक्षिणी अफ्रिका एवं और भी कई देशोंमें हमारे कपड़ेका निर्यात शुरू हुआ । भारतमें बने हुए सारे ऊनी कपड़ों को सरकारने खरीद लिया । जोहा तथा इलाहाबादकी तैयारी नौ बहुत ज्यादा बढ़ाई गई, नए टंगके इलाहाबाद, मालगाछी तथा मुल्के लिए धानइक धान्य कई सामग्रियाँ भारतमें बनने लगीं एवं कई एक सहायक टचोगोंकी प्रतिष्ठा हुई । विभिन्न प्रकारकी काँच की सामग्रियाँ, दवाइयाँ, कागज, छंटे छोटे इधिकार, साधारण बीजार, बिजलीका सरंजाम प्रभृतिकी भी पैदावार शुरू हुई । रसायनिक शिलानें कई एक कारखाने प्रतिष्ठित हुए जेकिन से हमारी सरकारके अनुसार रसायनिक सामग्रियाँ तैयार नही कर सकते । इसवक बिजगाष्ट्रममें जहाज बनानेका तथा मरम्मत करनेका कारखाना एवं बंगालोर में हिन्दुस्थान विमान-कन्पनी खोली गई ।

लड़ाईके वक हमारे पुराने कारखानोंमें मालकी तैयारी जरूर पड़ी जेकिन नए कारखाने होने गिने ही संस्थापित हो पाये । जीर्णोद्धारके अभावसे हमारे सारे पुराने कारखानोंकी अवस्था खराब होने लगी एवं सारे पुर्जे कमजोर होने के कारण उत्पादनमें कमी होने लगी । युद्धोत्तर समयमें उत्पादन घट जानेके धान्य कई कारण भी आ टपस्थित हुए । इस सम्बन्धमें कच्चे मालकी कमी एवं वक्तव्यात साधनोंकी समुविधाएँ उदेचनीय हैं । रक्त सदनका नया बननेके कारण अमिकों में असंतोह फैल गया जिमसे टहनलोंकी संख्या बहुत बढ़ गई एवं इससे भी उत्पादनमें हानि पहुँची । देखाता गया मासतमी अतीतक कुदियेमें भरा हुआ है । टचोगवन्धोंके बारेमें सरकारी नीति बहुत दिनों तक असमष्ट रही एवं पैदाशिकारी व्यक्तियोंके समाजवादी भावनोंसे पूर्वोक्तकी

का मन भी खट्टा पड़ गया। इसका असर इतना गहरा हुआ कि राज सरकारकी औद्योगिक नीति सुस्पष्ट होने पर भी पूंजोपतियों को भरोसा नहीं होता। १९४७ के दिसम्बर महीनेमें भारतसरकारने एक औद्योगिक सभा की जिसके सिद्धांतके अनुसार श्रमिक तथा मालिकों में त्रैवापिक शिल्पशान्ति का समन्वितता हुआ था एवं उत्पादन बढ़ानेके लिए सरकारने एक “शीघ्र-योजना” एवं एक “भविष्य योजना” ग्रहण किया लेकिन इनसे भी आशानुसृत फल नहीं निकला।

देशके स्वतंत्र होनेके बाद पहले सालमें औद्योगिक विस्तारके लिए भारत सरकारने जो कुछ किया उसके बारेमें दो तक बातें कह कर इस निबन्ध को समाप्त किया जायेगा। सन १९४८ के मार्च महीनेमें भारतमें बनी हुई ८ हजार टनकी जहाज जल ऊषा पहले पहल सिन्धियाके कारखानेसे समुद्रमें उतारी गई। भारतमें कमसे कम बीसलाख टन वजनकी जहाजें होनी चाहिए इस कमीको पूरा करनेके लिए वार्षिक ५० हजार टनकी जहाजें बनानी भारत सरकारका उद्देश्य है। बंगालोरके कारखानेमें अभीतक मरम्मत तथा पूजा जोड़नेकाही काम होता है। भारत सरकारने अमेरिकाकी एक कम्पनीके साथ बन्दोवस्त किया है ताकि आगामी दो वर्षोंमें कमसे कम ३० हजार जहाजें भारतमें बन सकें। टूटी-फूटी मोटर गाड़ियोंको मरम्मत करनेके लिए भारतमें सात कारखानें काम कर रहे हैं। कलकत्ता तथा बम्बईमें मोटर गाड़ी तैयार करनेके लिए दो कारखानें स्थापित किए गए हैं एवं उम्मीद है कि आगामी ६ वर्षोंमें भारतमें मोटर गाड़ियां बनने लग जायेंगी। टाटाके कारखानेमें रोलर बनाना शुरू होगया है। भारतमें वार्षिक ६२ हजार साइकल गाड़ियां, १५,०० सिलाईकी मशीनें, १२ लाख लालटेन बत्तियां, बिजलीकी मोटरें प्रभृति बनने लगी हैं। इस्पातका एक नया कारखाना तथा कोयलेकी खानों से खनिज तेल निकालनेके लिए मशीनोंके कई कारखाने खुलने वाले हैं। सिन्धुमें खाद बनाने वाला एक कारखाना स्थापित हुआ है और उम्मीद

है कि आगामी दो वर्षोंमें यह कारखाना वार्षिक ३॥ लाख टन ऐमोनियम सल्फेट तैयार कर सकेगा। इस प्रकारसे औद्योगिक विकासका कुछ कुछ काम चल रहा है परन्तु जब तक भारत सरकार एक निश्चित वार्षिक योजनाके आधार पर आगे बढ़नेका प्रयत्न नहीं करेगी तब तक हमारी दिशातः वार्षिक सम्भावना पूरी तौरसे कामयाब नहीं हो सकेगी।

भारतीय उद्योग-धन्योंमें रकमकी पूर्ति—औद्योगिक पूँजी विनियोग संस्था—विदेशी पूँजीकी महत्ता

हमारे उद्योग-धन्योंमें वर्तमान समयमें निम्न स्थानोंसे रकमकी पूर्ति होती है:—(१) मेनेजिंग एजेंट या प्रबन्ध अधिकर्ता, (२) बैंक, (३) अनामत, (४) शेयर, (५) कर्मचारी। बैंकोंसे आवेगमिलायी तथा मजबूतमिलायी रकम पायी जा सकती है, दीर्घमिलायी नहीं। अतीतमें औद्योगिक बैंक प्रतिष्ठित करने की चेष्टा बिकल हुई। अनेक शिक्कासिद्धियोंकी बैंकमें कर्म लेना पसन्द भी नहीं करी। इससे एक ओर तो कर्मचारी या छोड़े जानेवाले बैंकके पास पसन्द रखना पड़ता है एवं दूसरी ओर इनपर बैंकका कुछ दबाव भी रहता है। औद्योगिक अमानतें यानी पब्लिक डिपोजिट किन्तु अल्पमात्र एवं कुछ हदतक

बम्बईमें प्रचलित है। आधुनिक समयमें स्थापित किये गये उद्योग-धन्धोंमें शेरारी रकम तथा ऋणपत्रोंकी अधिकता है।

भारतीय उद्योग-धन्धोंमें प्रबन्ध अभिकर्त्ताओंका स्थान—जिनसब उद्योग-धन्धोंमें शेरारी मूलधन अधिक है वहाँ भी प्रबन्ध अभिकर्त्ताका प्रभाव ज्यादा रहता है। जिसवक्त भारतमें आधुनिक उद्योग धन्धोंकी शुरुवात हुई उसवक्त भारतमें राजनैतिक विश्रुत्या चल रही थी; उस वक्त बंगालमें अंग्रेज प्रबन्ध अभिकर्त्ताओंकी रकमसे पाटके कारखाने तथा बम्बईप्रांतमें भारतीय प्रबन्ध अभिकर्त्ताओंकी रकमसे कपड़ेके कई कारखाने स्थापित हुए थे। प्रबन्ध अभिकर्त्ताओंने उद्योग-धन्धोंकी स्थापित ही नहीं किया बल्कि प्रारम्भकालमें सारी रकम लगाई तथा इनकी सारी जोखम सारा प्रबन्ध अपने पर लेलिया। दूसरे जो लोग इन धन्धोंकी शेयरोंको खरीदते थे वे भी इन्हीं की महाजनी पर। बैंकोंसे उद्योग-धन्धोंकी जो अल्प तथा मध्यम निग्रादी रकम मिलती है वह भी प्रबन्ध अभिकर्त्ताओंके जिम्मेपर। पाश्चात्य देशोंमें कम्पनीके मूल संस्थापक कम्पनी चालू होने पर उससे सम्बन्ध नहीं रखते हैं लेकिन हमारे देशकी करीब सारी कम्पनियां प्रत्येक विषयमें प्रबन्ध अभिकर्त्ताओंके बलपर ही अवलम्बित होती हैं। इनका संस्थापन, इनके लिए रकम संग्रह, इनका प्रबन्ध, मंदीके समय इनका संरक्षण आदि सारे काम इन्हींको करना पड़ता है। इसलिए दोषगुणोंसे भरे हुए प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं पर हमारे उद्योग-धन्धोंकी अभितक निर्भर करना पड़ता है।

प्रबन्ध अभिकर्त्ताओंके द्वारा उद्योग-धन्धे स्थापित किये जानेमें कुछ त्रुटियां दिखाई पड़ने लगीं। इनका कारवार ज्यादातर पारिवारिक होनेके कारण अनेक क्षेत्रोंमें कमजोरियां दिखाई पड़ने लगीं। अधिकसे अधिक शेयर इन्हींके हाथोंमें रहनेके कारण प्रबन्धका पूरा दायित्व इन्हीं पर आ पड़ता है। बाहरी जो

लोग शेर खरीदते हैं वे ज्यादातर प्रबन्ध अभिकर्ताओं के घरों का परिचित व्यक्ति होते हैं। कई क्षेत्रों में प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने ऐसे धन्य शुक्र दिने जो अन्त में लाभदायक नहीं हुए। इसके अलावा एक कम्पनी की रकम दूसरे में लगा देना तो बहुत ही मामूली बात है। इन त्रुटियों को हटाने के लिए सन १९३६ में कम्पनी कानून में मौलिक परिवर्तन किया गया जिससे कोई भी बैंक प्रबन्ध अभिकर्ताओं के साथ सम्बन्धित नहीं रह सकती। दूसरी कम्पनियों में भी इनका प्रबन्ध २० साल से अधिक काल तक जारी नहीं रहेगा परन्तु इनको फिर से शेरधारोण प्रबन्ध अभिकर्ता के स्थान पर नियुक्त कर सकते। प्रबन्ध अभिकर्ताओं की दस्तूरी, उनके दफ्तर का सचिवा, एक कम्पनी की रकम दूसरी कम्पनी में लगाने का अधिकार आदि पर इस कानून के द्वारा नियंत्रण लगाया गया है।

वर्तमान व्यवस्था में कितनी भी त्रुटियाँ क्यों न रहे अभी हमारी स्थिति जैसी है उसमें उद्योग-धन्यों को आगे बढ़ाने का काम इन सब पूर्वापत्तियों के सहयोग पर ही अवलम्बित रहेगा कारण हमारे देश में न तो कम्पनी संस्थापक ही हैं और न रकम लगानेवालों की संख्या ही अधिक है। इसीलिए किसी भी उद्योग-धन्यों को क्यों न देना जाय, वहाँ ही आदि से अन्त तक प्रबन्ध अभिकर्ताओं का प्रभाव दिखाई पड़ेगा।

औद्योगिक अर्थ-विनियोग संस्था—कुछ दिन पहले सरकारने उद्योग-धन्यों में सहाय तथा दीर्घ मुदती वार्षिक मदद पहुंचाने के लिए इस संस्था को स्थापित किया है। उम्मीद किया जाता है कि अर्थ-प्रबन्ध के बारे में यह संस्था उद्योग-धन्यों को वास्तविक मदद पहुंचाने में सफल सिद्ध होगी एवं इससे भारतीय उद्योग-धन्यों का द्रुत विचारा तथा जीर्णोद्धार सम्भव होगा। इस संस्था के बारे में मुख्य बातें निम्न प्रकार की हैं—(१) इस संस्था का क्षेत्र विभिन्न प्रांतों में

जानकारों का कहना है कि देशमें लगभग हजार करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी कामोंमें तथा और एक हजार करोड़ की विदेशी पूंजी व्यापार तथा उद्योगधन्यों में लगी हुई है।

विदेशी पूंजी से असुविधा—इन उद्योगों के द्वारा करोड़ों रुपये प्रति वर्ष औद्योगिक लाभ के रूप में भारत से बाहर जाता है। इनके द्वारा स्वदेशी उद्योगों के विकास में बाधा पड़ी है। सन् १९१२ में अलफ्रेड च्याटरटन ने कहा है कि यदि भारतीय उद्योग-धन्यों को संरक्षित किया जाय तो उससे भारतीयगण लाभ न उठ सकेंगे कारण विदेशी पूंजी तथा संगठन भारत में आता रहेगा। सन् १९१८ में विदेशी पूंजी के विरुद्ध में मालवीयजीने अपना विचार प्रकट किया। सन् १९२५ में फिर विदेशी पूंजी समिति के भारतीय सदस्यों ने सम्मति प्रकट की कि भारतीय उद्योग-धन्यों का विकास विदेशी पूंजी की अपेक्षा भारतीय पूंजी के द्वारा हो किया जाय। सलाहकार योजना बोर्ड ने कुछ दिन पहले विदेशी पूंजी के बारे में लिखा है कि औद्योगीकरण के लिए भारतमें ही पूंजी प्राप्त हो सकेगी— निम्नलिखित औद्योगिक कलाविदों और पूंजीगत मालकी आवश्यकता अवश्य होगी परन्तु उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त विदेशी पूंजी को स्थान नहीं मिलना चाहिए।

विदेशी पूंजी से भारत को क्षति—(१) औद्योगीकरण का अभिकर्षण लाभ विदेशियों को होता है (२) विदेशी पूंजीवाद हमारे राजनैतिक प्रगति में बाधा उपस्थित करता है एवं भविष्य में भी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का घातक बन सकता है, (३) विदेशी पूंजीवति भारतीयों को औद्योगिक कला-कौशल सीखने का सुविधा नहीं देते, (४) विदेशी पूंजी से आर्थिक विकास होने पर राष्ट्रीय आयका ज्यादातर हिस्सा विदेश में जाता रहता है एवं जनता के जीवन-स्तर में वृद्धि करनी कठिन हो जाती है, (५) विदेशी पूंजी के विनियोग से अन्तराष्ट्रीय लेन-देन की सुगमता तो होती है नहीं बल्कि यह हरबल हो देशके प्रतिकूल बनो रहती है।

किया है कि इस सम्मन्धमें उसकी ६ अप्रैल १९४८ की घोषित औद्योगिक नीतिका ही अनुसरण किया जायेगा । यदि किसी उद्योगका राष्ट्रीय स्वाम्य हुआ भी तो उसके मालिकको चाहे वह भारतीय हो, चाहे विदेशी उचित प्रति पूरा मिलेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंकसे ऋण—भारत अपनी आर्थिक योजनाओंको कार्यान्वित बनानेके लिये इस बैंकसे ऋण लिया है । बैंकके सीमित साधनों और अल्प नियम सम्बन्धी बाधनोंके कारण हमें बैंकसे बहुत अधिक आशा नहीं रखनी चाहिये । वह कुछ विशिष्ट योजनाओंके लिये अर्थ दे सकेगा परन्तु राष्ट्रीय पुनर्निर्माणकी सम्पूर्ण योजनाओंके लिये उस पर निर्भर रहना उचित न होगा । कुछ दिन पहले रुपयेका जो मूल्य हास किया गया है उससे आलसको कीमत बढ़ गई है एवं हम जो विदेशी कर्ज लेंगे उसमें प्रतिशत ३० रुपये ज्यादा देना पड़ेगा और इसलिये विदेशी पूँजीके प्रति हमारा आकर्षण कम हो जायेगा । साथ ही साथ हमें इस विषय पर ध्यान रखना पड़ेगा कि रुपयेका विनिमय दर घट जाने के कारण हमारे आगत व्यापारमें जो रुकावट पहुँचेगी उससे बचनेके लिये विदेशी पूँजीपतिगण सरकारकी नवीन नीतिके सुयोगसे भारतमें रहम लगाकर कारखाने स्थापित करेंगे एवं छोटे-छोटे क्षेत्रों में उनकी प्रतियोगितासे हमारे उद्योग-धन्योंकी हानि पहुँचनेकी सम्भावना है; इन विषयों पर सरकारकी सचेतन दृष्टि रहनेकी आवश्यकता है ।

हमारी आर्थिक योजना—उसका लक्ष्य और आधार

वर्तमान समयमें आर्थिक-नीतिगत सम्मन्धमें हमारी आवश्यकताएँ दो होती हैं कि साधारण व्यक्ति भी इन रुढ़ियोंसे परिचित हो । किसी मजदूर के साथ

परिचित होना एक बात है पर उसके बारेमें पूरी जानकारी रखना बिल्कुल दूसरी बात है । इसलिये आर्थिक योजनाके मूल सिद्धान्तों पर प्रकाश डालने की चेष्टा की जाती है । पहली लड़ाईके पढ़े राष्ट्रीय सरकार आर्थिक व्यवस्थामें ज्यादातर हस्तक्षेप नहीं करती थी लेकिन अब आर्थिक उद्देश्य को सफल करनेके लिये आर्थिक व्यवस्थाको एक विशेष रीतिसे अपने प्रयोजनके अनुसार संगठित करने का प्रयत्न कर रही है । पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था बाधाहीन प्रतियोगिता के आधार पर स्थित है एवं इस में सिर्फ वही पूंजीपति सफल हो सकते हैं जिनके पास आर्थिक साधनों का बाहुल्य है । पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन धर्म की दृष्टि से सिर्फ बेचने ही के लिये सामग्रियां बनाई जाती हैं और बेचने का उद्देश्य सिर्फ मुनाफा करना ही होता है, जनता के जीवन का स्तर ऊंचा उठाना नहीं । इस विषय में जड़ मूल से परिवर्तन करना आर्थिक योजना का लक्ष्य है । आर्थिक योजना कायम करने के बाद भी सामग्रियां पैदा होंगी लेकिन सिर्फ मुनाफा करना इस पैदावार का लक्ष्य नहीं होगा । इसमें सिर्फ ऐसी सामग्रियां बनायी जायेंगी जो वास्तवमें जनकल्याण के लिये सहायक हो सकें । इसके अलावा बहुत सी चीजें जल्द खतम हो जानेवाली हैं, जैसे कि खनिज सम्पत्ति । इससे अगर पूरा फायदा उठाना हो तो इनकी खर्बादी रोकनी होगी और आर्थिक योजना के अनुसार इनकी इस तरह से काम में लगाना होगा जिससे ये ज्यादा दिन तक चल सकें । यही आर्थिक योजनाका लक्ष्य है । इस में सामग्रियों के उपभोग से लगाकर पैदावार, रकम विनियोग, व्यापारिक प्रवन्ध तथा आयका विभाजन आदि प्रत्येक विषय में राष्ट्रीय सरकार एक विशेष उद्देश्य को सामने रखकर हस्तक्षेप करती है । वर्तमान स्थिति में आर्थिक योजना सिर्फ आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि जनकल्याण की दृष्टि से भी विशेष जरूरी है ।

आज हमें राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त होनेके बाद आर्थिक स्वतन्त्रता पर

ध्यान देना पड़ेगा और इसके लिये एक विशेष आर्थिक योजना प्रस्तुत करनी पड़ेगी। बेकारी की समस्या का समाधान करना तथा पूर्ण विनियोग प्राप्त करना इस योजनाका लक्ष्य होना चाहिये। अब प्रश्न यह है कि हमारी आर्थिक योजना की रूपरेखा क्या होगी? यह प्रश्न हमारे लिये दूसरे देशों की अपेक्षा अधिकतर जटिल तथा महत्वपूर्ण है कारण पूर्ण विनियोग को कायम करने के साथ ही साथ हमें देखना होगा कि हमारी विभिन्न सम्पत्तियों का यथार्थ उपयोग हो रहा है या नहीं और विभिन्न प्रान्तों की आर्थिक उन्नति हो रही है या नहीं। सन् १९४२ से लगाकर आभोतक हमारे सामने कई एक आर्थिक योजनाएँ रखी गईं जिनमें निम्नलिखित योजनाएँ उल्लेखनीय हैं :— (१) बन्वड़े योजना, (२) भारत सरकार की १०००—करोड़ रुपये की कृषि योजना, (३) साम्यवादी योजना, (४) गान्धीवादी योजना, (५) दशवार्षिक सरकार की आर्थिक योजना, (६) भारत सरकारके द्वारा नियुक्त आर्थिक योजना के बारेमें सलाह देनेवाली समितिकी योजना, (७) राष्ट्रीय योजना समिति की योजना, (८) राष्ट्रीय महासभा के द्वारा नियुक्त आर्थिक कार्यक्रम समिति की आर्थिक योजना।

इनमें किसी किसीमें कृषिको महत्व दिया गया है और किसी किसीमें उद्योग-धन्योंको, लेकिन हमारे लिये वही आर्थिक योजना सबसे अधिक उपयोगी होगी जिसमें इन दोनों का समन्वय किया जाएगा। कृषि तथा शिल्प दोनों ही हमारे लिए विशेष आवश्यक हैं। हमारी वर्तमान स्थितिमें हमें जहां तक हो सके आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनी होगी। चिक कृषिको उन्नति हो हमें पूर्ण विनियोग प्राप्त हो सकता है लेकिन उससे देशको आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं हो सकती। इसलिए उद्योग-धन्योंका विस्तार विशेष जरूरी है। हम अपनी बढ़ती जन संख्या को अगर उद्योग-धन्योंकी ओर आकर्षित कर सकें तो हम कृषिमें भी जल्द सुधार कर सकेंगे। सबसे बड़ी दुश्मनी बात तो

यह है कि हमारा देश कृषि प्रधान होते हुए भी हम अनाज की आवश्यकता की पूर्तिके लिए दूसरों के मुखापेक्षी हैं और हमारी कृषिके सामने विभिन्न प्रकारकी समस्याएं उपस्थित हैं। औद्योगिक विकास होने पर जैसे एक ओर बेकारी की समस्या हल हो जायेगी वैसे ही दूसरी ओर कृषिमें भी जल्द उन्नति हो सकेगी। वास्तवमें कृषि तथा शिल्प एक दूसरे पर अवलम्बित हैं।

आर्थिक योजनाके बारेमें राष्ट्रीय योजना समितिने जो तथ्यपूर्ण विवरणसूची हमारे सामने रखी है उनमें हमारी विभिन्न समस्याओं पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है। वे इतने तथ्यपूर्ण हैं कि संक्षेपमें उनकी आलोचना असम्भव है लेकिन साधारण तौर पर हमारे सारे आर्थिक साधनोंका उपयोग करते हुए जनताका रहन-सहन का दर्जा ऊँचा करना, देशको आर्थिक दृष्टिसे स्वतन्त्र बनाना ही उनकी लक्ष्य है। यह समिति जब कायम की गई थी उस वक्त देश आजाद नहीं था; उस वक्त देश के विचारशील विशेषज्ञों को लेकर राष्ट्रीय महासभा ने इस समितिको आर्थिक सुन्ताव देनेके लिए कायम किया था। आज शासन सत्ता राष्ट्रीय महासभा के हाथमें आ चुकी है। अब इस समितिके सिद्धान्तों के अनुसार सरकारी नीतिको कार्यान्वित करनेमें किसी प्रकारकी असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

सन् १९४६ में भारत सरकार ने आर्थिक योजनाके बारेमें सलाह देनेके लिए जो समिति बनाई थी उसके सिद्धान्त पर ध्यान देने लायक कई एक बातें हैं। इस समिति ने पहले ही आर्थिक योजना के लक्ष्य पर ध्यान दिया है। हमारी आर्थिक योजना का लक्ष्य निम्न प्रकार होना चाहिये :— रहन-सहन का दर्जा ऊँचा करना, प्रत्येक व्यक्तिके लिए विनियोगका प्रबन्ध करना, पैदावार जहाँ तक हो सके बढ़ाना, उपयुक्त वितरणका प्रबन्ध करना तथा भारतके विभिन्न प्रान्तोंको आर्थिक उन्नति पर ध्यान देना ताकि कोई भी प्रान्त

नष्ट न जाए। देश रक्षाके लिए भी विभिन्न प्रान्तों में उद्योग-धन्यता स्थापित करना जरूरी है।

आर्थिक योजना से पूरा फायदा उठानेके लिए हमें पहले उन सब विषयों पर ध्यान देना चाहिए जो कि सबसे अधिक आवश्यक हैं। इस दृष्टिसे सबसे पहले हमारी दृष्टि कारिगरो के संख्या बढ़ाने पर पड़नी चाहिए। इस विषय में हमारी कमजोरी सबसे अधिक है और जब तक यह चलती रहेगी तब तक हम आर्थिक योजनाको सफल नहीं कर सकेंगे। साथही साथ हमें अनाज की पैदावार बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। उद्योग-धन्यों में किसको सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा यह कहना कठिन है। इसका कारण यह है कि यह बहुत दूर तक विदेश से मन्त्रोपकरणों के आयात पर निर्भर है लेकिन साधारण तौर पर कहा जा सकता है कि देशकी रक्षाके लिए जरूरी शिल्प, सिंचाई का प्रबन्ध तथा जल-विद्युत उत्पादन करनेवाले मन्त्र शिल्प, लोहा तथा इस्पात का कारखाना तथा रासायनिक शिल्प पर अधिक महत्व देना उचित होगा, उनभोग सामग्रियों पैदा करनेवाले शिल्प पर नहीं। उनभोग सामग्रियों की कमी से देशकी उतनी हानि नहीं पहुँचेगी जितनी कि मौलिक शिल्प के अभाव से पहुँचेगी। खातायात सामग्रियों के लिए इंजिन तथा गाड़ियों की बनाने पर ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी आर्थिक योजना में इन विषयों पर सबसे पहले ध्यान देना जरूरी है। इनके अलावा दूसरे विषयों में किसीको पहले स्थान दिया जायेगा और किसीको पीछे इन बात का निर्णय करने के लिए एक स्थायी संस्था कायम करनी होगी।

कुछ दिन पहले अखिल भारतीय कांग्रेस-समिति द्वारा नियुक्त आर्थिक कार्यक्रम समिति ने अपनी एक सम्बन्धित रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें आर्थिक कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न प्रकार बताया गया है :—अनसक्ति तथा प्राकृतिक साधनों के पूर्ण उपयोग द्वारा उत्पादन में वृद्धि, अक्षय का जयवन्तार जैसा उठाना, एक राष्ट्रीय न्यूनतम जयवन्तार कायम करना, पूर्ण विनियोग

को प्राप्त करना, राष्ट्रीय आय तथा सम्पत्ति का यथार्थ वितरण करना तथा औद्योगीकरण के द्वारा सम्भाव्य विपमताओंको रोकना । राष्ट्रीय आयके वितरण के बारेमें इस समिति का प्रस्ताव यह है कि सबसे कम मजदूरी पानेवाले से सबसे अधिक मजदूरी पानेवाले को ५० गुणा से अधिक नहीं मिलना चाहिए, एवं इस विपमता को भविष्य में २० गुणा से अधिक रहने देना उचित नहीं होगा । हमारी राष्ट्रीय आय कितनी है इसके बारेमें जांच कर लेने का प्रस्ताव भी रक्खा गया है और भविष्य की आर्थिक योजनामें राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक आत्मनिर्भरता तथा शहरी और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्थामें संतुलन करने पर भी महत्व दिया गया है ।

कृषि संगठन के लिए इस समिति ने कुछ प्रस्ताव किया है जो निम्न-प्रकार हैं :—प्रत्येक प्रान्त और क्षेत्रके लिए न्यूनतम मात्रा में अनाज आदि के उत्पादन का प्रबन्ध करना, समस्त मध्यवर्ती लोग जो कृषिका शोषण कर रहे हैं उन्हें हटाना, एवं उनके स्थान पर सहकारी समितियाँ संस्थापित करनी, किसानों के लिए पारितोषक-मूल्य तथा खेत मजदूरों के लिए निश्चिन्तता का प्रबन्ध करना, खेतिहर मजदूरों के ऋण में कमी करनी, कृषिके आधुनिक तरीके दिखाने के लिए बाट-खोलना तथा सहकारी खेतीके प्रयोग के लिए सरकारी देखरेखमें प्रारम्भिक योजनाएं कार्यान्वित करना, बहुप्रयोजन-सहकारी-समितियाँ खोलना, प्रत्येक किसान के पास कमसे कम कितनी जमीन रहेगी उसका निश्चय करना एवं निश्चित क्षेत्र से अधिक जमीन पर गाँवकी सहकारी समिति का अधिकार रहना, भूमि-राजस्व प्रणाली के स्थान पर भीरे-धीरे कृषि आय पर वर्धमान कर लगाना आदि । रिपोर्ट में कृषि में रकम लगाने के लिये सरकारी कॉर्पोरेशन स्थापित करने की योजना है । यह कॉर्पोरेशन सरकारी समितियों और गाँव-पंचायतों के द्वारा अपना कार्य करेगा । उद्योगधन्वों के बारे में समिति की रिपोर्ट में एक स्पष्ट विवेचन है । समिति की राय ऐसी है कि खाद्य सामग्री तथा उपभोग

सामग्रियां पैदा करने वाले उद्योग धन्यों को विकेंद्रित प्रणाली पर ही रचना चाहिये। जहाँ तक हो सके इन्हें छोटे पैमाने परही-रचना चाहिये। आर्थिक अस्थायित्व तथा प्रतिस्पर्धा मिटाने के लिये बड़े उद्योग-धन्यों और छोटे उद्योग-धन्यों का क्षेत्र निर्धारित करना चाहिये। छोटे उद्योग धन्यों को हर तरह से सरकारी मदद की आवश्यकता है। सुरक्षा-प्रबन्धी उद्योग, मौलिक उद्योग तथा लोक हितकारी कार्य सरकारी-स्वामित्व के अन्तर्गत ही स्थापित करना चाहिये। एकाधिकृत तथा छारे देश अथवा अनेक प्रान्तों के साथ सम्बन्धित उद्योग धन्यों को भी सरकारी-स्वामित्व के आधार पर ही संगठित करना चाहिये। वर्तमान उद्योगों का राष्ट्रीय करण पाँच वर्ष के पश्चात् होना चाहिये; विशेष उद्योग को इससे पहले भी लोकस्वामित्व में हस्तांतरित किया जा सकता है। पाँच वर्ष के समय में उल्लिखित उद्योगों को लोक स्वामित्व में लाने का तथा उनके संचालन का पूरा प्रबन्ध कर लेना चाहिये। राष्ट्रीय करण के बाद उद्योगों के कुशल विकास एवं संचालन के लिये निम्न संगठन स्थापित करना आवश्यक है:— (१) आर्थिक सिविल सर्विस, (२) औद्योगिक कार्यकर्ताका शिक्षण, (३) श्रमिकोंकी साधारण एवं शिल्प शिक्षा, (४) अनुसंधान संगठन, (५) रकम विनियोग, श्रम नियंत्रण, (६) आर्थिक पर्यवेक्षण। धनिक तथा श्रमिकोंके सम्बन्ध को नैमीपूर्ण बनाने के लिये लाभ-पंटाई योजना, उद्योगके प्रबन्ध में मजदूरों का स्थान, श्रमिकोंके प्रतिनिधित्व-प्रद्वित संचालक संस्था, श्रमविवादों की पंचायती, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक बीमा आदि का प्रश्न होना चाहिये। अन्त में छामति ने सुझाव रक्खा है कि उपयुक्त आर्थिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में सरकार की सहायता तथा सहायता देनेके लिये एक स्थायी कमिशन स्थापित करना चाहिये जो आर्थिक योजना के अलावा सरकार की करनीति, विशेष व्यापार-नियमन में लगाई हुई विदेशी रकम प्रवृत्ति के बारे में सलाह देनेके योग्य हो।

हमारी भावी आर्थिक योजना में राष्ट्र का स्थान क्या होगा यह प्रश्न काफी जटिल है । कोई भी आर्थिक योजना राष्ट्रीय सहयोग बिना कामयाब नहीं हो सकती, विशेषतः भारत के तरह एक महादेश में जहाँ कि राष्ट्रीय समस्याओं के अलावा प्रान्तीय समस्यायें भी काफी जटिल हैं । परन्तु आर्थिक समस्या के अलावा केन्द्रिय सरकार के सामने और भी बहुत सी समस्यायें हैं जिन पर जल्द ध्यान देना जरूरी है । इसलिये वर्तमान समय में एक केन्द्रवर्ती आर्थिक योजना के अधीन में सब के सहयोग के द्वारा नई आर्थिक रचना कायम करना ही अधिक उचित होगा । हमारी वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिये, देश को उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिये, जनता के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिये प्रत्येक दायित्वशील व्यक्ति को आगे बढ़ना होगा ताकि जल्द से जल्द भारत एक उन्नतिशील राष्ट्र बन सके ।

राष्ट्रीयकरण की समस्या

राष्ट्र के साथ आर्थिक व्यवस्था का सम्बन्ध किस प्रकार का होना चाहिये इसके बारे में दो प्रकार की विचारधारायें प्रचलित हैं । इनमें एक तो दार्शनिक विचार धारा है और दूसरी लौकिक वाधवा व्यवहारिक । जिन्होंने दार्शनिक विचार धारा को प्रकट किया है उनमें कुछ व्यक्ति राष्ट्र की उपयोगिता को ही अस्वीकार करते हैं । इनको अगर छोड़ दिया जाय तो हमें एक ओर व्यक्तिस्वातन्त्र्यवादी एवं दूसरी ओर समाजवादी दार्शनिकगण दिखाई पड़ते हैं । व्यक्तिवादी दार्शनिकगण चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना उत्पादन कार्य चलाने की पूर्ण स्वतंत्रता हो; ये

राष्ट्र पर बहुत ही कम दायित्व रखने वाले हैं। समाजवादियों का मार्ग दूसरा है। वे राष्ट्र पर ही अधिक से अधिक निर्भर करते हैं एवं वर्तमान के साधनों का खर्चित्व राष्ट्रीय सरकार के हाथों में ही देना चाहते हैं। औद्योगिक क्रान्तिके प्रारम्भमें अर्थशास्त्रोपगम प्रथम सिद्धांत का अनुसरण करने के पक्ष में थे लेकिन आजके नए वातावरण में हमारा तथा सारी दुष्टों का आर्थिक-जीवन जिस प्रकार से शीघ्रता के साथ जटिल होता जा रहा है उसमें राष्ट्र को पृथक् रखना न तो सम्भव है और न उचित ही है।

आदर्श की दृष्टि से जिन्होंने इसका विचार किया है उनका कहना है कि उत्पादन-साधनों के राष्ट्रीयकरण के द्वारा हमें समाजवाद प्राप्त होगा। परन्तु यह सुक्ति निराधार है। राष्ट्र के हाथ में सारे-आर्थिक व्यवस्था को खींच देना ही अगर समाजवाद होता तो इसको प्राप्त करने में कुछ भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। वास्तव में यह कहना सहज नहीं है। कारण यह है कि राष्ट्र को नालने का भार जिनके हाथ में है वे अधिकांश में ही किसी राजनैतिक दल के प्रतिनिधि होते हैं और इनमें ज्यादातर व्यक्ति तो गुरु पूँजीपति होने लगे हैं या पूँजी-पतियों के साथ सम्बन्ध रखने वाले होते हैं। इस परिस्थिति में निरंकुश राष्ट्रीयकरण के द्वारा किस प्रकार से समाजवाद की प्रतिष्ठा हो सकती है? आर्थिक विकास के उन्नीसवें शतक में समाजवाद का विद्यमान हो सकता है जिसमें मौलिक तथा व्यावहारिक सामग्रियाँ पैदा करने वाले उद्योग मन्थों का बहुत ज्यादा विस्तार हो चुका है तथा ऐसी सामग्रियाँ सैकड़ों की गयी हैं जितनी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रयोजन के लिये पर्याप्त हों। इसलिये पूँजीवाद के विस्तार के हम विरोध स्तर तक पहुँचना हमारा प्राथमिक लक्ष्य होगा। आधुनिक समय में निरंकुश व्यक्ति को केन्द्र में यह सम्भाव नहीं होता; इसलिये चाहे तो व्यक्ति के ह्रास राष्ट्र को दुरा

सहयोग देना पड़ता है और नहीं तो राष्ट्रीय पूँजीवाद को कायम करने की आवश्यकता होती है ।

राष्ट्रीयकरण के कई रूप होते हैं जिनमें मुख्य तीन हैं । एक तो यह कि राष्ट्रीय-सरकार ही उद्योग-धन्योंका प्रबन्ध तथा संचालन करे एवं उसके लिये आवश्यक पुँजी जुटावे; दूसरा यह कि राष्ट्रीय सरकार उद्योग-धन्योंका संचालन करे परन्तु रुकम-जुटाना तथा प्रबन्धका सारा काम व्यक्तिही करे और तीसरा यह कि उत्पादन-कार्यका संचालन तथा प्रबन्ध व्यक्तिके हाथमें हो और वह ही मुनाफेका अधिकारी हो, परन्तु उनका नियंत्रण सरकार करे । आज व्यक्ति-वादी देशोंमें भी उद्योग-धन्योंको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है; लाभका नियन्त्रण, मूल्य निर्धारण तथा कर नीतिके द्वारा राष्ट्रीय सरकार उद्योग-धन्यों पर उचित नियंत्रण रखती है; एकाधिकारी-क्षेत्रमें सरकारी नियंत्रण और भी अधिक है । रूसमें सारी आर्थिक व्यवस्थाही सरकारके हाथमें है; पर फ्रांस, ब्रिटेन जैसे पूँजीवादी देशोंमें भी राष्ट्रीयकरणकी माँग बढ़ती जा रही है । २५ प्रकारसे कम या ज्यादा प्रत्येक देशमें आजकल इसी नीतिका अनुसरण किया जा रहा है ।

राजनैतिक परिवर्तन होनेके कारण देशशासनका दायित्व भारतवासियों के हाथमें आ चुका है । आज हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह है कि भारतके उद्योग-धन्योंकी उन्नतिका रूप क्या होना चाहिए—व्यक्तिवाद या राष्ट्रीयकरण । इसके बारेमें निश्चय करनेके पहले हमें अपना आर्थिक आदर्श निश्चित कर लेना चाहिए एवं उसके बाद उसे क्रियात्मक रूप देनेके उचित साधनोंका प्रयोग करना चाहिए । हमारा आर्थिक आदर्श स्पष्ट है । हमें तो प्रत्येक व्यक्ति रहन सहन ऊँचा करना है; इसके लिये पैदावार बढ़ानेकी आवश्यकता है । हमारे देशमें धनको कमो है और वितरण प्रणाली भी सुलझस्थित नहीं है । हमारी आर्थिक नीति ऐसी होनी चाहिए कि हमसे भारतमें उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति-आयमें पर्याप्त वृद्धि हो, कृषिमें सुधार, गृह-उद्योग को स्वतन्त्र

तथा औद्योगिकरणके द्वारा पैदावार बढ़ सके तथा व्यक्तिकी आय भी बढ़े ।

अब राष्ट्रीय करणका क्षेत्र तथा उसकी मात्रा पर ध्यान देनेकी आवश्यकता है । राष्ट्रीयकरणकी मात्रा देश, काल तथा परिस्थितिके अनुसार भिन्न भिन्न प्रकारकी होती है, और दोनों भी चाहिए । हमारी वर्तमान स्थितिमें पूरा राष्ट्रीयकरण कहाँ तक सफल होगा यह सोचनेकी बात है । राष्ट्रीयकरणके बारेमें कांग्रेस आर्थिक प्रोग्राम कमीटीकी राय यह है कि देश-व्यापक तथा जनसाधारणके लिए जरूरी सामग्रियाँ पैदा करनेवाले उद्योग-धन्ये तथा मौलिक शिल्प सरकारके अधीनमें प्रतिष्ठित हो तथा जिन सब उद्योग-धन्योंके प्राग एकाधिक प्रांत या सारे देशका स्वार्थ संयुक्त है उनको भी सरकारके अधीनमें रखा जाय । जो सब उद्योग बहुत दिनोंसे प्रतिष्ठित हैं उन्हें पाँच साल बाद सरकारकी अपने हाथमें ले लेना चाहिये; विशेष क्षेत्रोंमें उसके पहले भी इनका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है । कुछ दिन पहले सरकारने जो आनेवाले शिल्प नीति प्रकट की है उसमें कहा गया है कि पूराने उद्योग-धन्योंका दस सालके अन्दर अपने हाथमें लेनेका विचार सरकार नहीं रखती है; लेकिन वर्तमान समयमें ५ या १० वर्षोंका समय बहुतही गानूची बात है । हमारी शिल्पजन्यताके जीर्णोद्धारके लिए जरूरी सामग्रियाँ तो इस देशमें पैदा होती हैं और न दूसरे देशोंसे ही चाको लागूदार्में अनी मिल सकती हैं । इस लिए वर्तमान समयमें यिर्की जीर्णोद्धारके लिए दो १० साल लग जायेंगे और १० साल बाद यदि राष्ट्रीयकरण निश्चित हो तो कोई उद्योगपति इस काममें रुकन लगानेके लिए तैयार नहीं होंगे । इसलिये राष्ट्रीयकरणका समय निर्देश करना चलन है । यदि दस वर्षके भीतर हमारी आर्थिक व्यवस्था राष्ट्रीयकरणके दायित्व बन जाये तो उस वक्त राष्ट्रीयकरण नीति कामयाब हो सकती है ।

हमारी वर्तमान स्थितिमें राष्ट्रीयकरणका क्षेत्र सीमित है । कुछ स्वरसत तथा धन्ये तो ऐसे होते हैं जिनका राष्ट्रीयकरण होना आवश्यक है, नीति कि

रेल, सड़कें तथा अन्य मुख्य यातायातके साधन। बहुतसे आधारभूत धन्ये ऐसे हैं जिनका उचित संचालन सरकार द्वारा अच्छी तरहसे हो सकता है, जैसे कि, भारी रासायनिक सामग्रियां का कारखाना, औज़ार बनानेका कारखाना इत्यादि। इनके लिए पर्याप्त रकम संग्रह करना तथा देश दितके उद्देश्यसे इनको चलानेका कार्य अधिक सुगमता से राष्ट्रीय सरकारही कर सकती है। इनके अलावा बहुतसे ऐसे कारखाने हैं जो उपभोग-सामग्रियां पैदा करते हैं। इनका राष्ट्रीय करण वर्तमान समयमें उचित नहीं होगा परन्तु इन पर राष्ट्रद्वारा उचित नियंत्रण होना चाहिए। छोटे पैमाने के उद्योग तथा गृह-उद्योगका संचालन राष्ट्रके हाथमें देनेकी आवश्यकता नहीं है लेकिन इनमें जिन साधनोंकी आवश्यकता होती है उनके सम्वन्धमें राष्ट्र को सहायता अवश्य करनी चाहिए। उद्योग-धन्धोंका पूर्ण राष्ट्रीयकरण हो या नहीं यह आवश्यक बात है कि किसी व्यक्तिको धन्धोंके स्थानीयकरण अथवा धन्य बातोंमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं हो सकती। राष्ट्रीय सरकारको यह देखना चाहिये कि देशके सभी प्रान्तोंमें विभिन्न धन्धोंकी उन्नति हो रही है या नहीं। बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रांत आदिमें यहां व्यक्तिगत पुँजी तथा व्यापारिक रकम पर्याप्त है वहां राष्ट्रीय नियंत्रण ही काफी होगा। जहां व्यापारिक रकम तथा दूसरे साधनों की कमी है वहां प्रोत्साहन देनेकी आवश्यकता है और इसका वास्तविक रूप परिस्थितिपर निर्भर करेगा। विभिन्न प्रान्तोंकी आवश्यकता के अनुसार धन्धोंका स्थानीय करण राष्ट्रीय सरकारका उत्तर दायित्व है।

आज आर्थिक विषयोंमें स्वाधीन भारतके सरकारका उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है और उद्योग-धन्धोंके राष्ट्रीय करणके बारेमें सरकारकी नीति किस प्रकारकी होगी इसके बारेमें उपर कुछ प्रकाश टाला गया है। परन्तु हमारी नई राष्ट्रीय सरकारको अभी तक इतनी योग्यता प्राप्त नहीं हुई है जिससे वह सारी आर्थिक व्यवस्थाओंको अपने हाथमें ले। कुछ दिन पहले कानपुरका बिजलीका कारखाना सरकारने धरने हाथमें लिया है।

सरकारके हाथमें जानेके बाद से ही इसमें सुकसान होना आरम्भ हो गया और ४॥ महिनेके अन्दर इसकी आमदनीमें करीब २ लाख काफ़ी कमी हो गई । इस प्रकारसे राष्ट्रीयकरण वर्तमान समयमें हमारे स्वार्थके प्रतिबुल है । कानपुरके वैद्युतिक-संस्था चलनेमें सरकारको जब इतनी असफलता हुई तो टाटा का साम्राज्य बढ़ किस प्रकारसे बढ़ सकती ? मन बात तो यह है कि हमारे राष्ट्रीय संसालनका दायित्व जिनके हाथों में है उनमें कई बातोंकी कमी दिखाई पड़ रही हैं । आज ने ब्रुटियां हमारे नए राष्ट्रकी नींवको शिथिल कर रही हैं । शासनका दायित्व जिनके हाथों में है उनमें पक्षपात छीन उदार दृष्टि स्थापित करनी हो हमारी आजकी सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या है । पारिवारिक स्वार्थ, दलीय स्वार्थ, साम्प्रदायिकता तथा प्रन्तीयताके प्रभावसे बुराईयां बढ़ रही हैं । भारत सरकारके भूतार्थ आर्थिक उपदेष्टा सर थोथोडोर प्रेनरीका कहना है कि "मन्त्रों तथा पदस्थ कर्मचारियोंके दफ्तरोंमें जो लोग गुलामद करते फिरते हैं उनमें से ज्यादातर व्यक्तियोंमें न तो समाज सेवा करनेकी इच्छा है और न योग्यताही । जिस देशकी राष्ट्रीय व्यवस्था इस प्रकारकी हो उस देशमें समाज सेवाकी अनुप्रेरणा कर आवश्यक होगी । इस देशकी सब सुचमें जानना शहरोंके आउम्पर, मंदिरोंके-दफ्तर या पदस्थ कर्मचारियोंको मोटर गाड़ियों से सम्भव नहीं है । इस देशका पूरा निम्न तो सिर्फ़ देशांतोंमें ही मिल सकता है जहां कि सदस्य मध्य भाषाहीन गरजारी दिन पर दिन बढ़ता, बीमारियां प्रभुतिके साथ संग्राम करते हुए बहुत सारे हावतसे जीवन निर्वाह कर रहे हैं और पदस्थ अधिकारीवर्ग इन्हींकी प्राण वासुका शोषण कर रहा है । इसलिए मेरा कहना है कि जब तक वास्तविक अनुप्रेरणाकी जागृति नहीं होगी, जब तक व्यक्ति, परिवार, दल तथा सम्प्रदायकी छोड़ कर हम सारे देशको पट्टखटियों नहीं देना सहेमें तब तक हम राष्ट्रीयकरणके असंभव आर्थिक क्षेत्रोंमें सफल नहीं बन सकते हैं ।

स्वतंत्र भारतकी आर्थिक नीति—युद्धोत्तर भारतका आर्थिक पुनर्गठन ।

विदेशी शासनकी घातक नीति—विदेशी शासन कायम होनेके पहले भारतमें संतुलित अर्थ-व्यवस्था थी एवं हमारी जन-संख्याका सबसे बड़ा हिस्सा घरेलू उद्योग-धन्धों पर अवलम्बित था । विदेशी शासन की घातक नीतिसे भारतकी संतुलित अर्थ-व्यवस्था नष्ट हो गई एवं भारत कृषि-प्रधान देश बन गया । कृषि-प्रधान देश होते हुए भी भारतीय कृषिके दुरवस्थाके बहुतसे कारण हैं (कृषिकी समस्यायें विषयक निबन्ध देखिये) । भारतीय घरेलू उद्योग-धन्धों पर पाश्चात्यकी औद्योगिक क्रान्तिका गहरा असर हुआ । अंग्रेजी सरकारकी व्यापार नीतिसे भारतमें बना हुआ कच्चा माल विदेशमें जाता रहा और बदलेमें शिल्पजात सामग्रियां आती रहीं । यातायात साधनोंकी किरायेकी नीति भी इस भांति निर्धारित की जाती थी कि कच्चा माल देशके घन्दरगाहों पर विदेशोंको जानेके लिए सस्ते किराये पर जाता रहा तथा विदेशी शिल्पजात सामग्रियां सस्ते किराये पर देशके आन्तरिक भागोंमें आती रहीं । इसलिए व्यापार क्षेत्रमें विदेशियोंकी भरमार जारी रही । सरकारकी भारत विरोधी उद्योग-नीतिसे इसमें मदद पहुँची । विदेशी पूँजीका स्वागत तथा भारतमें विदेशी पूँजीवादकी प्रतिष्ठा तथा विदेशी प्रतियोगिताके कारण घरेलू उद्योग-धन्धे पंगु हो गये ।

भारतीय अर्थ व्यवस्था पर लड़ाई का प्रभाव—लड़ाई शुरू होने के वक्त भारत की खतरनाक आर्थिक स्थिति—पहली लड़ाईसे भारतकी विदेशी हुकूमत पूरा फायदा न उठा सकी और न भारत में शस्ययुक्त तथा संशोधन-करण पैदा करनेवाले उद्योग-धन्धों की प्रतिष्ठा हो गई । दूसरी लड़ाईसे भी

मशीनों के धभाव से भारत में मूल शिल्प स्थापित न हो सके और भारत पर-निर्भर रह गया। दूसरी लड़ाई के सुयोग से भारत को छोड़कर ब्रिटिश साम्राज्यके दूसरे सारे देश आर्थिक दृष्टिसे स्वतन्त्र बन गये। बुद्धके समय बहुतसी कामजी आर्थिक योजनायें बनायी गईं (आर्थिक योजना विषयक निम्न देखिये) लेकिन वे कार्यान्वित न होने सकीं।

बुद्धोत्तर भारतमें राजनैतिक परिवर्तन—भारतको नवीन आर्थिक नीतिः—

कृषि—कृषि क्षेत्र में भारत को उपज में वृद्धि करना है—इसके लिये पानी, खाद तथा वैज्ञानिक यन्त्रोंकी आवश्यकता है—सिंचाई का प्रबन्ध तथा जलविद्युतका उत्पादन—भारत की खाद्य समस्या और उमड़ा सुम्भाव—भारत विभक्त होने के बाद पाट, रुई आदि कच्चे माल की कमी। रेलों की चक्रपन्दी करने की आवश्यकता—बंकार जमीन का उपयोग—सिंचाई का प्रबन्ध करने के लिये सरकार के सामने निम्नप्रकार की योजनाये हैंः—

योजना का नाम	सिंचाई का प्रबन्ध	जलविद्युत उत्पादन
तुंगभद्रा घाटी योजना	३००००० एकड़	१२०००० हिलोवट
मदानदी घाटी योजना	२५००००० ,,	५००००० ,,
दागोदर घाटी योजना	९६०००० ,,	३५०००० ,,
कोशी घाटी योजना	३०००००० ,,	१८००००० ,,
नर्मदा घाटी योजना	३७००००० ,,	१०००००० ,,

उद्योग-धन्ये—सन् १९४७ दिसम्बरमें औद्योगिक जलसः—३ लाख के लिये संपर्क विराम—शिल्प दफ्तर की शोध तथा भविष्य योजना—शोध योजना को १॥ वर्ष में तथा भविष्य योजना को ३ वर्ष में सफल बनाने का निश्चय—औद्योगिक शिक्षिता (औद्योगिक शिक्षिता विषयक निम्न देखिये)—पूर्ण विनियोग के लिये उद्योग-धन्यों के विस्तार की आवश्यकता है तथा छोटे पैमाने पर गृह-उद्योग स्थापित करने की आवश्यक-

कता है—औद्योगिक विस्तार के रास्ते पर रुकावटें: (१) मूल धन की समस्या (२) कारिगरों की समस्या (३) मशीनों तथा रासायनिक सामग्रियों की समस्या (४) औद्योगिक शिक्षा की कमी -- १० साल तक उद्योग-धन्धों का राष्ट्रीयकरण न करने का सिद्धान्त—(राष्ट्रीय करण की समस्या विषयक निबन्ध देखिये) विदेशी रकम विनियोग के बारे में सरकारी नीति (विदेशी मूल धन विषयक निबन्ध देखिये) ।

व्यापार—व्यापार के बारे में विदेशी सरकार की घातक नीति से शिल्पजात सामग्रियों के लिये भारत पूर्ण तौर से विदेशियों पर निर्भर करने लगा । भारतीय व्यवसायों की उन्नति तभी सम्भव हो सकती है जब कि देश का कच्चा माल देश के उद्योग-धन्धों में ही लगाया जाय—इन उद्योग-धन्धों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिये भारत सरकार को विदेशी सामग्रियों पर कर लगाना होगा तथा देशी सामग्रियों को संरक्षण देना होगा—व्यापारिक उन्नतिके लिये यातायात साधनोंकी आवश्यकता होगी ।

शिक्षा सुधार—स्वाधीन राष्ट्र में शिक्षा की महत्ता—साजेंट शिक्षा योजना—शिक्षा को लाभदायक बनाने की आवश्यकता ।

इस प्रकारसे स्वतंत्र भारत के नवीन सरकार को देश की कृषि, उद्योग-धन्धा तथा व्यापार के लिये नई नीति का निर्माण करना होगा ताकि दो सौ वर्षोंसे चली आनेवाली आर्थिक स्थिति में सुधार तथा परिवर्तन हो सके ।

भारतमें औद्योगिक शिथिलता

मुद्रोत्तर समयमें हमारे उद्योग-धन्योंमें उत्पादन की कमी निम्न प्रकार

थी:—	१९४५-४६	१९४६-४७	प्रतिशत कमी
कपड़ा	४६५१० लाख गज	३८६३० लाख गज	१७
सुता	५४८० लाख पाउन्ड	४७०० लाख पाउन्ड	१४
कागज	१६८१००० हन्डर	१२४४००० हन्डर	२६
चीनी	१०२३०००० हन्डर	८६६६००० „	१५
दियासलाई	२०२१० प्रोस	१२३९० प्रोस	३९
सिमेन्ट	२१४६००० टन	२०१६००० टन	६
पीग थायरन	१४२२००० „	१३६५००० „	४
स्टील इनगट	१२९९००० „	११६९००० „	८
फोनीन स्टील	१३३८००० „	११६०००० „	८
कोयला	२६५४३००० „	२६२१८००० „	१०३

सन् १९४८ में भी इनकी पैदावार घटती रही ।

औद्योगिक शिथिलताका कारण:—(१) बातायात सामानों की कमीके कारण यनी हुई सामग्रियां पूरी तौरसे न बिक सकी; (२) कच्चे मालकी कमी, विशेषतः देश विमक होनेके बाद; (३) दूसरे उत्पादन सामानोंकी कमी जिनके लिए भारत विदेशियों पर निर्भरशील है जैसे कि मशीनें, रसायनिक सामग्रियां इत्यादि; (४) देश विमक होने पर मुद्रोत्तरकाल सामग्रियों के भारत छोड़कर चले जानेके कारण चमड़ा, धातु आदि उद्योग-धन्योंमें पैदावार का कम होना; (५) अधिकतर धातुतंत्र तथा निरुत्पाद एवं धातु चीनी परनेकी प्रवृत्ति का होना; (६) पूंजीपतियोंमें अधिकतर दारोंमें धर्मदयता विमक कारण उद्योग-धन्योंमें रकमकी परिसर न होना । (७) सरकारी दफतरी की अक्षमता ।

पैदावार बढ़ाने के लिए सरकारी नीति—सन् १९४७ के दिवस में

शिल्पपति, मजदूर तथा सरकारी प्रतिनिधियों का आम जल्सा—३ वर्ष के लिए धनिक-श्रमिक विरोध न होने पावे इसके बारे में निश्चय—भारत सरकार के शिल्प दफ्तर की शीघ्र तथा भविष्य योजना—शीघ्र योजना की १॥ वर्ष में तथा भविष्य योजना की ३ वर्ष में सफल बनाने का तथा २०० करोड़ रुपये रकम विनियोग का सिद्धान्त—पैदावार बढ़ाने का लक्ष्य निम्न प्रकार रखना गया है :—

सामग्रियाँ	वर्तमान उत्पादन (१९४७)	शीघ्र योजना के अंत में उत्पादन	भविष्य योजना के अंत में उत्पादन
कपड़ा	३७७०० लाख गज	४६६०० लाख गज	५,१८० लाख गज
इस्पात	८५,०००० टन	१२६,४००० टन	१७७,०००० टन
सिल्वर	३५०० „	८००० „	२८००० „
सिमेन्ट	१४४,०००० „	२,११,५००० „	३,७५,३००० „
एमोनियमसालफेट	३८००० „	७६००० „	४२,६००० „
सल्फर फास्फेट	१०००० „	६०००० „	१,००,००० „
सोडा एस	१२००० „	५,५००० „	९,०००० „
कास्टिक सोडा	३००० „	१,५०० „	६६,००० „
सालफ्यूरिक एसिड	६५,००० „	१,००,००० „	१,५०,००० „

वास्तव में ये योजनाएँ सफल नहीं हुईं ।

सन १९४८ में भारत सरकारने एक औद्योगिक परामर्श समिति कायम की जिसका उद्देश्य निम्न प्रकार था :—(१) सरकार को औद्योगिक नीतिके बारे में परामर्श देना ; (२) बड़े बड़े उद्योग-धन्धों के उत्पादन पर ध्यान रखना एवं उनकी वर्तमान उत्पादन शक्ति के पूर्ण उपयोग के बारे में परामर्श देना ; (३) दुष्प्राप्य कच्चे माल के उपयोग के बारे में परामर्श देना ; (४) यंत्रोपकरण तथा उद्योग-धन्धों में लगनेवाले कच्चे माल के आयात के बारे में परामर्श देना ; (५) सरकार को आवश्यकतानुसार विषयों पर परामर्श देना—

औद्योगिक परामर्श समितिने सरकार के सामने निम्न प्रस्ताव रक्ता :—

(१) भारत में वस्त्र शिल्प में लगनेवाली मशीनें बनाने का प्रवन्ध करने के लिए विशेष पदाधिकारी नियुक्त करना ; (२) औद्योगिक मशीनें विदेशों से मंगवानेके पहले यह देखना चाहिए कि ये भारतमें बननेवाली हैं या नहीं एवं यदि बननेवाली हों तो उसका प्रवन्ध करना (३) मजदूरों के रत्न संहिता प्रवन्ध भारत के विभिन्न उद्योग प्रधान शहरों में एक दो प्रकार का होना एवं इसके लिए उद्योग संचालकों को भारत सरकार के साथ परामर्श करके प्रवन्ध करना ; (४) वाणिज्य विषयों में सरकार को सलाह देने के लिए उपयुक्त भंडा कायम करना ; (५) औद्योगिक मशीनें बनाने वाले उद्योगपतियों का एक संघ स्थापित करना ताकि वे निर्धारित मूल्य पर सरोदे हुए कच्चे मालोंका यथार्थ वितरण तथा पूर्ण उपयोग कर सकें ; (६) जिन उद्योग-धन्यों में पैदावार घटाने की जरूरत है वहां असंतोष फैलाने बिना श्रमिकों को हटाने के लिए एक मध्यस्थ समिति कायम करना ।

इस समिति ने उद्योग-धन्यों में रकम की पूर्ति न होनेका निम्न कारण बताया है :—(१) देश विपन्न होनेके कारण राजनैतिक तथा धार्मिक परिवर्तन हुआ है ; (२) उन सामाजिक वर्गोंके दाय में रकमका संवय हो रहा है जो उद्योग रकमको फिरसे उद्योग-धन्यों में नहीं लगाते ; (३) धाय-कर तदंत कमोमान के विनियोग से पूंजी विनियोग के बारे में अनिश्चयता फैली हुई है ; (४) सन १९४७ की लिआकत वाली बजट में जो कर-नीति रखी गई थी उसमें पूरा सुधार अभी तक नहीं हुआ, तथा सरकार की मजदूर नीति तथा विदेशी व्यापार नीतिमें सुस्पष्टता न रही ; (५) शेयर बाजारमें फटकावाही चलने के कारण अनिश्चयता की सृष्टि हुई । पैदावार बढ़ानेके लिए इन समितिने निम्न प्रकारका प्रस्ताव रक्ता है :—(१) कर-नीतिमें परिवर्तन दिया जाए ताकि उद्योगपतिगण उद्योग-धन्योंमें रकम लगानेमें उत्साहित हों, तथा मशीनेंके पिछाडके कारोंमें भी सरकारको धायकर नीतिमें उद्योगपतियोंके लिए

कुछ सुविधा देनी चाहिए, (२) सरकारी व्ययमें कमी (३) अनाज तथा आवश्यक सामग्रियोंका मूल्य घटाना तथा श्रमिकोंके जीवन निर्वाहके व्ययके साथ उनकी मजदूरीका सम्बन्ध स्थापित करना ; (४) खाद्यपदार्थोंकी पैदा बढ़ानी, (५) शेयर बाजारको सुधारना ताकि पूंजी विनियोगको उत्साहित किया जाय ; (६) अल्प पैदा करनेवाले लोगोंमें संचयके लिए प्रचार; (७) औद्योगिक सुधारका सारा प्रबन्ध करना तथा कारखानें जिसमें सामग्रियों के अभावसे बन्द न होने पावें उसका प्रबन्ध करना ; (८) सामग्रियों पर गुणात्मक नियंत्रण ; (९) विदेशी पूँजीका स्वागत करना ; (१०) उद्योग-धन्धोंके राष्ट्रीयकरणके पहले क्षतिपूर्ण देनेका निश्चित प्रदान ; (११) वैयक्तिक पूँजी विनियोग को हर तरहसे उत्साहित करना ।

आर्थिक संकट या व्यापारिक मंदी—बेकारीकी समस्या—भारतमें पूर्ण विनियोगकी आवश्यकता

व्यापार चक्रका स्वरूप—बाजार में जब सामग्री के लिये मांग और उसकी पूर्ति ये दोनों एक दूसरेके समान होती हैं, जब उत्पादन तथा उपभोगमें समानता रहती है और जब सामग्रियाँ सहजमें ही उपभोगकारियोंके पास पहुंचती हैं तब आर्थिक परिस्थिति में संकट नहीं आता परन्तु आजकल उद्योगपति और उपभोगकारियों के बीच में इतनी जटिलता पैदा हो गई है कि अधिकांशतः मौलिक सत्य अर्थात् “उपभोग के लिये ही उत्पादन प्रबन्ध होता है” यह स्पष्ट नहीं होता । यह स्पष्ट है कि उत्पादन और उपभोग में यदि किसी कारण से समानता नष्ट हो जाय तो संकट पैदा होने की संभावना हो जाती है ।

व्यापारिक संघट के बारे में मार्क्सवादी सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के ३ पहलू हैं :—(१) श्रमिकों की संख्या और श्रमिकों के लिये परिवर्तों की मांग या श्रमिकों की श्रमशक्ति की खरीदने में लगाने हुआ मूलधन इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध में होनेवाले परिवर्तन पर ही बेकारी का परिमाण निर्णय होता है। (२) सिद्धान्त के दूसरे पहलू में लागू-वृत्ति में कमी की बात कही गई है। (३) संयोजकता तथा भोगमानप्रिया बनाने वाले उपयोग-वस्तुओं के बारे में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि समाज की बढ़ती हुई उत्पादन शक्ति जनसाधारण की दक्षिण के कारण व्यर्थ रह गई है। मार्क्सवादी सिद्धान्त की यह बात तो यह है कि पूँजीवादी व्यवस्था के आविर्भाव के पहले जब भोग व्यवहार के अनुसार सामग्रियाँ पैदा होती थीं, तब इन दोनों में समानता थी जो पूँजीवादी व्यवस्था में नाष्ट हो चुकी है। इसके अलावा इस नयी परिस्थिति में सामग्री पैदा करनेवाला श्रमिक अपनी स्वतन्त्रता को खो देता है लेकिन कुछ गम्भीरता से देखने पर पता चलेगा कि यह पार्थक्य और भी गहरा है। पूँजीवादी व्यवस्था में धनिकता लक्ष्य है मृत से श्रमिकों को दूर दूर करके काम करना देना और इसके लिये जिसकी मिथ्या के बिना नहीं चल सकता मृत दलालों की ही व्यवस्था कर देना। इसलिये श्रमिक सम्पूर्ण काम का जानकार नहीं बन सकता। हमें श्रमिकों की आजादी सदा के लिये नाष्ट हो गई है और वे मुलानों की जंजीरों में फँस गये हैं। इस नये संगठन की विवेचना यह है कि उत्पादन और उपयोग अब पहले की तरह समान नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि आवश्यक उपयोग-वस्तुओं में उत्पादन-गति की वृद्धि करने की शक्ति पर ही ध्यान दिया जाता है। भोग व्यवहार पर नहीं।

पूँजीवादी धर्मशास्त्रीयान्ध्र धर्मित संघट के बारे में सन्देह नहीं है। धर्मित संघट के बारे में पूँजीवादी धर्मशास्त्रियों का सिद्धान्त—इस धर्म शास्त्रियों का सिद्धान्त यह है कि धर्मशास्त्रिक संघट धर्मित धर्मित व्यक्तियों से होता है और इनको रोकने पर यह समझा रह हो जायेगी।

इसका विश्लेषण निम्न प्रकार है :—जब उद्योगपतियों के सामने लाभ कमाने की सम्भावना दिखाई देती है तब वे उद्योग-धन्धों को बिना सोचे समझे बढ़ाये जाते हैं; बैंक व्यवस्था कर्ज की सृष्टि करके इन्हें मदद पहुंचाती है। इस तरह से पैदावार जितना बढ़ता है उतनी क्रयशक्ति जनता के हाथ में नहीं रहती। इसलिये बेकार सामग्रियां बाजार में इफट्टी हो जाती हैं और व्यापारिक मंदी दिखाई पड़ती है। इनका कहना है कि यदि कर्ज नियन्त्रण के द्वारा मुद्रास्थिति को विगड़ने से रोक दी जाय तो व्यापारिक संकट दिखाई देने की सम्भावना कम हो जायगी। वास्तव में व्यापारिक संकट सिर्फ आर्थिक कारणों से ही नहीं होता बल्कि किसी किसी क्षेत्र में आर्थिक प्रभाव के अतिरिक्त कारण ही अधिक महत्व रखते हैं। दूसरे अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यंत्रोपकरण पैदा करने वाले उद्योग-धन्धों में अतिरिक्त पूंजी विनियोग के कारण आर्थिक संकट होता है। इनके सिद्धान्त के अनुसार व्यापारिक संकट रुपये की कमी या बाहुल्य से नहीं होता, आर्थिक व्यवस्था में संतुलन नष्ट हो जाना ही इसका मुख्य कारण है और यदि संतुलित अर्थ व्यवस्था में विघटनला वा जाये तो आर्थिक साधनों से उसका सुलभाव नहीं हो सकता। इस समस्या को हल करने के बारे में इनकी राय यह है कि व्यापारिक मंदी को व्याज दर घटाकर नहीं रोका जा सकता लेकिन व्याज दर बढ़ाकर तेजी को रोकना सहज है एवं यदि अतिरिक्त व्यापारिक तेजी की सम्भावना नष्ट हो जाय तो मंदी अपने आप न हो पायगी। व्यापारिक संकट के बारे में तीसरा सिद्धान्त यह है कि उपभोग की कमी के कारण व्यापारिक मंदी आती है लेकिन इस सिद्धान्त में व्यापारिक तेजी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, वास्तव में मंदी तो तेजी का ही फल है। व्यापारिक मंदी के बारे में और एक सिद्धान्त में कहा गया है कि यह मानसिक कारणों से होती है। मानसिक कारण तो हैं ही लेकिन इनको मुख्य स्थान नहीं दिया जाता।

व्यापारिक संकट का समाधान—मुद्रा तथा कर्ज नियंत्रण, ताकि उद्योग-धन्यों में पूँजी का अस्वाभाविक विनियोग न होने पावे । सरकार को कर तथा व्यय नीति ऐसी होनी चाहिये कि तेजी के समय उद्योग-धन्यों पर ज्यादा कर लगाया जाय एवं वह रकम मंदी के समय मुक्ति-प्रयत्नमें लगाई जाय ताकि उद्योग-धन्यों से जो लोग बेकार हो जाते हैं उन्हें सरकारो रचनात्मक कामों में स्थान दिया जा सके लेकिन इस तरह से व्यापारिक संकट को रोकना सम्भव नहीं होगा । व्यापारिक संकट को रोकने के लिये उत्पादन तथा उपभोग में समानता लानी होगी । सिर्फ वार्षिक योजना के द्वारा व्यापारिक मंदी का मुक्त्य हो सकता है (“आर्थिक योजना” विषयक नियन्ध देखिये) ।

बेकारी की समस्या—बेकारी या बेरोजगारी क्या है ? जब किसी भी कारण से काम करनेवालों के अनुपात से काम की कमो हो जाती है यानी किसी भी पैतन पर काम नहीं मिलता तब उसे बेकारी कहते हैं । समाज में बेकारियों निम्न प्रकार की होती हैंः— (१) इच्छार्थक बेकारीः—जिनके पास संवित रकम है वे यदि काम न करें तो उसे खेचटा पूर्वक बेकारी कहा जायगी लेकिन समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में जहाँ कि प्रत्येक इन्सान को समाज के लिये अपनी सामर्थ्यानुसार परिश्रम करना पड़ता है इस बेकारी का स्थान नहीं है । (२) संपर्क के कारण बेकारीः—जब अर्थ-व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होता रहता है यानी जब हम एक आर्थिक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर जाते हैं तब कुछ न कुछ लोग बेकार हो जाते हैं और वह बेकारी नाहे वह समाजवादी व्यवस्था हो और कहे पूँजीवादी अवस्था होनेवाली है लेकिन ये बेकारी स्थायी नहीं होती । (३) अविच्छेदपूर्वक बेकारीः—वह पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था की विशेषता है यानी पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में कुछ कालीन स्थिति को छोड़कर पूर्णविनियोग कमो भी नहीं होता । एक ओर तो समर्थियाँ पैदा होती रहती हैं और

दूसरी ओर बेकारी के कारण जनता के हाथ में क्रयशक्ति के अभाव से इनकी ख़रीद नहीं होती। इसलिये बेकारी तथा व्यापारिक मंदी परस्पर सम्बन्धित है। सन् १९२९ की विश्व व्यापी व्यापारिक मंदी के बाद से अर्थशास्त्रियोंकी गवेषणा इन्हीं समस्या के विशेषण पर लगी हुई है लेकिन शुद्ध पूंजीवादो अर्थ-व्यवस्था में इसका समाधान असम्भव है। इसलिये प्रत्येक देश आज राष्ट्रीयकरण के द्वारा राष्ट्रीय पूंजीवाद को कायम कर रहा है तथा आर्थिक योजना के द्वारा कुछ हद तक इन समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहा है। भारत में किसानों की आंशिक बेकारी तथा शिक्षित मध्यमवर्ग में बेकारी की समस्या विशेष उल्लेखनीय है।

भारत में पूर्णविनियोग की आवश्यकता—पूर्णविनियोग निम्नलिखित विषयों पर निर्भर है :—क्रियात्मक अभियाचन, पूंजीकी सीमान्त उत्पादन शक्ति एवं व्याज। पूर्णविनियोगको सकलसिद्ध बनानेके लिए भारतमें शिल्पोपकरण बनानेवाले उद्योग-धन्धोंको स्थापित करने की आवश्यकता है—हमारे आर्थिक संगठनमें हमें निम्नलिखित विषयों पर ध्यान देना होगा :—

(१) व्याज दर—हमारी वर्तमान स्थितिमें अधिक व्याज की नीति ग्रहण करने में कुछ असुविधाएँ हैं। पूर्णविनियोग को प्राप्त करना हमारे लिए जैसे आवश्यक है संचय को बढ़ाना भी ठीक वैसे ही आवश्यक है। पूर्णविनियोग को प्राप्त करने के लिए व्याज कम करना चाहिए लेकिन संचय को बढ़ानेके लिए—विशेषतः हमें जब वैयक्तिक संचय पर निर्भर करना पड़ता है—व्याज बढ़ाना आवश्यक है। यदि वैयक्तिक संचयको बढ़ाना पड़े तो अधिक व्याज का लालच देना होगा। साथ ही साथ यह भी सोचने की बात है कि यदि व्याज को बढ़ाया जाय तो पूर्णविनियोग को प्राप्त करने के पहले ही एक ऐसी अवस्था आ पहुँचेगी जबकि विनियोग को रोक देना पड़ेगा। इसीलिए यदि पूर्णविनियोग को प्राप्त करने के समय तक हम मुद्रा का पं

आर्थिक संगठन की आवश्यकता के अनुपात से बढ़ाते हुए व्यय को घटाकर रख सकें तो हम इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं ।

(२) मजदूरी—मजदूरी को स्थिर रखने की आवश्यकता है । इसमें श्रमिकों की अवस्था की कोई अवहेलना नहीं है लेकिन मजदूरी के साथ लागत का प्रत्यक्ष सम्बन्ध होनेके कारण पूर्णविनियोग तक पहुँचने के लिए मजदूरी को साधारण तौर पर स्थिर रखकर लागत को कम करना ही उचित होगा । यदि मजदूरी बढ़ जानेके कारण लागत बढ़ जाय तो व्ययको घटाने पर भी कोई फायदा नहीं पहुँचेगा ।

(३) मुद्रा नीति—पूर्णविनियोग का प्रश्न मुद्रा नीति से सम्बन्धित है । पूर्णविनियोग को कार्यान्वित करने के लिए हमें मुद्रा का परिमाण बढ़ाना पड़ेगा । मुद्रा केवल उत्पादन साधनों को उपलब्ध करने के लिए ही आवश्यक नहीं वरन् उद्योगपतियों की धारणाओं पर भी इसका गहरा असर पड़ता है कारण मुद्रा के परिमाण के साथ मूल्य स्तर का एक विशेष सम्बन्ध है । यदि थोड़े सामग्रियों पैदा की जाय तो लागत कम हो जायगी और उद्योगपतियों का मुनाफा बढ़ता चलेगा । इस प्रकार से उद्योग-धन्यों को पूर्णविनियोग की ओर बढ़ने के लिए उन्हें उत्साह मिलेगा ।

भारतमें मजदूर समस्या—भारतके मजदूर आन्दोलन—मजदूर हित-कार्य—सामाजिक बीमा—
भारतमें सामाजिक बीमा

भारत में श्रम-श्रमिकों की संख्या भारतीय जन-संख्या का प्रतिशत १० है । भारत की तरह एक महादेश में श्रम-श्रमिकों की संख्या बहुत ही कम

है एवं ज्यादातर लोग कृषिकी तरह एक अनिश्चित वृत्तिपर अवलम्बित हैं । इन श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा कृषि से सम्बन्धित है यानी ये लोग उद्योग-धन्धों पर पूरी तौर से निर्भर नहीं करते । इसीलिए हमारे शिल्प-श्रमिकों में न तो पूरा संगठन ही है और न संगठन की इच्छा ही ।

श्रमिकों की समस्या—श्रमिकों की समस्या प्रधानतः आर्थिक प्रश्नों पर है—(१) भर्ती और सुरक्षित नौकरी का सवाल—कारखानों और शानों में श्रमिकों को भर्ती कराने को कई प्रणालियाँ प्रचलित हैं जिनसे न तो मालिक को ही फायदा होता है और न मजदूरों को—ठेकेदारों के द्वारा शानों में तथा चाय के बगानों में श्रमिकों का विनियोग—नित्यव्रति मजदूरों पर होनेवाले अत्याचारों को रोकनेके लिए विशेष कर्मचारियों की आवश्यकता । (२) भारत में शिल्प-श्रमिक ज्यादातर स्वायत्ती नहीं होते—कृषिसे सम्बन्धित होनेके कारण जबहि उन्हें मौका मिलता है तबहि वे कारखानों का काम छोड़कर घर चले जाते हैं और शायद ही वे फिरसे उन्हीं कामोंको करने के लिए लौटते हैं । जब तक कारखानों का काम उन्हें पूरी तौरसे आकर्षित न कर सकेगा तब तक हमारे मजदूर सुनिश्चित न बन सकेंगे । (३) मजदूरों की अनुपस्थिति—इनके बारेमें मालिकों की यह धारणा है कि उन्हें अधिक मजदूरों मिलनेके कारण वे बहुत दिनोंतक अनुपस्थित रहने हैं लेकिन विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात् यह सिद्ध हुआ है कि अनुपस्थिति का कारण दूसरा ही कुछ है, जैसे कि बिमारो, ज्यादा देर तक काम करने से थकावट, औद्योगिक संघर्ष, सामाजिक तथा धार्मिक रीति-रिवाज, मौसमी के स्वाभाविक कारणों से अनिश्चयता इत्यादि । (४) कारखानों के भीतर आधुनिक प्रणाली का अभाव—कारखानों में जगह की कमी, गन्दगी, दवा तथा रोगियों की कमी, पीनेका पानी, दवाई आदि की अव्यवस्था, विभाग गुरुों का अभाव इत्यादि कारणों से मजदूरों के स्वास्थ्य पर काफी हानि पहुँचती है—कारखानों में कल-पूजों भी ज्यादातर पुराने टंगके हैं और उनको मरामत भी

वैज्ञानिक हिसाबसे नहीं है। मजदूरों में औद्योगिक शिक्षाका समावेश— ज्यादातर अधिक पढ़ा परिष्कार के रज लिखे जाते हैं ; इनमें कारिगरी का समावेश होना स्वाभाविक है। (५) वेतन की दरें—एक ही प्रकार के कामके लिए एक ही केन्द्र या कारखाने में या भिन्न भिन्न केन्द्रोंमें भिन्न भिन्न वेतन की दरें होती । ज्यादातर मजदूरों का वेतन न तो उनके रहन-सहन के हिसाब से दिया जाता और न उससे उन्हें कोई निर्दिष्ट जिवन का दर्जा स्थापित करनेका सुयोग ही मिलता । वेतन नियमित रूपसे भी नहीं दिया जाता और उनके हिसाबमें भी हर एक मजदूर की जाती है । इसलिये निम्नतम मजदूरी मांग देनेकी आवश्यकता है। (६) मालिक वदा इस बात की आपत्ति उठाते हैं कि भारतीय मजदूर विदेशी मजदूरों के बराबर काम नहीं कर सकते लेकिन इसका उत्तरदायित्व बहुत दूर तक मालिकों पर ही है। मजदूरोंको काम पर भेजने के पहले उनको शिक्षा देनेकी आवश्यकता है । मजदूरों की अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, मकान, आनन्द-प्रमोद की सुविधा दवाई आदि उपलब्ध नहीं होनेके कारण उनकी कर्मशक्ति कम हो जाती है ।

फैक्टरी कानून—मजदूरों की मालिकों के अत्याचार से बचने के लिए कारखाना सम्बन्धी कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है । प्रथम विरजसुख के पहले कारखानों के बारेमें कुछ कानूनों बनाई गई थी लेकिन वे पूरी तौरसे कामयाब न थीं । सन् १९११ के एक कानून के अनुसार मजदूरों के लिए १२ घंटा श्रम समय माँग दिया गया था एवं उन्हें १॥ घंटा विश्राम करने का सुयोग भी दिया गया था । सन् १९२२ में श्रमिकों को श्रम समय ११ घंटा तथा साप्ताहिक ६० घंटा कर दिया गया था। सन् १९३४ में यह १० तथा ५४ घंटा कमकर दिया गया है एवं कारखानों के भीतर सुरक्षा-सुविधा लिए जलनर विशेष महत्व लगाया गया है । सन् १९४६के एक कानून के अनुसार सभी कारखानों में श्रमिकों को श्रम समय १० तथा ५० घंटा

किया गया है। चाय बगानों तथा खानोंमें काम करनेवाले मजदूरों के लिए स्वतन्त्र कानूनों बनाई गई हैं।

भारत में मजदूर आन्दोलन—पहली लड़ाईके पहले भारतीय मजदूर आन्दोलन बहुत ही कमजोर था एवं किसी किसी शिल्प केन्द्र में दो-एक छोटे छोटे मजदूर संघ बनाये गए थे। प्रथम महायुद्ध के फलस्वरूप मजदूरोंमें वर्गचैतन्यका उदय हुआ। सामग्रियों की कीमत बढ़ने के कारण मजदूरों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। मालिकों के घरों में चांदीकी बर्तानों होनेके कारण धन विभाजनकी असमानता और भी बढ़ गई। भारतीय मजदूर आंदोलन पर इसी क्रांतिक प्रभाव हुआ। सन् १९१८ में मद्रासके सूती कारखानों में पहले पहल शिल्प मजदूरों का संघ स्थापित हुआ। इस संगठन की लहर बम्बई, कलकत्ता और वाहमदाबाद में फैल गई। भारतीय मजदूर आंदोलन पर राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव पड़ा। युद्धोत्तर समय में भारतके विभिन्न शिल्प केन्द्रों में हड़तालें हुईं। सन् १९२० में मजदूर आन्दोलन का अखिल भारतीय संगठन स्थापित हुआ और संगठनने अपने प्रथम अधिवेशन में श्रम समय में कमी, मजदूरी बढ़ानेकी सुविधा, चिकित्सा का प्रबन्ध, मोंक्रीका हर्जाना, वृद्धावस्था तथा गर्भावस्था में आर्थिक सहायता इत्यादि प्रश्नों पर विचार किया। सन् १९२० में जमीना में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघकी स्थापना की गई और इसीके प्रस्ताव के पल्लवस्वरूप भारत सरकार ने सन् १९२२ में एक महत्वपूर्ण कानून बनाया। सन् १९२६ की मजदूर संघ कानून के अनुसार जो मजदूर संघ सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लेगी उस पर दिवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा यानी मजदूर संघको हड़ताल करनेका वैध अधिकार प्राप्त हो गया। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेसमें दो दल, दक्षिणपक्ष और वामपक्ष होनेके कारण ट्रेड युनियन फेडरेशन की स्थापना हुई। सन् १९२९ में विदेशवादी आर्थिक संकटका असर मजदूर आन्दोलन पर पड़ा। व्यापारिक संकटके कारण एक ओर

मजदूरों की छंटनी हो रही थी तथा दूसरी ओर देशमें बहुत-से दृष्टताले हुए, लेकिन अधिकतर दृष्टताले अशकल रहें। सन् १९२९ में सरकार ने औद्योगिक संघर्ष विरयक कानून बनाकर जनहितकर धन्योंमें बिना सूचित छिप दृष्टताल करना गैरमाननी बना दिया तथा औद्योगिक संघर्ष होने पर पंच नियुक्त करनेकी व्यवस्था मध्यस्थ नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की। सन् १९२६ में प्रकाशित लेबर कमोशनके रिपोर्ट के आधार पर सन् १९३४ में भारत सरकारने कारखाना सम्बन्धी एक व्यापक कानून बनाया। सन् १९३७ में विभिन्न प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रि-मंडल की स्थापना हुई और वे मजदूर-जांच-समितियाँ कायम किये तथा लेबर-आफिसर भी नियुक्त किये गये। सन् १९३८ में मजदूर आन्दोलन की दोनों अखिल भारतीय संस्थाएँ सम्मिलित हो गईं लेकिन यह एकता स्थायी नहीं हुई एवं कम्युनिस्ट तथा 'सवर्गार्दी' मजदूरगण राष्ट्रीय आन्दोलन का विरोध करते हुए सरकार की सत्ताज्जवादी लड़ाई में मदद पहुँचाने लगे। मजदूर आन्दोलन पर दूसरे महत्त्व का प्रभाव—सामग्रियों की कीमत बढ़ने के कारण मजदूरों पर कठिनाइयाँ—मजदूर अग्रान्तीन रोक्ने के लिए भँदगाई मत्ता आदिवा प्रसन्न—लड़ाई के अन्तमें फिरसे दृष्टतालों की बाढ़—कुछ दिन पहले साम्यवादी प्रभावित अखिल भारतीय मजदूर-संघ-कांग्रेस की बराबरी करने के लिए और एक अखिल भारतीय संस्था स्थापित हुई है, यह अखिल भारतीय राष्ट्रीय मजदूर-संघ-कांग्रेस के नामसे परिचित है। इसके अलावा हिन्दू मजदूर महा मण्डल और एक संस्था सुखोत्तर समय में स्थापित भी गई है। भारतीय मजदूरों में वर्गचैतन्य का उदय होने पर भी मजदूर आन्दोलन विश्वदृष्टा में नया हुआ है। अखिलांग मजदूर-संघ देशक दृष्टताल करना हो अथवा प्रथम न वर्तमान मनमो है। मजदूर आन्दोलन की दुर्बलता का मुख्य कारण यह है कि हमारे मजदूर जनशक्त हृदि पर अशक्तमित्त होयें हैं इसलिए औद्योगिक हृदि पर वे ही सीरसे ध्यान नहीं देते। इसके अलावा हमारे मजदूर

शिल्प केंद्रों में भारत के विभिन्न प्रान्तोंसे मजदूर इकट्ठे होते हैं ; इनकी भाषा, रहन-सहन, रीति-रवाज आदि एक दूसरे से भिन्न होता है । आर्थिक विषयों में इनकी दृष्टि में बहुत अन्तर रहता है और ये सम्मिलित होकर आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न नहीं कर सकते । आर्थिक दुस्स्थिति के कारण मासिक चन्दा देना भी इन्हें बोज़-सा मालूम पड़ता है । मजदूरों का नैतृत्व भी अभी तक ज्यादातर शिक्षित-वर्गों के हाथ में रहा है । इसके अलावा मजदूर संघों ने मजदूरों के हितोंके रचनात्मक कार्योंकी ओर ध्यान ही नहीं दिया । मजदूर आन्दोलन को शक्तिमान बनाने के लिए आवश्यकता इस बातकी है कि मजदूरों में सहो नैतृत्व हो और मजदूरों में रचनात्मक कार्य किया जाय ।

मजदूर-हितके लिए कार्य—मजदूर-हितके लिए रचनात्मक कार्य करने का उत्तरदायित्व सिर्फ मजदूरों पर ही नहीं बल्कि मालिक, राष्ट्रीय सरकार तथा सारे समाज पर है । संकीर्ण दृष्टिसे मजदूर-हित कार्य पर लगाई हुई रकम अ-लाभदायक मालूम पड़ती है लेकिन वास्तवमें इन कामोंमें पूँजीका विनियोग अन्तमें लाभदायक ही होता है कारण जैसे कल-पुर्जोंको कार्योंयोगी रखने के लिए सफाई का प्रबन्ध रखना पड़ता है ठीक वैसे ही मजदूरों के लिए इन कार्योंकी आवश्यकता है ताकि उनकी उत्पादन शक्ति बनी रहे । इसका सबसे बड़ा दायित्व तो मालिकों पर है लेकिन अभी तक वे इसे पूरा नहीं करते । जो लोग मजदूर हितके लिए कुछ प्रबन्ध करते हैं वे धार्मिक दृष्टिसे ही करते हैं व्यापारिक दृष्टि से नहीं । मालिकों की इस दृष्टिमें परिवर्तन की आवश्यकता है । मजदूर हितके उत्तरदायित्व का एक हिस्सा समाज पर भी आता है जिसको समाज के उदार दृष्टि सम्पन्न लोग तथा परोपकारी संस्थाएँ जैसे कि, वाई० एम० सि० ए०, मर्यन्टम् आदि इन्डिया सोसाइटी आदि, पूरी करती हैं । मजदूर कल्याण का सबसे बड़ा दायित्व राष्ट्रीय सरकार पर है जो विभिन्न कानूनों बनाकर उसे पूरा करती है ।

भारत में मजदूर संरक्षण के लिए अब तक बहुत-सी कानूनें बनाई गई हैं लेकिन उन्हें कार्यान्वित करने पर अब सरकार को ध्यान देना होगा। उन उत्तरदायित्व का कुछ हिस्सा मजदूरों पर भी आता है। ईश्वर भी उनकी सहायता करता है जो खुद अपनी सहायता करते हैं। इसलिए मजदूर संघोंको रचनात्मक कार्योंके द्वारा मजदूर कल्याण को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

सामाजिक बीमा—औद्योगिक क्रांतिके बादसे मजदूर वर्ग का शोषण जिस तरह से चल रहा है उसके फलस्वरूप उनमें वर्गनिरपेक्षता का आविर्भाव हुआ है तथा पूँजीवाद के खिलाफ समाजवादी भावना स्पष्ट हो रही है। इसको रोकने के लिए पहले पहल जर्मनी में सन् १८८०-८९ में जो प्रयत्न किये गये वह सामाजिक बीमा के नामसे परिचित हैं। जिन कारणों से मजदूरवर्ग में असन्तोष फैलता है उनमें आर्थिक कारण मुख्य हैं। जिस समय जर्मनी में सामाजिक बीमा कायम हो गई उस समय बहुत से लोगोंने इसकी समालोचना की भी लेकिन जल्दही यह योजना सफलसिद्ध हो गई एवं इंग्लैंड तथा दूसरे देशोंमें भी इसे अपना लिया। दूसरी लड़ाई के प्रारम्भ में पृथ्वीके विभिन्न देशोंमें सामाजिक बीमा पर विशेष महत्त्व दिया जाता है। जनता का ध्यान नानी आर्थिक कष्टको रोकना ही इसका लक्ष्य है। इस दृष्टि से सामाजिक बीमा प्रत्येक इन्सानके लिए एक न्यूनतम मजदूरी का प्रयत्न करना चाहती है। तिरक इतना ही नहीं बल्कि विमारियों को रोकना, अज्ञानता को दूरगुल से जगाना, निरपेक्षता तथा अलस को दूर दृष्टा कर प्रत्येक व्यक्तिही किसी न किसी लाभदायक काममें विनियुक्त करना सामाजिक बीमाका लक्ष्य है। सामाजिक बीमाको सफलसिद्ध करनेके लिए रक्षक तथा सार्वभौम पूर्ण मदयोग की आवश्यकता है। सामाजिक बीमा का लक्ष्य यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को पैसाएँ रखना तथा उन्हें आर्थिक दृष्टिको संरक्षित करना बल्कि वह प्रत्येक

व्यक्तिको काम पर उत्साहित करती है, उसे कामका सुयोग तथा पूर्णदायित्व देती है। युद्धके समयमें सर निर्ययम वेमरिजके द्वारा रची हुई सामाजिक विपन्न योजना विशेष विख्यात है। इसमें सिर्फ उत्लेखित विषयों पर ही ध्यान नहीं दिया गया है बल्कि स्त्रियों बच्चों तथा वृद्धावस्था को प्रत्येक पुरुषों पर भी ध्यान दिया गया है ताकि वे किसी भी स्थितिमें, चाहे वे सुस्थ हों या अस्वस्थ, चाहे वे विनियुक्त हों या बेकार, चाहे वे जिन्दे हों या मृत उन्हें किसी भी अवस्था में अपायका अनुभव न हो ; इसका सारा उत्तर-दायित्व समाज के स्कन्ध पर रक्खा गया है। सामाजिक बीमा के दारे में वेमरिज योजनाकी मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—(१) निम्नतम जीवन स्तर को संरक्षित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समान आर्थिक सहायता दी जायेगी (२) सामाजिक बीमा संचितियों प्रत्येक व्यक्ति को दान की मात्रा समान होगी (३) इसका सारा प्रबन्ध एक केंद्राती दायित्वशाल मंत्रिके हाथमें सौंपा जायेगा (४) आर्थिक सहायता प्रयाजन के अनुसार समायोज्य होगी कर दी जायेगी (५) जहाँ तक हो सके विभिन्न वर्गके लोगों पर तथा उनके विभिन्न आवश्यकताओंपर ध्यान दिया जायगा (६) विभिन्न लोगों के विभिन्न जीवनस्तरकी उपेक्षा नहीं की जायेगी।

भारतमें सामाजिक बीमा—भारतीय आर्थिक जीवनमें सामाजिक बीमा विशेष महत्त्व रखती है। हमारी समस्या सिर्फ राभाव, व्याधि, अज्ञानता, निदोष्यता तथा अलसता की ही नहीं बल्कि दायित्व, दान, सुख, संख्या, अत्यायु, पूर्ण बेकारी तथा अर्द्ध बेकारी की भी है। अभी तक भारत सरकारने इन समस्याओं पर ध्यान तक नहीं दिया। इंग्लैंडने ये सब समस्याएँ हमारी आर्थिक विकास को रोक रखी हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति के लिये एक निम्नतम मजदूरी का प्रबन्ध हो जाय तो उसके सिर्फ उसके व्यक्तिगत जीवन में ही फायदा नहीं पहुंचेगा बल्कि उसके करदाता के आधार पर सामाजिक उत्सादनका भी विचार होगा, लेकिन सामाजिक बीमा

योजनाको भारत की तरह एक महादेश में सफल सिद्ध बनाने में काफी रकम की आवश्यकता है तथा ये समस्याएँ हमारे देश में कुछ नीतिवृत्ता भी रखती हैं जिससे ये दूसरे देशों की समस्याओं से कुछ भिन्न प्रकार की हैं। हमारी राष्ट्रीय आय भी इतनी नहीं होती जिसको बाँटने पर भी प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर ऊँचा हो सके। जो भी कुछ हो सामाजिक बीमा को पूरी तौर से सफल सिद्ध बनाने में अमुविधायें जरूर हैं लेकिन इनकी आवश्यकता को भी सिर्फ मानविकता की दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से भी अग्रहेलना नहीं हो जा सकती। यदि इसको पूरी तौर से अपनाना सम्भव न भी हो तो इसके एक एक पहलू पर विचार करना उचित होगा जैसे कि अध्यापक आदरकर्मने स्वास्थ्य बीमा के बारे में भारत सरकार के सामने अपना प्रस्ताव रखा है। यदि सामाजिक बीमा के बारेमें इस तरह से हम कदम उठाते चले तो हमारी सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का समाधान होना कोई कठिन बात नहीं होगी।

भारत का आयात-निर्यात वाणिज्य और उसका भविष्य

इसमें कुछ दिनों से अन्तर्राष्ट्रीय भावों व्यापार की बातें हो आलोचना को प्रधान विषय बन गई हैं। प्रथम महाकुल की समाप्ति होने पर यह आना की गई थी कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में जो विघटनका भा उपस्थित हुई है वह स्थायी नहीं होगी और शीघ्र ही व्यापार में कुछ पूर्ण की स्थिति फिर से आ जायगी। परन्तु यह आका पूरी नहीं हुई। इसका कारण यह था, एक के बाद दूसरी समस्याओं का निरंतर बढ़ा होना। फल-स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य को फिर से कथम करने की प्रत्येक योजनाएँ हुई

यहां तक कि सन् १९२४ के मुद्रा नीति में संस्कार के बाद भी व्यापार से नियंत्रण हटाना सम्भव नहीं हुआ। दूसरी लड़ाई के प्रारम्भ से इस विषय पर फिर से आलोचना शुरू हुई। सन् १९४४ की जनवरी में 'इकानामिष्ट' पत्रिका में तीन निबन्ध प्रकाशित हुये थे। पहले निबन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मूलमुद्दों पर आलोचना की गई थी; दूसरे निबन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन की समानता तथा तीसरे निबन्ध में विनियोग समस्या के साथ व्यापार का सम्बन्ध के बारे में विचार किया गया था।

गत कई वर्षों में प्रत्येक देश के विदेशी व्यापार पर लड़ाई का गहरा असर हुआ। लड़ाई के वक्त से ही सामग्रियों की कीमत बढ़ चुकी थी और यह मंहगाई अभी भी नहीं गई। इसके अलावा धीरे धीरे कई एक नई बातें दिखाई पड़ रही हैं। जिनमें से पैदावार की कमी, अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन की असुविधायें, टालर की कमी तथा युद्धकालीन अवस्था से साधारण अवस्था तक पहुंचने में असुविधाएं मुख्य हैं। सिर्फ अमेरिका को छोड़कर करीब दूसरे सभी देशों के विदेशी व्यापार में एक गहरा परिवर्तन चल रहा है। उपर्युक्त कारणों के अलावा भारत के विदेशी व्यापार पर अन्य और कई कारणों का असर पड़ा है जिनमें निम्नलिखित विषय उल्लेखनीय हैं;—साम्प्रदायिक झगड़ा, राजनैतिक परिवर्तन, सरकारी नीति की अनिश्चयता, श्रमिक असन्तोष, इत्यादि। होते हुये इन वर्षों में हमारी स्ट्रालिंग रकम इकट्ठी होनी तथा भारत का महाजन देशों में एक बन जाना भारत के लिये एक उल्लेखनीय घटना है लेकिन इस रकम को लौटाने के बारे में भी काफ़ी जटिलता उपस्थित हो रही है। सन् १९३८-३९ में हमारी आयात वाणिज्य की कीमत १५२ करोड़ रुपये थी वह १९४६-४७ में २७७ करोड़ रुपये हो गई। आयात वाणिज्य में जो सामग्रियां मंगवाई जाती हैं उनमें विशेष परिवर्तन नहीं हुआ वर्षों

कि इनमें प्रतिशत ६० शिल्प-उत्पाद हैं, प्रतिशत २० कच्चेमाल तथा कारखानों में लगनेवाली असम्पूर्ण सामग्रियां हैं तथा अवशिष्ट भाग अत्यंत प्रगृहीत हैं। पहले से अधिक कीमत की कलपुत्रों तथा भारी मशीनों मंगवाई जाती हैं लेकिन इतनी कीमत इतनी बढ़ी है कि उसी कीमतमें लड़ाई के पहले जितनी मशीनें मंगवाई जाती थीं उससे अब बहुत कम मंगवाई जा सकती हैं। सन् १९३८—३९ में हमारे निर्यात वाणिज्य की कीमत १६३ करोड़ रुपये थी, सन् १९४६—४७ में यह २९९ करोड़ रुपये हुई। लड़ाई के वक्त भारत की सामग्रियां इंग्लैण्ड, ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे देश तथा प्राच्य के कई देशों में भेजी जाने लगीं जिससे हमारा निर्यात वाणिज्य बहुत बढ़ गया। हमारे निर्यात वाणिज्य में विभिन्न सामग्रियों का हिसाब निम्न प्रकार था:—शिल्प सामग्रियां सन् १९३८—३९ में प्रतिशत २९, १९४६—४७ में प्रतिशत ४७, कच्चेमाल तथा सम्पूर्ण सामग्रियां १९३८—३९ में प्रतिशत ४४, १९४६—४७ में प्रतिशत ३१। हमारे निर्यात वाणिज्य में कच्चेमाल का हिस्सा कम करने का उत्तरदायित्व सरकार के 'अनाज की पैदा बढ़ाओ' प्रचार पर है क्योंकि इससे कच्चेमाल की पैदा बहुत ही घट गई। परन्तु इस पर भी हमारा निर्यात वाणिज्य अत्यंत बड़े सामग्रियों के आधार पर ही निर्भर है, जैसे कि पाट तथा पाट से बनी हुई सामग्रियां, चाय, दूध, नमक, तिलहन, आदि। ये हमारे निर्यात वाणिज्य के प्रतिशत ६० हैं। लड़ाई के कई वर्षों बाद हमारा विदेशी व्यापार करीब करीब दुगुना हो गया है। सन् १९३८—३९ में इसकी कीमत ३२१ करोड़ रुपये थी, १९४६—४७ में यह ६०४ करोड़ रुपये हुई।

हमारे विदेशी व्यापार की गति की निम्नलिखित बातों से साफ पटल गई है। हमारे विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में ब्रिटिश साम्राज्य के मर्यादित अब बहुत कम हो गया है, तथा फ्रांस, जर्मनी, ईटली प्रभृति देशों से हमारा व्यापार विस्तृत बन्द हो गया है। दूसरी ओर अमेरिका के संयुक्त राज्य, मैक्सिको, आस्ट्रेलिया, मध्यप्रान्तदेश, दक्षिण अफ्रीका तथा

के साथ हमारा व्यापारिक सम्बन्ध काफी बढ़ रहा है। हम ब्रिटेन तथा युक्राज्य से औजार लोहा तथा इस्पात हथियार कल पूजा दवाइयाँ आदि मंगवाते हैं; मोटर गाड़ियाँ ब्रिटेन युक्राज्य तथा कैनाडा से आती हैं, खनिज तेल युक्राज्य मध्य प्राच्य देश तथा बर्मा से, लम्बे रेडोवाली रुई मिशर तथा उत्तरी अफ्रीका से, कागज तथा बोर्ड कैनाडा ब्रिटेन, युक्राज्य तथा स्कोटलैंड से एवं अनाज युक्राज्य कैनाडा, अर्जन्टाइन बर्मा तथा अष्ट्रेलिया से मंगाया जाता है। लड़ाई के पहले जर्मनी तथा जापान काफी परिमाण में औजार लोहा तथा इस्पात, रसायनिक पदार्थ तथा दूसरे शिल्पजात सामग्रियाँ भेजा करते थे लेकिन लड़ाई के वक़्त इससे हमारा व्यापारिक सम्बन्धका विच्छेद हो गया। लड़ाई नष्ट होने के बाद जापान फिर से भारत के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। भारत के निर्यात बाणिज्य में जो सब सामग्रियाँ महत्त्व रखती हैं उनका बाजार करीब पृथ्वी के विभिन्न देशों में है, इसका कारण यह है कि इन सब में बच्चे मालकी बाहर में काफी खपत होती है। लड़ाई के सुयोग में भारत की शिल्पजात सामग्रियों के लिये अष्ट्रेलिया, मध्यप्राच्य देश तथा उत्तरी अफ्रीका में नये बाजार खुले हैं जो लड़ाई के पहले जापान के एकाधिकार में थे।

लड़ाई नष्ट होने के साथ ही साथ भारत सरकार ने विदेशी व्यापार पर जो नियंत्रण रखा था उसे उठा लिया ताकि बहुत दिनों से दूरी हुई माँग पूरी हो सके तथा मुद्रास्फीति के दुष्परिणाम को कुछ हद तक रोका जा सके। इसका नतीजा यह हुआ कि विदेश से जरूरी सामग्रियों के साथ दूसरी बहुत सी सामग्रियाँ काफी ताबड़तोड़ में आने लगीं और हमारी स्टालिंग रकम कम होने लगी। इसलिये सरकार को फिर से व्यापार बाणिज्य पर नियंत्रण लगाना पड़ा ताकि स्टालिंग रकम के विनिमय में फिर दूसरी सामग्रियाँ ही मंगाई जायें। स्टालिंग रकम को संवित करने में हमें काफी

कष्ट उठाना पड़ा था ; इसलिये सिर्फ देश के आर्थिक विकास करने में ही इसका उपयोग होना चाहिये । इस वस्तु पृथ्वी के विभिन्न देशों में उालर की कमी चल रही है और अपने आर्थिक विकास के लिये भारत को साम्राज्यिक उालर संचिति से जो उालर मिलता है वह बहुत ही कम है । इसलिये भारत को ऐसा प्रयत्न करना पड़ा जिससे उालर उालर में पूरा फायदा उठाया जा सके । निर्यात वाणिज्य के बारे में सरकार की नीति यह रही कि जहां तक हो सके कच्चे माल के विनिमय से अनाज तथा दूसरी जल्दी सामग्रियां मंगवाई जायें ।

भारत विभक्त होने पर भारत के हाथ से वे दो वस्तुएं निकल गई हैं जिनसे भारत को सबसे अधिक विदेशी निर्यात प्राप्त होता था । ये पाट तथा रुई हैं । इनकी पैदावार अधिकांश में पाकिस्तान में होती है । सन् १९४६-४७ में १६ लाख गांठ पाट तथा ४६ लाख गांठ पाट से बनी हुई सामग्रियां बाहर भेजी गई थीं जिनकी कीमत ८६ करोड़ रुपये थी । यह हमारे निर्यात वाणिज्यका प्रतिशत २७ था । भारत विभक्त होने के बाद पाट की पैदावार प्रतिशत ७५ पाकिस्तान के हिस्से में आई लेकिन पाट के सारे कारखाने भारत में स्थित हैं । पाकिस्तान के हाथ में ज्यादातर पाट रहने के कारण हमारे पाट शिल के मानने कच्चे माल की कमी की समस्या था उपस्थित हुई है तथा विदेशी व्यापार में भी काफी सुधार पहुंचा है । पाट की तरह रुई, ऊन तथा चमड़े की पैदावार भी पाकिस्तान में ही अधिक है । रुई की कुल पैदावार का ६ पाकिस्तान को मिल गया कि ४५.१ करोड़ के कारखानों में केवल १४ पाकिस्तान के हिस्से में आए हैं । लम्बे रेडिकलो रुई तो अफिराँस में पाकिस्तान में ही उपजती है । भारत विभक्त होने के कारण हमारे विदेशी व्यापार में करीब २५ करोड़ रुपये का सुधार हुआ है ।

इस प्रसंग में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के वर्धन के बारे में इस प्रकार

उचित होगा। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए तथा इस पर जो रुकावटें लगाई जाती हैं उन्हें जहाँ तक हो सके बढ़ाने के लिये कुछ दिन पहले जेनिवा में विभिन्न राष्ट्रों का एक आम जलसा हुआ था जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विनियोग के बारे में एक अन्तर्राष्ट्रीय योजना खड़ी की गई। सम्मोद किया जाता है कि भविष्य का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार इस योजना के आधार पर प्रतिष्ठित होगा। इस योजना में पिछड़े देशों के आर्थिक विकास पर महत्व दिया गया है। यह भी माना गया है कि पिछड़े हुए देशों की आर्थिक उन्नति के लिये कुछ हद तक सरकारी सहायता एवं संरक्षण की आवश्यकता है। पिछड़े हुए देशों की आर्थिक उन्नति में उन्नतिशील देश हर एक ही मदद करेंगे ताकि अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य के वित्तार में मदद पहुंच सके। केवल विदेश स्थिति में ही सदाय देश अपने आयात वाणिज्यका नियंत्रण कर सकेगा। मुद्राविनिमय दर को सुस्थिर करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य संस्था को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राशोध के साथ पूरा सहयोग करना पड़ेगा। इस जलसे में भारत ने भी हिस्सा लिया था एवं कई देशों के साथ व्यापारिक समझौता भी हुआ। इन देशों के साथ समझौता करते समय हमारी आर्थिक तथा औद्योगिक दुर्बलताओं पर ध्यान दिया गया। आयात-नियंत्रण कर कम करने के बारे में निम्नलिखित ३ बातों पर महत्व दिया गया है—(१) दूसरे देशों की दिया हुआ अधिकार या सुविधा हमारे आर्थिक स्वार्थ के अनुकूल हो या प्रतिकूल न हो, (२) सुरक्षित उद्योग पध्दों या जो उद्योग-धन्धे आगामी ३ वर्षों में संक्षिप्त होने उनके बारे में किसी भी देशको सुविधा नहीं दी जायगी तथा (३) दूसरे देशोंको सुविधा देने के कारण सरकारी आमदनी में घाटा न हो, इस विषय पर भी ध्यान दिया गया है। भारत तथा पाकिस्तान को इन समझौते से निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे—सन् १९४४-४५ की संस्था के अनुसार भारत तथा पाकिस्तान

३१ करोड़ रुपये कीमत की माल के आयात पर सुविधा देना मंजूर किया । इसके बदले में हमें ३५ करोड़ रुपये कीमत की निर्यात पर सुविधा मिलेगी । इसके अलावा भारत तथा पाकिस्तान को लगभग १३ करोड़ रुपये के निर्यात पर परीक्षा सुविधा मिलेगी ।

रुपये का मूल्य हास तथा हमारे विदेशी व्यापार पर उसके असर—
(रुपये का मूल्य हास विषयक निबन्ध देखिए)

वर्तमान समयमें भारतके निर्यात वाणिज्यको बढ़ानेकी आवश्यकता है क्योंकि अभी हमारी ख़ासस्थितिके भुगर्भमें फौफो समय लगेगा तथा औद्योगिक विस्तारके लिए भी हमें बहुतसे साधनों की विदेश से नंगारना पड़ेगा । हमारी स्टालिंग रकम इनके लिए बहुत कम है और उमराज जो हिस्सा हम व्यवहारमें ला सकते हैं वह और भी कम है । इसलिए हमको अपने निर्यात वाणिज्यको बढ़ाने की विशेष आवश्यकता है । जो मरतुर् हमारे निर्यात वाणिज्यमें मदद रखती हैं उनको पैदावार बढ़ानेका प्रयत्न करना पड़ेगा तथा दूसरे देशों के साथ व्यापारिक समन्धीता करनेके वक़्त जिसमें दूसरे देशोंमें इनकी ख़पत बढ़ सके, उस विषय पर ध्यान देना होगा । भारतके लिए अमेरिका में बनी हुई सामग्रियाँ विशेष जरूरी हैं इसलिए अमेरिकाके साथ हमारे निर्यात वाणिज्यको बढ़ाने की विशेष आवश्यकता होगी । हमारे यहाँ बनी हुई विलासकी सामग्रियों का बाजार अमेरिका में बहुत अच्छा है । इसके अग़र हम पूरा फायदा उठा सकें तो हर साल हमें लाखों डॉलर की प्राप्ति हो सकेगी । भारतके मार्केट वाणिज्यका नज़रिया भी उज्जवल है । इसके अलावा भारत की तरफ़ एक निश्चित देश विदेशी भ्रमणकारियोंके लिए बहुत आकर्षण रखा है; अगर इसके बारेमें बक़रीति प्रचार किया जाय तथा विदेशियों के रहनेवाले उपयुक्त प्रयत्न किए जाय तो इसके भी हमें लाखों विदेशी निर्यात की आपनदनी हो सकती है । अन्तमें यह कहना ठीक है कि हमारे निर्यात वाणिज्य को बढ़ाने के लिए पैदावार को बढ़ाने की चेष्टा करनी होगी ।

अभी तक हमारी पैदावार घटती जा रही है ; पहले तो इसकी रोकना होगा और बाद में पैदावार बढ़ाने का प्रयत्न करना होगा ताकि हम ज्यादा ताबदाद में सामग्रियां बाहर भेज सकें ।

हमारे स्टार्लिंग पावने

प्राचीनकालसे आयात वाणिज्यसे निर्यात वाणिज्यकी अधिकता हमारे विदेशी व्यापारकी एक विशेषता है। इस अनुकूल वाणिज्य परिमाणके कारण भारत एक समय सम्पत्तिशाली देशोंमें गिना जाता था । पिछले दो सौ वर्षोंसे हमारे विदेशी व्यापारका ढाँचा नष्ट हो गया है एवं साम्राज्यवादी शोषणके कारण अनुकूल वाणिज्य परिमाण होते हुए भी हम बराबरके देनदार ही रहे । दूसरी लड़ाई शुरू होनेके बाद आयात वाणिज्य करोड़-करोड़ घट गया एवं निर्यात वाणिज्य बहुत ज्यादा बढ़ गया । इस प्रकारसे जो रकम भारतके हाथने आई उससे पहले तो इंग्लैण्डमें हमारा जो कर्ज था वह चुकाया गया एवं उसके बाद स्टार्लिंग रकम इंग्लैण्डमें हमारे हिसाबमें जमा होने लगी । दूसरी लड़ाई के अन्तमें यह रकम लगभग १६०० करोड़ रुपये भी जिसमें १५३५.३१ करोड़ रुपये कोमत के साख्तपत्र तो रिजर्व बैंक के नोटकारी विभागमें थे और ४८६ करोड़ रुपये कोमतके साख्तपत्र बैंकिंग विभागमें थे ।

हमारी स्टार्लिंग रकमका इतिहास बहुत ही विचित्र है और भारतीय आर्थिक स्थिति पर इसका नुंभीर असर पड़ा । आयातसे निर्यात अधिक होनेके कारण स्टार्लिंग रकमकी उत्पत्ति हुई । व्यापारका सामान्य नियम यह है कि हम जिस देशसे सामान खरीदेंगे उसी देशका रिफा हमें देना पड़ेगा लेकिन हमारे देशके मालके लिये यह नियम घिलड़ल परिचित कर दिया गया ।

इंग्लैण्ड जब भारतसे सामान नही देता था तब विनिमयने रुकना देना उसके लिये उचित होता लेकिन इंग्लैण्डने रुकना नहीं देकर स्टार्लिंग दिया और वह भी उसी देशमें जमा होता रहा । रिजर्व बैंक-कानून के अनुसार रिजर्व बैंकको नोट जारी करनेका एकाधिकार प्राप्त है परन्तु नोटोंके लिये बैंकको एक सुरक्षित कोष रक्कत पड़ता है जिसमें विधानानुसार कुछ स्टार्लिंग तथा रुपये सम्बन्धी साक्ष्यपत्र रक्कत जा सकते हैं; परन्तु युद्धके समयमें साक्ष्यपत्रको मात्रा अपरिमित कर दो गई । इस समय भारत तथा इंग्लैण्डकी सरकारकी धोरसे युद्ध सम्बन्धी साक्ष्यपत्रों निर्धारित नूतन पर भारतमें जारी की गईं । ब्रिटिश सरकारने इसके लिये साक्ष्यपत्र देते रहें जिनके आधार पर रिजर्व बैंकको नोट छापकर भारत सरकारको देना पड़ा । इस प्रकारसे हमारे स्टार्लिंग साक्ष्यपत्र इंग्लैण्डमें जमा होते रहे और भारतमें मुद्रा प्रसार होता रहा । इसका जो क्षतिकारक प्रभाव पड़ा उसके हम भव्योन्माति परिचित हैं । इंग्लैण्डको इस नीतिके काफी सुविधा हुई क्योंकि वहां हमारी इकट्टी स्टार्लिंग रक्कत कम व्याज पर ब्रिटिश सरकारको मिलने लगी और उन्हें मुद्रा प्रसारकी भी आवश्यकता नहीं हुई । भारतका सामान जाता रहा, भारतकी रक्कत इंग्लैण्डमें फंस गई, भारतमें सामग्रियोंकी कमी तथा मुद्रा प्रसारके कारण एक रतारनाक स्थितिही उत्पत्ति हुई । परिणाम यह हुआ कि सामग्री-कम तो भारतमें बहुत बढ़ गया लेकिन वस्तुएं नहीं बढ़ीं । पैदावार बढ़ानेके लिये उत्पादन सामग्रियोंकी आवश्यकता थी जो लड़ाईके कारण भारतमें नहीं आ सकी । सरकारी युद्ध-उद्यम बढ़ता गया, नोट छपती गईं, सामग्रियोंका मूल्य स्तर बढ़ता गया और स्टार्लिंग रक्कतकी मात्रा में वृद्धि होती गई । हमारी धोर इंग्लैण्डको नकद-कीमत देने बिना जरूरी सामग्रियां मिलती रही, रक्कत भी हममें मौजूद रही, मुद्रा प्रसार भी न हुआ और न सामग्रियोंकी कीमतमें ही विशेष परिवर्तन हुआ । इंग्लैण्ड केवल एक जबरन देता हमारी रक्कत प्रिय तरफसे फंस गई हममें महज-जब होने हुए भी हमारी अर्थिक स्थिति में उन्नति नहीं हुई । निरंकुशता ही नहीं बल्कि इस रक्कत के

उपयोग के बारे में जो हमारा अधिकार बहुत ही सीमित रहा और किस प्रकार से हम इस रकम को व्यर्थ कर सकते हैं यह एक भारी समस्या बन गई ।

हमारे स्टालिंग पावने के बारे में इंग्लैंड के बहुत से प्रमुख व्यक्ति तथा आर्थिक पत्रों को राय यह थी कि भारत को यह रकम पूरी नहीं मिलनी चाहिये । इनका कहना यह था कि इंग्लैंड ने भारत को जामानी आक्रमण से बचाया है । इसलिये युद्ध व्यय का कुछ हिस्सा भारत को देना उचित होगा । मैनेचेस्टर गार्डियन, किनान्सियल टाइम्स आदि पत्रों में ऐसे विचार प्रकाशित हुये हैं तथा बृटेन अमेरिका ऋण सम्बन्धी सम-मोते की धारा १० के अनुसार भी ऋण में कमी करने का धरेंत है परन्तु भारतीय उद्योगपति तथा अर्थ-विशेषज्ञ अपने इस विचार में अटल हैं कि बृटेन पर इस ऋण का पूर्ण उत्तरदायित्व है । जहाँ तक कि बृटेन वट्स कनफरेन्स में भारत के एक सदस्य ने कहा था कि जहाँ तक भारतीय मतका सम्बन्ध है वहाँ तक यह बात निर्विवाद है कि यदि इस समस्या को सुलझाने का कोई उपाय नहीं निकला तो हमारा देश प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषका सदस्य होना स्वीकार करेगा या नहीं, इस बात पर विचार करेगा । स्टालिंग रकम का प्रदान हमारे लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है । भारत के साथ इंग्लैंड का जो आर्थिक समन्धिता हुआ था उसके अनुसार भारत पहले ही युद्ध व्यय का अपना भाग दे चुका था । स्टालिंग पावने के साथ युद्ध व्यय का तनिक भी सम्बन्ध नहीं है । हमारी सामग्रियाँ जो कि इंग्लैंड को मदद पहुँचाने के लिये भेजी गई थीं यह स्टालिंग उनकी कीमत है और इन पर भारत का पूर्ण अधिकार है ।

स्टालिंग रकम का उपयोग किस प्रकार से किया जाय इसके बारे में लड़ाई के वक्त से ही वाद-विवाद चल रहा है । किसी किसी को यह राय थी कि हमारी सारी रकम को स्टालिंग के आकार में रखा जाना चाहिए

योग्य क्यों कि स्टालिंग का भविष्य अनिश्चित है। इसके अलावा सभी रक्तन स्टालिंग के रूप में रहने से हम दूसरे देशों से जल्द सामग्रियाँ नहीं मँगवा सकेंगे। इनका कहना था कि हमारी रक्तन का बड़ा हिस्सा यदि उत्तर के रूप में रहे तो हम जितने देश से चाहें सामान मँगवा सकते हैं लेकिन अनेक कारणों से ऐसा प्रबन्ध सम्भव नहीं हुआ। केनडा, अष्ट्रेलिया, अफ्रीका प्रभृति देशों ने अपने स्टालिंग के विनिमय में इंग्लैण्ड का जो कारदार इन देशों में था उन्हें खरीद लिया है। औद्योगिक विकास में भी इनकी स्टालिंग रक्तन लग चुकी है। इस प्रकार से इन सब देशों के उपयोग-धन्यों से विदेशी प्रभुत्व हट गया है। हमारा देश विदेशी हुकूमत के कारण इस प्रकार का फायदा नहीं उठा सका। सामग्रियों के विनिमय से इंग्लैण्ड भारत को सोना दे सकता था जिससे स्टालिंग के बारेमें सभी जो समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं वे नहीं हो पातीं लेकिन इंग्लैण्ड ने यह भी नहीं किया। किसी किसी का कहना था कि इंग्लैण्ड के पास सोना था ही क्या? बात सच है, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहना होगा कि कुछ दिन बाद इंग्लैण्ड ने अफ्रीका के सोने से भारत में आरक्षण करके काफी फायदा उठाया, पर सोना इंग्लैण्ड भारत को दे सकता था। जो भी हो यह सोना अगर हमें सामग्रियों के विनिमय में प्राप्त होता तो आज हमें जितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वह न होता और हम जितने देश से चाहें सामग्रियाँ खरीद सकते।

हमारी स्टालिंग रक्तन फट प्राप्त सम्पत्ति है और उसका अनुचित उपयोग होना विशेष जरूरी है। आज हमारे औद्योगिक उत्पादन की विभिन्न योजनाएँ मजदूरों-कर्मियों के अभाव से केवल कामची योजनाएँ ही चल रही हैं। इनको पर्याप्त करने के लिये यह रक्तन एक बड़ा साधन है लेकिन इंग्लैण्ड को अवरुद्ध ऐसी नहीं है कि वह हमें आवश्यकता-मुसार मजदूरों-कर्मियों दे सके। इसलिए हमारा ध्यान उन देशों की ओर जाना है

जो हमें बंत्रोपकरण दे सकते हैं, लेकिन इन देशों से वस्तुयें मंगाने के लिये हमें स्टालिन के स्थान में उन देशों का विद्या चाहिये। अतः जब तक हमें अन्य देशों से बंत्रोपकरण मंगाने के लिये बड़े-बड़े विनिमय प्राप्त नहीं होता तब तक किसी रचनात्मक योजना का कार्यान्वित होना असम्भव है।

दूसरी लड़ाई खतम होने के बाद कुछ दिन तक भारत भी बिना किसी रुकावट के सहायता से उपभोग वस्तुयें मंगाने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इस सुयोग से बहुत सी चेन्नार सामग्रियाँ भी आने लगीं और स्टालिन स्वयं जल्द से जल्द घटने लगीं। जनवरी १९४७ में भारत और इंग्लैण्ड में हुए आर्थिक समझौते के अनुसार भारत को यह अधिकार दिया गया था, साथ ही साथ स्टालिन को डालर अथवा अन्य निद्रों में परिवर्तित करने का भी उसको अधिकार था परन्तु वह समझौता अधिक दिन तक चला नहीं रहा। उसी साल अमेरिका के साथ इंग्लैण्ड का जो आर्थिक समझौता हुआ उसके अनुसार स्टालिन के द्वारे में इंग्लैण्ड के साथ भारत, अमेरिका-इन, मिशर प्रभृति देशों को नए सिरे से समझौता करना पड़ा। सन १९४७ के अगस्त महीने में भारत और ब्रिटेन के बीच एक दूसरा समझौता हुआ जिसकी अवधि ६ महीने की थी। सन १९४८ के जनवरी में उसका फिर ६ महीने के लिये नवकरण किया गया। इस समझौते के अनुसार इंग्लैण्ड के केन्द्रीय बैंक में रिजर्व बैंक के नाम से २ ट्रिलियन खोले गये। हर साल अनुकूल वाणिज्य से हमें जो स्टालिन प्राप्त होगा तथा हमारी जमा स्टालिन रकम से जितनी स्टालिन उपयोग करने का अधिकार भारत को मिलेगा वह नम्बर १ ट्रिलियन में रखा गया तथा पहले का इच्छा स्टालिन जिसका कि भारत अधिक उपयोग नहीं कर सकता उसको नम्बर २ ट्रिलियन में रखा गया। नम्बर १ ट्रिलियन में जो स्टालिन लगेगा उसको भारत उपयोग कर सकेगा। इस समझौते के साथ ही साथ भारत सरकार ने अपना

वाणिज्य पर कुछ रुकावटें लगा दी हैं जिन्हें कि सिर्फ वही समझेंगे संगीत जायें जो विशेष जरूरी हैं। इस समझौते की अवधि भी जून १९४८ में पूर्ण हो जाती थी। अतः नए समझौते की जरूरत हुई जिसमें निम्नलिखित ३ बिन्दु सूच्य थे:—(१) फौजों सामान आदि का मूल्य—वर्तमान समझौते के अनुसार भारत सरकार इनके मूल्य शोधनार्थ १३३ करोड़ रुपये की स्टालिंग दे दो; (२) अवसर प्राप्त कर्मचारियों के लिये बर्षिक—इन यूरोपियन पदाधिकारियों को देनेके लिये भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार से १९७ करोड़ रुपये की एक बर्षिक वृत्ति माँगी है जो हमारे स्टालिंग पावनों में से कम कर ली जायगी; (३) रक्षा का भेष बदलना—इसके अनुसार अविभाजित भारत सरकार को ७३ करोड़ रुपये की राशि ब्रिटेन से प्राप्त हुई है। पिछले समझौते के अनुसार भारत को १११ करोड़ रुपये की स्टालिंग रकम बढ़ाने का अधिकार था परन्तु उसमें से ४ करोड़ का उपयोग हुआ था। अतः अवशिष्ट १०७ करोड़ रुपये के स्टालिंग बढ़ाने का भारत को अधिकार है। इसके अतिरिक्त अगले ३ वर्षों के लिये ब्रिटेन १०७ करोड़ रुपये की स्टालिंग रकम चुकाने को तैयार हुआ है। संक्षेप में तीन वर्ष बाद सन् १९५१ के जून में ब्रिटेन भारत का केवल ५८६ करोड़ रुपये का देनदार रह जायेगा। पहले दो बातें गद्या है कि भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिये टालर सम्पन्न देशों से सामान मँगानेकी आवश्यकता है; जिसके लिये टालर की आवश्यकता होगी। अतः समझौते के अनुसार भारत को २० करोड़ रुपये के स्टालिंग की किसी भी अन्य विधि में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है।

स्टालिंग समझौते के तारे में इन देश में काफी चर्चा हुई है एवं भारत में इसका विधित स्वरूप हुआ है। श्री मन्त्र मुद्देबाजी ने कहा है कि ब्रिटिश के छोड़े हुए फौजी सामान एवं प्रतिष्ठानों के लिये १३३ करोड़ रुपये देना अनिवार्य नहीं होगा लेकिन वास्तव में यह रकम ६७

अधिक नहीं प्रतीत होती और काश्मीर की लड़ाई में इसका काफी प्रयोग भी हुआ है। वार्षिकी के बारे में भी काफी समायोजन हुई है। विवादास्पद मुख्य शर्त तो आगामी ३ वर्षों में मिलनेवाली स्टालिंग रकम के बारे में है। इसका परिमाण बहुत ही कम है। सन् १९४७ के शेष ६ महीने में हमें ६५० लाख पाउण्ड तथा १९४८ के पहले ६ महीने में १८० लाख पाउण्ड उपयोग करनेका अधिकार मिला था जिसमें हम केवल ४ करोड़ रुपये कीमतकी स्टालिंग का ही उपयोग कर सके। इसलिए व्यापारीवर्ग तो सरकारी आयात नीति को दोषी ठहराते हैं और सरकार व्यापारीवर्ग को। आगामी ३ वर्षों में हमें कुल में ८०० लाख पाउण्ड स्टालिंग के उपयोग करने का अधिकार मिला है यानी प्रत्येक वर्ष में हम औसत पर लगभग २६६ लाख पाउण्ड स्टालिंग कीमत की सामग्रियाँ मंगवा सकेंगे। हमारी आवश्यकता के अनुपात से यह बहुत ही कम है। इंग्लैण्ड के लिये वार्षिक ४०० लाख पाउण्ड कीमत की स्टालिंग रकम चुकाना कोई कठिन बात नहीं है क्योंकि यह इंग्लैण्ड के निर्यात वाणिज्य का २॥ हिस्सा मात्र है एवं इंग्लैण्ड की जातीय आमदनी का ०.४५ हिस्सा है। इंग्लैण्ड के लिये यह रकम नाम मात्र है और इसको यदि वह ऋणशोध के रूप में देते रहे तो हमें इससे काफी फायदा होगा।

सन् १९४९ के जुलाई महीने में स्टालिंग रकम के बारे में फिर से एक नया समझौता हुआ है जिससे १९४८-४९ में सामान खरीदने के लिये ८१० लाख पाउण्ड भारत को दिया जायेगा एवं १९४९-५० तथा १९५०-५१ में वार्षिक ५०० लाख पाउण्ड भारत को मिलेगा; पुराने समझौते के अनुसार इसका परिमाण ४०० लाख पाउण्ड था। सन् १९४८-४९ में सामग्रियों के आयात के बारे में जो फरमाइशें दी गई हैं उसके लिये भी भारत को स्टालिंग दिया जायेगा। इनके अलावा केन्द्रीय स्थान्तर योग्य स्टालिंग कीमतें ८४० लाखकी स्टालिंग भारत को "मदद" के तौर पर लण्डन समझौते के

आधार पर मिलेगा एवं सन् १९४९ में टालर सम्बन्धित देशों से हमारा प्रतिशुल्क वाणिज्य परिमाण चुकाने के लिए १४० लाख पाउण्ड प्राप्त होगा। नए समझौते में भारत स्टालिंग इलाके के दूसरे देशों की तरह टालर सम्बन्धित देशों से प्रतिशत २५ आयात घटाना मंजूर किया है। साथ ही साथ भारत फिर से स्टालिंग इलाके का पूर्ण सदस्य बन गया है एवं वेन्ट्र व कोप से दुःप्राप्य सिफा उठाने के बारे में भारत पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया था नए समझौते में उसका अन्त कर दिया गया है।

सन् १९५१ के बाद हमारी थोड़ी सी रकम ही इंग्लैण्ड में बच पड़ेगी जिससे अधिक विदेशी रकम हमारे देशमें ही लगी हुई है। इस दृष्टि से इस रकम के टूटने की आशंका नहीं है परन्तु स्टालिंग की कीमत घटाने जाने पर भी इस रकम के लिये हम स्टालिंग का सम्यन्ध नहीं छोड़ सकें चाहे वह हमारे लिये कितना ही अनिष्टकारक क्यों न हो। मन्त्रोपकरणों के अभाव से भी हमारी स्टालिंग रकम का पूरा उपयोग नहीं हो सता है जिसके लिए सरकार नौ कुछ हद तक दायी हैं। उपलब्ध सामग्रियों से पूरा फायदा उठाने के लिये उद्योगपतिओं के साथ सरकार को हर तरह से सहयोग देना पड़ेगा। इस रकम को इकट्ठी करने में हमें बहुत सी कठिनाइयाँ सहनी पड़ी हैं; अब यदि हम इससे पूरा फायदा उठाकर अपने आर्थिक भविष्य को उज्ज्वल बना सकें, औद्योगिक विकास कर सकें, जनता के जीवन का स्तर ऊँचा कर सकें तो हम आतीत के सारे दुःख कष्टों को भूल सरेंगें। यदि किसी की नी गलती से ऐसा करना सम्भव नहीं हुआ और हम रकम को खर्चाई हुई तो हमें उत्तर-पुरतों के सामने जबाब देना पड़ेगा। इस महान उत्तर-दायित्व को सफ़ियत रखकर हमें स्टालिंग रकम का उपयोग करना चाहिये।

डालरकी कमी—मार्शल याजना

डालर की कमी का कारण—गत महायुद्ध में एशिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों में बहुत से उद्योग-धन्धे तथा सामग्रियां नष्ट हुईं भी युद्धोत्तर समय में इन सब देशों की आर्थिक पुनर्गठन के लिये विशेष आवश्यकता है। सभी देश अमेरिका से आर्थिक सहायता की आशा लगाये बैठे हैं क्योंकि आज अमेरिका एकमात्र महादेश है जो अपनी आवश्यकता से अतिरिक्त सामग्रियां पैदा करता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राक्षेप, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था—इनका उद्देश्य दुनिया के विभिन्न देशों को आर्थिक मदद पहुंचाना है। आर्थिक आवश्यकता की दृष्टि से दुनिया के विभिन्न देशों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं एक तो यूरोप के विभिन्न देश जहां लड़ाई के पहले काफी औद्योगिक विकास हो चुका था लेकिन लड़ाई के कारण इसमें हानी पहुंची, एवं दूसरी ओर एशिया के विभिन्न देश जहां आज आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। अमेरिका ही ऐसा एक देश है जो इन सब देशों को अनुचित सामान तथा धन देकर सहायता कर सकता है।

अमेरिका का विदेशी व्यापार—सन् १९४२ में अमेरिका के आयात वाणिज्य की कीमत ५१० करोड़ डालर थी तथा निर्यात वाणिज्य की कीमत १२० करोड़ डालर थी यानी आयात-निर्यात में अमेरिका के लिये ७२० करोड़ डालर अनुकूल विपमता थी। अमेरिका को विभिन्न देशों से जहां लड़ाई के सामान बेचे गये उसमें लगभग १०० करोड़ डालर पाने थे। सन् १९४८ में अनुकूल विपमता का परिमाण ५५४ करोड़ डालर था।

इंग्लैण्ड में डालरकी कमी—लड़ाई के वक्त इंग्लैण्ड के निर्यात वाणिज्य में कमी हो गई। अमेरिका के साथ इंग्लैण्ड का ऋण इजारा समझौता हुआ जिसके

द्वारा अमेरिका के युद्ध कालीन चौदहो इंग्लैन्ड तक कर दी गई एवं अमेरिका इंग्लैन्ड को सामरिक वस्तुएं भेजता रहा। सन् १९४५ में इंग्लैन्ड के साथ अमेरिका का एक ठोकर समझौता हुआ जिसके अनुसार इंग्लैन्ड को ३७५ करोड़ डॉलर कर्ज देना निर्दिष्ट हुआ। कैनाडा से इंग्लैन्ड को १२५ करोड़ डॉलर कर्ज मिला इस पर भी डॉलर की कमी चरती रही एवं ब्रिटिश सरकार को डॉलर सम्पन्नित देशों से सामान खरीदने पर नियंत्रण लगाना पड़ा। लड़ाई के वक्त ही इंग्लैन्ड ने साम्राज्यिक डॉलर संविधि नामक एक संस्था को कायम किया एवं लड़ाई के समय अनुकूल व्यापारिक विषयता के कारण भारत आदि जिन देशों के हाथ में डॉलर इकट्ठे होते थे उन्हें इस संविधि में आकर्षित किए। इस डॉलर के बदले में सरकारी स्टैलिंग डॉलर विनिमय दर के हिसाब से, जो कि बाजार दर से बहुत कम था भारत को स्टैलिंग दिया गया एवं इस स्टैलिंग के आधार पर भारत में मुद्रा प्रसार हुआ। (हमारे स्टैलिंग पावने विषयक नियन्त्रण देखिये)

डॉलर की कमी और मार्शल योजना—यूरोप के देशों के वार्षिक संगठन के लिये इस योजना को कायम किया गया ताकि डॉलर की कमी होती हुये भी इन देशों के वार्षिक पुनर्गठन के लिये कमरेकी सहायता मिलती रहे। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के सचिव जार्ज मार्शल के शब्दों में “यूरोप विपत्ति प्रसूत है.....अतः उसके सारे देशों के पुनरुद्धार के बिना वास्तविक पुनर्जीवन सम्भव नहीं। इस पुनरुद्धार के लिये पारसी सहायता आवश्यक है... और इसकी पूर्ति का उत्तरदायित्व अमेरिका के लोगों पर था पड़ा.....” अमेरिका के कोई साम्राज्यवादी अभिप्राय तो नहीं है, परन्तु यह कहना ठीक नहीं होगा कि बिना पुनरुद्धार के लिये अपने मतलब देने के बदले में अमेरिका की कोई अपनी मानी नहीं है।” मार्शल योजना का सार्वजनिक समर्थन अमेरीकी जनता का विस्तार करता है।

अमेरीकी सहायता की आवश्यकता—इस सहायता का धरिदर्य भाग

मार्शल योजना के हिसाब में इंग्लैण्ड तथा यूरोप को मिला है। एशिया के विभिन्न राष्ट्रों को भी आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। इन सब देशों की आर्थिक उन्नति होने पर ही अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पूरी तौर से कायम हो सकता है। इसके लिये अमेरिका की आर्थिक नीतिमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है जिससे दूसरे देशों का माल अमेरिकामें खरीदा जाय और व्यापार-विनिमय की समस्या सुलभ जाय।

भारतमें डालर की कमी—लड़ाईके वक़्त से भारत तथा ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे देशों की डालर रकम साम्राज्यिक डालर संवित में एकट्ठे की जाती है एवं ये देश इस रकम के एक मान्यो हिस्से को ही अपनी आर्थिक उन्नतिके लिये उपयोग कर सकते हैं। यदि हमें लड़ाई के वक़्त अपने डालर के विनिमय से अमेरिका से सामान मंगाने का अधिकार रहता तो हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा नहीं बिगड़ती कारण एक ओर तो डालर के बदले में हमें जो स्टालिंग रकम मिली वह भी वित्तघेत में जमा होती रही एवं उसके आधार पर भारत में मुद्राप्रसार चलती रही तथा दूसरी ओर यंत्रोपकरणों के अभाव से हम औद्योगिक विकास न कर सके। सन् १९४८ के पिछले ६ महीने में हमें ४०० लाख डालर तथा सन् १९४८ के जुलाई से १९४९ के जून तक ६०० लाख डालर उपयोग करने का अधिकार मिला था। युद्धोत्तर समय में अनाज तथा दूसरी सामग्रियां आती रहीं और व्यापार की प्रतिकूल विपत्ति बढ़ती रही। देश विपन्न होने के कारण रुई, पाट, चमड़ा आदि जो डालर प्राप्त करने के मुख्य साधन थे वे भी हमारे हाथ से जाते रहे। हमारी आर्थिक योजनाओं को मजबूत-सिद्ध बनाने के लिये भी हमें डालर ही की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान समय में अमेरिका एक मात्र देश है जो दूसरों को सामान दे सकता है।

डालर संकट का सुझाव—यह समस्या तबही हल हो सकती है जबकि पृथ्वी के विभिन्न देशोंमें पर्याप्त सामग्रियां बनने लग जयें। साथ ही साथ

उद्योग-धन्यों को संरक्षित किए बिना तत्कालीन भारतीय आर्थिक स्थिति में उद्योग-धन्यों का द्रुत विकास होना असम्भव है ।

संरक्षण नीति का समर्थन करते हुए इस कमीशन ने इस विषय पर काफी प्रकाश डाला । कमीशन का कहना था कि भारत सरकार को अनाथ वाणिज्य नीति के कारण तथा पाश्चात्य के समृद्ध उद्योग-धन्यों की प्रतिस्पर्धा से भारतीय उद्यम पर पानी फिर रहा है । भारत में शिल्पज सामग्रियों की काफी खपत है; भारतमें विभिन्न प्रकार की कच्ची सामग्रियों की पैदावार होती है; भारतीय खनिज सम्पद अतुलनीय है ; जलविद्युत उत्पादनका बड़ा साधन हमारे पास है; हमारे पास काफी मजदूर हैं जिनकी निपुणता औद्योगिक शिक्षा के द्वारा बढ़ाई जा सकती है; भारतमें वैश्वक पूंजी का बनाव दिखाई पड़ रहा है लेकिन इसका दायित्व वर्तमान स्थिति पर है । भारत में संतुलित अर्थव्यवस्था को कायम करने के लिए औद्योगिक विकास की आवश्यकता है, जिसमें तरद-ताद के कारखाने भारत के विभिन्न प्रान्तों में स्थापित किए जाय । इन्हें बाल्यावस्था में संरक्षित करना पड़ेगा । भारत में औद्योगिक यंत्रोपकरणों की पैदा करने के लिए मूल शिल्प जैसे की लोहा तथा इस्पात के कारखाने, रासायनिक सामग्रियां पैदा करने वाले गिअर आदि स्थापित किए जाय इन्हें भी संरक्षित करने की आवश्यकता होगी । इनके अलावा जिन उद्योग-धन्यों पर विदेशी अनुचित प्रतिस्पर्धा का घुरा असर पड़ रहा है उन्हें भी संरक्षित करना होगा, आर्थिक सहायता देनी होगी । देश रक्षा के लिए आवश्यक उद्योग-धन्यों को संरक्षित करने के प्रश्न पर भी इस कमीशन ने महत्व दिया ।

संरक्षित शिल्प व्यवस्था में जो त्रुटियां रहती हैं तथा इससे उद्योग कारियों को जो कष्ट उठाना पड़ता है इनके बारे में कमीशन धनधान न थी । इनको रोकने के लिये कमीशन ने एक नई संरक्षण नीति पर महत्व

दिया जिससे बिना बिचारे किसी भी उद्योग को संरक्षित नहीं किया जावेगा। सिर्फ वही उद्योग-धन्यों संरक्षण के अधिकारी बनेंगे जिनकी विदेशी प्रतियोगिता से अनुविधायें हो रही हैं; इन्हें यदि कुछ दिन तक संरक्षित दिया जाय तो वे विदेशी प्रतियोगिता के सम्मुखिन हो सकेंगे। संरक्षण की माया भी सोच विचार कर स्थिर करनी होगी ताकि वह न तो अत्यधिक हो और न बेकार रहे। संरक्षण निदिष्ट काल तक दिया जायगा तथा इसे क्रमानुसार उठा लिया जायगा। यह नीति वैज्ञानिक या पक्षपातयुक्त संरक्षण नीति के नाम से परिचित है।

किसी भी उद्योग-धन्योंको संरक्षित करने के पहले जांच निकलनेके लिये एक संस्था यानी टेरिफ बोर्ड स्थापित किया जावेगा। इसका विद्यमान निम्न ३ विषयों पर आधारित होगा :—

(१) सिर्फ उन्हीं उद्योग-धन्यों को संरक्षित दिया जाय जिनके लिये आवश्यक साधन, मजदूर तथा बाजार भारतमें मिल सकते हैं; (२) वे उद्योग-धन्य ऐसे होंगे जिनके संरक्षित किए बिना उनकी उन्नति असम्भव है, उनका विकास जल्द न हो सकेगा, (३) वे उद्योग-धन्य ऐसे होंगे जो कुछ दिन संरक्षित होने पर विदेशी प्रतिस्पर्धा के सम्मुखिन हो सकेंगे। भारत सरकार ने संरक्षण के बारे में किसकल कमिशन के दून् विद्वान्तों को प्रश्न किया। इस नीति के अनुसार जिन उद्योग-धन्यों को संरक्षित किया गया है वे निम्न प्रकार के हैं :—लोहा तथा इस्पात का कारखाना, कारख. चीनी, दामन, दामन का मंड तथा दियाछलाईयां उत्पादन करनेवाले कारखाने। कारखाने में संरक्षण के बिना दून् उद्योग-धन्यों का टिकना असम्भव था। सिर्फ वही नहीं बल्कि संरक्षण के आचार पर चीनी पैदा करनेवाले दानेक कारखाने भारत में हो चुके हैं। सन् १९३०—३१ में भारत में चीनी पैदा करने वाले कारखानों की संख्या ३२ थी जिनकी पैदावार १ लाख ५८ हजार टन की थी। इस साल भारत में १० लाख टन चीनी विदेश से आई थी।

सन् १९३६—३७ में भारत तथा ब्रह्म देश में १३७ चीनी के कारखाने स्थापित हो गये जिन्होंने ११ लाख ११ हजार टन चीनी की उत्पत्ति की। इससे यह सुस्पष्ट हो रहा है कि भारत में संरक्षण की कितनी आवश्यकता थी। संरक्षण के आधार पर टाटाका कारखाना इतना बन्दोबस्त का घन गया; हमारे वस्त्र शिल्प पर जो व्यापारिक मंदी की पूरी चोट न आ सकी।

वैज्ञानिक संरक्षण नीति के पक्ष में कहने को बहुत सी बातें हैं लेकिन इनके विपक्ष में भी बहुत सी बातें हैं। बिना विचारे किसी भी उद्योग को संरक्षित करना क्षति कारक है; लेकिन “वैज्ञानिक संरक्षण” नीति से भारत की विदेशी हुकूमत को यह सुविधा मिली कि वह अपनी उच्छास्नकार उद्योग-धन्यों को संरक्षित करने लगी लेकिन भारतीय आर्थिक विकास की दृष्टि से नहीं। संरक्षण के बारे में सलाह देने का काम टेरिफ बोर्ड का था लेकिन इस सलाह के अनुसार काम होगा या नहीं इसका निर्णय करने का पूरा अधिकार भारत सरकार का रहा। इसलिये जिन उद्योग-धन्यों का विकास इंग्लैन्डकी साम्राज्यिक नीतिका विरोधी था जैसे कि मूलशिल्प, देश रक्षा शिल्प, यातायात साधन पैदा करने वाले शिल्प आदि इन्हें संरक्षण नीतिकी सहायता न मिली। संरक्षण नीति के साथ साम्राज्यिक रियायत की नीति प्रदण हो गई जिससे भारतीय व्यापार की धारा कृत्रिमता के साथ साम्राज्यिक देशों की ओर कर दी गई। इस कारण से भी भारतीय उद्योग-धन्यों को विदेशी नये उद्योगों को इस नीति से पूरा फायदा न हुआ। इसके अलावा विदेशी मूलधन के आयात तथा भारत में विनियोग पर कुछ भी निर्बन्धन न था। इससे जिन उद्योग-धन्यों को संरक्षित करने के लिये प्रवन्ध किया गया उनमें विदेशी पूंजी का विनियोग हुआ और इससे भारतीय उद्योग पर चोट पहुंची। दियासलाई पैदा करनेवाला शिल्प इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस तरह से साम्राज्यिक दबाव के कारण सरकारी संरक्षण नीति ने भारतीय उद्योग पूरा फायदा न उठा सका।

लड़ाई शुरू होने के बाद उद्योगपतिगणने सरकार से संरक्षण नीति को सशर्त करने के लिये कहा, लेकिन यह मांग बहुत दिनों तक उपेक्षित रही। अन्त में सरकार ने यह घोषित किया कि जो उद्योग-धन्य लड़ाई के वक्त प्रधानतः लड़ाई के लिये स्थापित किए जायेंगे उन्हें मुद्दोत्तरे समय में विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिये जितनी संरक्षण की आवश्यकता होगी उतना संरक्षण दिया जायगा। इत प्रतिभुति के अनुसार लड़ाई खतम होने के बाद उद्योग-धन्यों की स्थिति-निर्णय के लिये सरकार ने एक टेरिफ बोर्ड स्थापित किया। सिर्फ लड़ाई के वक्त स्थापित दिये गये उद्योग धन्यों की ही नहीं बल्कि दूसरे उद्योग-धन्यों की स्थिति निर्णयका दायित्व भी इसपर सौंपा गया। इस बोर्ड के सिद्धान्त के अनुसार कई छोटे छोटे उद्योग धन्यों को संरक्षित किया गया है। कई उद्योग-धन्यों के बारे में वर्तमान राजस्व शुल्क को संरक्षण शुल्कमें रूपान्तरित किया गया है जैसे कि कार्टोक सोडा, विलिंग पाउडर पैदा करने वाले शिल्प। कागज तथा लोहा और दरवाजा उत्पादन करने वाले उद्योग-धन्यों का संरक्षणप्रणव बढ़ा लिया गया है। मन् १९४८ के अगस्त महीने में टेरिफ बोर्ड को निम्न विषयों पर जांच करने का अधिकार दिया गया :—(१) सरकारी आवश्यकता के अनुसार टेरिफ बोर्ड किसी भी सामग्री की उत्पादन व्यवस्था की तथा थोक तथा फुटकर विक्रयमूल्य की निर्णय करेगी तथा सरकार को इनका तिारण देगा। (२) सरकारी आवश्यकता के अनुसार विदेशी माल की अनुचित प्रतियोगिता से भारतीय उद्योग-धन्यों को बचाने की सलाह देगी। (३) निम्न सामग्रियों पर मूल्यनुपाती तथा संरक्षणागार शुल्क के प्रभाव तथा दूसरे देशों को दिया हुआ शुल्क विवरण सुविधाओं पर जांच करेगी। (४) संरक्षित उद्योग-धन्यों में यदि एकाधिकार की उन्नति हो तथा उसके यदि जनसाधारण को अनुचितार्थ हो तो उन्हें रोकने के लिये यह बोर्ड सलाह देगी। (५) संरक्षित उद्योग-धन्यों की प्रगति पर अन्त

रखना तथा परिवर्तित स्थिति के अनुसार संरक्षण शुल्कको मात्रा में परिवर्तन करनेकी सलाह देने का दायित्व भी इसी संस्था पर रहेगा ।



भारतीय यातायात प्रबन्ध—जहाज़-निर्माण-शिल्प- असामरिक उड़न-विद्या

यातायात प्रबन्ध का महत्त्व—यातायात के आधुनिक प्रबन्धों के कारण व्यापार, स्थान तथा काल की सीमा को अतिक्रम कर गया है । पूंजीपदी उत्पादन व्यवस्था का विस्तार, विभिन्न देशों में पारस्परिक निर्भरशीलता, संक्षेप में एक विश्वव्यापी धर्म-व्यवस्था, आधुनिक यातायात प्रबन्ध के प्रभाव से ही सम्भाव हुआ है । इसका नतीजा यह हुआ है कि आज उत्पादन वितरण उपभोग तथा संपर्क इन सारी बातों को बिना की दृष्टि में सोचना पड़ता है । बड़े पैमाने पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय धर्म विभाग भी यातायात प्रबन्ध का फल है । भारत की धर्म व्यवस्थाके लिए आधुनिक यातायात प्रबन्ध सहायक हुआ है या नहीं इसके बारेमें विभिन्न मत प्रचलित हैं । कुछ लोगों का कहना है कि भारत में रेल सार्वत्रिक विस्तार होनेपर दुर्भिक्ष की तीव्रता कम हो गयी है तथा आधुनिक उद्योग-धन्धे की वृद्धि की उन्नति सम्भव हुई है; भारतीय कृषि व्यवस्था को भी इससे फायदा पहुँचा । दूसरे लोगों का कहना है कि आधुनिक यातायात प्रबन्ध होनेके कारण विदेशी सामग्रियाँ भारत में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर रही हैं जिससे हमारे सारे घरेलू उद्योग-धन्धे नष्ट हो गये हैं या कमजोर हो गये हैं ; भारत एक कृषि-निर्भर देश बन गया है तथा भारत की अस्तित्व धर्म-व्यवस्था में विघटन हुआ गयी है । इनके अलावा भारत में यातायात का प्रबन्ध करने

में जिस तरह से पूंजी की बर्बादी हुई थी वह भी सोचनेकी बात है । जो भी कुछ हो आधुनिक समय में वातावात प्रबन्ध का विरोध करना अनुचित है कारण इसके बालवा देश में पूंजीवादी उद्योग-वन्धे तथा व्यापार का विस्तार नहीं हो सकता ।

सड़कें—भारत में कुल सड़कों की लम्बाई २ लाख ९६ हजार मील है जिसमें पक्की सड़कें ६५ हजार मील हैं । ब्रूटन तथा संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के हिसाबसे भारतमें सड़कें बहुत कम हैं और इनमें भी ज्यादातर सड़कोंकी हालत शोचनीय है । भारत जैसे महादेश में प्रेण्ट्रूंक रोड की तरह बड़ी-बड़ी सड़कों की आवश्यकता है ताकि विभिन्न प्रान्त एक दूसरे से सम्बन्धित हो सकें । देशांतरों में सड़कें ज्यादातर कच्ची होती हैं जिससे वर्षा के समय वे क्रींचर से तथा जाड़े के समय धूल से भरी हुई रहती हैं जिससे उनको पार-गार में लाना मुश्किल हो जाता है । सन् १९२७ में ज्यादातर कमेटी की सलाह के अनुसार एक केन्द्रीय सड़क उन्नयन बोर्ड तथा एक सलाह देनेवाली संस्था स्थापित की गई है । सन् १९४३ में गागपुर में इंजिनियरों के एक जलमे में सड़कों के बारे में एक योजना बनाई गई थी । भारत सरकार ने इस योजना को स्वीकार किया है । इस योजना की मिलाद ५ वर्ष की है । सन् १९४७ से लगाकर आगामी ५ वर्षों में ३० करोड़ रुपये लगाकर १४ हजार मील लम्बी सड़कें बनाई जायेंगी ।

रेल-रास्ता—वातावात साधनों में रेल-रास्ता सबसे अधिक महत्व रखता है । भारत तथा पाकिस्तान में रेल-रास्तों की लम्बाई ४३ हजार मील है । ब्रूटन में प्रति सौ वर्गमील में २० मील पर रेल-रास्ते हैं । भारत में कुल २॥ मील हैं । भारतीय रेल-रास्तों का स्वामित्व कुछ तो भारत सरकार पर है, कुछ देशीय राज्यों पर और कुछ परिमित दक्षित फ्रान्सियों पर । सन् १८५३ में बम्बईसे कल्याण तक भारतका पहला रेल-रास्ता मूला । रेल-रास्ता कोलने में देश-रक्ष का लक्ष्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण था । इसके छोड़कर

और भी दो लक्ष्य महत्व पाते थे—एक तो व्यापारिक तथा दूसरा दुमिष्ट निवारण । भारतीय रेल-रास्तों के निर्माण का इतिहास बहुत ही विविध है । इनके निर्माण का पूरा दायित्व विदेशी कम्पनियों पर रक्का गया था और वे कम्पनियाँ जो रकम लगाती थीं उससे मुनाफा हो या नहीं, सरकार ने निर्दिष्ट व्याज स्वीकार कर लिया था । इससे रकम की बड़ी कमी होती हुई । एक समय भारत सरकार ने इस कमी को रोकने के लिए रेल-रास्तों का पूरा दायित्व अपनेपर ले लिया लेकिन ज्यादा दिन तक यह प्रबन्ध नहीं चल सका । जो भी कुछ ही भारतीय रेल-रास्तों के निर्माण में काफी विदेशी रकम लग गई । वर्तमान समय में लगभग ७०२ करोड़ रुपये विभिन्न रेल-रास्तों में विनियुक्त हैं । पहली लड़ाई के बाद रेल-रास्तों के राष्ट्रीयकरण का मुद्दा भारत सरकार के सामने आया । एकदम कमिटी की सलाह के अनुसार भारत सरकार ने रेल-रास्तों के राष्ट्रीयकरण का निश्चय कर लिया है एवं इस समय तक एक कम्पनी को छोड़कर सारे रेल-रास्तों का स्वामित्व भारत सरकार पर आ गया है । सन १९२९ के बादसे रेल-रास्तों की हालत बिगड़ चुकी थी । इसके बारेमें सलाह देने के लिये भारत सरकार की धोरतें सर आर० एल० वेजयुड के नेतृत्व में एक कमिटी नियुक्त की गई तथा इसकी सलाह के अनुसार भारतीय रेल-व्यवस्थामें काफी परिवर्तन भी किये गये। कुछोत्तर समय के लिए रेल-रास्तों के बारे में भारत सरकार ने ३२८ करोड़ रुपये कीमत की एक योजना बनवाई थी लेकिन युद्धोत्तर विभ्रंश के कारण यह कामवाचक न हो सकी । भारत विभक्त होनेपर लगभग ८ हजार मील रेल-रास्ता पाकिस्तान के हिस्से में आया है । भारत में इंजिन बनाने का कारखाना भी कुछ दिन पहले आसनसोल के पास स्थापित किया गया है । भारत की औद्योगिक क्रान्ति में रेल-रास्तों का प्रसार महत्वपूर्ण होगा इसमें कोई शक नहीं ।

रेल-महसूलनीति—भारतमें रेल व्यवस्थाके प्रारम्भसे रेल-महसूलनीति भारतीय उद्योग-धन्धोंके प्रतिकूल रही । महसूल-र इन प्रकारसे निर्धारित

क्रिये जाते हैं ताकि भारतमें उत्पन्न धनाज तथा कच्चे माल विदेश को जाने
 रहें और विदेशमें बनी हुई सामग्रियां भारतमें आती रहें। इसके अलावा
 हमारे बन्दरगाहोंमें उद्योग-धन्योंका इतना घन-समावेश भी रेल-महसूल
 नीतिके प्रभावसे हुआ है। रेल-रास्तोंका स्वामित्व जब तक विदेशी कम्पनियों
 के हाथमें था तब तक वे गनमानो महसूल-दर स्थिर करती थीं। सन्
 १८६८ में सरकारने सर्वोच्च महसूल-दर स्थिर कर दिया लेकिन इस पर भी
 दरों की विभिन्नता चलती रही। अतः सन् १८८७ में सरकारने सर्वोच्च
 तथा सर्वनिम्न दरोंको मान लिया लेकिन इस पर भी महसूल-दरमें सरलता
 नहीं आई कारण रेल-कम्पनियां एक ही सामग्री पर विभिन्न महसूलें वसूल
 करती रहीं। सन् १८९१ में सरकार महसूल-दरमें फिसे परिवर्तन की
 ताकि सामग्रियोंका वर्गीकरण हो जाय तथा कम्पनियां उस वर्गीकरणके अनुसार
 सर्वोच्च तथा सर्वनिम्न दरोंके बीचमें महसूल-दर निर्दिष्ट करे। सन् १९१०
 में पहले पहल पूरी तौरसे सारी सामग्रियोंके लिए महसूल-दर निर्दिष्ट किए
 गये। पहली लड़ाई खतम होनेके बाद सरकारने एकदम साहसके नेतृता
 में एक कमिटी स्थापित की जिसके परामर्श के अनुसार भेजने योग्य सामग्रियां
 १० श्रेणियों में विभक्त की गईं तथा महसूल-दरें भी पड़ाई गईं। सन्
 १९३६ में महसूल-दर-नीतिमें फिसे परिवर्तन हुआ जिसके अनुसार साम-
 ग्रियोंको १६ श्रेणियोंमें विभक्त किया गया। इस समयसे आने के समयमें
 प्रचलित रेल-महसूलों को हम ३ हिस्सोंमें बांट सकते हैं—एक तो 'फुल' ^{Full}
 दर, दूसरा 'पेजिटल' ^{Partial} दर, तीसरा स्टेशन-स्टेशन दर। भारतीय व्यापारी
 सर्वथा कहना है कि हमारी रेल-महसूल दरमें इतनी विभिन्नताएँ तथा जटिल-
 ताएँ हैं जिनको सहजमें व्यवहार करना कठिन है। इसके अलावा भारतमें
 कई रेल कम्पनियां रहनेके कारण अतीतमें लम्बी यात्राओं में महसूल-दर जंचा
 रहा है। रेल महसूलकी विशेषता यह होती है कि यात्राकी लम्बाईके साथ
 ही साथ महसूल दर घट जाती है लेकिन रेल कम्पनियां विभिन्न होनेके

कारण यात्राकी लम्बाईका फायदा व्यापारियोंको नहीं मिलता था ! धीरे-धीरे ज्यादातर कम्पनियों के बंद होनेके कारण तथा रेल रास्तोंका प्रबन्ध भारत सरकार के हाथोंमें आजाने के कारण यह दूसरी अवस्था बुरी हो चुकी है लेकिन महसूल-दरकी विभिन्नतायें तथा जटिलतायें अभी तक जारी हैं । रेलकी जोखिम पर जो माल भेजे जाते हैं उन पर भी महसूल दर काया रहा है यही व्यापारियोंकी राय है । इसके अलावा महसूल दरोंकी प्रति-कूलता के कारण हमारे उद्योग-धन्धोंको पूरा फायदा उठाना तो दूर रहा उनको हानि हुई है कारण यह नीति दरबन्दा हो विदेशी सामग्रियोंकी आयात बढ़ाती रही । वेजवुड कमिटीके शब्दोंमें भारतीय रेल रास्तोंका प्रबन्ध बहुत ही अव्यवस्थित तथा असन्तोषजनक है । इसे अगर सुधारना हो तो यातायातका अधिक सुविधा देना होगा तथा व्यापारिक वर्ग तथा व्यापारिक संस्थाओंके साथ हार्दिक सम्बन्ध स्थापित करना होगा ताकि एक-दूसरेसे पूरा फायदा उठा सके । सुदूरतर समयमें महसूल दरोंकी सुधारने के लिए रेलवे बोर्डने कुछ सलाह दी है जो निम्न प्रकार हैं—(१) 'फ्लेट' दरके बदले में टेलिग्राफिक दर कायम किया जाय ताकि लम्बी यात्रा पर महसूल दर पड़ता रहे । (२) सिडिल दरोंको उठा दिया जाय ताकि महसूल दरमें जो जटिलतायें तथा विभिन्नतायें हैं उनका अन्त हो जाय । (३) भेजनेवाले की जोखिम तथा रेल कम्पनी की जोखिम पर भेजे गये मालोंके दरों को अन्तर था उसे कम कर दिया जाय तथा स्टेशनसे स्टेशन तक भी कम्पनी की जोखिम पर माल भेजनेका प्रबन्ध किया जाय । जहां तक हो सके माल को सीधे-से-सीधे रास्तेसे भेजना चाहिए तथा महसूल दर दो प्रत्यक्ष होना चाहिए जैसे कि लम्बी यात्रा में भेजे गये मालों पर टेलिग्राफिक दर तथा स्टेशनसे स्टेशन दर । (४) अन्तमें रेलवे बोर्डका कहना है कि महसूल दर ऐसा होना चाहिए जिससे कृषि शिल्प तथा व्यापार इन तीनोंको पूरा फायदा प्राप्त हो सके ।

कलकत्तेमें भारतीय कम्पनीके द्वारा एक जहाज निर्माण शिपको प्रतिष्ठा दी जाय । वास्तवमें काम कुछ भी नहीं हुआ । तर्कसरकारने 'डककिन' नामक एक जहाज को भारतीय नाविकों के शिक्षाके लिए छोड़ दिया । सन् १९२८ तथा १९३६ में विदेशी कम्पनियोंकी अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिये कानूने बनाने का प्रयत्न किया गया था लेकिन उसमें भी कामयाबी न हो सकी । सन् १९३६ में केन्द्रीय महासभाके उच्चारणमें एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें सरकार को भारतीय जहाजों उद्यम को सुरक्षित तथा विस्तृत करनेके लिये अनुरोध किया गया । जब दूसरी लड़ाई शुरू हुई तब हमारी दुर्बलता और भी स्पष्ट हुई क्योंकि इस समय विदेशी जहाजों का मदद मिलना बिलकुल ही घट हो गया था । सन १९४१ में सिन्धिया कम्पनी के उद्योग से विजगापट्टन में जहाज बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया । दुःखकी बात तो यह है कि इस प्रयत्न में सिन्धिया कम्पनी को सरकारी मदद बहुत ही कम मिली । सिन्धिया कम्पनी ने पहले कलकत्ते में कारखाना बनाने का सोचा, लेकिन बन्दरगाही संस्था के असहयोग के कारण उन्हें कलकत्ते में स्थान न मिला । अन्त में विजगापट्टन में कारखाना बनाने का निश्चय किया गया । इसमें लगभग ११,५००० वर्गफुट जमीन में जहाज बनानेका आधुनिक प्रयत्न किया गया है । साथ ही साथ टूटो-कूटी जहाजों की मरम्मत करनेका भी प्रयत्न किया गया है । जहाजों शिप के बारे में यह पहला भारतीय उद्यम है और उसको सब तरहसे मदद देनेकी आवश्यकता है । सन् १९४४ में वाणिज्य सदस्य ने जहाजों शिप के बारे में सरकारी नीति को घोषित करते हुए कहा था कि युद्धोत्तर समय में भारतीय जहाजों उद्यम को सहायता दी जायेगी तथा 'भारतीय कम्पनियों के लिये समुद्रतटीय व्यापार तथा विदेशी व्यापार का एक बढ़ा-ता हिस्सा संश्लेषित किया जायेगा । युद्धोत्तर आर्थिक पुनर्गठन के लिये भारत सरकार ने जो पुनर्निर्माण-नीति-समिति कायम किया था उसको जहाज-शिप उद्यमकी तर-

समिति ने सन १९४७ के मार्च महीने में अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में एक आवश्यक जहाजी शिल्प स्थापन करनेकी आवश्यकता है जिससे कि समीपवर्ती देशों के साथ द्वितीय महायुद्ध का प्रतिफल ७० हिस्सा तथा दूर देशोंसे किये गये व्यापार का प्रतिफल ५० हिस्सा भारतीय कम्पनियों के हाथों में आ जाना चाहिये एवं समुद्रतटीय व्यापार का पूरा हिस्सा इनके लिये संरक्षित किया जाय। इनके लिये कमसे कम २० लाख टन भर्तीकी जहाजें बननी चाहिये। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राष्ट्र की सुरक्षा तथा व्यापार की दृष्टि को दृष्टि से जहाज शिल्प अत्यन्त आवश्यक है; अब तक विदेशी सरकार की घातक नीति से यह शिल्प उपेक्षित हो रहा है तथा भारतीय जनता को इसकी हानि पहुँची है। अब हमें इस कमी को पूरा करनी चाहिये ताकि आगामी ७ वर्षों में उल्लिखित भर्तीकी जहाजें भारतमें बन जायें।

आमरिका बहन दिया—जातायात साधनों में उद्यम-विकास सबसे अधिक आधुनिक एवं महत्वपूर्ण है। पहले लड़ाईके बादसे इसका विकास प्रचार हुआ है। विशेषतः बड़े-बड़े देशोंमें तथा व्यापार प्रचलन देशोंमें जातायातके इस नये साधन की विशेष आवश्यकता है। पहले लड़ाई के समय दुर्घट जहाजों का आविष्कार हुआ था लेकिन भारत में आमेरिक बहन दिया का आरम्भ सन १९२७ के बाद से हुआ। सन १९२७-३१ में कई दुर्घट मैदान बनाये गये तथा सन १९२७-३४ में सरकारी मदद से जोधपुर, मिर्जापुर, करांची, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ तथा लाहौर में उद्यम विकास प्रचार के लिये कई एक फलक स्थापित किये गये। एंग्लो-हिन्दू एनफोर्स मिनिस्ट्री ने पहले पहले भारत में जातायात मार्ग से जातायात का प्रवर्धन दिया। साथ ही साथ सरकार की ओर से भी दिवाली तथा कलौती के बीच जातायात का प्रवर्धन हुआ। सन १९३५ में भारत के बड़े-बड़े नहरोंमें पहले जहाजों के जातायात का प्रवर्धन करनेका विचार भारत सरकार का था लेकिन आमेरिक

मंदी के आविर्भाव से यह सकल न हो सका । इसके बाद वैयक्तिक उद्योग से कई एक हवाई कम्पनियां स्थापित की गईं जिनमें निम्नलिखित कम्पनियां उल्लेखनीय हैं—टाटा सन्स लिमिटेड, इण्डियन एयर सर्विसेज एण्ड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, इण्डियन ट्रांसकन्टिनेन्टल एयरवेज लिमिटेड, दिमालयन एयर ट्रांसपोर्ट एण्ड सर्विसेज लिमिटेड, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड । हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट सिन्धिया कम्पनी के उद्योगसे सन १९४० में बंगालो में स्थापित की गई थी । कुछ दिन बाद भारत सरकार ने इसको खरीद लिया है ।

युद्धोत्तर समयमें असाधारण टहन विद्याके प्रचारके लिए तथा यातायातके सुविधा के लिए भारत सरकारने एक व्यापक योजना तैयार की है जिसके अनुसार विभिन्न बड़े-बड़े शहरोंमें हवाई जहाजसे यातायात की सुविधा दी जाय । इस योजनाका लक्ष्य यह रहा कि आन्ध्रन्तरीन यातायातका प्रबन्ध भारतमें बनी हुई कम्पनियोंके हाथमें रक्खा जाय तथा भारतमें लगभग १०० हवाई स्टेशन बनाये जाय । इस योजनामें यह भी स्पष्ट किया गया है कि हवाई यातायात प्रबन्धके राष्ट्रीयकरणका विचार निरुद्ध मसिधमें नहीं है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सरकारकी ओरसे भी कम्पनियों काम कर सकती हैं । साध-ही-साध यह भी घोषित किया गया है कि हवाई यातायात प्रबन्ध का उन्मुख विस्तार करनेके लिए एक एयर ट्रांसपोर्ट लाइसेंसिंग बोर्ड स्थापित दिया जायेगा ताकि एक ही रास्ते पर एकाधिक कम्पनियोंकी प्रतियोगिता शुरू न हो जाय । हवाई जहाजों के बनाने के बारेमें सरकारी नीति उल्लेखनीय नहीं है कारण हिन्दुस्तान एयर क्रफ्ट कम्पनी जिसका लक्ष्य हवाई जहाज पैदा करनेका था वह हवाई जहाजोंके सम्मत करनेके तथा रेल गाड़ियों बनानेके काममें लगी हुई है ।

लक्ष्मिके बादसे असाधारण टहन प्रबन्धका काफी विस्तार हुआ है । एयर ट्रांसपोर्ट लाइसेंसिंग बोर्ड भी स्थापित किया गया है । किन्तु रास्ते पर

कौन-सी कम्पनी काम करेगी इसको निर्धारित करनेका अधिकार इस बोर्डको दिया गया है। युद्धोत्तर समयमें कुछ दिन तक सरकार हवाई संस्थाओं को आधिक मद्दद पहुंचाती रही लेकिन अब आधिक मद्दद बन्द कर दी गई है परन्तु हवाई मैदान ठीक रखना, चेतारका प्रबन्ध करना आदि सारा काम सरकार पर है। असाधारिक लोगोंके यातायात की सुविधाके लिए देशरेखा करनेका दायित्व भी सरकारी दफ्तरों पर है। इस प्रकारसे सन १९४६ के अक्टोबर महीने तक असाधारिक लोगोंके यातायातके सुविधाके लिए १९ कम्पनियां स्थापित की गई हैं। सन १९४८ के रिपोर्ट के अनुसार भारत में असाधारिक यातायात प्रबन्ध निम्न प्रकार था :—(१) कलकत्ता, बम्बई तथा दिल्लीमें ३ प्रधान हवाई मैदान हैं जहां पर सारे आधुनिक प्रबन्ध दिये गये हैं ; (२) अहमदाबाद, प्रयाग, लग्नज, मद्रास, नागपुर, पटना तथा बिजगापट्टममें बड़े हवाई मैदान हैं ; (३) इनके अलावा १३ मझोला तथा २२ छोटे मैदान भी हैं ; (४) भारतमें शामिल किये हुए देशीय राज्योंमें २६ मैदान हैं ; (५) इनके लिए सन १९४७-४८ में ४०५९००० रुपये की लागत थी ; (६) विभिन्न लगानोंसे तथा लाइसेन्स व सार्टिफिकेट फिसे चलानेका कर मैदान तथा स्टेशनका किराया आदिसे १६६५९३० रुपये आमदनी हुए थे। सन १९४८ के ३० जून तक गतम होगएले १ वर्षमें हमें हवाई कम्पनियोंसे निम्न प्रकारकी सेवा मिली, ३१५४८६ यात्री इससे फायदा उठा सके तथा ६२१६१२७ पाउण्ड वजनका माल, १३२०३९८ पाउण्ड वजनकी टाक सामग्रियां तथा २८०४२३० पाउण्ड वजनके अनुसार हवाई रास्ते पर भेजे गये।

भारतमें मुद्रास्फीतिके दुष्परिणाम—

युद्धोत्तर समयमें मुद्रास्फीति

द्वितीय महायुद्धके आरम्भ काल से भारत में जो मुद्रास्फीति हुई है यह हमारे देशके लिए एक नई अभिज्ञता है। मुद्रास्फीतिके कारण रुपयेकी क्रयशक्ति बहुत ही घट गई है। सन १९३९-४० में २०९ करोड़ रुपये कीमतके कागजी सिक्के भारतमें प्रचलित थे; सन १९४७ में भारत विभक्त होनेके पहले इनका परिमाण १२४२.८६ करोड़ रुपये हो गए। देश विभक्त होनेके बाद भारत तथा पाकिस्तानके कागजी सिक्के पृथक् हो चुके हैं लेकिन इनको अगर जोड़ा जाय तो इनका परिमाण १३०० करोड़ रुपयेसे भी अधिक होगा। यह तो सिक्केकी असली राशि है। वास्तवमें क्रियात्मक सिक्केका परिमाण कितना है इसका यथार्थ निर्णय करना असम्भव है। भारतमें जो मुद्रास्फीति हुई इसकी कई एक विशेषताएँ सड़जमें ही नजरमें आती हैं। साधारण स्थितिमें मुद्रास्फीति होनेपर सामग्रियोंकी कीमत बढ़ती है; इससे उद्योगपतियोंको मुनाफा अधिक होता है और वे पैदावार जरा तक ही सके बढ़ाकर इस परिस्थितिसे अधिक-से-अधिक मुनाफा उठानेका प्रयत्न करते हैं। हमारे देशमें जो मुद्रास्फीति हुई उसमें सिर्फ सिक्केकी राशि ही बढ़ाई गई; पैदावार न बढ़ी। इसलिए सामग्रियोंकी पूर्ति रखने के अनुपातसे बहुत ही कम रही और उनको कीमत बढ़ती चली। सबसे आश्चर्यकी बात तो यह है कि भारतमें लड़ाईका मोर्चा नहीं बनने पर भी सामग्रियोंकी कीमत सिर्फ चीन और घर्माकी छोड़कर सबसे अधिक बढ़ गई। सरकारने सामग्रियोंकी कीमत नियन्त्रित करनेका मानून्हे-सा प्रयत्न किया लेकिन यह कामयाब न हो सका। इसका नतीजा यह हुआ कि धन-वितरणकी असमानता और भी बढ़ गई।

लड़ाईके बख मुद्रास्फीति क्यों हुई ? विभिन्न वर्ग शास्त्रियोंने इसका विभिन्न कारण बताया है लेकिन इसमें दो कारण मुख्य हैं । एक ओर तो ईंग्लैण्डमें इनारी जो स्टालिंग स्कम इकट्ठी हो रही थी उसके आधारपर भारत में फागजी सिकके जारी किए जा रहे थे और दूसरी ओर भारत सरकारके अल्पमियादी ऋणवर्षोंके आधार पर भी फागजी सिकके छपाये जाने लगे । इस प्रकारसे सरकारके हाथमें कृत्रिम क्लबकपि इकट्ठी होने लगे जिसके द्वारा वह लड़ाईका सामान तथा अनाजको नियन्त्रित दर पर जारीद कर इटिम सरकारको भेजती रही । इससे सामग्रियोंकी कमी और भी बढ़ गई तथा काला बाजार स्थानी तोरपर कायम हो गया । यह स्थिति जल्द ही अर्थशास्त्रियोंकी दृष्टि आकर्षित की और उन्होंने पगामस दिया कि जिस रीतिसे इंग्लैण्ड की सामग्रियां भेजी जा रही हैं और स्टालिंग स्कम जमा हो रही हैं, मुद्रास्फीतिको अगर गौकना हो तो इसमें जल्द परिवर्तन कर देना चाहिये, कारण दूसरे देशोंमें स्कम इकट्ठी होने देना खर्च कारक है इंग्लैण्डको अगर भारत से सामान जारीदना हो तो वह नकद मूल्य देकर जारीद सकता है । जो स्टालिंग स्कम इकट्ठी हो चुकी उसके बारेमें भी इन्होंने सलाह दी कि इसको जल्दसे जल्द अपने अधिकारमें ले वाला चाहिये । चाहे तो ईंग्लैण्ड इसके बदलेमें सोना दे दे या सोना देनेकी प्रतिभुति दे और नहीं तो अन्न, गंधु, चावल, अमेरिका, कैंनाडा प्रभुत देशोंकी तरह भारत स्थित विदेशी उद्योग-धन्योंकी इस स्कमके विनिमयमें जारीद लिया जाए । वस्तुतःमें सरकारने ऐसी कोई भी कारवाइयां नहीं की और न स्टालिंग को जारी कीमतके बारेमें इटिम सरकारसे कोई प्रतिभुति ही प्राप्त हुई । इटलीजिने इंग्लैण्डकी रीतिसेके लिए सरकारी स्कम नियन्त्रित करनेकी आवश्यकता भी महिस सरकारी इन दिवस पर भी मान नहीं दिया । अन्ततःसरकारी क्लबकपि पकड़नेके लिए उन्होंने हर तरहका कर लगाया तथा विभिन्न सिध्दोंके माध्यम जारी किए । साथ ही साथ सरकारने मातृसहित सामग्रियोंके दर तथा

विक्रय नियंत्रित किया लेकिन इनमें अधिक सफलता नहीं हुई तथा सामग्रियों की कीमत बढ़ती चली ।

मुद्रास्फीतिके दुष्परिणाम कितने हो भयानक क्यों न हों, लड़ाई के वक़्त ये कुछ हद तक अवश्यम्भावी थे लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि लड़ाई के अन्त होने पर भी हमारे देशमें मुद्रास्फीति चल रही है और सामग्रियों की कीमत दिन पर दिन बढ़ रही है । वर्तमान स्थिति के लिए किसी एक कारण को दायी नहीं किया जा सकता ; इसके कई कारण तो लड़ाईके वक़्त से ही चले आ रहे हैं और कई कारण उसके बादकी स्थिति से आविर्भूत हुए हैं । लड़ाईके प्रारम्भसे सन १९४५-४६ के शेष तक भारत सरकार इंग्लैण्डको १७४४ करोड़ रुपये कीमत की सामग्रियाँ भेज चुकी थीं सन १९३९-४० से लगा कर १९४५-४६ तक भारत सरकारकी बज़टमें ७९५ करोड़ रुपयेकी कमी थी । इस प्रकारसे मोट पड़तीका परिमाण २५३५ करोड़ रुपया था । इनमें से सरकार को १२३६ करोड़ ढाया कर्ज मिला ; अवशिष्ट १२९९ करोड़ रुपयेकी कमी पूरी करनेके लिए सरकारको नोट छापना पड़ा । देश विभक्त होने पर भी लड़ाई के वक़्त जितने रुपये प्रचलित थे अब उससे अधिक हैं । युद्ध समाप्त तथा स्वराजकी प्राप्तिके बाद लोगोंने समझा था कि युद्ध-कालीन वस्तु अभाव के संकट शीघ्र दूर होंगे लेकिन यह आशा सृगतृण्णा हो रही ; रवैय्या पूर्ववत् ही चल्ती रही । युद्धोत्तर मुद्रास्फीतिके कारण निम्न प्रकार हैं :—

(१) उत्पादन तथा वितरण—देशमें खाद्यान्नोंका दुष्कास चल रहा है । हमारी अन्तरकालीन सरकारने इन्हें दूर करने के लिए प्रयत्न किया ; उत्पादन बढ़ानेके लिए सरकार दो योजनाएँ भी बनाई, पर उत्पादनके सोधे क्षेत्रमें युद्ध-कालीन विचारियोंसे शीघ्र छूट जाना और बढ़ा सकना टेढ़ी छोर थी । इसलिये विदेशोंसे अनाज मंगानेके प्रयत्न भी हुए । यह तो अल्प कालीन योजना थी । दीर्घ-कालीन योजनाओंमें दामोदर घाटी योजना, महानदी

योजना तथा कोलीनदी योजना सुरू हैं। साथ-ही-साथ अंतर तथा बंजर तोड़नेके लिए ट्रैक्टर-प्रणाली की भी कार्यान्वित की गयी ; परन्तु ऐसी दोषकालीन योजनाएँ अधिक समय पर तथा सरकार की सुदृढ नीति पर अवलम्बित होती हैं। फलतः वर्तमान साथ-संकट बना रहा। परन्तु-उत्पादन भी कम था। उद्योग-वन्धोंके क्षेत्रमें वयवि सरकारने धारणी धन नीतिमें उचित मजदूरीके समन्वितोंको उत्साहित किया, नंदगाई भत्तेका प्रवन्ध किया तथा कारखानोंमें सुधारोंको महत्वपूर्ण स्थान दिया तथावि वट वानिक सामग्रियोंकी पैदा करनेमें समर्थ न हो सकी।

(२) सरकारी व्यवस्था—विभिन्न कारणोंसे सरकारी व्यवस्था ; इनमें बहुतसे कारण अनावश्यक भी थे। साथ ही काश्मीर तथा हिमाचल पर व्यवस्था आवश्यक था ही और शरणार्थियोंको पुनः बसाना और उनके काम देना—इनपर सरकारी व्यवस्था करोड़ों तक पहुँच गई। इस प्रकार सरकार के सार्वजनिक ऋण बढ़े दिवस उनसे पूर्ण प्रवन्ध अवलम्बित था। सरकारी कर्मचारियोंकी अयोग्यता और उनका नैतिक अधःपतन भी इस स्थिति में साथ बटाया और इनके साथ अष्ट व्यापारी वर्ग भी आ सम्मिलित हुए।

(३) सरकारकी व्यापार तथा वातावरण नीति—रेलों द्वारा शीघ्रता से आवश्यक वस्तुओंका मन्वोपभोग परिवहन नहीं होता था और न इनकी विशेष पूर्णत्व हो दिया गया था। वस्तुओंका बौरे नियत चलता रहा। व्यापार क्षेत्रमें वित्तप्रिताकी वस्तुओंका प्रवेश कम-से-कम कुछ दिनोंके लिए रोक देना ही ठीक था लेकिन इनका प्रवेश अधिकारीवर्गकी हस्त पर चलता रहा और बाध भी चलता है। इसका एक परिणाम जीवन सम्बन्धी वस्तुओं के उत्तर पड़ता है। हमारी राष्ट्रीय सरकार अब इस और कुछ मजबूत हो रही है लेकिन मशीनों और यंत्रोपकरणों की प्राप्ति करना कठिन है इसलिए पैदावार भी उत्पन्न नहीं बढ़ावी जा सकती। साथ ही साथ सरकारकी उद्योगपरिप्रेषि

भी पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है जिसके लिए सरकार की शिस्तनिति तथा कुछ मंत्रियों की अस्थायी विचारधारा दायी है।

उपर्युक्त आर्थिक विद्वलेपन से यह सिद्ध होता है कि मुद्रास्फीति की भयंकर विमारी अत्यधिक वेगसे बढ़ गई थी। इस बीमारीका नाशभी हम राष्ट्र के पूर्ण सहयोग से ही दबाया जा सकता है। अतः सरकारने जो प्रयत्न करना शुरू किया, इनको दो भागोंमें बांटा जा सकता है—परामर्श दायी विचार तथा सरकारी कारवायें। अर्थ शास्त्रियोंकी परिपदमें सरकारी अर्थ-शास्त्रियोंके सुझाव, उद्योगपतियोंके परिपद तथा उनका स्मारपत्र, धर्मियोंका दृष्टिकोण प्रभृति पहले के अन्तर्गत थे। दूसरेके अन्तर्गत सरकारी ऋ अवद्वय की महत्त्वपूर्ण घोषणा आती है जिसमें परामर्शदायी विभागोंके आधार पर वर्तमान मुद्रास्फीतिके संकटको टालने के लिए विभिन्न विचारोंमें ३ मुख्य दिशाओंमें सुझाव दिये गये हैं—उत्पादन, मुद्रा और कर। उत्पादन बढ़ानेके लिए प्रायः सब मत एक हैं, किन्तु उत्पादन बढ़ानेमें जो विधि और साधन होने चाहिए उनमें वे एक नहीं हैं। मुद्रा और कर सम्बन्धी सुझावमें बड़ा ही पार्थक्य है।

मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को रटाने के लिये सरकार ने जो निश्चय किया है उन्हें हम ४ भागों में बांट सकते हैं। (१) सरकारी व्यय में कमी—१९४८-४९ की बजट में प्रान्तों को २९५ लाख रुपये की छूटाना और ४७५.३५ लाख रुपयों की विकासकारी तथा लोगों की पुनः रोजगार के लिये रक्षता गया था। परन्तु वष विद्याशालाओं की इन योजनाओं को रोक जायेगा जो तत्कालीन उत्पादन वृद्धि से सम्बन्धित नहीं हैं। इसी प्रकार जमींदारी रन्मूलन तथा मज-निषेध के लिये प्रान्तोंको केन्द्रीय सरकारका प्रयत्न हो। विभिन्न सरकारी दफ्तरों की व्यय में कुछ प्रसार से कमी की जा सकती है यह बात भी सोची जा रही है। (२) पूँज प्रदान करने मुद्रा-स्फीति निवारण—१९४८-४९ के बजट में १५० करोड़ रुपये पूँज देनेकी

व्यवस्था है। टाकनानेके संचय-प्रहायक बैंक में रुपये जमा करने की सुविधाएँ दी जावेगी। अब प्रत्येक व्यक्ति ५ हजार रुपये के खान पर १० हजार रुपये जमा कर सकेगा और २५ हजार तक के राष्ट्र भूत-संचय प्रमाणपत्र खरीद सकेगा। (३) जनता की क्रय-शक्ति को औद्योगिक व कृषि उत्पादन वृद्धि से कम करना—इसके निम्नलिखित निदान रखने गये हैं :—
 (क) नये उद्योगों की कुछ दिनों के लिए आय-कर से मुक्ति। (ख) धिक्कार प्रभृति के लिये नियमों की शिथिलता तथा (ग) कच्चे माल तथा यंत्रों के प्रवेश पर छूट। (४) अन्न निर्णय—(क) अन्न-वस्तुदि पर पुनः नियंत्रण (ख) लाभान्ती का सीमा-निर्धारण ताकि प्रतिवत् ६) रुपये से अधिक लाभाना न दिया जाय। (ग) अतिरिक्त लाभ-कर को जो राशि सरकार के पास है उसे वह तीन वर्ष तक सिर्फ आवश्यक समझनेपर ही निर्माण यंत्र खरीदने देगी। (घ) दूरताल सम्बन्धी कानून को सारे देश के लिये एक बनाया इत्यादि इत्यादि।

इन सब दिशाओं में कुछ भी काम नहीं हुआ है ऐसी बात नहीं, लेकिन इनमें सकलता विशेष नहीं हुई। इसका मूल कारण यह है कि वास्तुविक जटिल समस्याओं का समाधान अर्थशास्त्र के पुराने सिद्धान्तों के अनुसार नहीं किया जा सकता। इसके लिये सबसे पहले केन्द्रीय-सरकारके अधीन में एक स्वतन्त्र अर्थ विषयक दफ्तर खोलना हीनेकी आवश्यकता है। इस दफ्तर पर हमारे आर्थिक जीवन को संगठित करनेकी जिम्मेदारी होगी। साथ ही साथ विनियोग प्रबन्ध करना होगा ताकि बेकारी को समाप्त हो जाय। जिस देश में गृह-निर्माण, सार्वजनिक-निर्माण तथा संस्कार, नहरों का विस्तार तथा प्रायोजन, नदी की मरिती तथा मरु-नियंत्रण, जनकल्याणकारी संस्था स्थापन प्रभृति कामों में लाखों की लागत पर जनमरिती व्यय हो रहा है वही देश में ही बेकारी सबसे ज्यादा है। इनके अधिक निष्पत्ति बता रहा है मरिती है। इस सब जनकल्याण कामोंकी धनर कुछ दिना धन की

रकम को कमो न होगी । १९३३-३४ साल में जब जर्मनी में एक विराट् अव्यवस्था जारी थी उस वक्त भी इस प्रकार के प्रबन्ध किये जानेपर बेकारी का उन्मूलन हो गया था । इन कामों के लिये सरकार ने विनियोग प्रबन्धक ऋण ग्रहण किया । आज हमारे देश में भी इस प्रकार की कार्यवाहियों की आवश्यकता है । साथ ही साथ कृषि तथा उद्योग-धन्धों में व्यक्तिगत प्रचেষा को उत्साहित करनेकी आवश्यकता है । आज उद्योग-धन्धों में रकम लगाने के लिये हमें ज्यादातर पूंजीपतियों के व्यक्तिगत संचय पर निर्भर करना पड़ता है । इसलिये इनपर ज्यादा कर लगा देनेसे इनके उत्साह पर पानी फिर जायेगा और वे रकम लगाना मंजूर न करेंगे । इसलिये जो लोग पैदावार बढ़ाने में वास्तविक सहयोग देंगे तथा निर्दिष्ट काल में पैदावार बढ़ा सकेंगे उनपर से करों को हटा देना उचित होगा । आमदनी का जो हिस्सा शिल्प संस्कार या शिल्प विस्तार के कामों में लगाया जायेगा उस पर से आयकर हटा देनेकी बात भी सोची जा सकती है । साथ ही साथ नेताओं के प्रभाव के द्वारा पैदावार बढ़ानेके काम को उत्साहित करना होगा । संक्षेप में बिना पैदावार बढ़े हमारी वर्तमान समस्या का समाधान नहीं हो सकता । इसके अलावा कृषि तथा शिल्प में लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति तथा संस्था को आर्थिक दफ्तर के अधीन में स्थापित करना होगा तथा पैदावार में इनका हिस्सा निर्धारित कर देना होगा । आर्थिक जीवन पर इस प्रकार के पूर्ण नियंत्रण के अलावा पैदावार बढ़ाने की सम्भावना नहीं है । बागडोर योजनाएँ अभी तक बहुत हो चुकी हैं ; अंग्रेजों की रीति से अभी तक कमीटियों के पंटे काशी पैसा बर्बाद हो चुका है लेकिन इस प्रकार से आर्थिक विकास नहीं होता । वर्तमान अस्वाभाविक परिस्थिति के लिये ये सब गणतान्त्रिक नीतियां प्रभावकारी नहीं हैं । देश को यदि जल्द आर्थिक विकास के रास्ते पर लाना हो तो उसके लिए जल्द से जल्द निर्दिष्ट योजना ग्रहण करनी चाहिये एवं उसके अनुसार काम शुरू होना चाहिये । यदि ऐसा करना सम्भव न हो तो

नियंत्रण व्यवस्था और उनके साथ सम्बन्धित सुरक्षाओं स्थायी हो जायेंगी। हमसे न देश की उन्नति हो होगी और न कल्याण ही सम्भव होगा।

रुपये का मूल्य हास

कुछ ही दिन पहले सर स्टेफोर्ट क्रिप्स ने दुनियां को बताया था कि जबतक वे ब्रिटिश कोषाध्यक्ष रहेंगे तबतक पाउन्डके मूल्य हास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस घोषणा के बाद भी जब अचानक उन्होंने पाउन्डकी डालर कीमत ४०३ से घटाकर २८० बना दी तो सभी दुनियांसे बहुत ही आश्चर्य का माहुर पड़ा। परन्तु जानकार लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बिछले जुलाई माह में लन्दन में जो ब्रिटिश राष्ट्र मंडल के अर्थ-मंत्रियों का जलसा हुआ था एवं उन्होंने डालर से सम्बन्धित देशों के राजप्रधानमंत्रियों में २५% की कटौती करनेका निश्चय दिया था तभी अमेरिका के व्यापारीगण कहने लगे कि हमसे इंग्लैन्ड की असली समस्या का समाधान नहीं होगा। आगे चलकर इन्हीं ने बताया कि इंग्लैन्ड अपनी समस्या को स्वयं ब्रिट में नहीं देखता है और न देखने की शक्ति ही उसमें है क्योंकि इंग्लैन्ड में उत्पादन तथा विक्रय की लागत इनकी बहुत गहरी है कि इंग्लैन्ड के लिए पृथ्वी के बाजारमें दूसरे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना सम्भव नहीं। इस बिन्दु पर इस स्थिति को सुधारने के लिए डालर सम्बन्धित देशों से आग्रह व्यक्त करना पड़ा कि पर भी इस समस्या का समाधान नहीं होगा क्योंकि यदि पाउन्ड की कीमत नहीं घटायी जा रही है। इस दृष्टि से पाउन्ड की कीमत घटाना पड़ने ही वाली थी परन्तु ब्रिटिश कोषाध्यक्ष ने तब निश्चय

से अपनी नीति को अकरमात पलट दिया वह वास्तव में आदर्शन को पन्न है । इंग्लैन्ड की मुद्रादर नीति में यह परिवर्तन अमेरिकन डॉलरकोन का सम्पर्क कर रहा है ।

युक्ति की ओर से, सिक्के की कीमत घटाने पर यदि इसको अकारण होने का पूरा अवसर दिया जाय तो इससे आर्थिक स्थिति की अगमतिदां दूर हो सकती हैं एवं अन्तर्गष्ट्रीय आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है । सन् १९२४ से १९३१ तक लगातार बाणिज्यियों का मानना करने पर सन् १९३१ में जब पाउन्ड की कीमत घटायी गई थी तब भी इसका लक्ष्य इसी प्रकारका था परन्तु वास्तविकताका विचार तो वास्तविकताकी दृष्टिमें ही करना चाहिये । वास्तव में सिक्के का मूल्य ह्रास करने पर साधद ही इसको अकारण होने का पूरा अवसर दिया जाता है । बाजार में यदि एक मुद्रादर कम दर में सामग्रियां बेचे तो उसे जरूर फायदा होगा लेकिन यदि सारे दुकानदार अपनी सामग्रियों की कीमत घटा दें तो फायदा किसी को भी नहीं होगा और सबका मुनाफा कम हो जायगा । ठीक इसी तरह से जब कोई भी एक देश अपने सिक्के की कीमत घटा देता है तब दूसरे देश भी प्रतिस्पर्धा के तौर पर अपने सिक्के की कीमत घटाने में लग जाते हैं या आयात बाणिज्य पर प्रतिबन्ध लगाकर अन्तर्गष्ट्रीय अर्थिक स्थिति के सुधार के रास्ता तक नष्ट कर देते हैं । सन् १९३० के बाद से विभिन्न देशों के मुद्राविनिमय दर के बारे में हमारी अभिज्ञता भी टीढ़ इसी प्रयत्न को है । १९२९ से १९३७ तक अल्बानियाके प्रौद्योगिकी को छोड़कर दुनिया में ऐसा कोई भी देश न बचा जिसने सिक्के की कीमत न घटी । सन् १९३१ साल में इंग्लैन्डने अपने पाउन्ड की कीमत घटा दी । पाउन्ड की कीमत घटाने में इंग्लैन्ड के सामने दो लक्ष्य थे—पहला पाउन्ड की विनिमय कीमत जो बढ़ी थी उसका संशोधन करना एवं दूसरा इंग्लैन्डमें विदेशियों की जो रकम जमा भी उसे लौटाना । इंग्लैन्ड

के सामने बर्बाद समस्या थी। पण्डु अमेरिकाने जब सन् १९३३ में डॉलर की कीमत घटा दी तब उसका घुसा अन्तर हुआ। कारण अमेरिका के सामने डॉलर की शक्तिमुल्यन समस्या नहीं थी और न उसके आयात-निर्यात न निर्यात में प्रतिवृत्तता हो थी ; पृथ्वीका सारा सोना भी इस देश अमेरिका में इकट्ठा हो रहा था। इसपर जो जब उन्होंने डॉलर की कीमत घटायी तो इसका उद्देश्य इंग्लैण्ड के साथ प्रतिस्पर्धा करना था इसमें क्या संदेह रह सकता है ? डॉलर की कीमत घट जानेपर प्राँच तथा स्वर्ण सम्बन्धित देशोंके व्यापार पर चोट पहुँची और उन्हें भी अपने अपने सिक्केकी कीमत घटा देनेी पड़ी। बात तो यह है कि सिक्के के मूल्य हासका अगर विमुक्तो है ; इसके द्वारा वार्षिक स्थिति को प्रोत्साहित हो जा सकती है या इसको पूरी तौरसे बिगाड़ी भी जा सकती है। यदि देशके सिक्के का मूल्य वास्तव में बढ़ चुका हो तो इसके मूल्य हासके द्वारा सामग्रियों की पैदावार में उत्तेजना पहुँचाई जा सकती है लेकिन यदि अपने सिक्केका मूल्य हास करनेके लिये ही इस नीतिका आशय किया जाय तो उसके वार्षिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ जायेगी।

कुछ दिन पहले हमारे रुपये की विनियम कीमत घटाई गई है उसका विश्लेषण करना आवश्यक है। रुपयेके विनियम दर घटनेको दो दृष्टिको विचार करना होगा—एक तो डॉलर के अनुपात से रुपये का मूल्य घटना और दूसरा पाकिस्तान के रुपये के अनुपात से भारत के रुपये का दर घटना। सम्प्रति यह परिवर्तन निम्न प्रकार हुआ है :—

पाउण्ड तथा डॉलर का प्रचलित विनियम दर था पाउण्ड १ = डॉलर ४.० ३।

पाउण्ड तथा रुपये का विनियम दर है १ सि: ६ पे: = १ रुपया।

अतः १ पाउण्ड = ४.० ३ डॉलर = १३।८०

अतः १ डॉलर = २० (१३।८ - १३।८) = २० ३।८ (लगभग)

नया विनिमय दर निम्न प्रकार हुआ है :—

१ पाउन्ड = २.८० टालर = रु० १३.३५।

अतः १ टालर = रु० $(\frac{१३.३५}{२.८०}) = रु० ४।११$ २३ पाई = रु०

४. ७६१९०

यानी रु० १ = ०.१८६२१ ग्रेन शुद्ध सोना = २१.०० अमेरिकन सेन्ट

यानी रु० १६६ ६६७ = १ टूय आउन्स शुद्ध सोना।

परिवर्तन के बाद के कई विनिमय दर नीचे दिये जा रहे हैं :—

दक्षिणी अफ्रिका का पाउन्ड १ = ३८.४ ग्रेन शुद्ध सोना = २.८० टालर;

अष्ट्रेलिया का पाउन्ड = २.२४ टालर (इंग्लैण्ड का १ पाउन्ड =

अष्ट्रेलिया का १ पा० ५ शि०); निजिलैण्ड का पाउन्ड १ = २.८०

टालर; स्टेट्स सेटलमेन्ट का टालर १ = ३२.५ सेन्ट (पुर्गना दर ४६.७५

सेन्ट); बर्मा ४ ७६ रु० = १ टालर; डेनमार्क ६.९०७१४ कोनर (पुर्गना

दर ४ ८१) = १ टालर; नारवे ७.१४२८६ (पुर्गना दर ४ ९६)

कोनर = १ टालर; थायरलैण्ड १ पाउन्ड = २.८० टालर; इजिप्ट

पाउन्ड = २.८० टालर; मिशरका पाउन्ड = २.८७१ टालर।

पाकिस्तान के साथ विनिमय दर निम्न प्रकारका हुआ है :—

पाकिस्तानी रुपया = २५.९ पे;

पाकिस्तानी ९.२६ रु० = १ पाउन्ड;

पाकिस्तानी १०० रु० = भारतका १४४ रु०;

पाकिस्तानी ६९.५० रु० = भारतका १०० रु०।

हमारे शत्रु के विनिमय दरों में यह परिवर्तन हमारे विदेशी व्यापार को किस प्रकारसे प्रभावित करेगा? इस विषयको समझने के लिये हमारे विदेशी व्यापार की गति पर ध्यान देनेको आवश्यकता है। इसमें यह बात स्पष्ट होगी कि होते हुए कई वर्षों में हमारे विदेशी व्यापार में एक मौलिक परिवर्तन हो रहा

है। हमारे आयात तथा निर्यात इन दोनों व्यापारोंमें ब्रिटिश साम्राज्य के बाहरके देशोंका हिस्सा दिन पर दिन बढ़ रहा है। सन् १९१३-१४ में हमारे आयात सामग्रियोंका प्रतिशत ६४.१ हिस्सा इंग्लैण्डसे आता था; सन् १९१८-१९ में यह ४५.५ तथा सन् १९३२-३३ में ३६.८ हुआ एवं सन् १९४९ के मार्च महीने में यह कुलमें ३१.४ था। इस महीनेमें हमारे आयात बाणिज्य में अमेरिका तथा ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर के देशों का हिस्सा प्रतिशत लगभग ५० था। हमारे निर्यात व्यापार में सन् १९१८-१९ में इंग्लैण्ड का हिस्सा कुल में २९.२.४ तथा सन् १९३५-३६ में यह ३१.५.४ था; यह अब कुलमें २५.४ रहा है। इस व्यापार में इंग्लैण्ड तथा साम्राज्य के दूसरे देश वर्तमान समय में प्रतिशत ५३ हिस्सा लेते हैं; अमेरिका तथा दूसरे देशोंका हिस्सा ४४.४ है। सामग्रियों की ओर से भी अमेरिका तथा दूसरे देशों के साथ हमारा व्यापारिक सम्बन्ध दिन पर दिन गभीर होता जा रहा है। हमारे आधिक पुनर्गठन, जैनोंकार तथा संगठन के लिये जिन साधनों की आवश्यकता है तथा हमारे असंगठित को टालने के लिये जो साथ सामग्रियों हमें भंगाने पड़ती हैं वह भी ज्यादातर अमेरिका से या साम्राज्य के बाहर के दूसरे देशों से संग्रहीत जाती हैं। भारत सरकार ने इनकी आयात बन्द करने का निश्चय कर लिया है लेकिन हमारी वर्तमान आर्थिक स्थिति में जबकि नये उद्योग-धन्यों को काम करने की विशेष आवश्यकता है, जबकि हमारे पुराने उद्योग-धन्यों का जैनोंकार करना एकमात्र जरूरी है, जबकि साथ सामग्रियों की पैदा बढनेवाली योजनाएँ सरकारी दस्तों में सीमित हैं तब अवश्यतः इनका आयात बन्द कर देना सामग्यक होगा। आज हमारा आर्थिक पुनर्गठन तथा विद्युत का प्रयुग सबसे बड़ा है और इसी दृष्टिसे ही हमारी बाणिज्य नीति प्रभावित होती जायिगे लेकिन हमारी सरकार इस दृष्टिको छोड़ चुके है। पहले ही बाहर सम्बन्धित देशोंसे २५.४ आयात घटाने का निश्चय सरकार ने किया था अब करने का विभिन्न दर

२०% घटा दिया गया है। इन दोनोंके प्रभाव से अमेरिका से आनाज तथा धौजारों का निर्यात भारत के लिये बन्द हो जायगा और इंग्लैंड की स्थिति ऐसी नहीं है जिसके जरिये हम अपने अभाव को पूरा कर सकें। इसलिये हमारी वर्तमान मुद्राविनिमय नीति हमारे स्वार्थ के प्रतिद्वन्द्व होगी।

हमारी आर्थिक समस्यायें इंग्लैंडकी समस्याओं से पृथक् हैं—इनमें मौलिक अन्तर है। सन् १९२४-२९ की तरह आधुनिक समय में भी इंग्लैंड में उत्पादन-व्यय बहुत बढ़ चुका है और उन्हें घटाने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः ये सामग्रियां दूसरे देशों की सामग्रियों के साथ पृथ्वीके बाजारोंमें प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। इसलिये इंग्लैंड का अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन दिन पर दिन प्रतिकूल होता जा रहा है। इसको रोकनेके लिये इंग्लैंडने डालर सम्बन्धित देशों से आयात वाणिज्य घटाने का निश्चय किया तथा साम्राज्यके दूसरे देशों को भी इस तरह की वाणिज्यनीति प्रदान करने की सलाह दी ताकि साम्राज्य का सारा वाणिज्य जहांतक हो सके बाहरी देशों से न रहे। इस तरहसे इंग्लैंड पाउन्डकी मूल्य ह्रासके पीछे आत्म-रक्षा की चेष्टा कर रही थी। पाउन्डकी कीमत घट जाने पर यह प्रतिकूल स्थिति सदन में सुधर जायगी। सर स्टेफोर्ट क्रोफ़रने बताया कि हमें डालर आमादनी करने की ताकत बढ़ानी होगी; वही हमारी समस्या का एक मात्र स्थायी समाधान है, विशेषतः वर्तमान स्थितिमें जबकि मार्शल योजना, जिसके द्वारा हमें कुछ डालर मिल रहे हैं वह १९५२ साल में खत्म होनेवाली है। इंग्लैंड का साम्राज्यिक बाजार इस तरह से सुरक्षित हो गया। अब इंग्लैंड को न तो उत्पादन व्यय घटाने की हो आवश्यकता है और न जीवन का दर्जा नीचा करने की। साम्राज्य के सुरक्षित बाजार में इंग्लैंडकी अपनी की-मुमकी सामग्रियों को बेचनेका सुयोग पक्का हो गया।

हमारी आर्थिक समस्यायें दूसरी ही कुछ हैं। हमारी आर्थिक समस्यायें

अभी तक बाल्यावस्थामें है, इसमें आवश्यक सामग्रियोंकी कमी है, अस्म-
 तियोंसे भरी हुई है । इसमें एक ओर तो संगठनकी आवश्यकता है और
 दूसरी ओर जीर्णोद्धारकी । सरकारने रुपयेकी कीमत घटानेके समर्थनमें जो
 भी कुछ कहा है वह न तो आर्थिक स्थितिसे ही सम्बन्ध रखती है और न
 हमारे हृदयको स्पर्श हो करती है । एक सरकारी एलानमें बताया गया है
 कि भारतका आयात वाणिज्य नियन्त्रित होनेके कारण सिक्केके मूल्यह्रासके
 द्वारा सामग्रियोंकी अन्तर्वर्ती कीमत बढ़ानो न तो जरूरी होगी और न होगी
 ही चाहिये । हमारा निर्यात वाणिज्य संकोचन-प्रसारण रहित होनेके कारण
 रुपयेकी कीमत घटा कर हमारे निर्यात वाणिज्यको तथा आरक्षकी आमदनीको
 बढ़ानेकी सम्भावना भी ज्यादा नहीं है परन्तु जब इंग्लैण्ड तथा दूसरे कई
 देश अपने सिक्कोंकी कीमत घटानेका निर्णय किया तो हमारे लिये स्थिति ऐसी
 हो गई कि भारतको भी अनुरूप कदम उठाना पड़ा । अगर हम ऐसा नहीं
 करते तो हमारे व्यापारिक अनुमानोंपर इसका गूरा असर होता । क्या सरकार
 को इस मुश्किल कोई नैतिक आभार भी है ? इंग्लैण्डकी तरह हमें आज
 विदेशमें व्यापार बढ़ानेकी आवश्यकता नहीं है । हमारे सामान्यकी कमी
 घटानेके लिये तथा आर्थिक विकास तथा जीर्णोद्धार के लिये आवश्यक
 औजार मंगवानेमें जितने विदेशी सिक्कोंकी आवश्यकता है, हमारा विदेशी
 व्यापार उठानेमें ही सीमित रह सकता है । हमारी वर्तमान स्थितिमें अमे-
 रिकाने औजार तथा अनाजका आयात बन्द कर देना गतजगह होगा ।
 इंग्लैण्डको बचानेके लिये हमारी सरकार गलत रास्तेपर चल रही है ।
 स्टार्लिंगके साथ सम्बन्धित होनेके कारण हमें जितनी हालातों पहुंची हैं उनका
 इतिहास इतना आधुनिक है कि उसको दोहराना निम्नोक्त है । कोय वर्ष
 पहले हमारे देशकी विदेशी मुद्रामूल्य जिन बाजारोंमें स्टार्लिंग-मुद्रायोगकी ताकत
 की भी आज हमारी आजी सरकार भी उन्हीं बाजारोंकी दोहरा रही है ।
 इस संबंधके कारण भारतसे "क्रेडिट-मन्त्रित" होनेकी निर्यात हुई भी गिनती

रोकनेकी ताकत सरकारमें न थी। आज हमारी सारी शक्ति देशमें आर्थिक विकास पर विनियुक्त करनेकी आवश्यकता है।

अब प्रश्न यह है कि क्या हम रुपयेकी कीमत घटा कर निर्यात बाणिज्य को बढ़ा सकते हैं ? शायद नहीं। क्योंकि एक ओर तो औद्योगिक उत्पादन घटनेके कारण हमारे आर्थिक संगठनमें असुविधाएँ पहुँचिगी और दूसरी ओर देश विभक्त होनेके कारण हमारे हाथमें निर्यात योग्य सामग्रियोंकी कमी हो गई है। पहले पाट तथा रुई ये दोनों हमारे निर्यात बाणिज्यमें मुख्य थे और इनसे हमें काफी विदेशी किराने मिलते थे। १९४६-४७ ईसवीमें भारत से १६ लाख गाँठ कच्चा पाट तथा ४६ लाख गाँठ पाटमें बनी हुई सामग्रियोंका निर्यात हुआ था जिनकी कीमत ८९ करोड़ रुपये थी और यह हमारे निर्यात व्यापारमें २६% था। अब पाटकी पैदावारकी प्रतिगत ७५ पाकिस्तानके हिस्सेमें आ चुकी है। पाटकी तरह रुई, कन, समदा आदि काफी तायदादमें हमारे हाथसे निकल चुके हैं। भूतपूर्व वर्यमंत्री श्री श्री० एच० भामाके मतानुसार विभाजनसे हमें वार्षिक मुद्रागत लगभग २५ करोड़ रुपये पहुँचा। इस स्थितिमें रुपयेकी कीमत घटाकर हम जिस तरहमें निर्यात बाणिज्य बढ़ा सकते हैं। आज हमारे दयोग-भण्डोंमें जो कच्ची मालकी खपत होती है वे बाहरसे मंगाने जाते हैं। पाट पाकिस्तानके जाता है लेकिन पाकिस्तानके रुपयेकी कीमत न घटी। इस स्थितिमें हमारे दयोग-भण्डोंमें लगनेवाले कच्चे मालकी हम कहीं तक ज्यादा भावपर मंगवा सकते हैं और उनसे बनी हुई शिल्प सामग्रियों की निर्यातमें घटने भावपर येन सकते हैं। इस स्थितिमें हमारे अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देनकी प्रतिकूलता रुपयेकी कीमत घटानेसे जानेवाली नहीं है। साथ-ही-साथ अनाजकी घातकी घट्ट होनेके कारण हमारी खाद्य-स्थिति और भी नाजुक होनेकी सम्भावना है। हम कभी तक ऐसी कोई कृषि योजनाकी आवश्यकता नहीं बना सकते हैं जिससे निर्यात बाणिज्यमें हमारी खाद्य-स्थिति अपनी तरफसे सुधर सके।

आज हमारे निर्यात वाणिज्यको बढ़ानेकी आवश्यकता है परन्तु वह बिना
को कीमतको घटाकर नहीं बढ़ सकती । आज हमें नई-नई सामग्रियों पर
विदेशियोंका ध्यान आकषित करना होगा, इनके उद्योगसे विदेशियोंको परिचित
करना होगा ताकि वे इन्हें खरीदें । अभी तक हमारे देशसे जिन चीजोंका
निर्यात होता है जैसे कि चाय, पाटसे बनी हुई सामग्रियाँ, शकरक, मैंगलीक
आदि उनके बारेमें हमें प्रतिस्पर्द्धाका सामना नहीं करना पड़ता और वे ऐसी
चीजें हैं जिनकी खपत बढ़ानेके लिये भी हमको कीमत नहीं घटानी पड़ेगी ।
इनके साथ-साथ हमें विदेशियोंको अपनी विद्युत् सामग्रियोंके साथ परिचित
करना होगा ताकि विदेशी बाजारोंमें इनकी खपत बढ़े । मध्य प्रायद्व, उत्तरी
अफ्रिका, दक्षिण-पूर्वी एशियाके विभिन्न बाजारोंमें लक्ष्यके बजड़े हमारा जो
अधिकार जमा है उसे कायम रखनेके लिये भी दृष्टि रखनी होगी । लक्ष्यके
पहले हमारा मध्यप्रान्त व्यापार काको था ; उसे फिरसे चालू करनेपर ध्यान
देनेकी आवश्यकता है । इन सब तरीकोंको छोड़कर हमारी सरकार ऐसी
एक रास्तेपर चल रही है जहाँसे हमारा आर्थिक भविष्य उज्ज्वल नहीं दिखई
पड़ता । देशका निर्यात वाणिज्य तब ही बढ़ सकता है जब कि देशमें
पैदावार बढ़े । हमारी सरकारकी आर्थिक नीति इन दोनोंको ही ध्यानमें रखी
है । जब बीजार तथा कच्चे मालका आयात बन्द हो जायगा तब हम पैदा
पैदावार बढ़ानेकी बात सोच सकते हैं ? कृषिसे सब प्रकारके लाभ सम्पन्न
रहनेकी कीमत कितनी ज्यादा है ? आज हम इस कीमतका बढ़ावा कैसे
कर रहे हैं ।

हमारी स्थिति इसी प्रकारकी है । एक ओर पैदावार बढ़ाने की सम्भावना
जब कम हो जायगी और दूसरी ओर हमको कीमत घटाने के कारण
सामग्रियोंके निर्यातका दुष्परिणाम होगा जिससे देशमें सामग्रियोंकी कीमतें
ज्यादा हो एवं हमारी कीमत बढ़ने लगेंगी । सुदूरगमिके दुष्परिणामोंकी दृष्टि-
नेत्रे लिये सरकारने भी ध्यानमें रखा है । उन पर पूरी दृष्टि रखनी । सब

लिया जाय कि हमारी सामग्रियों का मूल्य स्तर पर रुपयेके मूल्य द्वारा पूरा असर हो रहा है तो यह प्रतिशत ३० बढ़ जायेगा । सामग्रियोंकी कीमत बढ़ जाने के कारण प्रत्येक उत्पादन-प्रापन के पीछे लागत भी बढ़ जायेगी जिसकी रोकना सरकार के लिये सहज-प्राप्य नहीं होगा । ऐसे ही वैसे हुए इस वर्षोंमें हमारी आर्थिक व्यवस्था पर बहुतसी चोटें आई हैं ; और फिर ये सामग्रियोंकी कमी होगी एवं श्रमिक असंतोष बढ़ता चलेगा । जब सरकार रचनात्मक कार्यों पर भी व्यय-संकोच कर रही है तब मूल्यवृद्धि का यह सुयोग देना किस प्रकार से उचित होगा ? सिका दर रास घोषित होनेके साथ ही साथ बाजार में अनिश्चयता फैल गई और हमारी वार्षिक व्यवस्थाके सामने अन्धेरा छा गया । इस तरहसे भविष्यमें सामग्रियों की कमी बढ़नेवाली है और सारी जनता के लिये, विशेषतः मध्यम वर्गके लिये और भी दुर्दिन आने-वाले हैं । अध्यापक भक्ति के शब्दोंमें, हमारे वान्तर्वासी मूल्यस्तर : स्टालिंग मूल्य तथा डालर मूल्योंसे अधिक है; इस दृष्टिसे अगर देखा जाय तो मूल्यस्तर घटाने के लिये हम रुपये की न्ययशक्ति बढ़ाने की बात समझ सकते हैं । पर यह जब असम्भव था तो रुपये का विनिमय कीमत घटाकर हमें मूल्यस्तरों के झूकाव को मदद देनी उचित नहीं थी ।

इस स्थिति में स्टालिंगके साथ रुपयेका सम्बन्ध फौरन तोड़ देना चाहिये । स्टालिंग के साथ रुपये को सम्बन्धित रखने में विशेष महत्त्व नहीं है, कारण हमारी स्टालिंग रकम का ३-४ हिस्सा खतम हो चुका है । अब जो स्टालिंग रकम बची है वह नाममात्र है । इसका वह हिस्सा जिसको हम डालर में बदल सकेंगे रुपये का मूल्य कम होने के कारण कम हो जायेगा । हमारे देश में सामग्रियों की कीमत बढ़ने पर हमारे स्टालिंग पत्र के विनिमय में हमें कम सामग्रियां मिलेंगी । दूसरी ओर संयुक्तराष्ट्र अमेरिका जिसके साथ हमारा सम्बन्ध गभीर होता जा रहा था वह नष्ट हो जायेगा । पश्चिम की रुपयेकी कीमत नहीं घटाने के कारण हमें और भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा ।

जानकारों का कहना है कि पाकिस्तानको यह नीति ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकती एवं भारत भी पाट की पैदावार बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है ताकि यह पाकिस्तान पर निर्भर न रहे। परन्तु इस दुर्किस्से हमें संतोष नहीं होता। दीर्घकालीन स्थिति में जो भी कुछ क्यों न हो वर्तमान समयमें देश का आर्थिक संगठन करना ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है जिसके लिये राज्य के साथ राज्य का पूर्वदर कायम रखना ही अधिक उचित होता। इसमें अमेरिका तथा पाकिस्तान इन दोनों देशों के साथ हमारा आर्थिक सम्बन्ध ठीक रहता एवं हमारी रचनात्मक आर्थिक नीति सकलसिद्ध हो सकती। पैदावार बढ़ाने के साथ साथ हमारी वर्तमान स्थिति एवं राज्य की अन्तर्बर्धों एवं विदेशी क्रयशक्ति की असमानता भी दूर हो जाती।

पाउण्ड तथा दूसरे देशोंके सिक्का-विनिमय दर ३० प्रतिशत घटने जाने पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाकी मर्यादों हानि पहुँचेंगी। यह संस्था अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिये तथा सिक्का विनिमय दर स्थिर करने के लिये कायम की गई थी। लक्ष्ये सतम होने के बाद फ्रैंक तथा दूसरे कई सिक्कों की विनिमय कीमत घटाई गई थी; साथ पाउण्ड तथा स्टर्लिंग सम्बन्धित सिक्कोंकी कीमत घटाई गई है। प्रत्येक देश यदि इस तरह से धातुन सिक्कों की कीमत मनमानी तौरपर घटाता रहे तो इन अन्तर्राष्ट्रीय संगठनोंकी मर्यादा क्या होगी? भविष्यमें यदि इसी तरहसे डॉलर की कीमत भी घट जाये तो सारी कार्रवाइयों पर पानी फिर जायगा। वर्तमान स्थितिमें भारत के लिये सोचने की बात यह है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय बँकके जो डॉलर धन लिया है उनके लिये भारतको प्रतिशत ३० रुपया अधिक देना पड़ेगा यानी इस दिग्गज से इस वर्जरा बोझ हमारे ऊपर बढ़ जायेगा। चिके नदी नहीं पब्लिक एमेरिकाकी सामग्रियाँ जब भारत तथा दूसरे स्टर्लिंग सम्बन्धित देशोंमें नहीं आ सकेंगी तब अमेरिकाके पूर्वीपश्चिम इन देशोंमें रहस्य समाकर जलवा उठानेकी कोशिश करेंगे। यह स्थिति हमारे उपयोग धन्यों के लिये और भी भयानक

होगी। रुपये की कीमत घटानेके पढ़ले भारत सरकारको इन सब धानेवाली धानियों पर गहरी तौरसे ध्यान देनेकी आवश्यकता थी।

भारतीय बैंक व्यवस्था—^{प्री.} बैंक व्यवस्थाका सुधार

भारतीय बैंकव्यवस्थाकी विशेषता—भारतीय बैंकव्यवस्थामें ऐसी कुछ विशेषतायें नजरमें आती हैं जोकि दूसरे देशोंमें नहीं पाई जाती। भारतमें एक ओर तो विभिन्न प्रकारसे संगठित बैंक हैं और दूसरी ओर इनकी व्यापार पद्धतिमें बहुत ही विभिन्नतायें हैं। हमारी बैंक व्यवस्थाको दो दिशोंमें बांटा जा सकता है—एक तो पुरानी और दूसरी आधुनिक। पुरानी व्यवस्थामें महाजन साहुकार, सराफ, चेट्टो आदि हैं और आधुनिक व्यवस्थामें कुछ तो भारतीय बैंक हैं और कुछ विदेशी जिनके बीच पारस्परिक सहयोग कम है। साथ ही साथ इंग्लिरियल बैंककी तरह एक बड़ी बैंक भी इस व्यवस्थामें शामिल है जोकि व्यापारिक बैंक होते हुए भी अभीतक केन्द्रीय बैंकका कुछ कुछ अधिकार रखती है। हमारी केन्द्रवर्ती बैंक यानी रिजर्व बैंक अफ एशिया कुछ नवीन संस्था है और इसे अभीतक इतनी सफलता नहीं प्राप्त हो सकी है जिसमें कि यह प्राचीन व नवीन सारी बैंक व्यवस्था पर प्रभुत्व धर सके।

प्राचीन बैंक व्यवस्था—हमारी बैंक व्यवस्थामें प्राचीन बैंक व्यवस्था अधिक महत्व रखती है। इसमें दो प्रकारके कारदारों दिशाई पड़ते हैं—एक तो महाजन जो कि देहातोंमें किसानोंको रुपया कर्ज देते हैं और दूसरे सराफदार जोकि वास्तवमें बैंकव्यवसायी हैं। इन बैंकव्यवसायियोंका व्यापार बहुत ही सुचारु है। जबकि पाश्चात्य देशोंमें बैंकका अस्तित्व तक न था और न इनका कोई नाम तक जानते थे तबहीसे भारतीय बैंक व्यवस्थालोगन बिके वस्तुद्वारा बैंक व्यवस्थामें

ही नहीं बल्कि विदेशी व्यापारमें भी पूरा हिस्सा लेते थे । आधुनिकताके दबावमें धीरे-धीरे व्यापारहीन संकुचित हो रहा है लेकिन इस पर भी भारतके आन्तरिक व्यापारमें इनका हिस्सा ही मुख्य है । अनुकारणन किसी निश्चित समयके लिए कर्म नहीं देते लेकिन साधारणतः फल लट जानेके बाद इसकी रचना लौट आती है । इनकी रचना ज्यादातर परक होती है; यहीही कर्म पैना या अमानत खोदकर करना इनकी व्यापार पद्धतिमें स्थान नहीं पाता । आज कल व्यापार बढ़ जानेके कारण ये लोग एक दूसरेको अपना कर्म देते हैं और कभी-कभी पैकोंसे भी कर्म लेते हैं । पैकोंसे कर्म लेनेके लिए वे लोग गुन्धी बेचते हैं । सर्वपर व्यापार बहुत बढ़ता जाता है परन्तु इनमें अनेक समय ऐसे कामोंमें रुक लगानी पड़ती है जिसमें कानूनी जोखिम है । हमारी प्राचीन पैदलपरवादा संगठन, इसकी आधिक संघति, मर्यादा तथा व्यापारिक भाव, व्यापारियोंसे इसका वैयक्तिक सम्बन्ध, इतना गंभीर तथा प्रभावशाली है जोकि किसी भी पैदलपरवादा में नहीं पाया जाता । भारतीय आर्थिक व्यवस्थाके साथ पैदलपरवादा विचारों सदृशतासे जुड़ा हुआ है । इनकी व्यापार पद्धति बहुतही सरल होती है तथा व्यापारियोंके प्रयोजनके साथ ही साथ हमने आसानीसे परिवर्तन भी किया जाता है । पैदलपरवादाके आधुनिक विचारों इनमें अभाव होते हुए भी इनके पास दली संचित अभिरुचि है जोकि विश्व से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है । आधुनिक समयमें इनका व्यापार आन्तरिक व्यापारिक कर्म तथा परेष्ट व्यवस्था-धर्मोंमें आधिक महत्त्वता करनेमें ही सीमित है । वत १९३५ में जब भारतमें रिजर्व बैंककी प्रतिष्ठा हुई थी तब उम्मीद किया गया था कि इस केन्द्रकी व्यवस्थाके साथ भारतीय पैदलपरवादा गंभीर सम्बन्ध स्थापित हो जायेगा कारण इसके अभावसे केन्द्रकी बैंक व्यापारको पूरी महत्त्वता नहीं प्राप्त हो सकती है । इसी वृद्धि के महत्त्व करनेके लिए रिजर्व बैंकने दो प्रस्ताव रखे थे जिसमें कहा गया था कि देशी पैदलपरवादाओंको पैदलपरवादाके अतिरिक्त दूसरे किसी व्यापारसे सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए

तथा उनको अपनी आर्थिक स्थितिका पूर्णनिर्वाण प्रकाशित करना न दिये। यह प्रस्ताव साहुकारोंको नजूर न था। उनका कहना यह था कि दिन पर दिन हमारा बैंक व्यवसाय जिस प्रकारसे सीमित होता जा रहा है उसमें दूसरे व्यवसायों को अपनाते के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। इन लिए आज तक केन्द्रवर्ती बैंकोंके साथ प्राचीन बैंकव्यवस्थाका सम्बन्ध नहीं स्थापित हो सका और यह हमारी बैंकव्यवस्थाकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर इन दोनोको सम्बन्धित करना हो तो रिजर्व बैंक को उचित होगा कि जिसमें इसका बैंक विषयक व्यापार बढ़े उसपर ध्यान दे तथा यदि ये लोग दूसरे व्यापारोंमें बैंक सम्बन्धी व्यापारको अलग रखते तो उसीमें ही संतुष्ट हो जाने कारण दिनों भी व्यवसायों, अचानक परिवर्तन करना सम्भव नहीं हो सकता।

आधुनिक बैंक व्यवस्था—(१) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (रिजर्व बैंक विषयक निबन्ध देखिये)।

(२) इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया—सन् १९२० में बंगाल, एन्डर तथा मद्रासकी प्रेसीडेन्सी बैंकों को सम्मिलित करके इम्पीरियल बैंक की प्रतिष्ठा हुई थी। इम्पीरियल बैंक भारतीय बैंक व्यवस्थामें एक विभिन्न प्रतिष्ठान है। भारतमें सन् १९३५ में रिजर्व बैंक की प्रतिष्ठा होने के समय तक केन्द्रीय बैंक का कुछ कुछ अधिकार, जैसाकि वर्तमान दिनोंमें इस बैंक पर था वैसा यह बैंक पूर्णतया केन्द्रवर्ती बैंकका अधिकार नहीं रखती थी किन्तु बैंक को बैंक बनने का अधिकार सरकारी मुद्राप्रचल पर था। साथ ही साथ यह बैंक व्यापारिक बैंकोंके साथ प्रतिस्पर्धिता करनेवाली शक्तोंमें ही गिनुका थी। इन कारणों से दूसरी बैंकें इम्पीरियल बैंक पर न तो पूरा भरोसा ही रखती थी और न इसके साथ सहयोग ही करती थी। केन्द्रवर्ती बैंक के कुछ अधिकारों के अतिरिक्त बैंक विषयक छारे शक्तोंका अधिकार भी इम्पीरियल बैंक पर था एवं सरकारी अमानतों भी इस बैंकके हस्त में रहती थी। सन् १९२३ में इस बैंककी एक शाखा लखनऊमें खोल दी गई। इस बैंक पर भारतीय

नियंत्रण भी कुछ हद तक जारी था। इसलिये जब भारत में केन्द्रीय बैंक स्थापित करने का सवाल पहले पहल आया तब अनेकों का सिद्धान्त ऐसा रहा कि इम्पीरियल बैंक को ही केन्द्रीय बैंक का पूरा अधिकार दे दिया जाय। अपने सिद्धान्त के समर्थनमें इनका कहना यह था कि भारतमें न तो व्यापारिक हुन्डों का बाजार ही है और न काफी ताबदादमें हुन्डियां ही पाई जाती हैं जिस से कि एक नई केन्द्रवर्ती बैंक की स्थापना की जाय। इसके अलावा इम्पीरियल बैंक की तरह एक बड़ी बैंक के पास एक नई केन्द्रवर्ती बैंक की स्थापना करना उचित नहीं होगा। परन्तु हिल्टनयंग कमीशन के ज्यादातर सदस्यों ने बताया कि वास्तवमें इम्पीरियल बैंक एक व्यापारिक बैंक, ही है केन्द्रीय बैंक नहीं। इसके पास इतनी अभिज्ञता, इतनी रकम, इतना प्रभाव, इतनी शाखाएँ हैं जो कि व्यापार की तरह तरह से फायदा दे सकती है। इसलिए इनकी राय एक पृथक् केन्द्रवर्ती बैंक स्थापित करने के पक्षमें रही। अन्तमें जब रिजर्व बैंक अध्र इण्डिया को स्थापना की गई तब इस बैंक के हाथमें केन्द्रवर्ती बैंक का जितना अधिकार था उस सब का अन्त कर दिया गया। परन्तु जिन सब जगहों में इम्पीरियल बैंक की शाखाएँ हैं वे आज भी रिजर्व बैंक की ओर से केन्द्रवर्ती बैंक का बहुत काम करती हैं। इस विषयमें रिजर्व बैंक के साथ १५ वर्षों के लिये एक समझौता हुआ था यह आज भी जारी है एवं भविष्यमें भी जारी रहेगा। यदि इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से सम्बन्ध तोड़ना चाहे तो ५ वर्ष पहले सूचना देनी पड़ेगी। इस प्रकारसे इम्पीरियल बैंक एक व्यापारिक बैंक होते हुए भी दूसरी व्यापारिक बैंकोंसे अधिक अधिकार रखती है तथा भारतकी मुख्य व्यापारिक बैंक भी नहीं है लेकिन हमारी बात तो यह है कि दूसरे बैंकोंके साथ सहयोग करना या भारतीय बैंक व्यवस्था को संगठित करने में इम्पीरियल बैंक की जितना क्षमता है उसका या हमसे यह आज भी चलन रही है।

(३) विदेशी बैंक—भारतीय बैंक व्यवस्था में विदेशी बैंकों का विशेष

महत्वपूर्ण स्थान एवं अधिकार है। दूसरे स्थानों भी स्वतन्त्र देशों में विदेशी बैंकों को इतना अधिकार नहीं दिया जाता जितना कि उन्हें भारत में दिया गया है। इन्हें हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं एक तो वे बैंक जिनकी सामान्तों का प्रतिशत २५ या उससे अधिक हिस्सा भारतीय जन साधारण से प्राप्त किया गया है और दूसरी वे बैंक जिनकी सामान्तों का प्रतिशत २५ हिस्से से भी कम भारतसे प्राप्त किया गया। भारतके विदेशी व्यापार में रकम लगाना दो इन बैंकों का मुख्य कारवार है। सन् १९३५ तक इंग्लैण्ड बैंकों की विदेशी हुन्डी का कारवार करनेका अधिकार न था और भारतीय बैंक व्यवस्था में इसकी अभिज्ञता तथा शक्ति न थी जिससे वह इन काममें साथ पड़ा सकती थी। इसलिये भारतके विदेशी व्यापार का आर्थिक प्रबन्ध पूरी तौरसे इन विदेशी बैंकों पर था और अभी भी इस व्यवस्था में कोई उद्योगशील परिवर्तन नहीं हुआ। इसके अलावा विदेशी बैंक, बैंक सम्बन्धी हर तरहके कारवार करती हैं और बड़े बड़े शहरों में जैसे कि दिल्ली, बालपुर, अमृतसर आदि शहरों में इनकी शाखायें फैल चुकी हैं। वर्तमान समयमें ये हमारे आन्तरिक व्यापार तथा गृह-उद्योग में भी रकम लगाती हैं। जो भी कुछ ही भारतीय व्यापार तथा उद्योग पर अतीतने इनकी घटानुभूति तथा घटयोग पड़ा हो कम होने के कारण भारतीय जनमत परावरसे इन बैंकों पर सरकारी नियन्त्रण बढ़ाती है। विदेशी बैंकोंका भारतीय विपदा बाजारमें कारवार करने पर भी हमारा सम्बन्ध ज्यादातर अपने अपने देशों की केन्द्रस्थी बैंकोंसे तथा हुआ रहता है मगर इनसे हमारी वर्षाव्यवस्था प्रभावित होने पर भी इन पर हमारी रिजर्व बैंक का कुछ भी हाथ नहीं है, यदातक कि अनेक समय में भारतीय व्यापारियों के खिलाफ काम करती रही हैं। इसलिए १९२९ में केन्द्रीय बैंक कायम होनेसे यह सलाह दी थी कि इन बैंकों पर नियन्त्रण तथा दिनांक न्याय ऐतिहासिक यह परामर्श अभी तक अकार्यक्षम नहीं हुआ। इसलिए अभी भारतीय बैंक इस विदेशी क्षेत्रमें सक्रिय नहीं पाती तथा विदेशी व्यापार या विदेशियों का

एकधिकार जमा हुआ है। स्वतंत्र भारतमें इस एकधिकारको तोड़ देनेकी आवश्यकता है ताकि प्रत्येक बैंकको हरतरहके कारबार करनेका सुयोग मिले। विदेशी बैंकोंके बारेमें हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए कि हम विदेशी बैंकोंको उतना ही सुविधा दें जितना कि वे हमारी बैंकोंको उन देशोंमें कारबार करनेके लिए दे रही हैं।

(४) भारतीय सम्मिलित पूंजी बैंक—इन बैंकोंका इतिहास बहुत ही आधुनिक है। उन्नीसवीं शताब्दीके अन्त समयमें कुछ देशी बैंक स्थापित हुई थी लेकिन १९०५ के स्वदेशी आन्दोलनके बादसे इनका व्यापक विस्तार हुआ। इस समय भारतीय जनसाधारणको बैंकोंके बारेमें अभिज्ञता न रहने के कारण बहुतसी बैंकों को कारबार बन्द कर देना पड़ा और इससे बैंक व्यवस्था के बारेमें जन-साधारणके मनमें छर पैठ गया। भारतीय बैंक व्यवस्थाके कई विशेषतायें हमारे नजरमें आती हैं। पहली, भारतीय बैंकव्यवस्था कायम होनेके पहले भारतमें आधुनिक उद्योग-धन्योंकी स्थापना होने लग गई थी; इसलिए जर्मनीकी औद्योगिक बैंकोंकी तरह भारतीय बैंक व्यवस्था उद्योग-धन्यों के विस्तारमें दाय न बटा सकी। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह उद्दिष्ट बैंकव्यवस्थाका अनुकरण को है। इसलिए इनका कारबार आभिमियादी कर्म देनेमें ही सीमित है, दीर्घमियादी कर्ज देनेमें नहीं। तीसरी विशेषता यह है कि हमारी बैंक व्यवस्था विदेशी व्यापारमें अभी तक उन्नेसवीं शताब्दी तक तथा आन्ध्रनगरीन, व्यापारमें भी इन्हीं मर्यादों का अनुसरण विदेशी बैंक तथा एम्पौरियल बैंककी प्रतियोगिताता सामना करना पड़ता है। चौथी विशेषता यह है कि हमारी बैंक व्यवस्थाके संगठनों इतनी कमजोरियाँ हैं जिनसे यह इन आगे नहीं बढ़ पाती तथा हरसमय ही कुछ न कुछ बैंकोंका कारबार बन्द हो जाता है। पाँचवीं तथा अन्तिम विशेषता यह है कि हमारी बैंकव्यवस्था पर केन्द्रित बैंकका नियंत्रण समान नहीं है। मिडिलेज बैंकोंके सम्बन्ध में जितना परिभाषित है दूसरे बैंकोंके लिये नहीं। सन १९१३-१८ को बैंक

(१५७)

दुर्घटनाके बादसे बैंकव्यवस्था बहुत कमजोर हो चुकी थी। इसने सुधारके लिए एक पृथक बैंक सम्बन्धी कानून बनानेके लिए सन १९२९ को बैंक लॉन समितिने सलाह दी थी। सन १९३६ में जब सम्बन्धी कानूनका संशोधन हुआ तब उसमें भी बैंक सम्बन्धी कई भारी जोड़ी गईं। सन १९३८ में फिरसे बैंक दुर्घटना की सम्भावना दिखाई देने लगी तथा बैंक सम्बन्धी कानूनकी आलोचना फिरसे शुरू होनेके कारण यह काम न कर सके। तब के वक्त बैंककी पूंजी तथा शाखा विस्तारके बारेमें सम्बन्धी कानूनमें कुछ संशोधन किये गये हैं। सन १९४९ में बैंक सम्बन्धी एक कानून बना है जिसमें बैंक व्यवस्थाकी पूर्णतौरसे सुधारने पर ध्यान दिया गया है। बैंक की पूंजीकी तरलता, पूंजीका विनियोग, संचालकोंसे बैंकोंका सम्बन्ध, सम्बन्धीका दायित्व आदि विषयों पर इतनी नवीन धारणें संयोजित हुई हैं जिनसे समीक्ष किया जाता है कि भविष्यमें बैंक दुर्घटना बहुत कम हो जायेगी। बैंक सम्बन्धी को यदि पूरी तौरसे सुधारनी हो तो तब के अनुसार कानून बनाने में ही नहीं होगा बल्कि साथ ही साथ बैंकोंकी व्यापार प्रवृत्ति, बैंकोंका प्रभुत्व, बैंकोंका संगठन, आदिमें भी यथोचित परिवर्तन करना होगा ताकि इनकी सम्बन्धीकी दूर हो जाएँ और हमारी बैंकव्यवस्था सफल स्वस्थ होकर चलने लग सके।

भारतीय रिजर्व बैंककी सहता—रिजर्व बैंकका राष्ट्रीयकरण

आधुनिक समय में एक भी देश ऐसा नहीं है जहाँ केन्द्रिय बैंक नहीं है। यहाँतक कि छोटा से छोटा और नया से नया देश भी अपना केन्द्रिय बैंक स्थापित कर चुका है। आधुनिक वाणिज्य व्यवस्थामें बैंक का हीरक पत्थर माना

रखता है कारण दिन पर दिन हम व्यक्तिवादो आर्थिक व्यवस्था को छोड़कर केन्द्रवर्ती योजनाओं के द्वारा परिचालित आर्थिक व्यवस्था की ओर जा रहे हैं और इस नई आर्थिक व्यवस्था में जोकि केन्द्रीय योजनाओं पर अवलम्बित है, केन्द्रीय बैंक का एक विशिष्ट स्थान है।

केन्द्रीय बैंक के बारे में पुरानी दृष्टिवाले अर्थशास्त्रियोंका प्रस्ताव यह था कि संस्था को जहां तक हो राजनैतिक प्रभावों से मुक्त रखना चाहिए और इसलिए वे शेयरधारी तथा सदस्य बैंकों के द्वारा केन्द्रीय बैंक की संचालक मंडली के चुनाव का समर्थन करते थे। आधुनिक समय में आर्थिक स्थिति इतनी बदल गई है कि कोई भी केन्द्रीय बैंक अपने को राष्ट्रीय प्रभावों से मुक्त नहीं रख सकता लेकिन इस पर भी दूसरी लड़ाई के पहले तब केन्द्रीय बैंकों को जहां तक हो सकता था निलिप्त रखा जाता था। सन् १९३४ की रिजर्व बैंक कानून भी इसी सिद्धान्तके आधार पर बनाई गई थी ताकि रिजर्व बैंकके संचालकमण व शेयरधारियोंके द्वारा निर्वाचित हों। इसके अलावा विभिन्न प्रान्तोंमें शेयरोंके बंधार्थ वितरणके लिए भी इस कानूनमें प्रवन्ध किया गया था ताकि रिजर्व बैंक किसी भी एक प्रान्तके मुद्दीमें न आ जाय। परन्तु वास्तवमें ये कार्यवाहियां सफल नहीं हुईं कारण एक ओर तो सरकारी मनोनीत संचालकोंकी संख्या दूसरे संचालकोंके बराबर रही तथा रिजर्व बैंकके गवर्नरको अतिरिक्त कानूनी अधिकार दे दिया गया तथा दूसरी ओर रिजर्व बैंककी ज्यादातर शेयरें गवर्नरके पूंजीपतियोंके वज्जेमें आ गईं। इस प्रकार ने कानूनी दृष्टिसे रिजर्व बैंक राष्ट्रीय प्रभावोंसे मुक्त होवे हुए भी वास्तविक रूप में ऐसा नहीं हुआ और कुछ दिन पहले जब रिजर्व बैंकका राष्ट्रीयकरण हुआ तो उससे रिजर्व बैंककी व्यापारिक नीतिमें कोई भी परिवर्तन करनेकी आवश्यकता नहीं हुई।

रिजर्व बैंक स्थापित होनेके पहले भारतमें पूर्ण दृष्टिसे कोई केन्द्रीय बैंक नहीं था। भारतमें केन्द्रीय बैंक स्थापित करनेका प्रयत्न बहुत ही प्राचीन

है। भारतकी तरह एक महारिश्तेमें सुझ-नौति तथा कर्ज व्यवस्था नियंत्रण के लिये एक केन्द्रीय बैंककी आवश्यकता सन १८३६ से ही सुझाई है। सन १८५६ में भारत सरकारके कार्य-सदस्य सर जेम्स फिन्चलेने भारतमें एक केन्द्रीय बैंक स्थापित करनेका प्रस्ताव दिया था। परन्तु तत्कालीन समय में जब केन्द्रीय बैंकके धामावसे आर्थिक व्यवस्थाका नाम बचका सादरनाम हो गया तब बंगाल, बम्बई तथा मद्रास प्रान्तोंके केन्द्रीय बैंकोंकी सम्मिलित दायें सन १९२० में इम्पीरियल बैंककी स्थापना की गई तथा कर्ज व्यवस्था का पूरा दायित्व इसी बैंकके हाथमें सौंप दिया गया लेकिन सुझ-नियंत्रण का काम सरकारके हाथमें रहनेसे तथा इम्पीरियल बैंक दूसरे बैंकोंके साथ समानरिक्त विषयोंमें प्रतिस्पर्धा करनेके कारण केन्द्रीय बैंकका पूरा दायित्व न बढ़ सका अतः इसकी कर्ज-नियंत्रण नीति असफल रही। सन १९२७ में सर जेम्स फिन्चलेने भारतमें केन्द्रीय बैंक स्थापित करनेके लिये एक कानून बनाया केन्द्रीय महासभामें रखा था लेकिन यह भी विभिन्न कारणोंसे सफल नहीं हो सका। अन्तमें सन १९३४ में जब रिजर्व बैंक कानून बना तब इसकी आर्थिक व्यवस्थाकी एक बहुत पुरानी मांगका सुझाव हुआ।

रिजर्व बैंक तथा सुझ व्यवस्था—रिजर्व बैंक स्थापित होनेके बाद सुझ-व्यवस्थाका पूरा काम सरकारने रिजर्व बैंकके हाथमें सौंप दिया। कानूनी सुझ जारी करनेकी नीतिमें भी परिमर्दन किया गया। इसने दिली मर इसकी सुझ-व्यवस्था इंग्लैण्डकी सुझ-व्यवस्थाके समान रहने लगी और इसमें गंभीर परिवर्तन हुआ। इस नयी व्यवस्थामें प्रति १०० रुपये के कानूनी सिक्के के पीछे ४० रुपये कीमतकी स्वर्णमुद्रा, नीनेस पाया जा सकता है सुझ रहती होगी। तबसे सुझ होनेके बाद रिजर्व बैंक कानूनी सुझ-व्यवस्था भारतमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है जिससे कि ईंग्लैण्ड तथा भारत सरकारके कानूननोंके आधारपर ही कानूनी सुझ जारी किया जा सकेगा।

इसके फलस्वरूप हमारे देशमें जो सुधारकोति हुई थी उसके दुष्परिणामोंसे हम परिचित हैं । (सुधारकोति विषयक निम्नलिखित देखिये) ।

रिजर्व बैंकमें दो दफ्तर हैं—एक तो नोट जारी करनेका दफ्तर और दूसरा बैंक विषयक काम करनेका दफ्तर । नोट जारी-दफ्तरकी पुंजी निम्न प्रकार होगी : स्वर्ण मुद्रा तथा सोनेका पासा, स्ट्रालिंग क्लयवत्र, चापा तथा भारत सरकारके क्लयवत्र । इनमेंसे प्रतिशत ४० स्वर्णमुद्रा या सोनेका पासा होंगे और इनकी सर्वनिम्न कीमत ४० करोड़ रुपये होंगे । बाकी छुट्ट होनेके बादसे इस धारामें परिवर्तन कर दिया गया है । बाकीका बाहरी कीमत नागो विदेशी सिक्कोंमें इसका विनिमय दर स्थिर रखनेका दायित्व भी इस दफ्तरपर सौंपा गया है । रिजर्व बैंक कानूनकी धारा ४० के अनुसार रिजर्व बैंक १ रुपया = १ स्ट्रालिंग ५५.५ पे. दर पर स्ट्रालिंग विक्रय करेगी तथा १ रु० = १ स्ट्रालिंग ६५.५ पे. दर पर स्ट्रालिंग खरीदेगी । भारत सरकारकी विदेशी सिक्केकी आवश्यकता पूरा करनेका दायित्व भी रिजर्व बैंकपर रख दिया गया है । रिजर्व बैंककी बैंक दफ्तरकी दोनो निम्न विषयों पर हैं : पुंजी संचयित तथा विभिन्न प्रकारकी अमादातें जोकि सरकार तथा निम्न बैंकोंमें प्राप्त होती हैं । इस दफ्तरकी जवाबदार निम्न प्रकार हैं : चापाकी तथा चापन डिता, गरीबी हुई मुद्रिकां और विदेशमें रखी हुई अमादातें व सरकार को दिया हुआ ऋण आदि ।

रिजर्व बैंक भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकारोंका साथ काम करती है । सन् १९३७ के राष्ट्रीय मन्त्रीको प्रत्येक प्रांतीय सरकार अपने नामसे दस्तावेज दिखाने पड़ेगी है तथा निम्नलिखित रकम जमा रखनी है । रिजर्व बैंक निम्नलिखित कार्योंकी तरफसे समस्त प्रयत्न करेगा, तथा ऋण लेना तथा ऋण चुकाना, निम्नलिखित सरकारों को आवश्यककारी कार्य देना आदि काम करेगा । भारतीय बैंक व्यवस्था में रिजर्व बैंक एक विशिष्ट स्थान है । बैंक व्यवस्था का नेतृत्व करना, जो कि एक संयुक्त प्रयत्न करने में सहन नहीं करता, सरकार के

आदि सारा काम रिजर्व बैंक पर है। इसके अन्तर्गत निम्न बाजार को नियंत्रित करनेका दायित्व भी रिजर्व बैंक पर है। वेनक बोने हुए २० वर्षोंमें सिखा बाजारको नियंत्रित करनेकी आवश्यकता रिजर्व बैंक को नहीं हुई। परन्तु सन् १९२९ से व्याज दर इतनी कम हो गयी है तथा बैंकिंग व्यवस्था इतनी नकद पूंजी इकट्ठी हो रही है कि उन्हें रिजर्व बैंकमें अधिक सहायता लेनेकी आवश्यकता नहीं हुई। परन्तु यह बात कहनी चाहिये कि उम्मीद पड़ने पर रिजर्व बैंक सिखा बाजार तथा कर्ज व्यवस्थाको नियंत्रित कर सकता है।

रिजर्व बैंकका राष्ट्रीयकरण—रिजर्व बैंकके राष्ट्रीयकरण का मत मतलब है मुख्य है जितना कि रिजर्व बैंकका था। यह बात बताने की ज़रूरत है कि रिजर्व बैंक एक स्वतंत्र संस्था होती हुई भी व्यवस्था में व्यवस्था नियंत्रण के अन्दर रहा जिससे इसकी नीति पूरी तौरसे स्वतंत्र न रहे। अन्य देशोंमें भी गत कई वर्षोंमें केन्द्रीय बैंकका राष्ट्रीयकरण करनेकी प्रवृत्ति और प्रवृत्ति रही है। कुछ दिन पहले ही इंग्लैण्ड तथा फ्रांसमें केन्द्रीय बैंकोंका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। भारत स्वतंत्र होनेके बाद हमारे देशमें भी यह प्रवृत्ति मुख्य हुआ। सन् १९४९ के जनवरी महीनेमें रिजर्व बैंकका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। रिजर्व बैंकके राष्ट्रीयकरणके पक्षमें कई विचार प्रयोग हैं।

(१) किसी भी संस्थाको सरकार दो कार्यों से दायरे में लेती है—पहला, यदि उससे समाजको पूर्ण लाभ न हो और दूसरा वह संस्था का काम सुचारु राजकोषमें लेने के लिए। रिजर्व बैंकके सुझावोंका क्या है यह दिनांक अभी तक सरकारके हाथमें जाता रहा लेकिन इसके अन्तर्गत भारतीय जनता वर्ग, वैश्यवर्ग तथा ग्रामीण जनताको जो लाभार्थी हैं वे भी के पूरे नहीं हुई। कुछ कालोंमें सुझावोंमें भी रिजर्व बैंकका वर्गीकरण रहा। यद्यपि कानूनके अनुसार यह सरकार की नीतिमें एकाधिकार करनेसे सम्भव था परन्तु फिर भी देशके केन्द्रीय बैंक होनेके नाते सरकार को केन्द्रकारी देश समझा

कृतव्य था । (२) सरकार के सामने जो वार्षिक योजनाएँ हैं उन्हें सफल बनानेके लिए सरकार तथा रिजर्व बैंकमें पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है जो कि राष्ट्रीयकरण के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है । (३) रिजर्व बैंक की ओरों वन्धु प्रान्तके कई एक पूँजीपतियोंके हाथमें इकट्ठी होनेके कारण इस सार्वजनिक संस्थानों कुछ हानी पहुँचती थी । इसे रोक्नेके लिए भी राष्ट्रीयकरणकी आवश्यकता थी । राष्ट्रीयकरणके बाद रिजर्व बैंकमें जितने परिवर्तन हुए वे निम्न प्रकारके हैं :—

(१) वर्तमान शेयरधारियों को १०० रु० के शेयर के बदलेमें ११८००० कोमत के स्थानी ३% व्याजके ऋणपत्र दिये जायेंगे ।

(२) निर्दिष्ट दिन में गवर्नर तथा सहायरी गवर्नरों को छोड़कर संसदक मंडली के सारे सदस्य पदस्वागत करेंगे । नई संसदक मंडली में गवर्नर तथा सहायरी गवर्नरों के अतिरिक्त ११ सहायरी मनोनित संसदक रहेंगे, जिन में एक तो सरकारी पदाधिकारी होंगे, ४ संसदक ४ प्रान्तीय शासकों से भेजे जायेंगे तथा ३ सदस्यों को सरकार विभिन्न दायित्व धर्मों आदि से मनोनित करेंगी ।

(३) रिजर्व बैंक की प्रान्तीय शाखाओं में ३ संसदक रहेंगे ।

(४) केन्द्रीय सरकार भी जरूरत पड़ने पर जनसंधारण के हाथों से मुद्रित करने के लिए रिजर्व बैंककी निर्देश देगी ।

(५) रिजर्व बैंक की गवर्नर की सारे काम के बारे में पूर्ण अधिकार रहेंगे ।

राष्ट्रीयकरण के बाद यदि रिजर्व बैंक की नीति वार्षिक योजना की पूर्ण और से मदद के लिये सभी राष्ट्रीयकरण मार्गक होगी ।

भारतमें बीमा व्यवसाय

बीमा व्यवसाय की महत्ता-आधुनिक व्यवसाय में व्यापारियों को हर तरहसे जोखिम उठाना पड़ता है। इन्हें हम ३ भागोंमें बांट सकते हैं—(१) अदृश्य तथा बीमा के अयोग्य जैसे कि अचानक लग्न या क्षति; (२) दम्भमान लेकिन बीमा के अयोग्य जैसे कि सामग्रियों की शीमत में घट-पट या मांग पर जनसाधारण की रुचि में परिवर्तन का प्रभाव; तथा (३) दम्भमान एवं बीमायोग्य। सिक्रे शेषोक्त जोखिम पर ही बीमा व्यवसाय आवश्यक होता है। इस प्रकार से बीमा व्यवसाय जो जोखिम उठाता है उसका सारा बोझ उसके अपने कंधेपर नहीं रहता कारण बीमाव्यवसायी प्रत्येक बीमा करने व्यक्ति या संस्थासे प्रिमियम या फिश्त ले लेता है जिसके द्वारा वह भविष्य पूरण कर सकता है। जोखिम तो साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति या संस्था पर नहीं आती इसलिए क्षतिपूरण देनेपर भी ज्यादातर क्षेत्रोंमें बीमा व्यवसायी को घबराहट होती है एवं साथ ही साथ जोखिमका सारा बोझ एक ही जगह पर नहीं आकर सारी समाज पर, बीमाकृत सारे व्यक्ति तथा संगठनों पर पड़ जाता है जिससे किसीपर लगेसनीय बोझ नहीं आता। बीमा व्यवसायका मुख्य सूत्र क्षतिपूरण देना है—बीमाकृत व्यक्ति या संस्था इसमें मुक्त न कर सकती यानी जोखिम आनेपर जितना मुकसान पहुँचता है ठीक उतना क्षतिपूरण देना ही बीमा व्यवसायका मूल सूत्र है।

भारतमें बीमा व्यवसाय—बीमा व्यवसाय भारतीय समाजमें कोई नई वस्तु नहीं है। प्राचीन कालमें जब दूर देशोंमें भारतका व्यापार चलता था तब भी सामग्रियों की जोखिम घेची जाती थी। पारम्परिक बीमा प्राचीन समयसे प्रचलित होनेपर पर भी जीवन बीमाके साथ जाने हमारा परिचित न था; कारण भारतीय समाज व्यवस्थामें प्रत्येक व्यक्तिही इस तरह से अपने

दिया गया था जिसमें जीवन बीमाकी आवश्यकता न थी। परिवारमें जिनने लोग रहते थे चाहे वे कान करने सकें या नहीं समीके जीवन निवाहका दायित्व परिवार पर ही रहता था ; इसलिए हमारी समाज व्यवस्थामें जीवन बीमाका सुयोग बहुत कम था। भारतमें जीवन बीमा व्यवसायके आरम्भका इतिहास आधुनिक है और यह भी युरोपियोंके प्रभावसे हुआ है। वर्तमान समयमें जीवन बीमा व्यवसाय ज्यादातर भारतीय कम्पनियोंके हाथमें है तथा दूसरा बीमा व्यवसाय जैसेकि अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा आदि विदेशी कम्पनियोंके हाथमें है।

भारतमें जीवन बीमा व्यवसाय—सन् १८७० के पहले भारतमें जीवन बीमा व्यवसायका उद्योगकीय प्रचार न था तथा इसके बाद भी कुछ दिन तक यह विदेशी कम्पनियोंके हाथमें था कारण इस समय सरकारी पदस्थ कर्मचारियों को छोड़कर बहुत कम लोग जीवन बीमा करवाते थे और न जनसाधारण को इसके बारेमें जानकारी ही थी। सन् १८७० के बाद कई एक कम्पनियाँ स्थापित की गईं जिनमें सम्प्रति म्युचुअल (१८७१) तथा ओरिएण्टल गवर्मेन्ट प्रिन्सिपलिटि लाइफ एश्योरेन्स कम्पनी (१८७४) उल्लेखनीय हैं। इसके बाद और भी कई भारतीय कम्पनियाँ स्थापित की गईं और दिनपर दिन इसका विस्तार होने लगा। बीमा व्यवसायमें संकट निवारण करने के लिए शुरू से ही भारतीय कम्पनियों का प्रयत्न रहा। किसी किसी कम्पनी को जिनमेवारी सरकार पर रही तथा रकम खाने के बारे में भी से झगड़ो हो स्थापना हो गईं। इसके अलावा बाधितवार कम्पनियाँ म्युचुअल वाली पारस्परिक संरक्तों के तौर पर होने के कारण इसकी जड़ मजबूत रही। पारस्परिक संरक्तों में धनिक सदस्य मुक्त दान करने लगे जिससे प्रारम्भ समय में इसकी शक्ति भी कम रही। सन् १९०५ में जब मॉरेले भारतीय सुदृढ़ता तर लगे में भी हमारी बीमा कम्पनियों को काफी सहायता तथा मदद मिली। इस समय बहुत ही छोटी बड़ी कई कई कम्पनियाँ

स्थापित हुई जिन में से अनेकों की जड़ मजबूत न थी। बीमा व्यवसाय में दुर्घटना को रोकने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता हुई जिसके फल-स्वरूप भारत सरकार ने सन् १९१२ में दो कानून बनाई। इन में एक तो इन्स्योरेन्स एक्ट थी और दूसरी प्रोभिटेन्ट इन्स्योरेन्स एक्ट। बीमा व्यवसाय पर इनका अच्छा असर हुआ। विदेशी कम्पनियाँ सरकार को अपना कार्य विवरण देना पसन्द नहीं करती थीं; इसलिए इनके विस्तार के रास्ते पर रुकावटें पहुंचने लगीं। बहुत सी कमजोर देशी कम्पनियाँ भी पन्द हो गईं। परन्तु यही हुई कम्पनियोंकी जड़ मजबूत होने के कारण बीमा व्यवसाय सुप्रतिष्ठित हुआ। पहली लड़ाई शुरू होनेके बाद बीमा कम्पनियों की परीक्षा शुरू हुई। एक ओर लड़ाई के समय युद्ध संख्या बढ़नेके कारण अधिक क्षतिपूरण देना पड़ा तथा दूसरी ओर बीमा व्यापारमें नई आ गई तथा प्रतिभूतियों की कीमत घट जानेके कारण भी इन्हें गुराँज पहुंचा। सन् १९१८ में इन्फ्लुएन्जा से भी मरुतसे लोग मारे गये। सन् १९१९ से जीवन बीमा व्यवसायमें फिरसे तेजी आई तथा मरुतसे नई कम्पनियाँ स्थापित की गईं जिनमें कुछ कुछ कमजोर कम्पनियाँ भी प्रतिष्ठित हो चुकी थीं। सन् १९३८ में कमजोर कम्पनियों का सरकार रोकने के लिए एक नई कानून बनाई गई जिसके अनुसार प्रत्येक बीमा कम्पनी को सरकारी अनुमोदन लेनी पड़ेगी तथा आगमने ५० हजार रुपये की प्रतिभूति जमानत देनी पड़ेगी एवं निदिष्ट समयमें इस प्रतिभूति का कीमत दो लाख रुपये कर देना होगा। लड़ाईके वष बीमा कानूनमें कुछ सुविधायें दी गईं। इस कारण फिरसे बीमा व्यवसायमें कमजोरियाँ आने लगी हैं। इन्हें रोकने के लिए नई कानून बनाने की बात सोची जा रही है।

जीवन बीमा व्यवसाय का भविष्य—आधुनिक व्यापारमें जीवन बीमा विशेष महत्व रखती है। इसलिए इस व्यवसायके भविष्यके बारेमें विचार

करने की आवश्यकता है। वर्तमान समयमें इस व्यवसायमें दिन प्रदिन बढ़ती मुक्तता है—कर्मियों की पूंजी विनियोग पर कटौतें, इस व्यवसाय पर सरकारों की नीति का प्रभाव, व्यापार कम होने का प्रभाव, लागत कम करना तथा कर्मियों ने पारस्परिक सहयोग करने की आवश्यकता। सन् १९३८ के कानूनों अनुसार बीमा कर्मियों की पूंजी विनियोग पर कुछ कटौतें लगाई गई हैं ताकि ज्यादातर पूंजी सरकारी प्रतिभूतियों में लगाई जाए। बीमा व्यवसाय सम्बन्धी जो नई कानून बनने वाली है वही इस विषयमें और भी कठिन व्यवस्था की जायेगी।

बीमा व्यवसाय—भारत की प्राचीन वाणिज्य व्यवसायमें एमें बीमा व्यवसाय के उद्भावन मिलते हैं। भारत का व्यापार बहुत व्यापक होने के कारण ही बीमा का प्रबन्ध करने की आवश्यकता हुई थी। यह बीमा व्यवसाय बैंक व्यवसाय के साथ संयुक्त था। वाणिज्यिक क्षेत्र में बीमा व्यवसाय की आरम्भ करने का कृतिर विदेशी कर्मियों की है। उनकी छोटी शाखाओं में कलकत्ता ही बीमा व्यवसाय का केन्द्र था तथा वहीं पर ज्यादा बीमा व्यवसाय करने वाली १ भारतीय तथा १३ विदेशी कर्मियाँ थीं। सन् १९३१ में बीमा व्यवसाय का आरम्भ कुछ दिन बाद होने पर भी बीमा व्यवसाय में सन् १९३१ ही बीमा व्यवसाय का मूल केन्द्र है। पश्ची लन्दन के बाद कुछ कुछ भारतीय कर्मियों का आगमन के इस क्षेत्र क्षेत्र में आने लगे। सन् १९४२ में भारतमें इसकी संख्या २९४ थी जिसमें १९८ कर्मियों भारत में प्रतिष्ठित हुई थी, ६४ बाहर की कर्मियाँ थी तथा ३ लण्डन के साथ सम्बन्धित थी। अति बीमा का आरम्भ और भी वाणिज्यिक क्षेत्र में हुआ। वाणिज्यिक क्षेत्र के पहले चलि बीमा की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी लेकिन इसके बाद ही आवश्यक दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाने के कारण बीमा बीमा की संख्या बढ़ गई। ये कर्मियाँ अति बीमा व्यवसाय करती हैं वही इस क्षेत्र में केन्द्र है तथा इस क्षेत्र के विदेशी कर्मियों का आगमन जारी

है। भारत में अग्नि बीमा व्यवसायमें निर्दिष्ट नमयके लिए निर्दिष्ट जोखिम को एक-गलिसी बेची जाती है। इसके अलावा जटिल तर्ज के अनुसार भी कुछ हदतक होता है।

बीमा व्यवसाय का भविष्य—जीवन बीमा व्यवसाय को छोड़कर दूसरे बीमा व्यवसाय में हम अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। इनका दायित्व कुछ हद तक बीमा कम्पनियों का होने पर भी सारा दायित्व इसका नहीं है। सरकारी उदासीनता, विदेशी बैंकों की घातक नीति तथा हमारे विदेशी व्यापार पर परदेशियों का अधिकार हमारी बीमा कम्पनियों को व्यवसाय के इस क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक रही हैं। सन् १९३८ में जब बीमा कानून बनने का तो थी उस वक्त कहा गया था कि भारतीय कम्पनियों को संरक्षित करने का प्रबन्ध इस कानून में होना चाहिए, लेकिन १९३५ की भारत शासन कानून के अनुसार भारत सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं था जिससे वे विदेशी कम्पनियों को छोड़ कर भारतीय कम्पनियों को संरक्षित कर सकती थी। भारत का विदेशी व्यापार परदेशी कम्पनियाँ तथा विदेशी बैंकों के अधिकार में रहने के कारण भी भारतीयों को मदद नहीं मिलती थी। इनके अलावा विदेशस्थित बीमा संस्थानों भी भारतीय कम्पनियों से सहयोग नहीं करती हैं। इस स्थिति को अगर सुधारना हो तो भारत सरकार को इस विषय में हस्तक्षेप करने की विशेष आवश्यकता है। भारतीय बीमा कम्पनियोंके संगठन में भी कई कमजोरियाँ हैं। इन्हें चाहिए कि इसका संरक्षित क्षेत्र पुष्ट हो ताकि व्यापारी वर्ग इस पर निर्भर कर सकें। भारतीय कम्पनियों की निर्मल भारतीय बाजार में ही सीमित रहना उचित नहीं होगा। भारत के आयात व निर्यात में जो सब देश हैं जहाँ पर व्यापार का विस्तार हो रहा है, निर्यात प्रोत्साहन के अनुसार बीमा व्यवसाय का प्रबन्ध नहीं है वहाँ इसका विस्तार होगा यदि और इस के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होगी। विदेश में यदि हमारी कम्पनियोंकी सकलता प्राप्त करने हो तो एक ओर तो हमारी व्यापार

नीति आधुनिक तथा सुन्दर होनी चाहिए तथा दूसरी ओर इन्हें विदेशियों की सहानुभूति आकर्षित करना पड़ेगा। घोमा व्यवसाय संघ मजबूत करने के लिए संघसक्ति को भी आवश्यकता है। कुछ दिन पहले बम्बई में इस प्रश्न के दो एक संघ कायम किये गये हैं लेकिन इंग्लैण्ड के चार्टर्ड इन्स्योरेन्स इन्सटिट्यूट की तरह एक अखिल भारतीय संघ कायम होने की आवश्यकता है। अन्त में यह कहना उचित होगा कि व्यापार के जिन क्षेत्रों में अभी तक व्यापार का प्रारम्भ नहीं हुआ है लेकिन घोमा प्रबन्ध होने की आवश्यकता है जैसे कि फल घोमा, सामाजिक घोमा आदि इन पर भी हमारी घोमा कम्पनियों को ध्यान देना चाहिए। और एक प्रश्न हमारी घोमा कम्पनियों के सामने आ रहा है ; वह घोमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण का सवाल है। हमारे देश में साधारण दृष्टि से राष्ट्रीयकरण की गंभीर आवश्यकता दिखाई पड़ती है कारण कि राष्ट्रीयकरण के द्वारा जनसाधारण की सहानुभूति आकर्षित करनी सदन होगी तथा विदेशी कम्पनियों की अनुचित प्रतिस्पर्धा भी रुक जायेगी लेकिन वास्तविक दृष्टि से राष्ट्रीयकरण में कुछ अनुविधान भी हैं। घोमा व्यवसाय दूसरे व्यापार की तरह नहीं है। इसमें परिस्थितिक परिवर्तन के साथ साथ द्रुत विज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए या तो व्यापारिक अभियान की भी आवश्यकता है। इसके लिए वर्तमान स्थिति में हम राष्ट्रीयकरण की बात नहीं सोचकर घोमा कम्पनियों के साथ सरकार के पूर्ण सहयोग की बात सोचें तो यही अधिक उपयोगी होगा।

धनका असम विभाजन और उसका परिणाम— आधुनिक राष्ट्रोंकी कर-नीति

आर्थिक विचारोंमें धनके असम विभाजनका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है । प्राचीन अर्थशास्त्रोपनिषद् इस विषय पर गहरी तीव्रता से ध्यान नहीं देते थे । उनका कहना यह था कि देशमें बनी हुई संपत्तियों उत्पादनके विभिन्न साधनोंमें उनकी उत्पादनशक्तिके अनुपातसे बांट दी जाती हैं । वितरण-नीतिकी यह व्याख्या बहुत ही सरल थी लेकिन इसके द्वारा धन वितरणकी विषमताको रोकना सम्भव न था । एक ओर तो धनिक अधिक धनशाली बनते रहे एवं दूसरी ओर दरिद्रताकी तीव्रता दिन पर दिन बढ़ती रही, यहाँ तक कि समाज में बनी हुई संपत्तियोंका ज्यादातर हिस्सा अल्पसंख्यक लोगोंके हाथमें आ गया और अधिक संख्यक लोग बिना मूल्यशक्तिके काट पाने लगे । धनका असम-विभाजन पूंजीवादो अर्थ व्यवस्थाका धर्म है । परन्तु यह स्थिति जल्दा दिन तक स्थायी नहीं रह सकती । पूंजीवादो अर्थव्यवस्थाके बारेमें गंभीर आलोचना शुरू हुई ; समाजवादोपनिषद् ऐसे जड़ मूल्योंके उत्पादनके लिए आन्दोलन करने लगे । अर्थशास्त्रके दृष्टिमंचमें भी परिवर्तन आ रहा है ; जातीय संपत्तिके विभाजनके बारेमें आलोचना करते हुए अर्थशास्त्रोपनिषद् अल्पसंख्यक कान्यनिक उत्पादन साधनोंकी बात छोड़कर व्यक्तिकी ओर ध्यान दे रहे हैं यानी जातीय विभाज्य संपत्तिका कितना हिस्सा जमींदार या रक्षा है और कितना हिस्सा पूंजीपति, कितना हिस्सा मजदूर पाता है और कितना जनसामान्य, यही विचार आज सबसे प्रधान हो रहा है । इसमें धन वितरणकी सामान्यता स्पष्ट नजरमें आती है ।

इस असमानताका क्या कारण है ? यह असमानता जितनी गंभीर है,

विभिन्न सामाजिक वर्गों के भोग व्यवहारमें बड़ा स्पष्ट नहीं होती; लेकिन इसमें शक नहीं कि अधिकांश दृष्टिसे उच्चवर्गके लोग भोग व्यवहारमात्रिक सम्पत्तिहा संयच करते हैं और निम्नवर्गके लोग संयच नहीं कर पाते । यह संयच अर्थ उत्तराधिकार कानूनके द्वारा इच्छा होता रहता है और भनवितरणकी विषमता भी बढ़ती रहती है । जयसे पूंजीवादी आर्थव्यवस्थाकी शुरुआत हुई तबसे यह विषमता और भी बढ़ गई कारण पूंजीवादी आर्थव्यवस्था अधिकियोंके शोषण पर ही प्रतिष्ठित है । इस विषमताके प्रभावसे आज सामाजिक जीवन पर भी प्रतिबल प्रभाव पड़ रहा है । ज्यादातर समाजोंमें जातीय सम्पत्तिचा ३ हिस्सा ३ अंश जयताके हाथमें है और ३ अंश सम्पत्तिसे ३ अंश जयताका जीवन निर्वाह होता है । हमारी आर्थव्यवस्था ऐसी है कि इसमें उत्तरादन माधनोंका सामिल अल्पसंख्यक पूंजीवरतियोंके हाथमें छोड़ दिया गया है ; इस समाजमें सम्पत्तिहीन व्यक्ति आजादीके साथ नहीं रह सकता ; उसे जीवन निर्वाह करने के लिए अपनी सर्वसाधिकी बेच देनी पड़ती है और यदि इस अनसाधिकी को छोड़नेवाला नहीं मिला तो उसे बेकार हो रहना पड़ता है । इस समाज व्यवस्थामें कानून तथा विचार व्यवस्था पूंजीवरतियोंका मदद ही करते हैं । यह व्यवस्था तब तक ही कायम रह सकती है जब तक कि जयता मिश्रणका कारण निर्वाह हो, दरिद्रताके कारण संगठित न हो लेकिन बादरके लिये नहीं ।

उत्तराधिकार कानून भगके अलग विभाजनकी मदद पहुँचा रही है । अतीत समयमें पदराज्यसे किसीको अधिक सम्पत्तिहा सामिल मिला था वही आज तक उत्तराधिकार कानून पर अधिन होकर चला आ रहा है और इस अधिकांसी उत्तरादन व्यवस्था पर भी इसका सामिल जमा हुआ है । इस दृष्टिसे आज पूंजीवादीकी जति कुछ है । इसके अलावा अनसाधिकीयके कारण समाजके विभिन्न वर्गोंके अलग-अलग भी अलग-अलग दिगड़े पड़ गये हैं । पूंजीवादी पूंजी मजदूरे के हाथों रहते हैं लेकिन निर्धन केवल अपने अनसाधिकी

पर ही अवलम्बित हैं। धन वितरणकी विषमतासे हमें और एक समस्याका सामना करना पड़ता है ; वह दरिद्रता है। दरिद्रता जब समाजके निर्दिष्ट हिस्सेमें सीमित रहती है तब कोई गंभीर समस्या दिखाई नहीं देती लेकिन दरिद्रताकी व्याप्ति होने पर समाजमें अस्थिरता आनेकी सम्भावना बढ़ जाती है। दरिद्र लोगोंको दान देनेका निर्देश सभी समाजोंमें दिया गया है लेकिन दानसे असमानता दूर नहीं होती। इसके अलावा दान एक वस्तु है और अधिकार दूसरी। दान देना तथा लेना दोनों ही प्रगति-विरोधी हैं। इसलिए समाज-वादियोंने अधिकारका प्रश्न उठाया है।

इस व्यापक दरिद्रताके तीन कारण हमारे नज़रमें आते हैं। पहला उत्पादन-व्यवस्थामें ऐसी कुछ त्रुटियाँ हैं जिससे विभिन्न उत्पादन साधनोंको उचित मजदूरी नहीं मिलती; दूसरा वर्तमान उत्पादन-व्यवस्थामें मजदूरों को इतना जोखिम उठाना पड़ता है तथा उनके शरीर व मन पर इतना प्रतिशूल प्रभाव पड़ता है जिससे भी दरिद्रता बढ़ती है तथा तीसरा वर्तमान समाज व्यवस्थामें निम्नस्तरसे उन्नतस्तरमें आनेका सुयोग सुविधा कम होनेके कारण मजदूरों की आर्थिक उन्नति नहीं होती। आर्थिक दृष्टिसे उन्नत देशोंमें भी धन वितरणकी विषमता तथा दरिद्रता कम नहीं है। वर्तमान समयमें जोखिम इतनी अधिक होती है जिससे श्रमिकों के जीवन पर हर तरहके ग़तरे आते रहते हैं और इससे समाज कमजोर होती है। इस वर्षादीको रोकनेके लिए संगठन तथा सुधारकी आवश्यकता है। सामाजिक धीमाके द्वारा श्रमिकों का जीवन सुरक्षित करना भी उचित होगा। इनके अलावा निम्नवर्गके लोगोंकी आर्थिक दुरवस्था दूर करनेके लिए साधारण शिक्षा तथा व्यावहारिक शिक्षाकी आवश्यकता है एवं साथ ही साथ विभिन्न धन्योंमें श्रमिकोंका यथोचित वितरण करना भी उचित होगा। इस प्रकारसे दरिद्रता कुछ हदतक दूर हो सकती है लेकिन धनवितरण की विषमता नहीं क्योंकि जपतक धनोत्पादि सम्पत्ति पर व्यक्ति स्वामित्व रहेगा तबतक विषमतायें भी रहेंगी।

इस लिए धन वितरण समानताके अधिकतम विद्यमान आर्थिक संगठन के प्रतिफल हैं। जो लोग वर्तमान अर्थ व्यवस्थाका सर्वोत्तम नतीजा देने के लिये तैयार दृष्टिवाले हैं वे भी आज इस व्यवस्थाको आर्थिक समर्थन नहीं देते। इसलिए आज प्रत्येक देश ऐसी रास्ते की नीति प्रदान कर रहा है जिससे धन वितरण की असमानतायें दूर हो जायें।

समाजवादकी रूपरेखा—भारतीय जीवनमें समाजवादकी उपयोगिता

जब भी पृथ्वीमें औद्योगिक देशों पर सबसे ज्यादा प्रभाव मार्क्सवाद की दर्शनात्मक हुआ है। इस विद्यमानके पक्षमें और विरुद्धमें अनेक लेख लिखे गये हैं। परन्तु यह साहित्य मौलिक रहने पर भी मार्क्सवादकी समझमें और समझानेकी क्षममें गौरवता नहीं है। मार्क्सवादके आधार पर दूसरे जो विद्यमान गये लिखे गये हैं, वे समूर्ण समाजवाद नहीं हैं। वे तो धिरे इसका एक कम या बहुत भाग हैं। इन विभिन्न विचारों पर उनके अपने देग और समर्थन प्रभाव हैं। इस दृष्टिसे देखा जाय तो यह बात नानकी ही पड़ेगी कि कम्युनिस्ट-वाद तथा सोवियत-वाद भी एक प्रकारकी समाजवाद की अधिक योजना थी। परन्तु इसे समाजवादका पूर्ण विचार समझना गलत होगा। क्योंकि समाज-वादकी और बढ़नेका प्रभाव प्रसंगिक होता है। परन्तु इन सब विचारोंका एक तथा मार्क्सवाद की विद्यमान एक नहीं माने जा सकते। मार्क्सवाद की विद्यमान विचार रूप है। यह विद्यमान ही प्रत्येक देग और समर्थन संगठन के अधिक विचारकी एक अभिव्यक्ति होती है, और सामाजिक व्यवस्था इस तरह उस की है

तक नहीं पहुँचे, तब तक मार्क्सवादी सिद्धान्त उपयोगी नहीं हो सकता । बहुतसे विचारक अन्य सिद्धान्तोंसे मार्क्सवादकी इस भिन्नता पर ध्यान नहीं देते हैं । मार्क्सके बड़े-बड़े समर्थकों और विचारकोंने भी यह भूल की है । फलतः मार्क्सवादो सिद्धान्तके सम्बन्धमें अनेक भ्रमात्मक बातें फैल गयीं ।

मार्क्स अपनी समकालीन आर्थिक परिस्थितिको देखकर सम्भवतः निराशा हो गये थे और शायद उनको अपने सिद्धान्तकी भावी सफलताके बारेमें शंका भी थी । परन्तु, यदि बादकी घटनाओंका ठीकसे विचार किया जाए, तो यह बात माननी हो पड़ेगी कि यह निराशा भ्रान्तिपूर्ण थी । मार्क्सवादो सिद्धान्त आर्थिक इतिहासके विश्लेषणका फल है और वह आर्थिक विकास अवस्था-विशेष में ही सत्यसिद्ध हो सकता है । गत सौ वर्षोंकी आर्थिक घटनाओंका अध्ययन करने पर ही मार्क्सवादी सिद्धान्तकी सत्यता प्रतीत होगी और तभी पूर्णरूपसे मार्क्सवाद समझा जा सकता है । सौ वर्षके बाद आज हम सम्भवतः मार्क्स-वादकी अधिक स्पष्टतासे अध्ययन कर सकते हैं और भावी वर्णशास्त्रो हमसे भी अधिक विस्तारसे समझ सकेंगे ।

मार्क्सकी रचनाएँ प्रकाशित होनेके बादसे उनके सिद्धान्तोंका असर सिर्फ दूसरे दार्शनिकों पर ही नहीं, बल्कि बहुत-से राजनीति और कूटनीति विशारदों पर भी हुआ । वे लोग मार्क्सके सिद्धान्तोंकी कार्यान्वित करनेके उपाय सोचने लगे, परन्तु ये सब प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए । अर्थात् वे मार्क्सवादको स्थापित करनेमें विफल हुए, क्योंकि वे सिर्फ जनसाधारणकी किसी एक आर्थिक समस्या के संशोधनके लिए किये गये थे । वर्तमान राष्ट्र—उसका रूप और नाम जो कुछ भी क्यों न हो—वह जनताकी हार्दिक सहानुभूति और समर्थनके बिना प्रतिष्ठित नहीं हो सकता । वर्तमान स्थितिमें जनताका सच और उसका आर्थिक कल्याण प्रत्येक राष्ट्रको सोचना ही पड़ता है ; परन्तु इन सब बातोंमें मार्क्सवादी समाजवादका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । आर्थिक कल्याणकी पक्षों मार्क्सवादके सामने गौण हैं—इसका तुच्छ पहलू मात्र है । राजनीति तो

आधिष्ठित विद्यमान ही विमोह-अवस्था है और किसी प्रकारसे भी इसका विमोह नहीं किया जा सकता । मार्क्सवादकी राजनैतिक दृष्टिमें ही वैयक्तिक भूत है । राजनैतिक दृष्टिमें मार्क्सवादकी विद्यमान पर ध्यान देनेके कारण ही पहले महा-कुलके बाद लोपमें बहुत दिन तक गदगद मची थी और उसके जवत्ताकी बहुत कठिनायियोंका सामना करना पड़ा था ; क्योंकि वह उस समय मार्क्सके अनुगमियोंके उनके विद्यन्तोंकी ठोकरों नहीं समझनेके कारण अपना अपनी दार्शनिक दृष्टिकोण लुप्तप्राय प्रसक्ति देगोंमें हलचल मचा दी थी । इन लोपमें अपने दलकी साम्यवादों या समाजवादी नाम देकर जवत्ताकी विद्यमानकी करण आरम्भ किया । यह सब नैष्टा विकल हुई । कुछ समयके लिए सब कोड़े जननमें पड़ गये कि क्या मार्क्सवादकी विद्यमान ही आन्तरिक है या व्यवस्था प्राप्त ही गलत है ? इन समस्याका समाधान नहीं मिला । इन दिनोंमें जिससे पुराने साम्य-सन्धकी प्रकृति हुई और ये कुछ दिनोंके बाद ही फासिष्ट, नारकी प्रकृति जन-आन्दोलनोंके सूत्रनके सामने तिरफकी तरह चढ़ गये ।

इसमें कभी शक्ति ही सबसे ज्यादा विद्यमानका कारण बन गई । इन शक्ति से बहुतोंके मनमें धारणा पैदा हुई थी, सब कोपने लगे थे कि मार्क्सवाद राजनैतिक और आधिष्ठित परिस्थितिकी जड़में समाजवाद का यह नहीं है कि समाज की जातकी केवल आज तक सर्वजन विहित है कि इन जातों के समान से गिर गया है । इसमें दुर्दिनमें बहुतोंकी विमोह करके इन सब मार्क्सवादी दार्शनिकियोंकी बहुत विद्यमान हुई । कई लोगोंकी इन अनुगमियों को भी आधिष्ठित विद्यमान हुई कि ये मार्क्सवादकी विद्यमानोंकी लगे दृष्टिकोणों की लोपमें लगे, परन्तु मार्क्सवादकी किसी अन्य दृष्टिमें लोपका विद्यमान मना है । पहले ही कहा गया है कि समाजवाद आधिष्ठित विद्यमानकी यह विमोह विमोह ही गलत ही सकता है : इस विमोह का बहुतोंके लगे यह सब समाज नहीं ही सकता । शक्तिके द्वारा सब विद्यमान ही आधिष्ठित विद्यमान मना है ।

बहुत आगे बढ़ गया है ; पुरानी राष्ट्र-व्यवस्थामें यह कभी शायद सम्भव नहीं होता। अर्थात् आर्थिक परिस्थितिमें अचानक कोई भी परिवर्तन होना सम्भव नहीं है। वही क्रान्तिको यदि इस दृष्टिसे देखा जाय तो निराशाका कोई भी कारण प्रतीत नहीं होता लेकिन समाजवादके विकासकी कई सीढ़ियाँ हैं। पहली सीढ़ीमें देशके आधुनिक शिल्प और व्यापारका विस्तार और एक शोषित श्रमिक वर्गकी उत्पत्ति अवश्यम्भावी है। दूसरी सीढ़ीमें श्रमिकोंपर किये गये अत्याचारोंके फलस्वरूप उनमें वर्गचेतना दिखाई पड़ती है। जागृतिसे प्रभावित होकर वे अपनी शक्ति संगठित करते हैं और पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्थाको जड़से उखाड़ देनेका निश्चय करते हैं। इसके लिये सदैव विप्लवकी जरूरत नहीं पड़ती; लेकिन विप्लवके द्वारा श्रमिक शीघ्र ही अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। मार्क्स अपनी दूरदर्शिताके कारण इन सब बातोंका अनुमान लगा सकते थे। उनका सिद्धान्त पूँजीवादी उत्पादन-शक्तिके विस्फोटपर आधारित है। परन्तु पूँजीवादके समाप्त होनेपर समाज व्यवस्था कैसी होगी, इसका अनुमान मार्क्सके समकक्ष दार्शनिक भी नहीं बता सके। इसलिए वे साम्यवादी समाजका एक साधारण चित्र खींचनेके अतिरिक्त कुछ भी न कर सके। साम्यवादी समाजके बारेमें मार्क्सका कहना है कि इस समाज-व्यवस्था में सब कोई अपनी-अपनी सामर्थ्यके अनुसार काम करेंगे, परन्तु प्रत्येकको अपनी अपनी आवश्यकतानुसार सामग्रियाँ उपयोग करनेका अधिकार रहेगा।

‘नोथा प्रोग्रामकी समालोचना’ नामक ग्रन्थमें मार्क्सने लिखा है—‘साम्य-वादी समाज अपने-आपे आविर्भूत नहीं होता ; उसका विकास पूँजीवादी समाजसे ही होता है। फलतः आर्थिक, नैतिक और मानसिक दृष्टिसे इस समाजपर इसकी जन्मदातृ पूँजीवादी व्यवस्थाके चिन्हाँ वय तक शेष हैं।साम्यवादी समाजके प्रारम्भिक कालमें इन दुर्घटनाओंसे मुक्ति पाना असम्भव है ; क्योंकि पूँजीवादी समाजसे ही इसकी उत्पत्ति हुई है। साम्यवादी समाजकी उन्नत अवस्थामें जब कि व्यक्तिका पूरा विश्वास हो

जायेगा और जब उत्सादन अधिक विस्तार हो जायेगा और जब सामाजिक सम्पत्ति भग्नेही भाराकी तरह बँगवती हो जायेगी, केवल तभी पूँजीवाद की संकीर्ण सीमाएँ हम पूरी तौर से टलेंगी नर सकेगी ।" मार्क्स के इस कथन की राय है कि पूँजीवाद उत्सादन-रीति का अन्तनात अन्त कर देने से ही साम्यवाद समाज कायम नहीं हो सकती । साम्यवाद सामाजिक व्यवस्था पूँजीवाद समाज से अस्तित्व के द्वारा या स्वयं मन्दगति से आविर्भूत होगी, और कुछ दिनों तक इन दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं में इतना सम्बन्ध रहेगा कि इनका पार्यन्त भी स्पष्टनः दिखाई नहीं देगा । एक समाज का अन्त होकर दूसरी आविर्भाव के सम्भवकाल में दोनों समाज का मिश्रण हो जायेगा और वह तब तक कायम रहेगा जब तक कि पूँजीवाद समाज का निन्द तक लुप्त न हो जाय । मार्क्स ने वास्तविकता का निज हमारे सामने उद्घोषित किया है । परन्तु प्रश्न यह पड़ सकता है कि पूँजीवाद व्यवस्था कब तक कायम रहेगी ? इसका जवाब निर्णय करना असम्भव है ; पूँजीवाद समाज को अपने आविर्भाव तक की प्रगति ही इसका निर्णय करेगी ; देखिय इसका कहा जा सकता है कि जब उत्सादन-शक्ति बढ़ेगी और सामाजिक सम्पत्ति भी वृद्धि होगी तब ही समाजवाद सम्भव हो सकता है, उसके पहले नहीं ।

आधुनिक पूँजीवाद अर्थशास्त्र में समाजवाद को नहीं मानी थी मनी है; लेकिन यह तो पता चलता है कि उत्सादन के लिए अधिक से अधिक पूँजी लगाने पड़ती है और इससे तब तक आगे रुकना पड़ता है जब तक कि उत्सादन के साधनों का परिमाण पर्याप्त न हो जाय । पूँजीवाद अर्थशास्त्र को भाषा में पूँजीवाद और मार्क्स को भाषा में उत्सादन-वृद्धि यह दोनों बातें पर्याप्तानी हैं । इतिहास के सर्वमान्य ने देखेगा कि यह है कि 'सिद्धांत' की ओर उत्सादन पड़ने के ही मार्ग है । यदि हम ऐसा निश्चय करें कि उत्सादन के साधन बढ़े-बढ़े बढ़ने से भी रुक सकता है, और हमें उत्सादन को बहुत बढ़नी चाहिए, तो ऐसा निश्चय हमारे पहले पहले मार्ग को

(१७७)

उचित ध्यान देना पड़ेगा। मेरे विचार में समाजकी ओरसे उत्पादन साधनोंकी इतनी वृद्धि होनी चाहिए कि किसी भी समय उनकी कमी न आवे। यह समाजवादका वह स्तर है, जहाँपर पूँजीवादी उत्पादन लुप्त हो जाता है। इस स्तरमें पूँजीवादी उत्पादनका इतना विस्तार हो चुका है, कि उत्पादन साधनोंका परिमाण अशेष बन जाता है। फिर इन सब साधनों को कितना ही उपयोगमें क्यों न लाया जाय, इनके परिमाणमें कमी नहीं पड़ेगी। समाजवादके केवल इस स्तरमें पहुँचने से ही उपभोग्य वस्तुएं प्रचुर मात्रामें उपलब्ध हो सकती हैं और प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुसार मिल सकती हैं।

भारतीय-जीवनमें समाजवाद की उपयोगिता—ऊपरके विश्लेषण से यह स्पष्ट हो रहा है कि समाजवाद समाजके आर्थिक विकासके एक विशेष स्तरमें सम्भव होता है और इसके लिए सबसे पहले उद्योग-धन्धोंका विस्तार होना आवश्यक है। भारतीय जीवनकी वर्तमान स्थितिमें समाजवाद उपयोगी होगा या नहीं इसके बारेमें निश्चय करनेके पहले हमें रूसी क्रान्तिकी शिक्षा से लाभ उठाना चाहिए। क्रान्तिके पहले रूसी आर्थिक स्थिति हमारी स्थितिसे कोई अच्छी नहीं थी। इसलिए लेनिनने जो समाज व्यवस्था स्थापित की थी वह समाजवाद न हो सका। मार्क्सके समाजवादी आदर्शका कुछ हिस्सा जोकि लेनिनतंत्रमें रह गया था वह भी नई आर्थिक नीतिके पश्चात् लुप्त हो गया। इसके बाद पंचवर्षीय आर्थिक योजना कार्यान्वित की गई। भोग सामग्रियाँ बनाने वाले उद्योग-धन्धों को इस योजनामें गौण स्थान दिया गया क्योंकि रूसके उत्पादन-साधन उस समय तक इतने गिरे हुए थे कि उस परिस्थितिमें भोग सामग्रियोंकी उत्पादनमें वृद्धि करनेमें थोड़े-थोड़े दिनोंमें ही उत्पादनसाधनों का अन्त हो जाता। जिन अर्थशास्त्रियोंने भोग-सामग्री बनानेवाले उद्योगोंको अधिक महत्व दिया है, उन्होंने गलती की है। भोग-सामग्री बनाने वाले उद्योग तभी हमेशाके लिए कायम हो सकते हैं जबकि आर्थिक व्यवस्था उन्नत अवस्थामें हो और उत्पादन साधन

आवश्यकतानुसार बिना किसी रुकावटके बन सकते हों । इसके पक्षे अन्तर्-भोग-सामग्रियों बनानेकी कोशिश की जाय और उनमें अपनी सारी शक्तिकें लगा दो जाय तो भी वे मुश्किलें लिए नहीं बन सकती । आर्थिक विकास के एक विशेष स्तर तक उत्पादन साधन पैदा करने वाले उद्योगों को अधिक बढ़ाना पड़ेगा । उसके बाद इनके साथ साथ भोग-सामग्रियोंके उत्पादनमें रुक करनी होगी । इस प्रकारसे आर्थिक विकासके एक विशेष स्तरके परन्तु उत्पादन-साधन-उद्योगोंको बढ़ानेके लिए ही भोग-व्यवहार बढ़ाना पड़ेगा लेकिन उस स्तर तक उत्पादन-साधन-उद्योगोंको ही अधिक महत्व देना होगा । भारतीय जीवनमें अभी तक उत्पादन-साधन-उद्योगोंकी प्रतिष्ठा नहीं हुई तथा भोग-सामग्रियां पैदा करनेवाले उद्योग-धनमें भी काफी ताबदादमें नहीं हैं । इसलिए वर्तमान स्थितिमें आर्थिक समाजवाद हमारे लिए असम्भव है । यह तो तभी सम्भव हो सकता है जबकि अनेक उद्योग-धनमें देशमें स्थापित हो चुके हों तथा उत्पादन साधन भी काफी ताबदादमें देशमें ही बनाने योग्य इस स्तर तक हों पूर्णजीवाद पर ही अवलम्बित रहना पड़ेगा, चाहे यह व्यक्तिगत पूर्णजीवाद हो और चाहे राष्ट्रीय पूर्णजीवाद । यद्यपि लोग आर्थिक व्यवस्थाके राष्ट्रीयकरण को ही समाजवादी व्यवस्था समझते हैं लेकिन यह गलत है कारण जबतक पूर्णजीवादका पूर्ण विकास न होगा, जबतक उद्योग-धनमें काफी ताबदादमें स्थापित न होंगे तबतक पूर्णजीवादकी उपयोगिता नष्ट न होगी एवं साथही साथ राष्ट्रीय नीतिपर पूर्णजीवितियोंका अधिकार जमा हुआ रहेगा । इसलिए राष्ट्रीयकरण तथा समाजवाद एकार्थ बोधक नहीं हैं । पक्षे तो हमें आर्थिक विकास पर गंभीर ध्यान देना होगा । यह जब सम्भव होगा, देशमें जब विशेष सामग्रियां पैदा होने लगेंगी तब अपने आप भोग-व्यवहार बढ़ने की बातें सोचनी पड़ेंगी । उस दिन समाजवाद रोकने पर भी न रहेगा । उस दिन ही भारतीय जीवनमें समाजवादकी प्रतिष्ठा होगी, उस दिन पूर्णजीवाद अपने आप नष्ट हो जायेगा ।

पारिभाषिक शब्द

Above par—निर्धारित मूल्यसे ऊपर, अंकित कीमतसे ऊपर, अर्थात् मूल्य पर (वर्धा) ।

Acceptance—स्वीकृति, मंजूरी

” General—साधारण स्वीकृति या सकारना

” for Honour—महाजनी रक्षाके लिए स्वीकृति

” Qualified—विशेषित स्वीकृति, शर्तसहित सकारना ।

Account, Capital—पूँजी खाता

” Cash—रोकड़ खाता

” Cost—लागत खाता

” Current—चालू खाता

” Deposit—भ्रमानत खाता, जमा खाता

” Fixed—स्थायी खाता

” Sale—विक्री खाता, विक्री का हिसाब

” Suspense—उचरन्ती खाता

Advalorem duties—मुल्यानुसार कर

Allotment—(शेअरोंकी) बटनी, वितरण

Amalgamation—मिश्रण, एकीकरण, सम्मेलन

Annuity—वार्षिक वृत्ति (Consolidated)—ठोस, Deferred—

स्थगित या विलम्बित, Perpetual—चिरस्थायी, Reversio-

nary—उत्तराधिकार, Terminable—समाप्य या सावधि ।

Arbitrage—मध्यस्थ लाभ, अन्तर पणन (वर्धा)

Articles of Association—संघनियमावली, कम्पनी के नियमावली,
गर्भद अन्तर्निधन (वषी)

Assets—पूंजी, जलदाद, सेवक, सम्पत्ति (Fixed—स्थाय,
Floating or Circulating—आवृत्ति, अस्थायी का चल,
Frozen—नष्ट, Intangible—अस्पर्श का अस्पृश,
Tangible—पूंजी, Movable—आवृत्ति ।

At par—निर्वाण मूल्यनुसार, अर्थात् मूल्यपर

At Sight—दर्शनी, दर्शनीतर

Auctioneer—नीलाम करनेवाला

Average General—सामान्य जहाजी नुकसान पर दत्ता ।

„ Particular—सामान्य दत्ति, आन्तरिक नुकसान होने वाले
जहाजी नुकसान पर दत्ता ।

Aviation. Civil—आवृत्ति तरुन निष्ठा

Backwardation—दार्ढ्य, अर्थात् पुरान

Balanced Economy—समंजस का संतुलित आर्थिक-व्यवस्था

Balance Favourable—आवृत्ति अनुकूल विपत्ति

„ of Payment—(विदेशीयों के साथ) अर्थात् देन देने के समान

„ „ Trade—आवृत्ति-विपत्ति के समानता, आवृत्ति-विपत्ति का समानता

„ Sheet—कलक. विपत्ति-विपत्ति

Bank—बैंक, अर्थात् (वषी) । (Central—केन्द्रीय, Charge—

बैंक के समान का बैंक दत्त, Credit—समा का दत्त दत्त दत्त,

Clearing—बैंक का दत्त, Commercial—आवृत्ति-विपत्ति दत्त

दत्त दत्त का दत्त दत्त, Exchange—विपत्ति बैंक, Indus-

trial—आवृत्ति बैंक, Joint Stock—आवृत्ति पूंजी बैंक,

Private—निर्वाण बैंक, Rate—केन्द्रीय बैंक का दत्त, Sched-

uled—आवृत्ति दत्त बैंक) ।

(३)

Bankers, Indigenous—साहूकार, महाजन, देशी बैंक व्यवसायी

Banking Crisis—बैंकके कारबारमें संकट

„ Nationalisation of—बैंकोंका राष्ट्रीयकरण

Bargaining, Collective—सम्मिलित मोक्ष, समूही विपणन

(वर्धा), सामूहिक मौल भाव

Bear,—मन्दी वाला, मूल्यपाती (वर्धा)

Bilateralism—दो देशोंका परस्पर व्यापार

Bill, Accomodation—सिफारिशो हुन्दी, (Clean—ठुली,

Documentary—जोखमो, of Exchange हुन्दी, of

Lading—बिल्टी,) ।

Bimetallism—व्यधातुसुद्ध पद्धति

Blocked—रोका हुआ (सिक्का), रोकी हुई (रकम)

Board of Directors—संचालक मंडल

Body Corporate—अनुमोदन प्राप्त कम्पनी

Bond—बंधक पत्र, दस्तावेज, इकरारनामा

Bonded Warehouse—शुद्ध बाकी रखनेकी गुदाम । तिल पर

Bonus—अतिरिक्त लाभान्श

Boom—तेजी, व्यापारिक धूम

Bottomary—जहाज गिरवी रखकर फर्ज देना

Brokerage—दालाली

Bucket Shop—जुआड़ियों की कोठी

Budget—आय व्ययका अन्दाजपत्र या सालाना व्यौरा, घनट, आय-
व्ययक (वर्धा)

Bull—तेजी वाला, मूल्यारोपी (वर्धा)

Bullion—सोने चांदी की सिल

Business Cycle—व्यापारिक चक्र

Business Organisation—व्यापार संगठन

By-product—प्रदुब्धारी का गौण उत्पाद

Call—देखरौंदा शेष राधा प्रमा कराने की मांग (Money—मंगली राधा, मुद्रासामान्य मुद्रासे जाने गौण रकम ।)

Capital—रकम, पूँजी, मूलधन, (Authorised—अनुमोदित, Called up—मांगी हुई, Circulating—अवगत की मांग की हुई, Issued—जारी की हुई, Paid-up—प्रदत्त, Subscribed—बोली हुई, Watered—रुद्धिम या बनावटी, अधिपूँजी (वर्षा), Working—कार्यशील, धर्मवादक या सक्रिय ।)

Capitalisation—पूँजीकरण

Capitalism—पूँजीवाद

Cash Register—रोकर पट्टी

Centralisation—केन्द्रीयकरण

Certificate of Origin—उद्गम प्रमाण पत्र

Chamber of Commerce—व्यापारी मंडल

Cheap money—सस्ता राधा दर

Cheque—चेक, पत्रपेन (वर्षा), (Ante-dated—निष्ठली निष्ठली, Bearer—गली वोग, Marked—निष्ठली, Mutilated—पट्टी हुई, Order—आदेश, Post-dated—अगली निष्ठली, Stale—नष्ट ।)

Clearing House—निष्ठली केन्द्र, चेक मुद्रा भाग, समालोचन मुद्रा

Coinage—मुद्राकरण, मुद्रा (वर्षा) Free—बन्धहीन, (वर्षा)

Brassage—मुद्रा के मुद्रा मुद्रा, Gratuitous—निष्ठली,

Signiorage—मुद्रा के मुद्रा के अधिकार मुद्रा मुद्रा, मुद्राकरण)

Combination—एकीकरण, संयोजन, सम्मेलन, संयोग (वर्धा),
Horizontal—एक ही प्रकार कारखानों का एकीकरण, क्षैतिज-
संयोग (वर्धा), Vertical—शिल्पके विभिन्न कामोंका एकीकरण,
उदग्र-संयोग (वर्धा ।)

Commercial Treaties—व्यापारिक संधियाँ

Company—कम्पनी, प्रमण्डल (वर्धा) : (Holding—सूत्रधारी,
Limited—परिमित दायित्व, Promoter—मूलसंस्थापक,
Public—सार्वजनिक लोक प्रमण्डल । (वर्धा)

Competition—प्रतियोगिता, स्पर्धा (Cutthroat—हानिकारक,
कंठच्छेदी, Fair—उचित, Free—बाधाहीन, अबाध, Imperfect-
बाधायुक्त, Perfect—शुद्ध, प्रतिस्पर्धा ।)

Concentration—समावेश, गुट्ट

Confirmed Banker's Credit—शाह-स्विकृत-साख

Consideration—सुरञ्जती (Money—साइं, पयाना)

Consignee—माल पानेवाला, परेपणी (वर्धा)

Consignment—चलान, रक्ना, परेपण (वर्धा)

Consignor—चालान करने या भेजनेवाला

Consular Invoice—राष्ट्र दूतके द्वारा जारी की हुई चालान

Consumer—उपभोक्ता, ग्राहक, (Consumption—उपभोग,
खपत)

Contango—हरजाना, क्षति पूरण

Convertibility—विनिमय साध्यता, परिवर्तन योग्यता

Co-operative Credit Society—सहकारी कर्जदान समिति

Coparceners—भागोदार, हिस्सेदार, पांतीदार

Cornering of Market—बाजारको हाथमें या मुट्ठीमें करना

Cost—खर्च, मूल्य, लागत (Free—मुफ्त, बिना लागत, of Living—गहन छद्म का मूल्य, Overhead—ऊपरी मूल्य, Price—लगत मूल्य, Prime—प्रथम या प्रमुख लागत, Supplementary—अपको लागत

Cottage Industries—गृह-उद्योग

Credit—क़त्ता, क़ाबल, उधार, कर्ज प्रतिष्ठा, समावयन (वर्षा) ।
Book,—कर्म क़त्ता, Control—कर्म नियंत्रण, Creation—
कर्म सृष्टिरूप, Letter of—क़ाबलपत्र, Policy—कर्म दान नीति
Note—क़त्ताको चिट्ठी, Sale—उधारपर चिट्ठी ।)

Creditor—क़र्जदाता, उत्तरार्ज (Judgement,—निर्णये केतुद्वारा)

Crisis—क़ंजट (Commercial—व्यापारिक)

Crossing—रेखांकन, रेखन (वर्षा) । General—सामान्य,
Special—विशेष, Not negotiable—दस्तावर रहितकारक,
अ-व्यावयन (वर्षा) ।

Cross Rate—विविध दर

Cultivation—कृषि (Extensive—विस्तृत, Intensive—
गहन)

Currency—प्रचलित का चलू क़त्ता, चक्रवर्त्य (वर्षा) । (Depre-
ciation—मूल्य ह्रास, Managed—गठ्ठ नियंत्रित मात्र परिचय,

Pegging—बाहरी मूल्य बांधना, Standard—सुमत मान

Cycle, Trade—व्यावयन चक्र

Cypher Code—संकेत लिपि

Days of Grace—विश्रामकी दिन

Death duty—मृत्युदर

Debenture—क़ाबलपत्र, (Irredeemable—अपको का अर्पण,
Mortgage—क़र्ज, Redeemable—विपरीत का अर्पण

- Debit Note—नामे खातेकी बिल्टी
 Debt—कर्ज, ऋण, उधार (Bad or Deadweight—अनादायी,
 External—विदेशी, Floating—अल्पकालीन या धोरी
 Conciliation—कर्ज समझौता, Consolidated—
 संघनित, Conversion—परिवर्तन या स्वांतर, Funded—
 दीर्घकालीन, स्थायी, Productive—सार्वक, Public—सरकारी,
 Redeemable—शोध्य ।)
 Decimal System—दशमलव प्रणाली
 Deficit Financing—आधिक कमी पूरी करने का प्रवन्ध, दीनायें
 प्रवन्धन (वर्धा)
 Deflation—मुद्रा संकोचन, अपस्फीति
 Demand—मांग, अभियाचन (वर्धा) । (Draft—दर्शनी हुण्टी)
 Demonetisation—निमुद्राकरण
 Demurrage—(माल उठाने में) देरी या रुकावट का दर्जाना,
 विलम्बशुल्क
 Deposit Account—अमानत खाता । (Fixed—मियादी या
 स्थायी जमा ।)
 Depreciation—अपकर्ष, घिसावट
 Depression—मन्दो
 Devaluation—मुद्रा न्यून्य हासकरण, विनिमय दर घटाना
 Deviation—विवर्तन
 Discount—बट्टा (Discounting of a Bill—हुण्टी भुताना)
 Dishonour—नामंजूर करना, अस्वीकार करना
 Discrimination—पक्षपात । (Discriminating Protec-
 tion—शुल्क पक्षपात) ।

- Disequilibrium—अस्थिति ।
 Disinflation—मुद्रा प्रसार मुधारना
 Distribution—वितरण
 Dividend—लाभान्न (Cum-dividend—लाभान्नसहित, Ex-dividend—लाभान्न रहित ।)
 Draft—पैचकी हुण्डो, सरकारनेके पदले व्यापारिक हुण्डोको भी श्रावट कहते हैं ।
 Draw Back—वापस दी हुई मदसूची रकम ।
 Dumping—लागत से कम मूल्य पर विदेश में बेचना ।
 Earmarked sum—निर्धारित रकम ।
 Effective charges—क्रियात्मक व्यय ।
 Elasticity of Demand—मांगको लोच ।
 Endorsement—बेचना । (Blank—खाली का अन्वति होन, Facultative—इच्छाधीन, Restrictive—प्रतिबन्ध युक्त, Special—विशेष आदेश युक्त ।)
 Entrepreneur—उद्योगपति, जोकिम उद्योग चलाय
 Equilibrium—स्थिति
 Excess Profits Tax—अतिरिक्त मुनाफा कर
 Excise duty—उत्पादन कर
 Exchange Control—विनिमय विविध दर नियन्त्रण (Rate—विविध दर ।)
 Export—निर्यात
 Ex-Right—अतिरिक्त रहित
 Factor of Production—उत्पादन माध्यम
 Favourable balance of trade—अनुकूल वणिज्य संतुलन

- Fiat money**—सरकारी हुकुमपर प्रचलित कागजी मुद्रा, अपरिवर्त्य कागजी मुद्रा ।
- Fiduciary issue**—बगैर जमानतकी या विश्वासाश्रित कागजी मुद्रा ।
- Financial agreement**—आर्थिक समझौता
- Fire Insurance**—अग्नि बीमा
- Firm**—कारवारी संस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान । (**Equilibrium**—स्थिति सूचक कारवारी संस्था, **Optimum**—सबसे बढ़ी हुई कारवारी संस्था, **Representative**—प्रतिनिधि कारवारी संस्था ।)
- Fiscal Policy**—संरक्षण-राजस्वनीति ।
- Fluctuations, Cyclical** (चक्राकार उदयान-पतन)
- Foreign exchange**—विदेशी सिद्धा विनिमय
- Forward Contract**—सौदा, **Purchase**, अगाज खरीद
- Forwarding**—माल भेजना
- Free on Rail**—रेलपर चढ़ने तक बिना व्यय
- Freight**—मालका किराया
- Fund, Sinking**—ऋण परिशोध कोष
- Futures Market**—मुद्दी सौदेका बाजार
- Garnishee**—रोकना, (**Order**—अदालत से रोकने का निर्देश, प्राधमर्ण-निर्देश (वर्धा), सुपुर्दगोदारके नाम अदालती हुकम)
- Geometrical Progression**—असमान्तर गति
- Gilt-edged Bill**—उत्तम या साहूकारी हुन्डी ।
- Glut of Capital**—पूँजी की भरमार, (**of market**—बाजारमें मालकी प्रचुरता ।)
- Gold Bullion Standard**—स्वर्ण बिंदमान, (**Currency Standard**—स्वर्ण मुद्रामान, **Exchange Standard**—स्वर्ण-विनिमयमान, **Stand Reserve**—स्वर्ण-मान-कोष

Good, Economic—परिमित वा विकल्प सामग्री, (Will—
नेवकासी, प्रवृत्ति, वस्तु)

Graduated tax—वर्धमान कर

Handicraft—हस्त-उद्योग

Handsel—जनिम रजम, घातना, गार्दे

Hard Currency—दुम्रण विदेशी धन

Hire Purchase System—वित्तपर मूल-देय मज-मददक ।

Holder in due course—निवमानुसार हुपरी रखनेवाला

Holding uneconomic—धैमुनाकेस गेस, (Fragmentation
and subdivision of—छोटे और बिचारे हुप गेस, Consoli-
dation of—गेसोंकी बढवन्दी

Hydro-electricity—जलविद्युत, जलमक्ति

Hypothecation—बन्धक, (Letter of—बन्धक पत्र

Imperial preference—गमनाजान्तर्गत विभाजक, कार्यान्वित
वस्तुता ।

Impact of Taxes—कर संघात, करावत (वषां)

Incidence of Taxes—कर भार, वस्तुता (वषां)

Income—धन, (Inequality of—अवरोधवस्तुता, Natio-
nal धन, Per capita—प्रतिव्यक्ति धन ।)

Incorporation—वस्तुकी प्ररचना वा संघातना

Indebtedness, Rural—हवि वस्तु ।

Indemnity—हर्षा, वीम, हविद्वय ।

Indent—कराई, कार्यान्वित (वषां), मज नेवगे की वस्तु ।

Index Number—मूल्यमा मज वषां ।

Industrialisation—औद्योगिक विद्युत, औद्योगिकता ।

Inflation—स्फीति, सुद्रा प्रसार (Galloping—द्रुतस्फीति,
Hyfer—अति स्फीति)

Insurance—बीमा

Investment—पूँजी-विनियोग ।

Invoice—बीजक

Kartell—विक्रय संघ, संयुक्त विक्रय व्यवस्था ।

Law of Diminishing Return—घटती उपजका नियम ।

„ „ „ Utility—ह्रसमान उपयोगिताका नियम

„ „ Increasing Return—वर्धमान उत्पादन नियम ।

„ „ Marginal utility—सीमान्त उपयोगिता विधान ।

„ „ Total utility—कुल उपयोगिता का नियम ।

Letter of Credit—साखपत्र, of Indemnity—हर्जाना पत्र,
क्षतिपूर्ति का पत्र ।

Liability—दायित्व, देनो, (Limited—परिमित दायित्व ।)

Liquidator—दिवालिओंका ऋण चुकाने का प्रबन्ध

Localisation of Industries—उद्योग धन्योंका स्थानीय करण

Managing Agent—मैनेजिंग एजेन्ट, प्रधान प्रबन्धक, प्रबन्ध अभि-
कर्त्ता (Director—प्रबन्ध संचालक ।)

Marginal—सीमान्त

Marine Insurance—जहाज़ी बीमा

Market rate of discount—बट्टा का बाजार दर

Memorandum of Association—कम्पनी का संगठनपत्र

Merger—व्यापार संघ

Mint price of bullion—धातुकी सरकारी कीमत

Mobility—गति शीलता

Money Convertible—(विनिमय साधन मुद्रा, Token—चिह्न-मुद्रा ।)

Monopoly—दुरुपयोग, (Discriminating—व्यभेदक मुद्रा)

Moratorium—वर्षा मुद्रा को बंदी हुई निवृत्ति

Most-Favoured-Nation (M. F. N.) Clause—निर्वाह अनुदान व्यावहारिक भाग

Negotiable instruments—विनिमय साधन या दस्तावेज योग्य

Nationalisation—राष्ट्रीयकरण

Notary Public—समंजस को गरी हुज्जों को समझोद करने वाला अधिकारी ।

Noting—समंजस को गरी हुज्जों को समझोद करना ।

Optimum—अनुकूल्यता, प्रयत्न, शक्ति ।

Option deal—संजी मंडी का व्यवहार ।

Overcapitalisation—अधिक पूँजी विनियोग, अधिवर्धन (वर्धन)

Overdraft—अमानातिरिक्त धन

Overhead Charges—ऊपरी खर्च (Costs—ऊपरी लागत)

Owner's Risk—मालिक की क्षति

Partition Economics—विभाजन का व्यवहार

Partnership—सहकारी (Agreement—सहकारी का समझौता)

Permanent settlement—स्थायी बंधन

Planning, Economic—आर्थिक योजना

Power of Attorney—अनुमति

Price—दर, मूल्य, (Ceiling—ऊपरी मूल्य, Floor—निम्न दर, Level—मूल्य)

- Principle of Substitution—बदल सिद्धान्त
- Produce Exchange—कपज का सट्टा-बाजार
- Profiteer—मुनाफा खोर
- Profit Sharing—नफ़ा बांटना
- Progressive taxation—वर्धनशील कर
- Prospectus—परिचायक पत्र, विवरण पत्र
- Protective tariff—शिल्प संरक्षण शुल्क
- Public ownership—(उद्योगपर) राष्ट्रीय कर्तृत्व ।
- Purchasing Power Parity theory—(बिफ़ा विनिमय दरमें)
क्षयशक्ति की समता सिद्धान्त ।
- Quantity theory of money—(क्षयशक्ति के बारेमें) सिक्केका
परिमाण विषयक सिद्धान्त
- Quota System—अंश निर्देश व्यवस्था, आयात नियंत्रण व्यवस्था
- Rate of Exchange—विनिमय दर
- Reciprocity—परस्पर वाध्यता
- Reflation—नियंत्रित मुद्रास्कीति
- Ring—जहाजी कारवारिओंका गुट्ट
- Rural reconstruction—ग्रामोद्धार, गाँव सुधार
- Sans recourse—दायित्व रहित
- Scientific management—वैज्ञानिक परिचालन या संचालन
- Security—तनस्सुक, जमात
- Shares, Debenture—क़णसूचक हिस्सा या शेयर (Deferred—
विलम्बित हिस्सा, मुद्दती शेयर, Preference—रिआयती शेयर ।)
- Single Standard—एक मुद्रा पद्धति
- Sliding Scale—न्यूनाधिक क्रम

- Specimen Signature—नमूने का हस्ताक्षर
 Speculation—कटु
 Subsidy—सरकारी मदद
 Surrender value—बीटने पर बीमाका मूल्य
 Stock exchange—शेयर बाजार
 Tenancy Legislation—किसानों के अधिकार संरक्षण कानून
 Textile Protection Bill—कपड़ा संरक्षण बिल
 Trade discount—कटौती, कमिशन, (Union—मजदूर संघ)
 Trial balance—परीक्षा विवर
 Utility, Marginal—सीमांत उपयोगिता
 Underwriting—बिलों या बीमाका जिम्मा लेना
 Wages, Piece—कामके हिसाब से मजदूरी, (Time—कामके हिसाब से ।)
 Warehouse, Bonded—शुल्कके लिए गारंटी देने का गुराह
 Wear & tear—पिघलाव
 Wholelife assurance policy—आजीवन बीमा पत्र ।
-

